कहानी

शबनम परी

मंद-मंद समीर बह रही थी । पूर्व दिशा से सूरज धीरे-धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की-सी सुनहरी लाली छा गई थी। हरजोध नींद से जल्दी जाग गया, आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था । वह अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूँदें ऐसे लग रही थीं, जैसे किसी ने हरे मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों।

वह झुककर एक ओस की बूँद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरण उस बूँद पर पड़ी – और बूँद अचानक सात रंगों में चमकने लगी! हरजोध की आँखें चौंधिया गईं। वह खुशी से चिल्लाया – 'वाह! ये तो इंद्रधनुष बन गया!'

वह कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस कण पर जब किरण गिरती, तो उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल – सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोध को यह जादू-सा लगा। वह बोला, 'ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छिपे रहते हैं? '

उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदों में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसके कपड़े पारदर्शी थे, बाल चाँदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। वह मुस्कुराई और बोली, 'मैं शबनम परी हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूँगी। '

हरजोध हँस पड़ा, 'सचमुच तुम ओस से निकली हो? '

परी बोली – 'हाँ, हर बूँद में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है, तो प्रकाश सात रंगों में बिखर जाता है। इसीलिए मैं इंद्रधनुष जैसी लगती हूँ – यह प्रकृति का खेल है, और मैं हूँ उसका रूप! '

हरजोध के होठों पर मुस्कान खेल रही थी, उसने पूछा – 'ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है? '

परी मुस्कुराई, 'तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है! घास धरती की सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है, और रात में जब हवा ठंडी होती है, तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर ठहर जाती है। वह नमी ही ओस बन जाती है। बस यूँ समझो – घास और ओस माँ-बेटी जैसी हैं। घास धरती से जन्म लेती है, और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती हैं तो धरती मां मुस्कुराने लगती है। '

हरजोध की नज़र बगीचे के फूलों पर पड़ी, उन पर भी ओस की बून्दें चमक रही थीं, उसने पूछा, 'और फूलों का क्या रिश्ता है ओस से? '

परी ने कहा – 'फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं, तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है, और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस न हो, तो फूल मुरझा जाएँ। इसलिए तो कहते हैं –

'जहाँ ओस गिरे, वहाँ जीवन खिले।' '

हरजोध कुछ सोचते हुए बोला – 'लोग ओस की तुलना आँसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं? '

परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली – 'क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग-अलग रूप में समझी जाती है। देखो – जब किसी की आँखों से आँसू गिरते हैं, तो कभी वे दुख के होते हैं, कभी खुशी के। ओस भी ऐसी ही होती है – कभी धरती के दुख के आँसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की हँसी।'

हरजोध ने उत्सुक होकर पूछा – 'और पसीना? '

परी प्यार से बोली, 'हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ओस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है, तो रात को वह ठंडक पाकर अपने रोम-रोम से नमी छोड़ती है – जैसे कोई मेहनती किसान खेत जोतने के बाद पसीना बहाता है या कोई मज़दूर सारे दिन के सख्त काम से पसीने से नहाया-सा लगता है। इसलिए ओस में मेहनत और विश्राम दोनों की कहानी छिपी है। '

'और अमृत?' हरजोध ने आख़िरी प्रश्न किया।

परी ने अपनी हथेलियों में चमकती बूँदें उठाईं और बोली – 'जब कोई व्यक्ति सुबह ही ओस को देखता है, तो उसका मन ताज़ा और शांत हो जाता है। इसीलिए पुरानी कथायों में इसे देवतायों का अमृत कहा गया है। क्योंकि यह जीवन को नई ऊर्जा देता है। '

हरजोध ने कहा, 'तो क्या ओस सिर्फ़ पानी नहीं है? '

परी मुस्कुराई, 'नहीं हरजोध, ओस केवल पानी नहीं – यह धरती की साँस, आकाश का दुलार, और जीवन की मुस्कान है।

आवश्यक चुनाव सुधारों की प्रतीक्षा

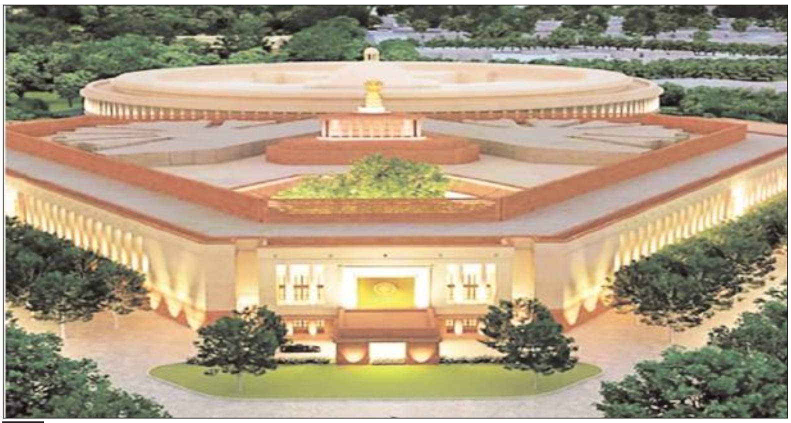

धनबल के दुरुपयोग होते हैं। खर्चीली रैलियां, होटल, वाहन और सैकड़ों चार्टर्ड विमान और आकाश में उड़ते हेलिकाप्टर चकित करते हैं। आखिरकार यह धन कहां से आता है? अधिकांश दल चुनाव में माफिया और धनबल का इस्तेमाल करते हैं। माफिया को टिकट देते हैं। अधिकांश दल पैसे वाले प्रत्याशी के साथ बाहुबली पर भी दांव लगाते हैं।

अपने देश में स्वस्थ-दलतंत्र का विकास नहीं हुआ। अनेक दलों में आजीवन/वंशानुगत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी दलों के संगठन चुनाव भी चुनाव आयोग को कराने के कानूनी प्रविधान होने चाहिए। उम्मीदवारों के पैनल भी स्थानीय समितियों, जिलों से होते हुए ऊपर आने चाहिए। जो दल अपने दल में जनतंत्र नहीं लाते, आय-व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं करते, चुनावी जीत के लिए माफिया/धनबली को उम्मीदवार बनाते हैं, उनसे ही चुनाव सुधारों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब माफिया के निधन की स्थिति में पत्नी या पुत्र प्रत्याशी हो जाते हैं।

प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वोहरा समिति (1993) ने संसदीय संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। चुनाव में कालेधन के प्रभाव और माफिया की पकड़ को घेरना जरूरी है। आखिरकार चुनाव सुधारों पर गंभीरता से विचार क्यों

संसदीय जनतंत्र की सारी कार्रवाई दलतंत्र से होती है। निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र का आत्मा है। जनतंत्र की सफलता का दारोमदार दलतंत्र पर है। आदर्श चुनाव प्रक्रिया से ही कार्यपालिका और विधायिका बनती है। इसी चुनावी प्रक्रिया में लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, पर चुनाव में धनबल और माफिया की भी भागीदारी है। इसलिए चुनाव आदर्श तरीके से नहीं हो पाते। निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 324) है। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी आयोग की ही है। सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान जारी है, पर इसे लेकर विपक्ष अकारण वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष और उसके नेता निर्वाचन आयोग के अधीन हुए चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़े थे। वोट चोरी होती तो विपक्ष की भारी संख्या में सीटें न होतीं। संसद के बीते सत्र में चुनाव सुधारों पर बहस अवश्य हुई, लेकिन वह वास्तविक सुधारों को लेकर नहीं हुई। सारा ध्यान एसआइआर पर रहा। यह समझा जाना चाहिए कि चुनाव सुधारों की गति धीमी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता 1967 में बनी थी। आचार संहिता का पालन सबका कर्तव्य है, मगर चुनाव अभियानों में अधिकांश दल आचार संहिता तोड़ते हैं। जनतंत्र में जन गण मन अपने भाग्य विधाता चुनते हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया बाहुबल और धनबल के द्वारा सत्ता प्राप्ति का खेल बन गई है। राजनीतिक दल इस खेल में मुख्य खिलाड़ी हैं। दल अपने नियमित संचालन पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन विचार और कार्यकर्ता आधारित संगठन नहीं बनाते। चुनाव नजदीक आते ही जिताऊ प्रत्याशी की खोज शुरू हो जाती है। धनबल के दुरुपयोग होते हैं। खर्चीली रैलियां, होटल, वाहन और सैकड़ों चार्टर्ड विमान और आकाश में उड़ते हेलिकाप्टर चकित करते हैं। आखिरकार यह धन कहां से आता है? अधिकांश दल चुनाव में माफिया और धनबल का इस्तेमाल करते हैं। माफिया को टिकट देते हैं। अधिकांश दल पैसे वाले प्रत्याशी के साथ बाहुबली पर भी दांव लगाते हैं।

अपने देश में स्वस्थ-दलतंत्र का विकास नहीं हुआ। अनेक दलों में आजीवन/वंशानुगत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सभी दलों के संगठन चुनाव भी चुनाव आयोग को कराने के कानूनी प्रविधान होने चाहिए। उम्मीदवारों के पैनल भी स्थानीय समितियों, जिलों से होते हुए ऊपर आने चाहिए। जो दल अपने दल में जनतंत्र नहीं लाते, आय-व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं करते, चुनावी जीत के लिए माफिया/धनबली को उम्मीदवार बनाते हैं, उनसे ही चुनाव सुधारों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब माफिया के निधन की स्थिति में पत्नी या पुत्र प्रत्याशी हो जाते हैं।

प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वोहरा समिति (1993) ने संसदीय संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। चुनाव में कालेधन के प्रभाव और माफिया की पकड़ को घेरना जरूरी है। आखिरकार चुनाव सुधारों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं होता? दलतंत्र के गलत आचरण से सुयोग्य और विचारनिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी टिकट नहीं पाते। चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। निर्धारित खर्च की सीमा से दस गुना, बीस गुना से भी काम नहीं चलता। सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने की बहस पुरानी है। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने भी ऐसी ही सिफारिशें की थीं। चुनाव आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए 2006 में दलीय परामर्श लिया था, लेकिन चुनाव सुधारों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। सुझाव यह भी था कि प्रत्याशी और दलों को अतिरिक्त खर्च से रोककर सरकारी खर्च पर चुनाव की व्यवस्था की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे व्यावहारिक नहीं माना। इंग्लैंड, आयरलैंड आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की सरकारें सीमित चुनाव खर्च देती हैं। अमेरिका में चुनाव का खर्च निजी क्षेत्र ही उठाते हैं।

राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में भी बहुत काम करना शेष है। जो धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचार के सहारे चुनाव जीत जाते हैं, उनसे कोई आशा कैसे की जा सकती है। माफिया जीतते हैं। मतदाता डरते हैं। पूंजीपति जिताऊ हैं। वे समर्थन खरीदते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पालिटिकल डायरी (पृष्ठ 146) में लिखा है, 'भारत में दल एक ही विचार करते हैं कि प्रत्याशी ऐसा हो जो चुनाव जीते।' उन्होंने सभी दलों से अपील की थी कि ईमानदार पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए। अगर प्रत्याशी आदर्श कार्यकर्ता नहीं है तो उसे वोट न दें।

संविधान निर्माता भविष्य के चुनावी भ्रष्टाचार और उसके परिणामों के प्रति सतर्क थे। सभा (16.6.1949) में हृदयनाथ कुंजरु ने आशंका व्यक्त की कि दोषपूर्ण निर्वाचन की व्यवस्था से लोकतंत्र विषाक्त होगा। केएम मुंशी ने कहा था, 'भारत की जनता को अपने प्रतिनिधि संदेह और पक्षपात रहित स्वस्थ प्रणाली के माध्यम से चुनने का अधिकार होना चाहिए।' प्रस्तावक डा. बीआर आंबेडकर ने कहा था, 'मताधिकार ही जनतंत्र का प्राण है।' संविधान सभा ने निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर लंबी बहस की। उन्होंने निर्वाचन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाया, लेकिन पहले आम चुनाव (1952) से ही निर्वाचन में धांधली शुरू हो गई। संविधान निर्माताओं की आशंका सच निकली। धांधली के आरोप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित बड़े-बड़ों पर भी लगे। जिस देश में प्रधानमंत्री को भी चुनावी कदाचरण का दोषी पाकर सदन की सदस्यता खारिज की गई हो, उसी देश में चुनाव सुधारों की धीमी गति से निराश होना स्वाभाविक है। चुनाव सुधारों पर समग्रता से विचार की गति बहुत धीमी क्यों है? जब दुनिया के कई देश निष्पक्ष चुनाव प्रणाली बनाने और उसे लागू करने में कामयाब रहे हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्री देश होने और आदर्श चुनाव प्रणाली विकसित करने का श्रेय भारत क्यों नहीं लेता?

सम्पादकीय

खाली बिस्तर पर लेटने पर डॉक्टर का आपा खोना, संवेदनशीलता पर बड़े सवाल

चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान और कौशल से मरीजों का जीवन बचाने और उसे बेहतर बनाने का काम करता है। चिकित्सक को मरीज के शारीरिक कष्ट का ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में चिकित्सक का व्यवहार और संवेदनशीलता कई मायनों में महत्त्वपूर्ण होती है। लेकिन कोई चिकित्सक अगर इलाज के दौरान आपा खोकर मरीज पर ही हमला कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में सोमवार को ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें एक चिकित्सक ने मरीज के साथ बहस के बाद उसकी पिटाई कर दी। मामले ने तूल पकड़ा, तो अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी चिकित्सक को निलंबित कर घटना की जांच शुरू कर दी। सवाल है कि अगर कोई मरीज असंतुलित व्यवहार भी करता है, तो क्या चिकित्सक का इस कदर आक्रामक होना उचित है? क्या उसका यह दायित्व नहीं है कि वह मरीज की मनोदशा समझकर संवेदनशील और संयमित तरीके से प्रतिक्रिया दे? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के अभाव का संकट बढ़ता जा रहा है, जिस कारण काम का दबाव भी बढ़ गया है। ऐसे में कई बार चिकित्सकों का व्यवहार सख्त हो सकता है, लेकिन उनसे मरीज के साथ मारपीट करने जैसी हरकत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शिमला के अस्पताल में जिस मरीज के साथ मारपीट की गई, वह फेफड़ों में तकलीफ की शिकायत लेकर वहां आया था। जांच के बाद सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे अस्पताल में ही कुछ समय के लिए आराम करने की सलाह दी गई। इसके बाद वह एक वार्ड में खाली पड़े बिस्तर पर लेट गया और इसी को लेकर चिकित्सक के साथ उसकी बहस हो गई। सवाल है कि अगर कोई मरीज भर्ती हुए बिना अस्पताल के खाली पड़े बिस्तर पर कुछ देर आराम कर ले, तो उस पर किसी चिकित्सक को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? चिकित्सक का प्राथमिक दायित्व मरीज के प्रति संवेदनशील होना और उसे राहत देने का होना चाहिए या नियम की दुहाई देकर उसे प्रताड़ित करने का? चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

बड़े खतरे के सामने बांग्लादेशी हिंदू

इस कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों की जमीनों पर कब्जा करना आसान था। यह कानून पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी वह अस्तित्व में रहा। इस कानून के कारण हिंदुओं और बौद्धों की लाखों एकड़ भूमि कब्जाई जा चुकी है। अराजक तत्व फर्जी कागजों के जरिये उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं की जमीनों से जुड़े लाखों मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। हालांकि शेख हसीना सरकार ने इस कानून में संशोधन किए, लेकिन वे अपर्याप्त साबित हुए। माना जाता है कि शेख हसीना की सरकार में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित पाते थे, लेकिन यह एक हद तक ही सही है। उनके शासनकाल में भी हिंदुओं का उत्पीड़न होता था। इतना अवश्य है कि खालिदा जिया शासन के मुकाबले कुछ कम होता था। इस कारण वहां से हिंदुओं का पलायन कभी थमा ही नहीं। समर्थ हिंदू विदेश जाते रहे और गरीब भारत

बांग्लादेश के मैमन सिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या जिस बर्बर तरीके से की गई, वह इकलौती ऐसी घटना नहीं, जो इस देश में हिंदुओं की दुर्दशा और उनके समक्ष उभर रहे खतरे को दिखाती हो। वे लगातार खतरे में रहे हैं और आगे यह बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद ही वहां के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर आफत टूट पड़ी। सच यह है कि भारत विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के हिंदू कभी चैन से नहीं रह पाए। भारत विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदुओं और विशेष रूप से दलित हिंदुओं की संख्या अधिक थी और इसका कारण दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल थे।

उन्होंने यह मानकर जिन्ना की मुस्लिम लीग का साथ दिया कि नए बने देश में दलित ज्यादा सुरक्षित और अधिकार संपन्न होंगे। उनका पूर्वी पाकिस्तान में अधिक प्रभाव था। मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री तो बने, लेकिन जिन्ना के निधन के साथ ही उनकी उपेक्षा और हिंदुओं की प्रताड़ना का सिलसिला कायम हो गया। मंडल तो इस्तीफा देकर चुपचाप कलकत्ता लौट आए, लेकिन उनके आश्वासन के चलते वहीं रहे गए हिंदू ठगे रह गए। हिंदुओं की प्रताड़ना पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में होती रही। पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के भागकर भारत आने का जो सिलसिला कायम हुआ, वह कभी थमा नहीं। जब पूर्वी पाकिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब वहां से पलायन कर भारत आने वाली अधिकांश आबादी हिंदुओं की ही थी। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों ने चैन की सांस ली, लेकिन इस नए बने देश में भी उनकी प्रताड़ना कम नहीं हुई। कट्टरपंथी तत्व जब-तब उन्हें निशाना बनाते रहते। इसमें एक भूमिका शत्रु संपत्ति कानून की भी रही। इस कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों की जमीनों पर कब्जा करना आसान था। यह कानून पाकिस्तान ने बनाया था, लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद भी वह अस्तित्व में

रहा। इस कानून के कारण हिंदुओं और बौद्धों की लाखों एकड़ भूमि कब्जाई जा चुकी है। अराजक तत्व फर्जी कागजों के जरिये उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं की जमीनों से जुड़े लाखों मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। हालांकि शेख हसीना सरकार ने इस कानून में संशोधन किए, लेकिन वे अपर्याप्त साबित हुए। माना जाता है कि शेख हसीना की सरकार में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक अपने को सुरक्षित पाते थे, लेकिन यह एक हद तक ही सही है। उनके शासनकाल में भी हिंदुओं का उत्पीड़न होता था। इतना अवश्य है कि खालिदा जिया शासन के मुकाबले कुछ कम होता था। इस कारण वहां से हिंदुओं का पलायन कभी थमा ही नहीं। समर्थ हिंदू विदेश जाते रहे और गरीब भारत भाग आते रहे। शेख हसीना अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाले जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ जिहादी तत्वों को काबू में रखती थीं। उनकी सरकार के तख्तापलट बाद ऐसे तत्व वहां बेकाबू हैं और इसीलिए पिछले 16 महीनों से वहां उनका दमन बढ़ गया है। तख्तापलट के बाद बनी छात्रों की नई पार्टी एनसीपी और इंकलाब मंच जैसे राजनीतिक समूहों की विचारधारा जमाते इस्लामी के निकट ही है। पिछले दिनों मारा गया छात्र नेता उस्मान हादी इंकलाब मंच का ही था। वह कट्टर भारत विरोधी था। बांग्लादेश के मौजूदा हालात वैसे ही खतरनाक दिख रहे हैं, जैसे शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दिख रहे थे। उस दौरान हिंदुओं पर जमकर हमले हुए थे। उनके घरों, दुकानों के साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। उस समय भी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस ने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आश्वासन दिए थे और इस समय भी दे रहे हैं, लेकिन वे खोखले ही साबित हो रहे हैं।

चिंतित करता बांग्लादेश, भारत को रहना होगा अलर्ट

बांग्लादेश में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी के भाई ने जिस तरह उसकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार को ही कठघरे में खड़ा किया, उससे यह साफ है कि इस मामले में भारत को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से काम किया गया। बांग्लादेश में हादी को गोली मारने वाले के भारत भाग जाने की अफवाह कई दिनों तक चलती रही, लेकिन वहां की सरकार और पुलिस ने इस पर कुछ न कहना ही बेहतर समझा। जब हादी के हत्यारे के भारत में छिपने की अफवाह के बहाने वहां उपद्रव बेलगाम हो गया और मीडिया के साथ-साथ हिंदुओं को भी निशाना बनाया जाने लगा, तब जाकर यह स्पष्ट किया गया कि हादी का हत्यारा बांग्लादेश में ही कहीं छिपा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि यह स्पष्टीकरण इसलिए दिया गया, क्योंकि

भारत विरोध अपनी हदें पार कर गया एवं उसकी चपेट में बांग्लादेश भी आ गया और अंतरिम सरकार की क्षमता पर सवाल उठ खड़े हुए। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व हमेशा से रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद उन्हें खुली छूट दे दी गई। अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने न केवल भारत विरोधी तत्वों को बेलगाम होने दिया, बल्कि उन्होंने खुद भी समय-समय पर उकसावे वाले बयान दिए। उन्होंने कभी बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को भारत से किया जाने वाला दुष्प्रचार बताया और कभी पूर्वोत्तर में चीन को सक्रिय होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उस पाकिस्तान से सहयोग का सिलसिला भी शुरू किया, जिसने बांग्लादेश में कहर ढाया था। इसी तरह उन्होंने जमाते इस्लामी और इस जैसे अन्य भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों की पीठ पर हाथ रखा। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त आधार हैं कि बांग्लादेश में भारत विरोधी जो माहौल बनाया जा रहा है, वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और यदि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के सहयोगी इस साजिश में शामिल नहीं हैं तो उसकी अनदेखी तो कर ही रहे हैं। लगता है कि शेख हसीना के प्रति अपनी चिढ़ के चलते वे भारत से संबंध खराब करने पर तुले हुए हैं। यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अवश्य हैं, लेकिन भारत को उनके रवैये को लेकर सावधान रहने के साथ ही यह भी देखना होगा कि बांग्लादेश में उसके हितों के खिलाफ जो काम हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्किये और पश्चिमी देश भी शामिल हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पश्चिमी देश और विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के खतरनाक उभार को लेकर किस तरह मौन साधे हुए हैं। ऐसे में भारत को बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर सतर्कता और चौकसी बरतने के साथ ही अपने कूटनीतिक कौशल का भी परिचय देना होगा।

सरकार की सकारात्मक पहल

केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टे जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देष दिए हैं। यह कदम स्वागत योग्य और सकारात्मक पहल है। आखिर यह फैसला अरावली की पास्थितिकी को बचाने और उत्तर भारत के पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण है। इस बाबत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद आईसीएफआरई को ऐसे संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे नए इलाके भी चिन्हित करने को कहा गया है जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह रोक पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा होगी। यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य अरावली की भौगोलिक संरचना को सुरक्षित रखना और अनियंत्रित खनन को रोकना है। बता दें, अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर पूरे राजस्थान को पार करती हुई हरियाणा के महेंद्रगढ़ और दिल्ली तक विस्तृत है। दरअसल गत माह बीस नवंबर को उच्चतम न्यायालय के एक फैसले में अरावली पहाड़ की दी गई परिभाषा को लेकर विवाद छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि सौ मीटर फार्मूला पुराना है जो पहले ही खारिज हो चुका है। इससे तो खनन माफिया को फायदा पहुंचेगा। जबकि केंद्र और भाजपा का कहना था कि यह परिभाषा पहले से कठोर है जिसमें केवल सौ मीटर या इससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा मानकर खनन प्रतिबंधित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने नई खनन लीज पर रोक लगाई है। दीर्घकालिक खनन योजना को अनिवार्य किया है। लेकिन पहाड़ियों की ऊंचाई की परिभाषा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेताओं के दिए गए बयानों से राजनीति भी काफी गरमाई। भाजपा नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस शासन दौरान अरावली पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया। अपने शासनकाल में दी गई परिभाषा को लेकर अब वह जनसामान्य में भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन की ओर से 'अरावली बचाओ, जीवन बचाओ' आंदोलन शुरू कर दिया गया। विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। राजधानी जयपुर में तो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने तो बाकायदा पदयात्रा निकालकर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। इसमें कोई दोराय नहीं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। भू-जल रिचार्ज का स्रोत है। दिल्ली-एनसीआर यहां तक उत्तर भारत में यह रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के साथ पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पिछले कुछ वर्षों से अनियंत्रित खनन से मिट्टी का कटाव बढ़ा। वनों की अंधाधुंध कटाई हुई। जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन आया। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अरावली में नए खनन पट्टों पर लगाई रोक और संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाने के लिया गया फैसला विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन लाएगा। जरूरत पुराने पट्टों पर निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्यवाही करने की है। इससे अरावली को स्थायी रूप से बचाया जा सकेगा।

यह सुधारवादी कदम प्रदेश के लिए कारगर साबित हो रहा

रूढ़ियों से मुक्ति की ओर राजस्थान

अभिमत

> आर्य समाज की पहली शाखाएं अजमेर और बीकानेर में 1880 के दशक के अंतक तक स्थापित हो चुकी थीं। धीरे-धीरे इसके प्रभाव का विस्तार पूरे राज्य में हो गया और इसने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में अहम योगदान दिया।

राजस्थान में यूं तो बाल विवाह की दर 25.4 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत 23.3 से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह राज्य बाल विवाह के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं, जिन्हें किसी समय समाज सुधारों की दिशा में क्रांतिकारी समझा जाता था। इसमें प्रमुख है आर्य समाज, जिसकी जड़ें राजस्थान में काफी गहरी हैं। आर्य समाज की पहली शाखाएं अजमेर और बीकानेर में 1880 के दशक के अंतक तक स्थापित हो चुकी थीं। धीरे-धीरे इसके प्रभाव का विस्तार पूरे राज्य में हो गया और इसने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में अहम योगदान दिया। इसने शादी विवाह में अनावश्यक खर्चों और आडंबर पर रोक लगाने के लिए सादा आर्य विवाह आंदोलन चलाया, जिससे सामूहिक विवाह समारोहों की प्रथा शुरू हुई। इन विवाह समारोहों में सभी जातियों और वर्गों के लोगों का एक साथ विवाह संपन्न होता था, जो रूढ़ियों और परंपराओं से बंधे इस राज्य में एक बेहद क्रांतिकारी कदम था।

सुधारवादी कदम

यह सुधारवादी कदम राजस्थान के लिए प्रतिगामी बन गया, जब इन सामूहिक विवाह समारोहों में नाबालिग जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाने लगा। हालांकि राजस्थान सरकार इससे अंजान नहीं थी और अक्षय तृतीया के मौकों पर बाल विवाहों को रोकने के लिए सतर्कता बरतती थी, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते रहे। वर्ष 2024 में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ने अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जेआरसी ने हाई कोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में एक सूची भी सौंपी, जिसमें कुल 57 बच्चों के बाल विवाह के ब्योरे दर्ज थे और इसमें 46 ऐसे थे, जिनका अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना था।

चौंकाने वाली कमी

पुलिस, प्रशासन व सरकार के बीच आपसी समन्वय और नागरिक संगठनों के सहयोग से पिछले साल अक्षय तृतीया पर बाल विवाह में चौंकाने वाली कमी दर्ज की गई। इससे साबित होता है कि कानूनी सख्ती, प्रशासनिक समन्वय व नागरिक समाज का सहयोग हो और बाल विवाह के खात्मे की प्रतिबद्धता हो तो इसे रोका जाना संभव है। इसके नतीजे अब जमीन पर दिख रहे हैं। सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहैवियरल चेंज फॉर चिल्ड्रेन की एक हालिया रिपोर्ट टिपिंग प्वॉइंट टू जीरो एविडेंस टूवाड्र्स ए चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के अनुसार राजस्थान में, पिछले तीन सालों में लड़कियों के बाल विवाह में 66प्रतिशत और लड़कों के बाल विवाह में 67प्रतिशत की कमी आई है। न्यायिक फैसलों ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को धार दी है, सफलता का श्रेय राजस्थान सरकार के प्रयासों को जाता है।

अंतरिम आदेश जारी

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस पर महज 36 घंटे में अंतरिम आदेश जारी करते हुए इन सभी 46 शादियों को रुकवाने का आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बावजूद बाल विवाह हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार बाल विवाह की रोकथाम का जिम्मा पंचों व सरपंचों का है। लिहाजा कहीं बाल विवाह होता है तो पंचों व सरपंचों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पंचों व सरपंचों की जवाबदेही तय करने का फैसला गेमचेंजर साबित हुआ क्योंकि राज्य के शहरी इलाकों में जहां बाल विवाह की दर 15.1 है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 28.3 प्रतिशत है। ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और हाई कोर्ट ने पंचायतों की जवाबदेही तय कर यही किया।

पंजीकरण अनिवार्य

सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने, शादी के निमंत्रण पत्र पर दूल्हा-दुल्हन की उम्र लिखने व सामूहिक विवाह समारोहों में भाग लेने से पहले उम्र के सत्यापन जैसे कारगर कदमों के साथ ही स्थानीय शासन में बाल विवाह की रोकथाम को शामिल करने और गांव स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन जैसी बहु-आयामी रणनीति अपनाई। जागरूकता अभियानों का असर भी दिख रहा है। नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों से लड़कियां अब खुद अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए आगे आ रही हैं। यहां तक कि बाल विवाह की पीड़ित लड़कियां अपना विवाह शून्य करने यानी विवाह को खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर रही हैं।

अदालती निषेधाज्ञा

नागरिक संगठनों और बाल संरक्षण एजेंसियों की मदद से बाल विवाहों की रोकथाम के लिए अदालती निषेधाज्ञा उपाय भी कारगर साबित हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार, न्यायपालिका और नागरिक संगठनों के प्रयासों के नतीजे उत्साहजनक दिख रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। इस नवाचारी प्रयास को गति देने की जरूरत है, ताकि सतत विकास लक्ष्यों की प्रप्ति के लिए 2030 तक राजस्थान व पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की विशेष जरूरत है। यदि पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों का दोबारा स्कूलों में दाखिला करा दिया जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्तियों से जोड़ दिया जाए, तो बाल विवाह के खात्मे का मुश्किल दिखने वाला लक्ष्य भी 2030 तक की तय समयसीमा में हासिल किया जा सकता है।

-नानूलाल प्रजापति
उपनिदेशक राजस्थान महिला कल्याण मंडल, अजमेर

जीवन बोध

समय बड़ा बलवान

जीवन में सदैव कोई न कोई समस्या रहती ही है। हम उस समस्या का सामना किस प्रकार करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और हम जो भीतर हैं, उसी का प्रतिस्वरूप हमारे आसपास होता है। अगर हमारे भीतर समस्या है, तो हमारे बाहर भी समस्या होगी। अगर हमारे भीतर समस्या नहीं है, तो हमारे बाहर भी समस्या नहीं होगी। हमें उस समस्या से भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समस्या कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है और समय ही सभी समस्याओं का हल है। इसलिए वर्तमान की किसी भी समस्या से भयभीत न हों। प्रत्येक समस्या को हम कितना महत्व देते हैं, वह हमारे ऊपर निर्भर है। अपने इष्टदेव पर विश्वास रखो और संपूर्ण समर्पित होकर विश्वास रखो और अपने जीवन की डोर उस परमात्मा को सौंप दो, जो आत्मा के रूप में भीतर बैठा है। वास्तव में, यही सत्य है लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपने आपको ही अधिक महत्व देते हैं। यह मैंने किया, वह मैंने ही किया, कहते हैं लेकिन जब कुछ गलत होता है, तो उसे परमात्मा की इच्छा कहते हैं। यह गलत है। अच्छा भी किया तो भी परमात्मा ने किया, बुरा भी किया तो भी परमात्मा ने किया। वो जिस स्थिति में रखे, रहना चाहिए। हां प्रयत्न हमारे हाथ में हैं। प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए।

-शिवकृपानंद स्वामी

हेल्थ इज वेल्थ

- ठंड में रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हृदय और मस्तिष्क पर खतरा काफी बढ़ जाता है।
- हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति आने का मूल कारण ठंड के दिनों की कुछ लापरवाहियां हैं, हमें कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। ठंड में सबसे बड़ी लापरवाही शरीर को पूरी तरह से न ढकना और सुबह-शाम की ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आना है।
- कई लोग सिर, कान और पैरों को खुला छोड़ देते हैं, जबकि शरीर की अधिकांश गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकलती है।
- जब ठंडी हवा सीधे शरीर से टकराती है, तो रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ जाती हैं।
- इससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और हृदय को शरीर के अंगों तक खून पहुंचाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जो अचानक हार्ट अटैक का कारण बनता है।

जल तरंग

स्वदेशी अपनाओ

विदेशों में किए गए अध्ययन मुझे हमेशा आकर्षित, प्रभावित और द्रवित करते रहे हैं। वह बात दीगर है कि हमारे लोकप्रिय नेता कुछ अंतराल के बाद यह कहते रहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और जीवन चलाओ लेकिन, होता कुछ ऐसा है कि विदेशी वस्तुओं,का आकर्षण बढ़ता ही जाता है। विदेशी तकनीक जिंदगी में इतनी ज्यादा भीतर तक घुस आई है कि जितनी बार पूछेंगे बता सकते हैं। वैसे तो इस तरह की तकनीक हमारे यहां सदियों पहले थी, लेकिन यहां आए विदेशी शासकों ने उसे तहसनहस कर दिया था। हम खुद भी अपना काफी कुछ भूल गए थे। अब याद आता रहता है, तो हमारे नेता याद दिलाते रहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और आनंद पाओ। वह बात दीगर है कि सुधरना मुश्किल होता है और बिगड़ना आसान। अब यह, विदेशी छोड़ो और स्वदेशी जोड़ो के विशुद्ध नारे के कारण मानसिक शांति बर्बाद होने लगी है। व्यक्ति नाश्ता करने के बाद निश्चय करता है कि आज रात को खाना जल्दी खाएगा, थोड़ा टहलेगा, एक दो भजन सुनकर फोन बंद कर दूर रख देगा और सो जाएगा। कल सुबह ब्रह्म मुहर्त में उठ जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। विदेश में किया एक अध्ययन भी, भारतीय शैली में, दिमाग की शांति उगाने का फार्मूला बता रहा है। दिलचस्प यह है कि विदेशियों ने सुबह के तीन बजे के आस पास के समय को मस्तिष्क के लिए सबसे असुरक्षित माना। इत्तफाक से यह समय हमारे ब्रह्ममुहर्त के आसपास का ही है। उनके अनुसार इस समय चिंता और डर बढ़ा हुआ होता है, संभवत तभी इस समय को हमारे यहां बिस्तर छोड़ने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नुक्ते सुझाए हैं, ताकि शांति बनी रहे। उनके अनुसार दिन ढलने से पहले कागज पर लिख लें कि किन बातों पर आपका नियंत्रण है और किन पर नहीं। जिन पर है उन्हें अगले दिन की कार्यसूची में डालें बाकी को भूल जाएं, इससे चिंता स्थगित हो जाएगी। कोई किताब पढ़ें या खेल खेलें इससे दिमाग चिंता से बाहर निकलेगा। पास रखे पत्थर, लकड़ी या कपड़े के टुकड़े को छूएं, धीरे धीरे पानी पिएं, हल्का संगीत सुनें, यह बेचैनी कम करेगा। करवटें न बदलें, उठकर मंद रोशनी में कुछ करें, जैसे कपड़े तह करना या ड्राअर का सामान ठीक करना, इससे दिमाग बिस्तर को नींद से जोड़ेगा। दिन की मामूली बात रात को बड़ी लगती है, खुद से कहें सुबह देखेंगे। खुद से कहते रहें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा, सबसे पहले आराम जरूरी है, इससे मन स्थिर होगा। आखिरी सलाह है यदि कभी कभी नींद उचाट हो तो कोई बात नहीं। नींद टूटना सामान्य बात है, कोशिश करें आ जाएगी। उनकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन, इस मामले में हमें महा स्वदेशी फार्मूला ही ज्यादा सफलता दिलाएगा। हमारे अस्त व्यस्त और मस्त जीवन में सबसे सफल फार्मूला है, देर रात तक डाटा का मनचाहा प्रयोग जिससे सबसे ज्यादा शांति मिलती है।

-संतोष उत्सुक
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

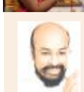

जो सुख में साथ दे उसे रिश्ता कहते हैं, जो दुख में साथ दे, उसे फरिश्ता कहते हैं। फरिश्तों का सम्मान कीजिए और फरिश्तों को सम्हालकर रखिए।

-श्री चंद्रप्रभ जी

विंडो टू द वर्ल्ड

लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, तेलंगाना

हेमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, जो तेलंगाना के वारंगल जिले के मल्लूर गांव में स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर पुट्टकोंडा नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की मूर्ति इस पहाड़ी से स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर 4000 साल पुराना है,यहां नरसिंहा की मूर्ति हार्ड नहीं,बल्कि ह्यूमन बॉडी की तरह सॉफ्ट है।

अपनों से अपनी सी बात

दिव्यता के लिए स्वाध्याय

अपने आप को दिव्य बनाने के लिए, दिव्यता से युक्त होने के लिए हमेंचाहिए कि स्वाध्याय करते हुए अपनी आत्मा को निखारें। प्राचीन परम्परा रही है कि गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद विदाई के लिए गुरु चरणों में जब शिष्य पहुंचता था, तब गुरु अपने शिष्य को उपदेश के आखिरी वचन कहते थे, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना। स्वाध्याय में प्रमाद, आलस्य नहीं करना। ऋषियों द्वारा रचित ग्रन्थ जिनमें डुबकी लगाने पर विचारों के हीरे-मोती मिले, वे ही स्वाध्याय के योग्य हैं। जिन ग्रन्थों को हमारे ऋषियों और अवतारी पुरुषों ने दिया उन्हें पढ़िए। उपनिषद, सूत्र ग्रन्थ, नीति ग्रन्थ, वेद, दर्शनशास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, सन्तों की पवित्र वाणीयां, ये सब हमारे स्वाध्याय के लिए हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किये गए अन्वेषण और महापुरुषों की जीवन गाथाओं का हम स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। हमारे अन्दर विशेषताएं आने लगेगी। हमारे विचार ऊंचे होंगे। याद रखें जैसी विचार शक्ति हम अपने अन्दर रखेंगे, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। दिव्यता की तरफ जाने के लिए दिव्य विचारों को अपने अन्दर आने दो, विचार जो हमें ऊंचा उठाएं। निराशा के ऐसे विचारों को अपने अन्दर कभी नहीं आने देना जो हमें गहरी खाइयों में धकेल दें। कुविचार अच्छे विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। कुविचारों को उखाड़कर बाहर फेंक दें और सुविचारों को खाद-पानी डालते रहें, जिससे वे और पनपे और अपनी जिन्दगी खिलती चली जाए। स्वाध्याय का एक मतलब स्वयं का अध्ययन करना भी होता है। स्वयं का अध्ययन करने का मतलब है अपने आपको जानना, अपने साथ मीटिंग करना।

-ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

स्मृति शेष

शुक्ल, अपने समय से थोड़ा आगे, अपनी भाषा में बहुत भीतर थे

वह चला गया विचार की तरह देह को छोड़कर

> वह चला गया विचार की तरह पुरानी देह को छोड़कर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1960 की कविता है। अब से 65 साल पुरानी। और उसी विचार की तरह चलने वाला आदमी विनोदकुमार शुक्ल, अपने समय से थोड़ा आगे, अपनी भाषा में बहुत भीतर और अपनी सादगी में इतनी गर्माहट कि साहित्य का पूरा जाड़ा उसमें टिक जाए।

वह कवि था। वह चला गया विचार की तरह पुरानी देह को छोड़कर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1960 की कविता है। अब से 65 साल पुरानी। और उसी विचार की तरह चलने वाला आदमी विनोदकुमार शुक्ल,अपने समय से थोड़ा आगे, अपनी भाषा में बहुत भीतर और अपनी सादगी में इतनी गर्माहट कि साहित्य का पूरा जाड़ा उसमें टिक जाए। विनोदकुमार शुक्ल का नया गरम कोट कोई वस्त्र नहीं, उनकी भाषा है। वह भाषा, जो बहुत सीधी, बहुत घरेल लगती है,लेकिन पहनते ही दुनिया का ताप बदल देती है। वे विचार की तरह चलते हैं। बिना शोर, बिना प्रचार, बिना सड़कों पर पोस्टर। उनकी चाल में घोषणापत्र नहीं, संवेदना की चुप तड़प है और इसी में उनका अनूठा कृतित्व चमकता है।

तयशुदा आलोचना

रबड़ की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया। उनके पीछे चलने वाला पाठक अक्सर रबड़ की चप्पल में ही होता है यानी अपनी आदतों, अपनी व्याख्याओं,अपनी तयशुदा आलोचना-भाषा में। शुक्ल की रफ्तार अलग है। वे जटिल को सरल बनाकर नहीं, सरल के भीतर जटिलता को बचाकर आगे निकल जाते हैं। इसलिए हम पिछड़ते हैं और यही पिछड़ना उनके साहित्य का पहला दीक्षा-मंत्र है। जाड़े में उतरे हुए कपड़े का सुबह छः बजे का समय। सुबह छः बजे की तरह। उनका जीवन और लेखन दोनों का समय अक्सर सुबह छः बजे वाला है। हल्की धूप, हल्का कोहरा, काम पर निकलती दुनिया और भीतर की दुनिया का जागना। पेड़ के नीचे आदमी था। विनोदकुमार शुक्ल के यहां पेड़ के नीचे आदमी बार-बार मिलता है। एक ऐसा आदमी जो मंच पर नहीं, छाया में है। उनके पात्र, उनकी आवाज, उनकी दृष्टि सब किसी पेड़ के नीचे खड़े मिलते हैं।

उनका जीवन-शिल्प

साधारण, टिके हुए और दुनिया की तेज धूप से थोड़े बचे हुए। यही उनका जीवन-शिल्प भी रहा। चमक-दमक से दूर रहकर भी साहित्य के सबसे जीवित हिस्से में मौजूद। कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। यह पंक्ति जैसे उनके जीवन का भी रूपक है। सार्वजनिक जीवन के कोहरे में वे धब्बे की तरह दिखते हैं। कम दिखाई देने वाले, कम प्रचारित। लेकिन उसी धब्बे के अंदर वह आदमी है। एक पूरा लेखक, एक पूरा संसार, एक पूरा नैतिक ताप। उनका कृतित्व इसी भीतरपन से बना है बाहर कम, भीतर अधिक। पेड़ का धब्बा बिलकुल पेड़ की तरह था। शुक्ल की खासियत यही है। वे प्रतिरूप को भी वास्तविक बना देते हैं। उनकी भाषा धब्बा नहीं लगती वह बिलकुल पेड़ की तरह लगती है। इसलिए उनके वाक्य, जो पहली नजर में सामान्य हैं, असल में जीवन की हूबहू बनावट हैं। वे रूपक नहीं थोपते,वे जीवन को उसी के धब्बों सहित उठा लाते हैं।

मनुष्यता की मुख्यधारा

दाहिने रद्दी नस्ल के घोड़े का धब्बा, रद्दी नस्ल के घोड़े की तरह था। यहां शुक्ल का नैतिक संसार प्रकट होता है। वे जिनको समाज रद्दी कह देता हैं, उन्हें वे कविता के केंद्र में रख देते हैं। उनका साहित्य हाशिए के जीवों, अदृश्य लोगों, छोटे कामों, छोटे डर, छोटे सुख सबको मनुष्यता की मुख्यधारा में वापस लाता है। घोड़ा भूखा था, तो उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था। उनके जीवन-कृतित्व की सबसे अनूठी बात यही करुण कल्पना है भूख के सामने भी भाषा हार नहीं मानती, वह कोहरे को घास बना देती है, धोखा देने के लिए नहीं, जीवित रखने के लिए। शुक्ल का लेखन गरीबी,अकेलेपन, मामूलीपन और असहायता को रोता नहीं,वह उन्हें देखने लायक बनाता है, उसी में एक चुपसा सहारा उगा देता है। कई मकान, कई पेड़, कई सड़कें इत्यादि कोई घोड़ा नहीं था। यह उनकी सभ्यता-आलोचना का सबसे शुक्ल-शैली वाक्य है।

लेखक का विनय

अकेला एक घोड़ा था। मैं घोड़ा नहीं था। यहां लेखक का विनय है और दूरी की ईमानदारी भी। शुक्ल कभी मैं ही सब हूं, नहीं कहते। वे अपने पात्रों के दुख में घुसते हैं, पर उनकी जगह हड़पते नहीं। यही उनकी नैतिक शुद्धता है और यही उनके कृतित्व की गरिमा। लेकिन हांफते हुए, मेरी सांस हुबहू कुहरे की नस्ल की थी। यह पंक्ति उनकी भाषा के अद्भुत जीव-विज्ञान की तरह है सांस की नस्ल ! उनकी सांस कोहरे की नस्ल की है यानी वे जिस वातावरण में लिखते हैं, उसी से बने हैं। यदि एक ही जगह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वह मालिक आदमी था, तो उसके लिए मैं दौड़ता हुआ, जूते पहिने हुए था, जिसमें घोड़े की तरह नाल ठुकी थी। यह उनके पूरे साहित्य का सामाजिक नक्शा है मालिक स्थिर है,मैं दौड़ता है। व्यवस्था पेड़ के नीचे आराम से खड़ी है श्रम हांफता है। और श्रम को मनुष्य रहने के लिए भी घोड़े की तरह बनना पड़ता है,जूते में नाल, चाल में मजबूरी, जीवन में प्रतिस्पर्धा। शुक्ल की ताकत यह है कि वे यह सब नारे में नहीं कहते, वे एक दृश्य में रख देते हैं और दृश्य पाठक के भीतर देर तक टिकता है।

-त्रिभुवन
यह लेखक के अपने विचार हैं।

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 26-12-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH08 User: cci Time: 12-25-2025 22:02 Color:

> जहां नैतिकता न हो उस राजनीति का कोई अर्थ नहीं है।
>
> – महात्मा गांधी

यूनुस पर सवाल

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के स्वनिर्वासन के बाद गुरुवार को देश लौटे, जिन्हें देश का अगला पीएम माना जा रहा है। इस बीच, अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जिन कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया था, आज वही देश में शांति-सौहार्द के लिए चुनौती बन गए हैं।

गंभीर आरोप । शेख हसीना को पद से हटाने के बाद छात्र नेताओं ने इस उम्मीद के साथ मोहम्मद यूनुस को कमान सौंपी थी कि वह एक बेहतर व्यवस्था की नींव रखने में मदद करेंगे।

तारिक की वापसी

हालांकि कुछ महीनों बाद ही यह उम्मीद टूटने लगी थी और चुनाव को लेकर जिस तरह की खींचतान मची, उससे लगा कि अब लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन नहीं, सत्ता कब्जाने की है। इस कड़ी में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके भाई के लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं।

कट्टरपंथियों की साजिश । हादी के भाई का कहना है कि सरकार से जुड़े लोगों ने हादी को मरवाया, ताकि चुनाव टाला जा सके। सभी दलों को समान अवसर नहीं देने के कारण यह चुनाव पहले ही संदेह के घेरे में है। इस आरोप का मतलब है कि सत्ता में शामिल कुछ तत्व जानबूझकर बांग्लादेश को अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं और वहां भारत विरोधी झूठा नैरेटिव बनाने में भी उन्हीं की साजिश है।

भारी पड़ेंगे सवाल । हादी कट्टर विचारधारा के युवा नेता थे, जो जुलाई क्रांति से उभरे थे। बांग्लादेश के मौजूदा माहौल में उनका कद बहुत बढ़ गया था, ऐसे में उनके परिवार की ओर से उठाए गए सवाल मोहम्मद यूनुस पर भारी पड़ सकते हैं। खराब कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए उन पर पहले से अंतरराष्ट्रीय मंचों का दबाव है।

निष्पक्षता पर शक । इस बात पर शुरू से संशय था कि शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाएगा। अब सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है और वह भी उस दिन, जब तारिक रहमान देश लौटे हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे तारिक को अंतरिम सरकार में ही राहत मिली और उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ। उन्हें पीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। उनकी पार्टी BNP फिलहाल आगामी आम चुनाव जीतने के लिहाज से सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन, क्या अवामी लीग के बगैर होने जा रहे इस चुनाव को बांग्लादेश की जनता का सही मत माना जाएगा।

तिराहा

सब्ज़बाग़

कमला को सुधर्मा डांटे जा रही थीं। जितनी बार वह सड़क देखतीं, उनका पारा चढ़ जाता। सुखनंदन ने माजरा समझा तो पता चला, सड़क घर के फर्श से ज्यादा चमक रही थी, लेकिन उसे रगड़े जाने का क्रम जारी था, इधर भीतर कमला थककर बैठ गई थी।

प्रेम शंकर मिश्र

सुखनंदन ने समझाया, 'प्रिये! आज देश के प्रधान आ रहे हैं, इसलिए चमक है। कल से यथावत हो जाएगी। इसके लिए इस बेचारी को मत कोसो।' सुधर्मा तुनक गईं, 'आज भी वैसे ही रहने देते, हकीकत तो पता चलती।' सुखनंदन मुस्कुराए, 'पगली, तुम तो व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दोगी। तुम्हें सिद्धार्थ की कथा नहीं पता?'

'राजा शुद्धोधन के घर पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि यह बड़ा होकर फकीर बनेगा। परेशान राजा ने सिद्धार्थ को सुविधाओं के बंधन से बांध दिया। वह जहां जाते, वहां ऐश्वर्य का सब्जबाग ही दिखता। लेकिन, एक दिन गलती से उनकी नजर एक शवयात्रा पर पड़ गई, मिथक टूट गए, दुःख का भान हुआ। उन्होंने विरक्ति का मार्ग पकड़ लिया।'

'इस कथा का आज से क्या लेना-देना?' सुधर्मा ने जिज्ञासा व्यक्त की। 'प्रिये! शुद्धोधन व्यवस्था यानी तंत्र का प्रतीक है। उसका कार्य है सब्जबाग को बनाए रखना। नेतृत्व बुद्ध हो गया तो तंत्र के दुख को पहचान लेगा। यथार्थ जान उसे उन व्यवस्थापकों से विरक्ति होने लगेगी जो उसके आंख-कान हैं। इसलिए उनका लाभ उसे बुद्ध नहीं, 'बुद्धू' बनाने में है। वैसे भी बापू का रामराज्य हमारा आदर्श है - नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। प्रजा न सही, राजा ही रामराज्य उतरता महसूस कर ले। तंत्र का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।' सुखनंदन ने समझाया।

'अरे देश में राजशाही थोड़े है, लोकतंत्र है?' संशय भरा प्रश्न उठा। 'प्रिये! लोकतंत्र में उतना ही 'लोक' है, जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन। लोक वह घोड़ा है, जिसे घास दिखा उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है। सावन के अंधे की तरह हरे भाव से भरा वह दौड़ता रहता है और तंत्र सवारी का लुत्फ उठाता है।' सुखनंदन ने जवाब दिया।

एकदा

संकलन : रेनू सैनी

सीखने की ललक

18वीं सदी के प्रभावशाली और महान चित्रकारों में ब्रिटेन में एक नाम उभरा, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। उन्होंने अपनी चित्रकला से दुनिया को प्रभावित किया। यह उन दिनों की बात है जब वह अपनी कला को निखारने के लिए बेचैन थे।

Subrata Dhar

इसी सिलसिले में वह एक बार इटली गए। वहां उन्होंने वेटिकन में राफेल और माइकल एंजेलो की कलाकृतियों का गहन अध्ययन किया। उनकी कृतियों का अध्ययन करते समय वह अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। उन दिनों वेटिकन में बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। रेनॉल्ड्स अपने काम में इतने अधिक रमे हुए थे कि उन्हें बिगड़ते मौसम का भी आभास न हुआ और उन्हें गंभीर सर्दी लग गई। वह इतना बीमार हो गए कि उनकी सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। उनके मित्र ने कहा, 'यदि आप इटली नहीं जाते तो आपकी सुनने की क्षमता नहीं जाती।' इस पर रेनॉल्ड्स ने कहा, 'यदि कला को निखारने के लिए मुझे सौ बार भी सुनने की क्षमता गंवानी पड़े, आंधी-तूफान और बर्फ का दबाव झेलना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन कला के साथ समझौता करना स्वीकार नहीं। वहां जाकर ही मुझे चित्रों में छिपे गूढ़ अर्थ मिले हैं।' कला के प्रति इतने उच्च मापदंडों के कारण ही रेनॉल्ड्स आज भी विश्व के महान कलाकार के रूप में याद किए जाते हैं।

आर्थिक, सामाजिक समेत विभिन्न मानकों पर अब भी महाराष्ट्र और गुजरात अव्वल

नॉर्थ का प्रदर्शन सुधरा, पर साउथ आगे

गंगाधर ढोबले

वर्ष 2025 में कौन सा राज्य हीरो कहलाने लायक है? इस साल सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप पांच राज्यों में हैं - महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। एक निजी रिसर्च एजेंसी 'केयर' ने यह रैंकिंग जारी की है। ऐसा पहला सर्वे 2023 में किया गया था। उसमें भी महाराष्ट्र पहले और गुजरात दूसरे नंबर पर था, जबकि तब तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु इस बार पांचवीं पोजिशन पर फिसल गया है। 2024 में सर्वेक्षण नहीं हुआ था।

रैंकिंग का आधार । सर्वे के लिए कुछ मानक तय किए गए - आर्थिक, राजकोषीय, सामाजिक, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, शासन और पर्यावरण। इन मानकों के और लगभग 50 उपमानक तय किए गए, जैसे राज्यों का सकल GDP, निवेश, उद्योग विकास, बजट, राजस्व, कर्ज, बिजली, सड़क, रेल, जल संसाधन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। हर मानक को वेटेज दिया गया है। उनके कुल जोड़ से एक इंडेक्स बनता है, जिससे उस राज्य की रैंकिंग तय होती है।

समग्र विकास । टॉप 5 को छोड़कर अन्य राज्य किसी न किसी मानक में अव्वल जरूर हैं, लेकिन समग्रता में पिछड़ गए। स्थिर विकास लक्ष्य (SDG) पाने में उत्तराखंड और केरल शीर्ष पर हैं। सुशासन में आंध्र प्रदेश अव्वल है। रोजगार और कौशल में उत्तर प्रदेश और बिहार, कृषि और ग्रामीण विकास में उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार ने अच्छा स्कोर किया है।

istock

राज्यों का प्रदर्शन | कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है टॉप 5 में शामिल | दूसरे राज्यों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर किया | यूपी और एमपी की अर्थव्यवस्था में दिखा सुधार

महाराष्ट्र आगे । आर्थिक क्षेत्र में टॉप 5 राज्यों के विकास मॉडल में मामूली अंतर दिखाई देगा। महाराष्ट्र राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। देश की GDP में उसका योगदान 20% से अधिक है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी तो है ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार भी है।

2025 के हीरो

गुजरात मॉडल । गुजरात का आर्थिक मॉडल निर्माण, उद्योग और निर्यात पर आधारित है। वह भारत का सबसे उद्योग अनुकूल राज्य रहा। बंदरगाहों का जाल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों ने इसे निवेशकों की पहली पसंद बनाया। गुजरात का विकास अपेक्षाकृत अधिक समान और अनुशासित दिखाई देता है।

कर्नाटक का दबदबा । कर्नाटक का आर्थिक विकास, शासन और पर्यावरण के क्षेत्रों में अच्छा दबदबा दिखाई देता है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान अधिक है। नीति क्रियान्वयन और प्रशासनिक क्षमता बेहतर है। स्वच्छ ऊर्जा और वायु गुणवत्ता बेहतर है। लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में कुछ कमजोर दिखता है।

तमिलनाडु की ताकत । तेलंगाना उद्योग अनुकूल नीतियां लागू करने में सफल रहा। आईटी, फार्मा, बायोटेक और सेवा क्षेत्र में उसने अच्छा स्कोर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में तेजी लाई है। उसने कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वहीं, तमिलनाडु संतुलित मार्ग अपनाता दिखाई देता है। यहां विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है।

पक्ष बनाम विपक्ष । राजनीतिक स्थिरता और शासन की गुणवत्ता में पांचों राज्यों के अनुभव अलग-अलग हैं। गुजरात राजनीतिक स्थिरता और नीति निरंतरता का अनुपम उदाहरण है। इसके विपरीत महाराष्ट्र राजनीतिक जटिलताओं का राज्य रहा। फिर भी मजबूत नौकरशाही और संस्थागत ढांचे ने राज्य को पटरी से उतरने नहीं दिया। इसी तरह कर्नाटक की सरकार में आंतरिक कलह दिखती है, लेकिन वह भी विकास की गति बनाए रखने में सफल रहा है। तेलंगाना और तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है, जिससे विकास को बढ़ावा मिला है। इन टॉप पांच राज्यों में से केवल गुजरात व महाराष्ट्र में ही BJP की सत्ता है। कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस शासित राज्य हैं, जबकि तमिलनाडु में DMK की सरकार है।

उत्तर का प्रदर्शन । हिंदी भाषी राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखा। यूपी में एक्सप्रेस नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और निवेश सम्मेलनों के कारण औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज आधारित उद्योगों में प्रगति की। राजस्थान में पर्यटन, सौर ऊर्जा और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं दिखाई दीं, लेकिन रोजगार सृजन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। हरियाणा में आर्थिक स्थिति मजबूत रही। कुल मिलाकर हिंदी भाषी राज्यों की अर्थव्यवस्था विकासशील रही, पर गुणात्मक विकास और प्रति व्यक्ति आय के मामले में दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से पीछे रही।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

क्या उलटा घूम रहा भारतीय खेलों का पहिया

मनोज जोशी

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पिछले दिनों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की एथलेटिक्स की इवेंट चल रही थी। महिलाओं की 400 मीटर इवेंट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा 400 मीटर के ट्रैक पर अकेली दौड़ रही थीं क्योंकि इस इवेंट में भाग लेने वाले पांच एथलीटों में से चार ने आखिरी क्षणों में अपना नाम वापस ले लिया था। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रुचित मोर भी अकेले ही दौड़े। कुश्ती में तीन इवेंट्स में दो और एक इवेंट में तीन ही प्रतियोगी थे।

खतरे की घंटी । यह नजारा उन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का था, जिस पर सरकार अपने हर सालाना बजट में करोड़ों रुपयों का इजाफा करती है। वैसे खिलाड़ियों को एक बड़े स्तर पर मौका देने की सोच बुरी नहीं है लेकिन उनकी दिलचस्पी न होने के कारणों का पता लगाने की जरूरत है। इसे खतरे की घंटी के तौर पर लेना होगा।

नाडा की दहशत । ऐसे में 2036 के ओलिंपिक की दावेदारी भी सवालों के घेरे में है। ऐसा लगने लगा है कि भारतीय खेलों का पहिया उलटी दिशा में चल रहा है। भारतीय खेलों में डोपिंग के मामले इतने घुल-मिल गए हैं कि खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नाम से ही दहशत होने लगती है। वह जानते हैं कि मेडल जीतने पर वह डोपिंग में फंसेंगे और उनका करियर तबाह हो जाएगा। इसी वजह से या तो वे कॉम्पिटिशन के पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं या फिर अपने राइवल को वॉकओवर देकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं।

कॉमन रूम

AI Image

खेल एक, फेडरेशन अनेक । बॉक्सिंग को ही लें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दुबई गई भारतीय टीम के 13 में से 11 खिलाड़ी पहले ही राउंड में बाहर हो गए। कारण टीम में टॉप बॉक्सर नहीं थे। टॉप बॉक्सर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास थे और इन बॉक्सरों को भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन लेकर गया था।

मुकदमों से नुकसान । खेलों पर खर्च की जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट-कचहरियों में चल रहे मामलों पर खर्च हो रहा है। पिछले दस वर्षों में खेलों से जुड़े 770 मामले कोर्ट में दर्ज हुए। इनमें 462 केस हाई कोर्ट में और 22 सुप्रीम कोर्ट में आए।

पैसों की कमी । इन सब मामलों में खेल फेडरेशनों का इतना नुकसान हो चुका है कि कई फेडरेशनों के पास तो किसी प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों को देने के पैसे तक नहीं हैं। जाहिर है, फेडरेशनों को अपनी आय के सोर्स बढ़ाने की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार और टीवी कॉमेंटेटर हैं)

कमज़ोर और वंचित के लिए आशा का संदेश है क्रिसमस

जनीना गोम्स

जीवन की यात्रा में हमें अनेक पड़ाव पार करने होते हैं। क्रिसमस को जब तक हम याद रखेंगे, जीवन में प्रेम और करुणा का अंत नहीं होगा। जीवन अनिश्चित है और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। यीशु के जन्म का संदेश हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे कितनी त्रासदियां और कठिनाइयां क्यों न आएं, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा - वह हमेशा हमारे साथ है।

क्रिसमस ईश्वर के मनुष्य बनने के उपहार का उत्सव है। यह जितना सामुदायिक है, उतना ही पारिवारिक भी, क्योंकि इसमें हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं। यह आनंद केवल किसी विशेष या संपन्न वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सद्भावना रखने वाले सभी लोगों के लिए है। हमारा उद्धार करने के लिए यीशु मनुष्य का रूप और स्वभाव धारण करके आए। वह सब कुछ समझते थे।

AI Image

उन्होंने बीमार और असहाय लोगों को चंगा किया। उन्होंने उस विधवा के दुख को समझा, जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। उन्होंने भीड़ की भूख और प्यास को महसूस किया। वह हमेशा करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की ओर बढ़े।

आज बहुत से लोग यह भूल गए हैं कि वास्तव में मनुष्य होना क्या है। वह उन लोगों की पुकार सुनते हैं जो क्रूरता के शिकार हैं और जिनके लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया है। वह धरती माता की कराह भी सुनते हैं, जिसे प्रकृति के प्रति हमारी लापरवाह उपेक्षा ने उजाड़ दिया है। कमजोर केवल वे नहीं हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कारणों से वंचित हैं, बल्कि वे भी हैं जो युद्धों, उत्पीड़न, जलवायु संकट और अन्य खतरों से बचने के लिए अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं।

आइए! इस क्रिसमस पर हम प्रेम का परिधान धारण करें। ऐसा प्रेम जो समस्त मानवता को अपने आलिंगन में ले। ईश्वर के मनुष्य बनने के रूप में प्रकट यह दिव्य प्रेम हमें आमंत्रण देता है कि हम 'दूसरे' के प्रति घृणा त्याग कर सबको ईश्वर की दृष्टि से देखें, क्योंकि दिव्यता किसी के साथ पक्षपात नहीं करती।

कांटे की बात

> अरावली पर सरकार की नई परिभाषा के मुताबिक, 90% से अधिक पहाड़ियों को सुरक्षा नही मिलेगी। उन्हें माइनिंग, रियल एस्टेट और दूसरी गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जिससे इकोसिस्टम को और नुकसान होगा।

जयराम रमेश, *पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री*

सप्ताह की शख़्सियत

दीपिका ने अपने गांव को शहर से जोड़ दिया

भारतीय टीम ने पिछले महीने विमिंस ब्लाइंड T20 विश्व कप जीता था। महिला टीम की कप्तान टीसी दीपिका की जब आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मुलाकात हुई, तो इनाम की जगह उन्होंने एक ही इच्छा जाहिर की - उनके गांव में सड़क बन जाए।

बचपन में हादसा

दीपिका के गांव का नाम है ताम्बालाहट्टी, आंध्र और कर्नाटक की सीमा पर मौजूद - विकास से कोसो दूर। इस पूरे इलाके के लिए ही दीपिका नई उम्मीद बनकर उभरी है। वह केवल 5 महीने की थी, जब अपनी ही अंगुली आंखों पर मार ली। आसपास अस्पताल नही था। मजदूर मां-बाप ने बेटी का इलाज कराने में कोई कसर नही छोड़ी, लेकिन दीपिका की रोशनी वापस नही आई।

AI Image

क्रिकेट बना सहारा

कुणिगल और मैसूर के स्पेशल स्कूल में दीपिका ने पढ़ाई की। स्कूल-हॉस्टल फ्री थे, लेकिन पैसो की ऐसी तंगी थी कि पिता को बेटी से मिलने जाना होता, तो किराये के लिए कर्ज लेना पड़ता था। इस संघर्ष में क्रिकेट ने उन्हें राह दिखाई। 2019 में उन्हें सिलेक्शन ट्रायल की पहली कॉल आई थी। तब से दीपिका का सफर जारी है और उन्हें भरोसा है कि अब उनका गांव भी बदलेगा।

जनता जंक्शन

इरफ़ान

अटलजी के लिए देश हमेशा दल से ऊपर रहा

डॉ. दिनेश शर्मा

कहते हैं, राजनीति में विरोधी भी सामान पर धूल की तरह ही जमा हो जाते हैं। मगर हमारे पास एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसे झूठा साबित किया। वह ऐसे इंसान थे, जिनके प्रतिद्वंद्वी तो थे, पर कोई दुश्मन नहीं। दुनिया के लिए वह भारत को नया रूप देने वाले प्रधानमंत्री थे, मेरे और लखनऊ वालों के लिए बस अटल।

पश्चिम के आगे अडिग रहे

यह लिखते-लिखते मैं अमीनाबाद की तंग गलियों और मेरे घर में उनके आने की यादों में खो गया हूं। पहली बार वह जब मेरे यहां आए, तो मैंने उन्हें खीर परोसा। घबराहट में मुझसे थोड़ी खीर उनके कपड़ों पर गिर गई। इस पर नाराज होने की बजाय वह हंस पड़े। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम ही नहीं, बल्कि एक अभिभावक थे। उन पर लिखना 'गागर में सागर' भरने जैसा है।

उन्हें विरासत में सत्ता नहीं मिली थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनसंघ से उन्होंने राजनीति शुरू की। 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और उनकी प्रतिभा देख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था कि 'यह लड़का किसी दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा।' 1980 में जब जनता पार्टी का प्रयोग विफल हुआ और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, तब अटलजी ने BJP का गठन किया। उनका यह कहना कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं की जुबां पर है। उन्होंने BJP को आक्रामकता की नींव पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के स्तंभ पर खड़ा किया।

आज सच्चे राजनेता के तौर पर अटलजी की विरासत एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि गैर-कांग्रेसी सरकारें भी कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। 20 से अधिक दलों को साथ लेकर NDA का गठन किया। हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करने वाले अटल जानते थे

कि भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र की ताकत उसका लचीलापन है। लखनऊ में मैंने कई बार देखा कि वह सुबह किसी आलोचक के साथ हंसी-मजाक करते और शाम तक वह शख्स सरकार के विधेयक का समर्थन कर देता। उनके लिए विपक्ष दुश्मन नहीं रहा और देश हमेशा पार्टी से ऊपर। पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें कश्मीर पर पक्ष रखने के लिए जिनेवा भी भेजा।

पीएम बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया। तब पश्चिम ने हमें डराने की पूरी कोशिश की, मगर वह अटल रहे। अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उन्होंने कई काम किए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की। शहर को गांव से जोड़ने के लिए PMGSY उन्हीं की सोच थी। आज हर हाथ में मोबाइल उन्हीं की टेलिकॉम क्रांति की वजह से है। अंधाधुंध सरकारी खर्च पर रोक लगाने के लिए वह FRBM अधिनियम लेकर आए।

पाकिस्तान के साथ शांति के लिए तत्पर रहे। 1999 में बस से लाहौर गए। मीनार-ए-पाकिस्तान का दौरा किया। नवाज शरीफ को गले लगाया, मगर पाकिस्तान ने करगिल में घुसकर हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी और पाकिस्तान से युद्ध में हमें जीत मिली।

हम नहीं झुकेंगे

अटलजी उम्दा कवि थे। परमाणु परीक्षण के बाद जब दुनिया ने भारत को अलग-थलग करने की कोशिश की तो उन्होंने प्रेस बयान जारी किए बगैर एक लाइन लिखकर दुनिया को बता दिया कि 'हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे।' उनका न होना एक भारीपन का अहसास कराता है। भाषण के बराबर ही उनका मौन अहम माना जाता था। उनके भाषण को सत्ता पक्ष के साथ-साथ पूरा विपक्ष भी सुनता था। आपातकाल में उन्हें जेल भेजा गया, मगर अटलजी ने कभी इसका बदला नहीं लिया। मैं जब उनके जीवन को देखता हूं तो लगता है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नीति या इमारत नहीं, बल्कि वह विश्वास था जो उन्होंने कमाया।

लखनऊ वालों के लिए अटलजी गए नहीं हैं। वह हजरतगंज की हवाओं में हैं, पुराने कॉफी हाउस की चर्चाओं में हैं और शहरी तौर-तरीके व तहजीब में हैं। मैं बस यही कहूंगा कि अटलजी आपके करोड़ों शिष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस दीये को जलाकर रखे हुए हैं। आपकी भविष्यवाणी की तरह ही कमल खिल चुका है और सूरज चमक रहा है।

(लेखक राज्यसभा सांसद हैं और UP के उप-मुख्यमंत्री रहे हैं)

दैनिक सवेरा टाइम्स

नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 दिसम्बर 2025

सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए। लोग केवल वही सुनते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। -पाउलो कॉएल्हो

सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध

कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आतंकवादियों की कुचेष्टाओं से कहीं न कहीं हिंसा, विस्फोट या नशीले पदार्थों की तस्करी की खबरें मानवता को चिंतित नहीं करतीं। भारत और पाकिस्तान के बीच लम्बी-चौड़ी सरहद है जो पंजाब से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। इस पूरी सीमा पर आतंकी तत्वों की हरकतें देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करती रहती हैं। चाहे पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित बताने का नाटक करता रहता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों का, नशा तस्करों और हथियार व्यापारियों का सबसे बड़ा निशाना पंजाब ही रहता है। कभी पंजाब के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां तो कभी पाकिस्तान से कनाडा तक बिछा हुआ आतंकी चक्रव्यूह पंजाब को घेरने की कोशिश करता है। अब पंजाब की सीमा पर आतंकियों की खोज-खबर लेने और उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक नई रणनीति बनाई गई है।

इसे नये वर्ष के आगमन पर अच्छी खबर भी कह सकते हैं। लंबे समय से पंजाब में सीमा पार से नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई निरंतर जारी है। पंजाब की शांति भंग करने के लिए हिंसक घटनाएं अंजाम देने से भी आतंकी बाज नहीं आते।

देखा गया है कि आतंकी तत्वों द्वारा ड्रोनों के द्वारा मादक पदार्थ और हथियार तस्कर किए जाते हैं। अब सीमा के पास 50 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन पहचानने वाली मशीनरी तैनात की जा रही है ताकि ड्रोन की घुसपैठ होते ही उस पर हमला किया जा सके। पंजाब पुलिस की ओर से 585 अंति संवेदनशील जगहों पर 2367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन पर 49.58 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस पर कम शुरू हो गया है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ लगे बार्डर पर फ्रंट लाइन सिक्योरिटी बीएसएफ के जिम्मे है लेकिन अब पंजाब पुलिस भी तरनतारन, फिरोजपुर व अमृतसर (देहाती) जिलों में बार्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन तीनों जिलों के संवेदनशील इलाकों से ही हथियारों, नशीले पदार्थों व विस्फोटकों की सबसे ज्यादा तस्करी होती है।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ कई विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। इसे दूसरी पंक्ति की सुरक्षा कहते हैं। बीएसएफ की सुरक्षा के बाद इसको ताकतवर करने का बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब पुलिस ने बुलेटप्रूफ गाड़ियों के साथ स्पैशल ऑप्रेशन ग्रुप, स्पैशल सिक्योरिटी ग्रुप और घातक पलटन टीमों सहित स्पैशल फोर्स तैनात कर दी है। पाकिस्तान के साथ सटी पंजाब की 553 किलोमीटर सरहद आतंकवादियों के निशाने पर रहती है।

अधिकतर क्षेत्र में फैंसिंग और कंटीली तार लगाई गई है। लेकिन जहां से रावी और सतलुज नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, वहां फैंसिंग नहीं है। इन इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ और पंजाब पुलिस एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार कर रही हैं। नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई है। इस साल पंजाब पुलिस ने बड़ी छापामारी करते हुए 2021 किलोग्राम हैरोइन पकड़ी गई है। जो क्रॉस बार्डर ड्रग सिंडिकेट बन गया है, वहां से नशा भेजा जा रहा है। इसके अलावा राइफल्स, पिस्तौलों, आईईडी, आरडीएक्स, हैंड ग्रेनडे, डैटोनेटर, आरपीजी आदि भी आ रहे हैं। लक्ष्य यह है कि हिंसक घटनाओं से दहशत फैलाना और क्षेत्र की शांति को तहस-नहस करना। नये वर्ष के अवसर पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा नई चुनौती का सामना करना एक अच्छी खबर है। इस आतंक विरोधी अभियान में सफलता तभी मिलेगी जब देश में छिपे हुए या बिके हुए आस्तीन के सांपों का फन कुचला जा सके। -शीतल विज

अब पंजाब में बिना मंजूरी नहीं कटेगा एक भी पेड़

पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। इसकी खेतीबाड़ी की वह शोभा है कि इसे देश के अनाज का भंडारी राज्य कहा जाता है लेकिन स्वतंत्रता के बाद देखते ही देखते आधुनिकता, शहरीकरण, वैध-अवैध औद्योगिकरण ने यह करिश्मा दिखाया कि खेतीबाड़ी और हरा-भरा पंजाब हरियाली से महरूम होने लगा। वन क्षेत्र का कटान होने के कारण इसका रकबा कम होने लगा। चारों तरफ हरियाली के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में अंधाधुंध वन कटान से पंजाब में राजस्थान से भी कम हरियावल क्षेत्र रह गया है जबकि सर्वविदित है कि राजस्थान एक तरह से रेगिस्तान के लिए जाना जाता है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अब अपना हित साधने वालों को पंजाब में पेड़ काटने से रोकना है। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि अब बिना हमारी अनुमति के एक भी पेड़ नहीं कटेगा। कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर स्थिति है। कोर्ट की चिंता है कि यदि इसी प्रकार वृक्ष कटते रहे तो पंजाब में वृक्ष बचेंगे ही नहीं।

इसे अभी रोकना होगा, नहीं तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वृक्ष गायब हो जाएंगे और हरियाली रहित जमीनों पर ऊंची-ऊंची इमारतें नजर आएंगी। कोर्ट ने याचिका को सुनते हुए इसका दायरा बढ़ाते हुए आदेश दे दिया है कि अब पंजाब में कहीं भी पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। वैसे जो जनहित याचिका दाखिल हुई थी, उसमें तो मोहाली में तीन राउंड अबाउट बनाने के लिए 251 वृक्षों की कटाई का मामला उठाया गया था।

याचिका कहती थी कि विभिन्न प्रोजैक्टों के लिए पेड़ों का यूं कटान किया जा रहा है और हरितिमा की अपूर्ण क्षति हो रही है। पंजाब सरकार ने भी एक शर्त लगा रखी है कि जहां पेड़ कटेगा, उसके एवज में पांच गुणा पौधारोपण होगा और पांच साल तक इनकी देखभाल भी करनी होगी। याचिका में कहा गया कि यह आदेश अस्पष्ट है। इतना भी नहीं बताता कि अगर फलदार पेड़ काटा है तो उसकी जगह कौन से पौधे लगाए जाएंगे। बेशक इस कानून का प्रतिबद्धता से पालन नहीं किया गया। तभी तो आज पंजाब में वन क्षेत्र केवल 3.67 प्रतिशत रह गया है, जो देश में सबसे कम है। राजस्थान रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, वहां भी कुल वन क्षेत्र पंजाब से अधिक 4.07 प्रतिशत है। सरकार ने जो वृक्ष संरक्षण नीति बनाई है उसका उचित पालन नहीं हो रहा। अब हाईकोर्ट ने फिलहाल वृक्षों की कटाई पर एकदम रोक लगाकर स्थिति को बिगड़ने से बचाने का प्रयास किया है। -शीतल विज

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

मर्यादाएं

चन्द्र मोहन

संपादकः वीर प्रताप

chander_m@hotmail.com

BLOG: chandermohan.net

बच्चों को उनका बचपन लौटा दो

बदल रहा समाज केवल श्रेष्ठ को ही सलाम करता है, सब बच्चे अव्वल नहीं आ सकते, कई कमजोर टूट जाते हैं

पिछले कुछ सप्ताह में कई अलग जगहों से स्टूडैंट्स द्वारा आत्महत्या करने के दुखदाई समाचार पढ़ने को मिलें हैं। जिस उम्र में बच्चों के खेलने-कूदने के दिन है, कुछ मुक्ति पाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल की दसवीं क्लास के 16 वर्षीय लड़के ने एक मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर जान दे दी और यह नोट छोड़ गया, 'सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोडूंगा'। इस एक वाक्य के पीछे बच्चे की कितनी मजबूरी छिपी थी? वह बच्चा क्या-क्या बर्दाश्त करता रहा होगा कि यह आखिरी कदम उठा लिया? क्या कहीं से कोई सहारा नहीं मिला? कोई समझाने वाला नहीं? स्कूल में भी नहीं, और जैसा आजकल नई शिकायत मिल रही है, घर में भी नहीं?

यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन रही है। आंकड़े बहुत तकलीफदेह हैं। 2023 में नैशनल क्राइम रिकार्डज ब्यूरो ने 14000 स्टूडेंट सुसाइड दर्ज किए थे। यह देशभर में कुल सुसाइड का 8.3 % है। एक दशक में ऐसे सुसाइड में 65% की वृद्धि हुई थी। यह राष्ट्रीय सुसाइड रेट से अधिक है। हमारे जमाने में तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं जाती थी। कभी-कभार कोई इश्क के चक्कर में जान दे देता था पर शिक्षा संबंधी या शिक्षा संसथान संबंधी सुसाइड कभी नहीं सुना था। क्या समाज की गति और अपेक्षा, और उपेक्षा, इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे बराबर दौड़ नही पा रहे वह निकलने का आसान रास्ता ढूंढने लगे है? कोटा के 'शिक्षा-कारखानों' से हर साल कई बच्चों के आत्महत्या करने के कष्टदायक समाचार मिलते है। वहां भारी शैक्षिणक दबाव है। अभिभावकों की उम्मीद का दबाव होता है। समाज भी बहुत तेजी से बदल रहा है और केवल श्रेष्ठ को ही सलाम करता है। सब बच्चे तो अव्वल नहीं आ सकते, कई कमजोर टूट जाते हैं।

इस सारे मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे ने मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाई वह टीचर्स के हाथों बार-बार अपमानित होने की शिकायत कर गया है। एफआइआर में लिखा गया है कि उसने काउंसलर को बताया था कि 'वह सुसाइड करने की सोचता है' पर स्कूल ने परवाह नहीं की और न ही उसके मां-बाप को बताया। जयपुर में नौ वर्ष की बच्ची ने बार-बार उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जिस दिन उसने आत्महत्या की उस दिन 45 मिनट में पांच बार उसने टीचर से शिकायत करने की कोशिश की कि उसके साथ सहपाठी अश्लील मजाक कर रहे हैं। पर टीचर ने कोई परवाह नहीं की। लड़की ने चौथी मंज़िल से कूद कर जान दे दी। रतलाम में 8वीं क्लास के छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। वह बच गया पर यह घटना भी स्कूली उपेक्षा का परिणाम है। स्कूल में मोबाइल लाने पर पाबंदी है पर यह छात्र ले आया। क्लास का वीडियो बनाकर उसने अपलोड कर दिया। स्कूल ने उसके मां-बाप को बुलाया। बताया जाता है कि लड़के ने 52 बार माफी मांगी पर प्रिंसिपल ने उसका कैरियर तबाह करने की धमकी दे दी। वह स्केटिंग में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। कुछ ही क्षणों बाद उसने छलांग लगा दी।

स्कूल में मोबाइल न ले जाने देना बिल्कुल जायज है। हर स्कूल में यह पाबंदी चाहिए, न केवल बच्चों पर बल्कि टीचर्स पर भी। पर जब लड़के ने बार-बार माफी मांग ली तो प्रिंसिपल को भी उदारता दिखाते हुए मामला छोड़ देना चाहिए था। स्कूल का काम बच्चे को सुधारना है, बिगाड़ना नही। ऐसा ही विचलित करने वाला मामला महाराष्ट्र में वसई से है जहां स्कूल देर से आने पर 13 वर्ष की नाजुक लड़की से 100 बैठकें निकलवाई गईं। वह वहीं बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। स्कूल में अनुशासन चाहिए पर वह क्रूरता की हद तक नहीं जा सकता। वह जमाना गया जब आप बच्चों को मुर्गा बनाने की सजा दे सकते थे। संतुलन रखना अध्यापकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि समाज बदल गया। बहुत बच्चे जिन्हें डिस्टर्ब्ड फैमिली कहतें है, से आतें हैं। एक स्कूल प्रिंसिपल जो कमजोर परिवारों के बच्चों के स्कूल को चलातीं हैं, ने मुझे बताया कि आधे बच्चे 'ब्रोकन फैमिली' अर्थात टूटे परिवारों से आते हैं। ऐसे बच्चों को सम्भालना और अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।

लेकिन इस समस्या का एक और पहलू भी है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, मां-बाप और परिवार की जिम्मेवारी। दिल्ली के जिस लड़के ने मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाई थी उसने स्कूल के काउन्सलर को बताया था कि वह सुसाइड करने की सोचता है। मेरा सवाल दूसरा है। स्कूल की लापरवाही तो है ही, पर मां-बाप को क्यों पता नहीं चला कि बच्चा इतना हताश और निराश हैं कि सुसाइड करने के बारे सोच रहा है? घरों में बच्चों के साथ संवाद क्यों नहीं होता? स्कूल अब बच्चों से संवाद करने और उनकी तकलीफों को बारे जानने के लिए काउंसलर रखते हैं। पहले तो ऐसा नही होता था। अब जरूरत क्यों पड़ गई? एक काउंसलर ने मुझे बताया कि छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी बात कहने आते हैं।

क्या घर में सुनने वाला कोई नहीं? कई परिवारों में दोनों पति-पत्नी काम करते हैं, जिससे बचा कटा महसूस करता है। अपनी बात अंदर छिपा कर रखता है जिससे घुटन पैदा होती है जो कई बार यह अप्रिय मोड़ ले लेती है।

कई परिवार सारी जिम्मेवारी स्कूल पर डाल कर बैठ जाते हैं। यह सही नहीं है। कई बाप तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। जवाब मिलता है, 'टाइम कित्थे है जी!' आजकल के समय जब बच्चों पर बाहरी प्रभाव बहुत बढ़ गया है, अभिभावकों की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है कि वह बच्चे पर निगरानी रखें कि किधर जाता है और किससे बात करता है? मोबाइल फोन ने तबाही मचा दी है। बहुत विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अत्यधिक सोशल मीडिया सम्पर्क बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है। मैटा की अपनी रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया से बच्चों की मानसिक और शैक्षणिक क्षमता पर असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। आस्ट्रेलिया की अपनी स्टडी बताती है कि 10-15 वर्ष के बच्चों में 10 में से 7 में सोशल मीडिया के प्रभाव हानिकारक पाए गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि ऐसे बच्चों में बोलने और लिखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। उनमें खाने में विकार से लेकर सुसाइड के बारे सोच पाई गई। दूसरे देश भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहें हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है? कई बच्चे सदमे में हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि 'बच्चों की दिनचर्या में सोशल मीडिया गहराई से जुड़ चुका है'। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करेंगे? यह मां-बाप की असफलता है जो बच्चे को बिजी रखने के लिए छोटी उम्र में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चों को आउटडोर गेम्स में व्यस्त रखने की जगह मोबाइल में व्यस्त रखा जाता है।

बच्चों में जल्द गुस्सा आना, आंखों में दर्द, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना सब मोबाइल से जुड़े हैं। पढ़ाई में ध्यान कम हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि छोटे बच्चों से माइग्रेन की शिकायत आने लगी है जो पहले सुना भी नहीं जाता था। भारत में मोबाइल पर कोई पाबंदी नहीं है, पर पैरैंट्स को उनके स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है। यह तो सही है पर जहां मां-बाप बच्चे को इस लत से बचाने में नाकाम हो रहे हैं वहां कुछ सरकारी दखल की जरूरत बनती है। पर केवल मोबाइल ही बच्चों को खराब नहीं करते। ज्योत्सना मोहन भार्गव ने शहरी बच्चों पर लिखी अपनी किताब स्टोंड, शेम्ड, डिप्रैस्ड में लिखा है,'सड़क पर खतरे के निशान बिखरे पड़े हैं फिर भी मैं शहरी घरों में बेबसी की भावना देखती हूं'। जो सामने है उसे नकारा जा रहा है, जिसके कई बार बहुत भयानक परिणाम निकलते हैं।

अब तो कई पेरैंटस गर्व से कहते हैं कि हम अपने बच्चे के 'फ्रैंड' हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पेरैंट को पेरैंट रहना चाहिए, बच्चे का दोस्त नहीं बनना चाहिए। उनका काम बच्चे को गलत प्रभाव से बचाकर सही दिशा में डालना है। पिछले कुछ सालों में हमारा समाज बहुत हिंसक हो गया है। ड्रग्स का बहुत चलन है और आसानी से मिल जाते है। सब 90% से अधिक नम्बर भी नहीं ला सकते। ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी कीमत बच्चा मानसिक या शारीरिक तौर पर न अदा करे। अगर आप का बच्चा डिप्रैस्ड या दुखी है या गलत आदतों में फंस गया है तो स्कूल से पहले घर को पता चलना चाहिए। पश्चिम में बहुत मां-बाप बच्चों पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हमें सावधान रहना है। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के पास मोबाइल नहीं है। अगर उसके फ्रैंड्स ने उससे बात करनी होती है तो उसकी मां के फोन पर सम्पर्क करते हैं। कितने पैरैंट्स के पास यह दम है कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखें? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी लगाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का कहना है कि 'हम बच्चों को उनका बचपन लौटा रहे हैं'। क्या हमारी सरकार भी बच्चों को डिजिटल प्रदूषण से बचाकर उनका बचपन लौटाने के बारे सोचेगी?

सिख सिद्धांतों का पालन, साहिबजादों की शहादत का सम्मान

'**गु**र सतगुर का जो सिख अखाए
सु भलके उठि हरि नाम धिआवै।।
उदमु करे भलके परभाती
इसनानु करे अमृतसरि नावै।।'
(श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग 305)

'सो सिखु सखा बंधपु है भाई
जि गुर के भाणे विचि आवै।।
आपणै भाणै जो चलै भाई
विछुड़ि चोटा खावै।।'
(अंग 601)

'सतिगुर की बाणी सतु सरूपु है,
गुरबाणी बणीऐ।'
(अंग 304)

ये तीनों छंद मिलकर पूरे सिख जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। वे अनुशासित जीवन का एक स्पष्ट ढांचा बताते हैं–जल्दी उठना, ईश्वर का स्मरण, ईमानदार प्रयास, गुरु की इच्छा के प्रति समर्पण, और सबसे ऊपर, गुरबानी का पूर्ण अधिकार। यहां कोई अस्पष्टता नहीं है, न ही ऐसी व्याख्या की कोई गुंजाइश है जो जिम्मेदारी को कमजोर करे।

फिर भी, आज सिख समाज के सामने एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है: अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जीवित, पूर्ण और शाश्वत गुरु हैं, तो सिख जीवन तेजी से जीवित उपदेशकों, डेरों, बाबाओं और सत्ता के समानांतर केंद्रों पर निर्भर क्यों होता जा रहा है? सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने औपचारिक रूप से झुकते हैं, फिर भी मार्गदर्शन, आशीर्वाद, आश्वासन और समाधान कहीं और क्यों ढूंढते हैं?

यह विरोधाभास समकालीन सिख जीवन में नैतिक संकट के मूल में है। यह विश्वास का संकट नहीं है, न ही सिख दर्शन की विफलता है। सिख विचार मानवता के लिए ज्ञात सबसे कट्टरपंथी, नैतिक और सार्वभौमिक आध्यात्मिक प्रणालियों में से एक है। यह संकट अभ्यास, आत्मविश्वास और गुरु नानक देव जी द्वारा परिकल्पित और गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा निश्चित रूप से स्थापित गुरु-केंद्रित जीवन से धीरे-धीरे दूर जाने का है।

गुरु गोबिंद सिंह जी ने व्यक्तिगत गुरु परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु घोषित करके, उन्होंने बिचौलियों, वंशानुगत आध्यात्मिक अधिकार और दिव्य स्थिति के मानव दावेदारों के लिए दरवाजा बंद कर दिया। सिख धर्म को गुरु और सिख के बीच एक सीधे संबंध के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल शब्द के माध्यम से होता है। किसी भी जीवित व्यक्ति को साधक और गुरु के बीच खड़ा नहीं होना था। यह फैसला क्रांतिकारी और बेमिसाल था। इसने यह सुनिश्चित किया कि सिख धर्म कभी भी व्यक्ति पूजा या पुरोहितों के प्रभुत्व में नहीं बदलेगा।

फिर भी, समय के साथ, व्यवहार में गुरु को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि अधिकार चुपचाप इंसानों के हाथों में चला गया है। जत्थेदारों, ग्रंथियों, बाबाओं और करिश्माई उपदेशकों का बढ़ता प्रभाव आध्यात्मिक जीवन शक्ति का सबूत नहीं है; यह गुरबानी-आधारित जीवन से दूरी का लक्षण है। जब गुरु को सिर्फ समारोहों तक सीमित कर दिया जाता है और उन्हें रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उस खालीपन को भरने के लिए आगे आते हैं। इससे सिख स्वायत्तता कमजोर होती है और सामूहिक चेतना खंडित होती है।

उतनी ही चिंताजनक बात यह है कि कई गुरुद्वारों का धर्मस्थलों से गुटबाजी की राजनीति और सत्ता संघर्ष के अखाड़ों में बदलना। गुरु नानक देव जी ने पूजा स्थल को धर्मस्थल के रूप में वर्णित किया था-धर्म का पालन करने, समान रूप से एक साथ बैठने, मानवता की सेवा करने और नैतिक चरित्र को आकार देने की जगह। 'गुरुद्वारा' शब्द का ही अर्थ है गुरु का द्वार। इसे कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता या चुनावी लामबंदी का मंच बनने के लिए नहीं बनाया गया था।

जबकि सिख इतिहास इस बात का गवाह है कि जब न्याय की मांग हुई तो राजनीतिक प्रतिरोध किया गया, लेकिन गुरुद्वारों में पक्षपातपूर्ण राजनीति का नियमित हस्तक्षेप आध्यात्मिक अधिकार को कमजोर करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में अरदास के बाद राजनीतिक भाषण, व्यक्तिगत हमले और गुटबाजी की लामबंदी उस स्थान की पवित्रता को कमजोर करती है। जो समुदाय अपने पवित्र संस्थानों का राजनीतिकरण करता है, वह धीरे-धीरे नैतिक स्पष्टता खो देता है। शक्ति सिद्धांत की जगह ले लेती है, और संख्यात्मक शक्ति नैतिक आचरण की जगह ले लेती है।

गुरबानी चयनात्मक आज्ञाकारिता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। 'सतगुर की बाणी सत सरूप है।' गुरु का वचन स्वयं सत्य है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं हैं; यह धार्मिक आचरण, सामाजिक

वीर बाल दिवस पर विशेष

सद्भाव, आर्थिक न्याय, नैतिक शासन और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह असमानता, शोषण, अत्याचार, पाखंड और नैतिक कायरता को अस्वीकार करता है। यह ईमानदारी से कमाई, सम्मान के साथ साझा करना, शक्ति के सामने निडरता और हुक्म के प्रति समर्पण सिखाता है। सबसे बढ़कर, यह साधक को ईश्वर के साथ एकात्मता की ओर मार्गदर्शन करता है।

फिर भी समकालीन सिख जीवन अक्सर अनुशासन के बिना अनुष्ठान, नैतिकता के बिना पहचान, और विनम्रता के बिना दावे को दर्शाता है। गुरबानी सुबह जल्दी उठने, नाम सिमरन, ईमानदार मेहनत और दूसरों के साथ साझा करने की बात करती है। आजकल लोग अक्सर बिना जिम्मेदारी के आराम, बिना मेहनत के शॉर्टकट, और बिना अंदरूनी बदलाव के तारीफ चाहते हैं। गुरु नहीं बदले हैं। संदेश अभी भी पूरा और काफी है। हम ही भटक गए हैं।

यह सच्चाई 21 से 26 दिसंबर तक साहिबजादों की शहादत की याद में मनाए जाने वाले दिनों में खास तौर पर सामने आती है। ये दिन सिख इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक हैं–शायद सबसे काला हफ्ता, न सिर्फ इसलिए कि कितनी क्रूरता की गई, बल्कि इसलिए भी कि समुदाय से कितने नैतिक साहस की उम्मीद की गई थी। चार साहिबजादों का बलिदान सिर्फ दुख मनाने के लिए एक भावनात्मक घटना नहीं थी। यह खालसा की अंतरात्मा के सामने हमेशा के लिए एक सभ्यतागत चुनौती थी।

गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द सदियों तक गूंजते हैं:

'चार मुए तो किया हुआ, जीवत कै हजार।'
(अगर चार शहीद हो गए तो क्या हुआ, हजारों जिंदा हैं।)

यह संख्यात्मक गर्व का बयान नहीं था। यह निरंतरता और चरित्र की परीक्षा थी। गुरु शरीर नहीं गिन रहे थे; वह यह माप रहे थे कि क्या खालसा उन मूल्यों पर चलेगा जिनके लिए साहिबजादों ने शहादत दी थी। आज, दुनिया भर में सिखों की संख्या करोड़ों में है, फिर भी एक सामूहिक नैतिक शक्ति के रूप में, समुदाय अक्सर बिखरा हुआ, हिचकिचाता हुआ और अनिश्चित लगता है। संख्याएं बढ़ी हैं; स्पष्टता कम हुई है।

इसलिए साहिबजादों की याद सिर्फ एक रस्म बनकर नहीं रहनी चाहिए। मोमबत्तियां, भाषण और भावनात्मक कहानियों का मतलब तभी है जब वे आत्मनिरीक्षण और सुधार की ओर ले जाएं। साहिबजादे याद किए जाने के लिए नहीं मरे; वे यह सुनिश्चित करने के लिए मरे कि निडरता, सच्चाई और नैतिक संप्रभुता ज़िंदा रहे। उनकी शहादत हर सिख के सामने एक सीधा सवाल खड़ा करती है: आज आप कहां खड़े हैं जब सच बोलना मुश्किल है, जब न्याय महंगा है, और जब अंतरात्मा से ज्यादा चुप्पी सुरक्षित लगती है?

दुख की बात यह है कि समुदाय को रास्ता दिखाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ने वाले कई धार्मिक उपदेशक खुद उसका पालन नहीं करते। गुरबानी साफ चेतावनी देती है:

'अवर उपदेसै आप न करै॥
आवत जावत जनमै मरै॥
जिस के अंतर बससे निरंकार॥
तिस की सीख तररे संसारु॥'

जो लोग उपदेश देते हैं लेकिन खुद पालन नहीं करते, वे अपना जीवन और अपने अनुयायियों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। उतनी ही चिंताजनक बात यह है कि जो लोग पंथ के नेता होने का दावा करते हैं, उनमें से कई ने कभी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। ज्यादातर ने पाहुल नहीं लिया है या खुद को खालसा रहत मर्यादा के प्रति समर्पित नहीं किया है। उनमें से कुछ को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप झेल रहे अपराधियों के साथ पकड़े जाने के बाद भी शर्म नहीं आती। ऐसी विरोधाभासों से भरे लोगों के नेतृत्व वाली कम्युनिटी का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्दों को पूरी ईमानदारी से पढ़ा जाना चाहिए:

'जब लग खालसा रहियो न्यारा,
तब लग तेज देओ मैं सारा।'

यह कोई श्राप नहीं है; यह एक शर्त वाला वादा है। ताकत, गरिमा और दिव्य समर्थन तभी तक सुनिश्चित हैं जब तक खालसा अपने आचरण, मूल्यों और अनुशासन में अलग रहता है। जिस पल गुरमत सिद्धांतों को कर्मकांड, निर्भरता या उधार की परंपराओं से कमजोर किया जाता है, गुरु अपना विश्वास वापस ले लेते हैं- गुस्से में नहीं, बल्कि नैतिक सुधार के तौर पर। सिख संस्थानों और नेतृत्व की मौजूदा कमजोरी को इसी नजरिए से समझना चाहिए।

सिखों को 'हारने वाला' कहना बहुत आसान होगा। भारत और मानवता के लिए सिखों का योगदान बहुत बड़ा और निर्विवाद है। लेकिन यह भी उतना ही बेईमानी होगा कि नैतिक अधिकार में गिरावट आई है, इस बात से इनकार किया जाए। बिखराव, भरोसे में कमी और भ्रम एक ही मुख्य कारण की ओर इशारा करते हैं: सिख दर्शन से दूर होना, जिसे असल ज़िंदगी में जिया जाता है।

यह पल आत्मनिरीक्षण की मांग करता है, न कि आरोप-प्रत्यारोप की। सिख इतिहास का अध्ययन पुरानी यादों के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के लिए किया जाना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पहले से ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान देते हैं। जरूरत है तो बस उस पर चलने के साहस की। गुरुद्वारों को फिर से सीखने और सेवा के धर्मस्थल बनना होगा। प्रचारकों को शिक्षक के रूप में काम करना चाहिए, न कि बिचौलिए के रूप में। सिख धर्म को एक बार फिर मानवता के लिए एक सार्वभौमिक नैतिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि अपनी ही चिंताओं में डूबी एक बंद पहचान के रूप में।

गुरु ने खालसा को नहीं छोड़ा है। वादा अभी भी कायम है। सवाल यह है कि क्या खालसा फिर से न्यारा रहने के लिए तैयार है-नारों में नहीं, बल्कि विवेक में; राजनीति में नहीं, बल्कि आचरण में; कर्मकांड में नहीं, बल्कि जीती-जागती सच्चाई में। तभी साहिबजादों की शहादत सच में वर्तमान का मार्गदर्शन करेगी और भविष्य को आकार देगी, और तभी सिख धर्म मानवता के लिए एक नैतिक प्रकाशस्तंभ के रूप में अपना सही स्थान फिर से हासिल करेगा।

इकबाल सिंह लालपुरा

पूर्व चेयरमैन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार

(iqbalsingh_73@yahoo.co.in)

कार्टून कोना विश्वा मित्र

उन्मादी भीड़ भविष्य के परिणामों से अंजान है

हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी भी क्या नफरत है कि वे जब भी जहां भी अवसर मिलता है एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं। समाज के बीच रहकर यदि कुछ अनबन हो जाए, तो उसे सहजता से मिल-बैठकर सुलझाया भी जा सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। मामूली बात को भी इतना तूल दिया जाता है कि हत्या तक कर दी जाती है। यही तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। ढाका की एक फैक्ट्री में कार्य करने वाले युवा मजदूर दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार दिया गया।

यह ठीक है कि जब भीड़ उन्माद पर उतारू हो जाती है, तो वह उन्माद के अगले प्रभाव पर विचार नहीं करती है, लेकिन ऐसा भी क्या उन्माद कि हम किसी को पीट-पीटकर मार दें। ऐसा नहीं है कि इस तरह के उन्मादी केवल बांग्लादेश में ही रहते हैं, भारत तथा विश्व में इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पर अकूत विश्वास रखने वाले सभी देशों में प्रायः समय-समय पर पाए जाते रहते हैं। आखिर इस दुराग्रहपूर्ण मानसिकता को कैसे बदला जाए, इस पर तो कोई एक दो देश को नहीं, पूरे विश्व को विचार करना होगा। वैसे भारत के अतिरिक्त विश्व के सभी इस्लामिक देशों में इस तरह ईशनिंदा पर सजा का प्रावधान है। जांच से जो बात सामने आई है उससे तो यही लगता है कि निरपराध दीपू चंद्र दास की हत्या उन्मादी भीड़ द्वारा बहकावे में आकर की गई है। ईशनिंदा कानून किसी धर्म, उसके प्रतीकों, पवित्र वस्तुओं या धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान, अवमानना या मजाक उड़ाने को गैर-कानूनी मानते हैं, जिसके लिए विभिन्न देशों में सजाएं तय हैं।

ये कानून अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल होने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के आरोपों का सामना करते हैं, हालांकि भारत में बीएनएस की धारा 295ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है, न कि अलग से ईशनिंदा कानून। यह ईश्वर, धर्म, धार्मिक भावनाओं, प्रतीकों या पवित्र वस्तुओं के प्रति अनादर, अपमान या अवमानना दिखाने वाले कार्यों या बयानों को दंडित करता है। इसके तहत

सांप्रदायिकता

किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक सभाओं में बाधा डालना या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण, लेखन या दृश्य शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों में इसके तहत मौत की सजा का प्रावधान है और अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं।

भारत में कोई अलग ईशनिंदा कानून नहीं है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 295ए के तहत, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनके धर्म का अपमान करना दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। कई पश्चिमी देशों में ऐसे कानून या खत्म हो गए हैं (जैसे अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण) या केवल अपमानजनक भाषणों को प्रतिबंधित करते हैं, न कि आलोचना को। बांग्लादेश में ईशनिंदा के लिए कोई विशिष्ट 'ईशनिंदा कानून' नहीं है, बल्कि यह दंड संहिता की धारा 295(ए) जैसे प्रावधानों के तहत आता है, जो 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने' के लिए सजा का प्रावधान करता है, हालांकि इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा मौत की सजा की मांग की जाती है।

ऐसी स्थिति में जब की बांग्लादेश में ईशनिंदा के लिए दंड संहिता की धारा 295ए ही लागू है, तो फिर ऐसे उन्मादी भीड़ को क्या वहां की न्यायपालिका कठोर दंड दे सकने में सक्षम है? हत्या के इस मामले की जल्द जांच करके अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन, आशंका इस बात की भी है कि कहीं महज इसकी कागजी खानापूर्ति करके मामले को दाखिल दफ्तर न कर दिया जाए। ऐसा नकारात्मक विचार इसलिए भी आता है कि जिस बांग्लादेश के निर्माण के लिए सर्वाधिक भागीदार भारत ही रहा है, तो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को दीपू चंद्र दास की तरह पीटकर मार देने के बाद पेड़ पर लटकाकर जला दिया जाए, इस तरह का अमानवीय कृत्य शायद ही विश्व में स्वीकार्य हो सकता है।

अतः इसके लिए आवश्यक है कि जो भी अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की हत्या के लिए अपराधी हों, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, अन्यथा इस तरह के उन्मादी कम होने के बदले बढ़ते ही रहेंगे, जिसका परिणाम किसी भी दशा में सकारात्मक नहीं होगा। भारत ने अपने अफसरों के साथ संपर्क में रहकर अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के प्रयासों पर बल दिया है।

निशिकांत ठाकुर

वरिष्ठ पत्रकार/ राजनीतिक विश्लेषक

दैनिक सवेरा टाइम्स

सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।

DELHIN/2013/53563

पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27

फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009

समाचार (फैक्स) 0181-2224455

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

मातृएं ही भविष्य के विषय में विचार कर सकती हैं, क्योंकि वे अपनी संतानों में भविष्य को जन्म देती हैं।
–**मैक्सिम गोर्की**, रूसी साहित्यकार

एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का भरोसेमंद स्तंभ बनता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की वाणिज्यिक डील के तहत श्रीहरिकोटा से अपने सबसे ताकतवर रॉकेट एलवीएम-3 के जरिये अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल के 6100 किलोग्राम वजनी 'ब्लू बर्ड ब्लॉक-2' सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करना ऐतिहासिक इसलिए है, क्योंकि यह भारत का अब तक का सबसे भारी और तकनीकी रूप से जटिल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च है, जिसे महज 52 दिन की तैयारी में और बिना किसी बाहरी सहयोग के, मात्र डेढ़ किलोमीटर के अंतर से कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। इससे पहले 4,000 किलो से ज्यादा के सेटेलाइट के लिए अमेरिका या फ्रांस से मदद लेनी होती थी। साथ ही इसरो ने एस 200 बूस्टर को नियंत्रित करने वाले नए कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण भी कर लिया, जिसे गगनयान में इस्तेमाल होना है। इससे भारत 'सिर्फ वैज्ञानिक मिशन' करने वाले देश से आगे बढ़कर वैश्विक स्पेस सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है।

'ब्लू बर्ड ब्लॉक-2' का उद्देश्य स्पेस से सीधे धरती पर मौजूद सामान्य स्मार्टफोन्स तक बिना किसी डिश, टॉवर या अतिरिक्त एंटीना के 4जी या 5जी कनेक्टिविटी पहुंचाना है। दरअसल यह एक उड़ता हुआ मोबाइल टॉवर है। इसकी सिग्नल पकड़ने की क्षमता इतनी अधिक है कि पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्र के बीच भी नेटवर्क की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। पुरानी पीढ़ी की तुलना में यह प्रणाली लगभग दस गुना अधिक शक्तिशाली है, जो दूरस्थ इलाकों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। स्वाभाविक सवाल है कि क्या इसका लाभ भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं को मिलेगा? तकनीकी रूप से हां, क्योंकि यह नेटवर्क वैश्विक कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि, शुरुआती चरण में इसकी सेवाएं महंगी हो सकती हैं, क्योंकि स्पेस-टू-फोन तकनीक अभी नई है, लेकिन जैसे-जैसे सेटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा आएगी, कीमतों में गिरावट तय मानी जा सकती है। दीर्घकाल में यह आपदा प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों, समुद्री संचार और डिजिटल समावेशन के लिए गेम-चेंजर होगा।

प्रक्षेपण के बाज़ार में इसरो का मुकाबला अब स्पेसएक्स जैसी कंपनी से है, जिसका रॉकेट फाल्कन-9 लो अर्थ ऑर्बिट तक 22,800 किलोग्राम ले जाने और रीयूजेबल होने के चलते आक्रामक प्रतिस्पर्धा देता है, लेकिन इसरो की ताकत विश्वसनीयता और सटीकता है, जिसे कंपनियां ज्यादा महत्व देती हैं। इसरो आज भी छोटे रॉकेट्स और पीएसएलवी के क्षेत्र में सबसे किफायती विकल्पों में गिना जाता है। अगला कदम रीयूजेबल लॉन्च व्हिकल का है। 'सूर्य' कोडनेम वाले भारतीय रीयूजेबल रॉकेट पर काम चल रहा है, इस दशक के अंत तक प्रारंभिक परीक्षण की उम्मीद है। तब लागत और प्रतिस्पर्धा दोनों मोर्चों पर हम मजबूत होंगे। एलवीएम-3 को ही गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। हालिया सफलता ने गगनयान के रास्ते को और स्पष्ट कर दिया है।

प्रसंगवश

रिश्तों को थामें रखें विश्वास की डोर से

किसी भी रिश्ते में जब हम विश्वास की डोर से जुड़े होते हैं, चाहे वह रिश्ता दोस्ती हो, प्यार हो या पारिवारिक, तब हम उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी-कभी चीजें अचानक ही बदल जाती हैं, इसके लिए किसी बड़ी घटना का होना जरूरी नहीं होता। फिर पता चलता है कि सब कुछ तो बस एक नाटक की तरह था और हमें यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल लगता है।

आज के समय में यह कहानी लाखों-करोड़ों लोगों की है, जब हम किसी को बेतहाशा महत्व देते हैं, उसकी हर बात आंख बंद करके मान लेते हैं, उसके लिए अपने सपने, अपनी खुशी, अपना वक्त तक कुर्बान कर देते हैं, और एक दिन अचानक वही इंसान या रिश्ता हमें नजरअंदाज करने लगता है या पलटकर कह देता है, 'जैसे हम तो कुछ थे ही नहीं कभी'। उस पल सचमुच लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता हमने ही की है।

अम्बिका 'अम्बी'
लेखिका

आज परिवार भी इस धोखे से अछूता नहीं रहा। मां-बाप, जिन्होंने पूरी उम्र बच्चों के लिए खपा दी, आज वही बच्चे बड़े होकर माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। घर की दीवारें तो खड़ी हैं, पर उनमें पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। बहू-बेटे, सास-बहू, भाई-बहन के बीच टकराव आम हो गया है। सच तो यह है कि जितनी तेजी से हमारा समाज और तकनीक बढ़ी है, उतनी ही तेजी से रिश्ते सुविधा और जरूरत तक सिमट गए हैं। अब लोग एक-दूसरे के लिए 'विकल्प' बनकर रह गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम खुद मूर्ख हैं?

हमें अपनी इस मूर्खता पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि रिश्ते और दोस्ती में जब कोई हमें यह एहसास दिलाता है कि हम उसके लिए महत्व रखते हैं, तो यह भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी अपनापन और लगाव पैदा होता है। मगर एक दिन अचानक पता चलता है कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी, हम तो सिर्फ एक विकल्प थे। उस वक्त मन-मस्तिष्क पर क्या बीतती है, कभी सोचा है?

सब कुछ जानकर भी हम अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते। नकारात्मक बातों और घटनाओं को हम दूर ठेल देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर रिश्तों के प्रति प्रेम और सम्मान अभी भी जिंदा है। हम कीमती हैं। जो हमें समझेगा, वही हमारे साथ रहेगा, यह बात सौ फीसदी सच है। फिर भी कभी-कभी यह भी याद रखना चाहिए कि जो चला गया, उसकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है। शायद वह इंसान अंदर से टूट चुका हो, खाली हो चुका हो। या शायद हम उसकी नजर में लायक रहे ही न हों।

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमारी कीमत कम हो गई। मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हमें तभी महत्व देते हैं, जब तक हम उनके लिए उपयोगी या विकल्प होते हैं। उसके बाद का भविष्य किसी को नहीं पता। हम मूर्ख नहीं होते। हम सिर्फ प्रेम और भावनाओं से बंध जाते हैं।

हम वे लोग होते हैं जो रिश्ते को 'सच' मान लेते हैं, क्योंकि हम खुद उसी सच से जीते हैं। जब हम किसी को अपना समझते हैं, तो सचमुच अपना सब कुछ कुर्बान कर दे देते हैं, बिना कुछ सोचे-समझे। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कभी-कभी हमें सबसे गहरा दुख भी देती है, लेकिन यही दुख हमें अंदर से मजबूत बनाता जाता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला देता है।

नई गैलेक्सी अलकनंदा की रोमांच भरी खोज

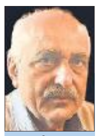

रनबीर सिंह
विज्ञान लेखक

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च से संबद्ध एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई गैलेक्सी, अलकनंदा की पहचान करके बड़ी खोज की है। यह एक मेच्योर स्पाइरल गैलेक्सी है, जो बिग बैंग के सिर्फ़ साढ़े दस अरब साल बाद बनी थी। इस नयी गैलेक्सी को यह नाम भारतीय खोजकर्ताओं ने दिया है। यह खोज गैलेक्सी बनने के मौजूदा मॉडल को चुनौती देती है, क्योंकि अलकनंदा हमारी मिल्की-वे जैसी ही साफ़ भुजाओं वाली एक मेच्योर बनावट दिखाती है और यह पहले सोचे गए समय से बहुत कम समय में हुई है। हर साल लगभग सूर्य से दस गुना बड़े द्रव्यमान के बराबर यह गैलेक्सी बहुत तेज़ दर से तारे बना रही है, जो हमारी मॉडर्न मिल्की-वे में तारे बनने की रफ़्तार से लगभग बीस गुना ज़्यादा है।

इस खोज ने गैलेक्सी बनने और कॉस्मिक एव्ल्युशन के बारे में ज्ञात थ्योरी को नया रूप दिया है, जिससे पता चलता है कि गैस एक्रीशन और डिस्क सेटलमेंट जैसे प्रोसेस पहले सोचे गए समय से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। गैलेक्सी की तश्तरीनुमा रचना, कुडंली जैसी भुजाएं और इनमें एक प्रकार की स्थिरता दिखाने वाले कंप्यूटर जेनरेटेड चित्र अभिभूत करने के लिए काफी है। एक ग्रैंड स्पाइरल बनाने में समय लगता है। गैस को आस-पास की जगह से लगातार बहना चाहिए। इसे 'गैस एक्रीशन' कहा जाता है, एक घूमती हुई डिस्क में सेटल होना चाहिए, फिर धीमी गति से चलने वाली वेव्स जिन्हें 'डेंसिटी वेव्स' कहा जाता है, स्पाइरल आर्म्स को शेप देने के लिए डिस्क को डिस्टर्ब कर सकती हैं। पूरे सिस्टम को दूसरी गैलेक्सीज़ के साथ ज़ोरदार टक्करों से बिना डिस्टर्ब हुए रहना चाहिए। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से तीन लाख, 30 हज़ार गुना अधिक होता है।

> टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से संबद्ध एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई गैलेक्सी, अलकनंदा की पहचान करके बड़ी खोज की है। यह एक मेच्योर स्पाइरल गैलेक्सी है, जो बिग बैंग के साढ़े दस अरब साल बाद बनी थी।

एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल के नवंबर 2025 के अंक में इस खोज की घोषणा करने वाला पेपर 10 पन्नों में प्रकाशित हुआ है, जिसके लिए खोजकर्ताओं ने 85 से ज्यादा महत्वपूर्ण संदर्भ दिए हैं, जिन्हें खगोलविद्या के ख्यात जर्नल्स जैसे कि मंथली नोटिसेस ऑफ़ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, साइंस, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, नेचर, प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और पब्लिकेशंस ऑफ़ द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ़ पैसिफिक से लिए गए हैं। यह खोज काफी समय तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए किए गए अवलोकन से प्राप्त डाटा के विश्लेषण को पहले के डाटा के संदर्भ में देख कर हुई है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्ज़र्व्ड फ्रेम नियर इंफ्रारेड सेंसिटिविटी और रिज़ॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे पहली बार रेडशिफ्ट पर स्पाइरल गैलेक्सी का पता लगाना मुमकिन हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स ने हाई रेडशिफ्ट पर मॉर्फोलॉजिकल डिस्क गैलेक्सी की एक बड़ी आबादी की खोज की है। हाई-रेडशिफ्ट डिस्क गैलेक्सी की खोज गैलेक्सी बनने की हमारी मौजूदा समझ के लिए चुनौती खड़ी करती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी हमें हाई-रेडशिफ्ट डिस्क गैलेक्सी में स्पाइरल फीचर्स का पता लगाने में भी मदद करती है। रेड-शिफ्ट का अर्थ है ब्रह्मांड में एक पिंड तेज़ी से पृथ्वी से दूर हो रहा है।

हमारे दो खगोलविदों राशि जैन और योगेश वदादिकर का यह बरसों का काम है। ये दोनों पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हैं। राशि जैन खगोल भौतिकी केंद्र में पीएचडी स्कॉलर हैं। राशि ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है, जिसमें यूक्लिड और ग्राउंड-बेस्ड डेटा का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा लाल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिआई का अध्ययन करना शामिल है। उन्होंने विस्टा/विरकाम टेलीस्कोप और भारत के पहले स्पेस-बेस्ड टेलीस्कोप एस्ट्रो सैट/यूवीआईटी से इंफ्रारेड डेटा के साथ भी काम किया है। राशि की विद्या संबंधी रुचियों में एस्ट्रोनॉमिकल डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस और विजुअलाइज़ेशन के साथ-साथ एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाना शामिल है। राशि का अगला लक्ष्य नई खोजी गई गैलेक्सी अलकनंदा में तारों और गैस की गति का अध्ययन करना है।

उक्त रिसर्च पेपर में दिया गया साइंटिफिक आंकड़ा काफी जटिल है, जिसे खगोलविदों की भाषा में उच्च प्रशिक्षण से समझा जा सकता है। इसमें दी गई एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोफिजिकल टर्म्स को समझने के लिए विषय से संबंधित कैटेलॉग्स और शब्दावली कोश देखने की जरूरत महसूस होती है। कुल मिलाकर राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वदादेकर द्वारा की गई खोज को विश्व के ख्यात खगोलविदों और अमरीका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा है।

इस खोज का श्रेय तो भारत के खाते में आया ही है, लेकिन भविष्य की खगोल विद्या में बढ़त के लिए इसका महत्त्व स्पष्ट हुआ है, क्योंकि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर की घटनाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है। इस गैलेक्सी में बारे में जो भी सूचना प्राप्त हुई है, उससे सृष्टि के निर्माण के प्रारंभिक सूत्र मालूम हो सकते हैं और यह भी कि किस प्रकार से ग्रेविटी और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिज्म एनर्जी और पदार्थ रूपांतरण को प्रभावित करते हैं। रोमांच से परे सृष्टि निर्माण के रहस्यों के उद्घाटन की यह कहानी अभी और विस्तार पाएगी।

स्टडी के को-ऑथर योगेश वदादेकर कहते हैं कि अलकनंदा से पता चलता है कि शुरुआती यूनिवर्स हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से गैलेक्सी बनाने में काबिल था। किसी तरह, यह गैलेक्सी कुछ सौ मिलियन सालों में दस अरब सोलर मास के तारों को एक साथ लाने और उन्हें एक खूबसूरत स्पाइरल डिस्क में ऑर्गनाइज़ करने में कामयाब रही। यह कॉस्मिक स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत तेज़ है और यह एस्ट्रोनॉमर्स को यह सोचने पर मजबूर करता है कि गैलेक्सी कैसे बनती हैं। साइंटिस्ट अब इस बात पर बहस करेंगे कि अलकनंदा की स्पाइरल आर्म्स कैसे बनीं।

आमने सामने

एमपी-एमएलए कमीशन वसूलते हैं, एक रुपये में 10 पैसे कमीशन आता है। अपने पार्टी फंड में दिए 40 लाख भी कमीशन से आए थे। मैंने बेटे संतोष सुमन से कहा कि विकास फंड से 5-10% कमीशन लेकर पार्टी मजबूत करें, हर विधायक-सांसद ऐसा करता है।
–जीतन राम मांझी,
केंद्रीय मंत्री

वे सात दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से, उसी माध्यम से, बिना किसी शर्त के माफी मांगें। अपने बयान को वापस लें और भविष्य में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करने का लिखित भरोसा दें। अगर ऐसा नहीं किया, तो आपराधिक और दीवानी कार्रवाई की जाएगी।
–सोमनाथ भारती
नेता आम आदमी पार्टी

अयोध्या की राजकुमारी की 'घर वापसी'

धनीश शर्मा
लेखक

हमारे देश भारतवर्ष में यदाकदा मूर्तियों का अनावरण होता रहता है। हर साल न जाने कितनी ही मूर्तियां चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगाई जाती हैं। अधिकतर मामलों में ये प्रतिमाएं किसी न किसी राजनीतिक, धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित कोरिया मेमोरियल पार्क में स्थापित की गई प्रतिमा सामान्य मूर्ति-अनावरण से अलग है और अपने भीतर एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व समेटे हुए है।

यह प्रतिमा राजकुमारी सूरी रत्ना की है, जिन्हें कोरिया में 'रानी-हो (हेओ ओक)' के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कोरियाई ग्रंथों के अनुसार, वह लगभग दो हजार वर्ष पहले (48 ईस्वी के आसपास) अयोध्या से समुद्री मार्ग के जरिए दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत पहुंची थीं। वहां उन्होंने गया राज्य के राजा किम सुरो से विवाह किया और आगे चलकर 'रानी-हो' के नाम से प्रसिद्ध हुईं। कोरियाई पुराणों और ग्रंथ समगुक यूसा में उनका उल्लेख राजकुमारी 'सुरीरत्ना' या 'हेओ ओक' के रूप में मिलता है, जिनकी उत्पत्ति कुछ विद्वान भारत के 'आयुत' अर्थात अयोध्या से जोड़ते हैं, हालांकि इतिहासकारों के बीच इस कथानक को लेकर मतभेद हैं और इसके ठोस प्रमाण आज भी बहस का विषय बने हुए हैं।

> अयोध्या में राजकुमारी सूरी रत्ना की प्रतिमा स्थापित की गई है। वह लगभग दो हजार वर्ष पहले अयोध्या से समुद्री मार्ग के जरिए दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत पहुंची थीं।

कहते हैं, राजकुमारी सूरी रत्ना के माता-पिता को एक सपना आया था, जिसमें एक दिव्य आवाज ने उन्हें अपनी बेटी को गिमहे भेजने का निर्देश दिया था। वजह यह थी कि गिमहे के राजा सूरो को अपने लिए एक उपयुक्त रानी की तलाश थी। इसके बाद राजकुमारी ने समुद्री मार्ग से लगभग 4500 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी कर अपने सपनों के राजकुमार तक पहुंचने का साहसिक निर्णय लिया।

बताया जाता है कि भले ही राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा किम सुरो के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां सीमित हैं, लेकिन आज कोरिया में दोनों के 60 लाख से अधिक वंशज माने जाते हैं, जो कुल कोरियाई आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हैं। यही कारण है कि कोरियाई समाज में अयोध्या को आज भी 'ननिहाल' के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2019 में राजकुमारी सूरी रत्ना की स्मृति में भारत और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से एक डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं भारतीय संस्कृति की जड़ें उनके वंशजों में आज भी जीवित हैं। यही कारण है कि हर वर्ष उनके वंशज भारत आकर राजकुमारी सूरी रत्ना और अयोध्या से जुड़े अपने सांस्कृतिक संबंधों को स्मरण करते हैं।

कोरिया और अयोध्या के इन पुराने संबंधों को नई पहचान देने के उद्देश्य से सरयू नदी के किनारे स्थित कोरिया मेमोरियल पार्क में 12 फुट ऊंची और लगभग 1.2 टन वजनी राजकुमारी सूरी रत्ना 'रानी-हो' की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा विशेष कोरियाई धातु से तैयार की गई है और इसे आधुनिक तकनीक से सजाया गया है, ताकि भारत और कोरिया के बीच प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों की स्मृति को लंबे समय तक सहेजकर रखा जा सके।

भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या पहले ही वैश्विक पर्यटन के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर चुकी है। अब कोरिया मेमोरियल पार्क और राजकुमारी सूरी रत्ना की प्रतिमा के जुड़ने से अयोध्या की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूती मिली है। जानकारों का मानना है कि प्रतिमा स्थापित होने के बाद दक्षिण कोरिया से आने वाले बौद्ध और अन्य पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या अब केवल एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रही है।

भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध केवल सांस्कृतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा जुड़ाव है। जहां एक तरफ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोरियाई कंपनियो की धूम पूरी दुनिया में है, वहीं कोरियाई कंपनियों का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एक बड़े बाजार के रूप में भारत मे स्थापित हो चुका है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में कोरियाई कंपनियां लंबे समय से भारत में निवेश कर रही हैं। ऐसे में अयोध्या में कोरियाई पर्यटकों के आगमन से स्थानीय व्यापार, पर्यटन उद्योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई गति मिलेगी।

राजकुमारी सूरी रत्ना की प्रतिमा केवल एक ऐतिहासिक कथा का स्मरण भर नहीं है, बल्कि यह भारत और कोरिया के बीच सदियों पुराने रिश्तों को वर्तमान संदर्भ से जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सेतु है। यह स्मारक इस बात का प्रमाण है कि जब इतिहास और संस्कृति को सम्मान के साथ सहेजा जाता है, तो वे समाज और देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि राजकुमारी सूरी रत्ना आज भी भारत और कोरिया के बीच एक जीवंत सेतु की तरह मौजूद हैं।

सोशल फोरम

रूप बदलते 'ईश्वर'

आज से कोई चार हज़ार साल पहले बेबीलोन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। बेबीलोन का सम्राट स्वयं को मार्दूक नामक ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता था। उसका कहना था कि उसने जो नियम और संहिताएं तय की हैं, वो उसे स्वयं मार्दूक ने कहकर सुनाई थीं! आज जब आप मार्दूक के बारे में पड़ताल करने जाते हैं, तो एक वाक्य पर आपका ध्यान टिक जाता है- 'मार्दूक बेबीलोन का अधिपति और पैतृक-ईश्वर था!'

सुशोभित
लेखक

ध्यान रहे- मार्दूक 'था', है नहीं। मार्दूक अब नहीं है। मार्दूक मर गया! किंतु वह आज से चार हज़ार साल पहले 'अतिशय जीवित' था। कालान्तर में बेबीलोन नष्ट हो गया, उसका सम्राट हम्मूराबी मर-खप गया, उसके द्वारा बनाए गए नियम-क़ायदे मिट्टी में मिल गए, तो उसके साथ ही मार्दूक भी धीरे-धीरे विलुप्त हो गया! तब, मार्दूक बेबीलोन का अधिपति था या फिर बेबीलोन ही मार्दूक का जन्मदाता था? ईश्वर अमर नहीं है! समय के साथ ईश्वर मर जाते हैं। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि समय के साथ ईश्वर अपहृत कर लिए जाते हैं। यूनानियों के साथ यही हुआ। जब रोमनों ने यूनान को जीता, तो उनके ईश्वर भी हथिया लिए और उनके नाम बदल दिए!

नतीजा, जो यूनानियों के लिए ज़ीयस था, वह रोमनों के लिए जुपिटर हो गया, जो यूनानियों के लिए ओदिसियस था, वह रोमनों के लिए यूलिसस हो गया, जो यूनानियों के लिए अफ्रोदाइत थी, वह रोमनों के लिए वीनस हो गई। किंतु यूनानियों पर कृपा करके रोमनों ने अपोलो का नाम नहीं बदला। उसे अपोलो ही रहने दिया।

जब एक सभ्यता दूसरी को जीत लेती है, तो उसके शहरों का ही नाम नहीं बदलते, उसके देवताओं के नाम भी बदल देते हैं। एथेंस और देल्फ़ी के मंदिरों में यूनानी जिन देवताओं को पूजते थे, उन बेचारों को क्या मालूम था कि बुरा समय आने पर वो ऐसे पाला बदल लेंगे कि वो ईश्वर के भरोसे नहीं थे, ईश्वर उनके भरोसे थे!

ईश्वर अलग-अलग सभ्यता के अनुसार रूप-रंग बदल लेते थे। ईजिप्ट में आठ प्रमुख ईश्वरों की पूजा की जाती थी, किंतु वो ईजिप्शियनों की तरह लंबी-पतली दाढ़ी रखते थे। अब इन अकेर, अमुन, अन्हुरादि ईश्वरों ने ईजिप्शियनों को अपने रूप में रचा था या ईजिप्शियनों ने ही इन ईश्वरों को अपनी छवि में ढाल दिया था? मेसोपोटामिया के ईश्वर टोपी पहनते थे। ठीक वैसी, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस के दोआब में रहने वाले सुमेरियन और अक्कादियन बाशिंदे पहना करते थे। यूनानियों के देवता घने बालों वाले थे। वो यूनानी दार्शनिकों सरीखे दिखाई देते थे। **-फेसबुक वाल से**

सामयिकी

कोहरे से हारती जिंदगी व मुश्किल होता सफर

उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में थोड़ी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को मथुरा के पास कोहरे के कारण सुबह करीब साढ़े तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें आठ बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे से ठीक दो दिन पहले भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। विजिबिलिटी कम होने के कारण यूपी-हरियाणा में एक के बाद एक कई हादसे हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इन सभी हादसे की वजह कम विजिबिलिटी बताई जा रही है।

घने कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बन जाती है। खासकर उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान कोहरा इतना घना हो जाता है कि कुछ मीटर आगे देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में थोड़ी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, होने वाले कुल सड़क हादसों में करीब नौ फीसदी सड़क हादसे धुंध की वजह से होते हैं। धुंध की वजह से होने वाले सड़क हादसों में मौतों से दोगुनी संख्या घायलों की होती है। रिपोर्ट की मानें तो कई हजार लोग घायल हो जाते हैं। पिछले साल संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि साल 2019 में कोहरे कि वजह से 35,602 सड़क दुर्घटनाएं हुई, वहीं साल 2020 में 26,541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। साल 2021 में 28,934 दुर्घटनाएं घटीं तो साल 2022 में कोहरा 34,262 सड़क दुर्घटनाओं की वजह बना।

रोहित माहेश्वरी
स्वतंत्र पत्रकार

16 दिसंबर को पंजाब में घने कोहरे से बरनाला और तपा मंडी में हुए दो सड़क हादसों में एक ही परिवार के तीन लोगों समेत पांच लोगों की मौत हुई। वजह वही, घने कोहरे के चलते दृश्यता में कमी और स्थिति का आकलन न कर पाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। विडंबना है कि जब हमने चांद और मंगल ग्रह तक दस्तक दे दी है तो राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों के जान-माल की रक्षा के लिए धुंध से मुक्ति की तकनीक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं?

बीते 14 दिसंबर कोहरे के कोहराम से 66 वाहनों के टकराने से एक छात्रा समेत चार लोगों की मौत हरियाणा में भी हुई। चरखी दादरी में एक स्कूल बस और रोडवेज की बस की आमने-सामने की टक्कर में एक ग्यारहवीं की छात्रा की मौत हो गई और तीस से अधिक छात्राएं और शिक्षक, बस चालक समेत घायल हो गए। वहीं तेज रफ्तार वाले नेशनल हाईवे 152-डी पर एक के बाद एक, अनेक वाहन दृश्यता की कमी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए। निश्चय ही निर्दोष लोगों का यूं असमय काल-कवलित होना बेहद दुखद ही है।

कमोबेश दुर्घटनाओं की संख्या कम करके जान-माल का नुकसान कम करने का प्रयास होना ही चाहिए। यह सजगता नागरिकों के स्तर पर भी जरूरी है। यात्रा के समय के चयन और धुंध के बीच वाहन चालन में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर पर्याप्त रोशनी और धुंध में दृश्यता बढ़ाने के तकनीकी प्रयास किए जाएं। मौसमी बाधा के बीच दुर्घटना का एक बड़ा कारण राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से जगह-जगह खोले गए ढाबे भी बनते हैं। दरअसल, होटल-ढाबों के पास वाहनों को अपने परिसर में खड़ा करने की जगह नहीं होती, जिसके चलते ट्रक व अन्य वाहन सड़कों में खड़े रहते हैं, जिसके चलते अक्सर तेजी से आने वाले वाहन दृश्यता की कमी से इन खड़े वाहनों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

सम्पादकीय

पंचायतों के बढ़ते दायरे

प्रगति, विकास और स्थानीय स्वशासन की बागडोर में नए संकल्प और सुधार लाने की जरूरत से पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में परिवर्तन आ रहा है। हालांकि परिवर्तन का परिणाम छोटा है, फिर भी मकसद की शर्त पर कुछ कसौटियां तय हो रही हैं। सोलन और ऊना में छह नई पंचायतों का गठन सिर्फ चुनाव के नए दायरे नहीं, बल्कि नए क्षितिज की तलाशी भी है। इन दोनों जिलों में कई पंचायतें पूरी तरह औद्योगिक रूप से चिन्हित हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में नई पंचायतों का वजूद भी आर्थिक व राजनीतिक निवेश को आमंत्रण दे रहा है। हिमाचल की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के बीच स्थानीय निकायों की बनावट व चुनावी लिखावट का एक खास मुकाम है। इसी संदर्भ में नई पंचायतों के अलावा 31 का पुनर्गठन अपने संकेतों से प्रदर्शित है। हालांकि एक सीमित परिदृश्य में पंचायती राज संस्थाओं के दायरे बदले जा रहे हैं, फिर भी इस प्रक्रिया के मुकम्मल होने के बाद ही चुनावी माहौल बाहर आएगा। हिमाचल की छोटी-बड़ी चुनावी कसरतें अपनी शुरुआत में गांवों की परिक्रमा करती हैं और यही दस्तूर सियासी दलों के लिए साहसिक हो जाता है। पूरा महकमा छह नई पंचायतों के गठन से औद्योगिक शहरों की फैलती सूरत देख रहा है, जबकि प्रदेश में शहरीकरण के फैलाव ने टीसीपी कानून के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू की है। भले ही धर्मशाला-शिमला के नगर निगमों की शहरी गणना के बाद मंडी, सोलन, पालमपुर और अब हमीरपुर-ऊना की शहरी तस्वीर में कई पंचायतें दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन पंचायतों में घुसे शहरों को व्यवस्थित करने के लिए कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का वजन घटाना पड़ेगा, तो कहीं स्थानीय निकायों के पुनगर्ठन में कुछ पंचायतों का लेबल हटाना पड़ेगा। हम चुनाव की खुराक में ग्रामीण हलकों को पुष्ट रखते हैं, जबकि शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा ग्रामीण आर्थिकी की घटती जमीन का मकसद अब नए शहरी निकाय ही पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए प्रदेश के छावनी क्षेत्र से बाहर हो रहे क्षेत्रों को पंचायतों की जिल्द में सांस मिलेगी या इनकी व्यवस्था कि लिए शहरी निकाय को आवाज देनी होगी। योल छावनी से मुक्त हुए क्षेत्र पंचायतों के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं, जबकि आजादी के पहले से ही इन इलाकों के बाशिंदे शहरी व्यवस्था में अतिरिक्त नागरिक सुविधाएं पा रहे थे। नतीजतन योल कैंप के नागरिक क्षेत्र में कुछ ही अवधि के बाद कूड़े के ढेर, सड़ांध और बाकी सुविधाओं की शून्यता पैदा हो गई है। कायदे से यह क्षेत्र धर्मशाला नगर निगम के तहत शहरीकरण के दायरे में आ चुका है, लेकिन नागरिक चेतना अब गांव में सुस्ताना चाहती है। गांव व शहर की परिभाषा के सारे मायने हिमाचल में नेताओं की मुट्ठी में बंद हैं, जहां मुफ्त की सेवाओं में नागरिक को मतदाता के रूप में देखा जाता है। एक ओर टीसीपी के प्रावधान और दिक्कतों के बीच मंत्री महोदय के समाधान,लेकिन आज तक शहरी एवं ग्रामीण सीमाओं का पुनगर्ठन स्पष्ट नहीं हो पाया।

संसद में 'बिरला' का भाषाई यज्ञः प्रधानमंत्री ने भी माना, कोटा के लाल ने बढ़ाया भारत का मान

डॉ नयन प्रकाश गांधी

हाल के संसदीय सत्रों में जो एक सुखद औरदूरगामी बदलाव दिखाई दिया है, वह है ,सदन के पटल पर गूंजती भारत की विभिन्न बोलियां और भाषाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद अब केवल हिंदी और अंग्रेजी तक सीमित न रहकर, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं की जीवंत संवाहिका बन रही है। इस भाषाई क्रांति की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने की है, जो न केवल अध्यक्ष के विजन की पुष्टि है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी है।ओम बिरला ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया कि भाषा किसी भी जन-प्रतिनिधि के लिए बाधा न बने।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना का दर्पण होती है। हाल के संसदीय सत्रों में जो एक सुखद औरदूरगामी बदलाव दिखाई दिया है, वह है ,सदन के पटल पर गूंजती भारत की विभिन्न बोलियां और भाषाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद अब केवल हिंदी और अंग्रेजी तक सीमित न रहकर, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं की जीवंत संवाहिका बन रही है। इस भाषाई क्रांति की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने की है, जो न केवल अध्यक्ष के विजन की पुष्टि है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी है।ओम बिरला ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया कि भाषा किसी भी जन-प्रतिनिधि के लिए बाधा न बने। तकनीकी सुविधाओं और रीयल-टाइम अनुवाद की व्यवस्था को सुदृढ़ कर उन्होंने सदन के भीतर एक ऐसा वातावरण तैयार किया है, जहां एक सांसद अपनी मातृभाषा में अपनी बात गर्व के साथ रख सकता है। जब एक सांसद तमिल, बांग्ला, मराठी या राजस्थानी पुट वाली हिंदी में अपनी बात कहता है, तो वह केवल एक विचार नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की संस्कृति और अस्मिता को दिल्ली के इस सर्वोच्च सदन से जोड़ता है।कोटा वासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि वहां के प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ी है।

संसदीय कूटनीति और वैश्विक पहचान

ओम बिरला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय संसदीय प्रणाली की गरिमा को नई ऊँचाइयां दी हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन और इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियनजैसे वैश्विक मंचों पर उन्होंने लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। हाल ही में बारबाडोस की यात्रा और अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से उन्होंने संसदीय कूटनीति का विस्तार किया, जिससे वैश्विक पटल पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और बढ़ा है।

संसदीय उत्पादकता के नए कीर्तिमान

ओम बिरला का कार्यकाल केवल भाषाई सुधारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके नेतृत्व में संसद की कार्यक्षमता में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। 17वीं लोकसभा के दौरान सदन की औसत उत्पादकता लगभग 97त्न रही, जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। विशेष रूप से कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने सत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया और एक समय तो उत्पादकता 167त्न तक जा पहुँची। यह उनके अनुशासन और समय प्रबंधन का ही परिणाम है कि सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान अधिक से अधिक सदस्यों को लोकहित के मुद्दे उठाने का अवसर मिला।

18वीं लोकसभा- उत्पादकता के नए शिखर (111% से 118% तक)

ओम बिरला के दूसरे कार्यकाल में संसद की कार्य-उत्पादकता ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र (दिसंबर 2025) में लोकसभा की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही। इससे पहले, बजट सत्र 2025 के दौरान सदन की उत्पादकता 118 प्रतिशत के प्रभावशाली स्तर तक पहुँच गई थी। बिरला ने यह सुनिश्चित किया कि सदन केवल हंगामे का केंद्र न बने, बल्कि देर रात तक बैठकर लोक-महत्व के विषयों पर चर्चा हो। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ नयन प्रकाश गांधी का मानना है कि लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के उत्कृष्ट नेतृत्व में ही ऐतिहासिक रूप से %जीरो ऑवर% (शून्यकाल) के दौरान रिकॉर्ड संख्या में सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर रूप से उजागर करने का मौका मिला,जो जमीन हकीकत से सीधे लोकतंत्र के अस्तित्व को सही मायनों में प्रदर्शित करता है।

महत्वपूर्ण विधायी कार्य और विकसित भारत का संकल्प

बिरला के वर्तमान कार्यकाल में कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक पारित हुए हैं। इनमें विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (जी राम जी) विधेयक 2025 प्रमुख है, जिसने मनरेगा जैसे पुराने ढांचे में सुधार कर ग्रामीण रोजगार की नई दिशा तय की। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुरक्षा,परमाणु ऊर्जा और बीमा कानूनों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा और उनके सफल पारित होने के पीछे बिरला की कुशलता और सभी दलों के बीच समन्वय बिठाने की कला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने भी उनके इस कौशल की सराहना करते हुए इसे संसदीय दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।

संसदीय नवाचारAI और सांसद भाषिणी

बिरला ने तकनीक को संसदीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना दिया है। उनके विजन से विकसित डिजिटल संसद और सांसद भाषिणी ने भाषाई बाधाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब कोई भी सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलता है, तो तकनीक के माध्यम से उसका अनुवाद तुरंत अन्य भाषाओं में उपलब्ध हो जाता है। यह पहल न केवल उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि सदन के भीतर भारत की एकता और विविधता को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करती है।वैश्विक मंचों, जैसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भी भारत के इस डिजिटल मॉडल की जमकर प्रशंसा हुई है।

अनुशासन और लोकतांत्रिक मर्यादा

ओम बिरला ने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अनुशासन को सर्वोपरि रखा है। उनका मानना है कि सदन चर्चा के लिए है, व्यवधान के लिए नहीं। उन्होंने बार-बार सांसदों से आत्मनिरीक्षण का आग्रह किया ताकि संसदीय समय का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में हो सके। उनके शांत लेकिन सख्त व्यवहार ने सदन में स्वस्थ बहस की परंपरा को पुनर्जीवित किया है, जहाँ विपक्ष की आवाज़ को भी पर्याप्त स्थान मिलता है और सरकारी कार्यों को भी गति प्राप्त होती है।युवा मैनेजमेंट विश्लेषक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ नयन प्रकाश गांधी का मानना है कि बिरला की कार्यशैली सहिष्णुता और अनुशासन का संगम है।

स्कूल के बाहर खड़ी आधी आबादी : जब बेटियाँ बीच रास्ते लौट आती हैं

डॉ. प्रियंका सौरभ

छूटी हुई पाठशाला, छिनते सपने भारत की बेटियों की अधूरी शिक्षा; अधिकार से वास्तविकता तक लड़कियों की स्कूली ड्रॉपआउट की क्रूर सच्चाई; स्कूल के बाहर खड़ी आधी आबादी जब बेटियाँ बीच रास्ते लौट आती हैं; किताब, काँच और क़ैद पितृसत्ता के साये में लड़कियों की शिक्षा; ड्रॉपआउट की दीवार के पार भारत की बेटियाँ और शिक्षा का संघर्ष; अनुच्छेद 21 से आगे की लड़ाई क्यों छूट जाती हैं बेटियाँ स्कूल से?; संविधान ने हक़ दिया, समाज ने रोका लड़कियों की अधूरी स्कूली यात्रा; सायकिल, शौचालय और सुरक्षा तीन कुंजियाँ, जो बेटियों को स्कूल में रोक सकती हैं; बाल विवाह, घरेलू बोझ और डर लड़कियों की शिक्षा के अदृश्य दुश्मन; जब स्कूल नहीं, घर बनता है किस्मत बेटियों की शिक्षा और भारतीय समाज।

भारत में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की कहानी आज़ादी के बाद के विकास-वृत्तांत की सबसे जटिल और मार्मिक कड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, पर ज़मीनी तस्वीर बताती है कि जैसे-जैसे कक्षा बढ़ती है, लड़कियों की संख्या कम होती जाती है और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते बड़ी संख्या में बेटियाँ स्कूल से बाहर हो चुकी होती हैं। यह केवल शैक्षणिक ढाँचे की विफलता नहीं, बल्कि गहरे बैठे सामाजिक पूर्वाग्रह, पितृसत्ता, आर्थिक अभाव और राज्य की अधूरी प्रतिबद्धताओं की संयुक्त देन है।

सबसे पहले बात स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की, जो लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार और शिक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बीच की सबसे कठोर दीवार बनकर खड़ी हैं। आज भी अनेक सरकारी स्कूलों में अलग, सुरक्षित और कार्यशील शौचालयों की कमी है; जहाँ शौचालय बने भी हैं, वहाँ साफ-सफाई, पानी और रखरखाव की स्थिति अक्सर बेहद खराब रहती है। किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ और सम्मानजनक व्यवस्था जीवन की बुनियादी ज़रूरत है; लेकिन जब स्कूल इस ज़रूरत को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो परिवार के लिए सबसे आसान विकल्प लड़की को घर बैठा देना होता है। स्वच्छ पेयजल, सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता, कचरा निस्तारण जैसी बातें कागज़ी योजना-दस्तावेज़ों में चाहे जितनी आकर्षक दिखें, ज़मीन पर उनकी कमी लड़कियों के हौसले को बार-बार तोड़ती है। यह वही उम्र है जहाँ शिक्षा आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का रास्ता खोल सकती है, लेकिन अवसंरचना की कमी उसे 'ड्रॉपआउट' के आँकड़ों में बदल देती है।

दूसरा बड़ा कारक स्कूल तक पहुँच का है, जिसमें दूरी और सुरक्षा दोनों शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अक्सर गाँव से कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं। लड़के किसी तरह साइकिल या पैदल यह दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में हर किमी के साथ असुरक्षा, झिझक और जोखिम भी बढ़ जाता है। रास्ते में छेड़खानी, उत्पीड़न, सुनसान सड़कें, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और देर से घर लौटने का डर, माता-पिता के मन में यह धारणा गहरी कर देते हैं कि इतनी दूर भेजना सुरक्षित नहीं। जहाँ-जहाँ साइकिल वितरण, छात्राओं के लिए सुरक्षित बस-सेवा, या क्लस्टर-स्कूल जैसा मॉडल ईमानदारी से लागू हुआ, वहाँ यह साफ़ दिखा कि परिवहन-सुरक्षा की समस्या हल होते ही लड़कियों की उपस्थिति, ट्रांज़िशन रेट और बोर्ड तक बने रहने के आँकड़े बेहतर हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सही नीतिगत हस्तक्षेप से दूरी नाम की बाधा को शिक्षा का रास्ता रोके बिना भी संभाला जा सकता है।

तीसरी वजह घर की चारदीवारी के भीतर छिपी है—घरेलू काम और देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना में बेटा अक्सर भविष्य का कमाने वाला और बेटी परिवार की ज़िम्मेदारी मानी जाती है। गरीब और निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों में माँ के साथ खाना बनाना, बर्तन-कपड़े धोना, छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना, पानी लाना, खेत या दुकान में मदद करना—इन सभी कामों का सबसे आसान विकल्प लड़की ही बनती है। उसके स्कूल-समय को लचीला समझा जाता है; जैसे ही घर का बोझ बढ़ता है, सबसे पहले उसकी पढ़ाई कटती है। सर्वेक्षण बार-बार दिखाते हैं कि बहुत-सी लड़कियाँ पढ़ाई में रुचि नहीं की वजह से नहीं, बल्कि घर के काम और परिवारिक ज़िम्मेदारी के कारण स्कूल छोड़ती हैं, लेकिन डेटा में इसे अक्सर गलत ढंग से दर्ज कर दिया जाता है। यह अदृश्य श्रम, जो घर और समाज के पहियों को चलाता है, लड़की के अधिकारों और भविष्य के रास्ते में सबसे बड़े रोड-ब्लॉक में बदल जाता है। चौथा निर्णायक तत्व है बाल विवाह और विवाह-केंद्रित सामाजिक मानसिकता। आज भी अनेक समुदायों में यह मान्यता जीवित है कि लड़की की इज़्ज़त और भविष्य का असली उपाय उसे जल्दी ब्याह देना है, न कि लंबी शिक्षा देना। ज़्यादा पढ़ाई को कई बार बिगड़ने, पति न मानने या शादी देर से होने के ख़तरे के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर के सर्वे साफ़ दिखाते हैं कि अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी लड़कियों में 18 वर्ष से पहले विवाह की संभावना कहीं अधिक होती है, जबकि उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों में यह अनुपात बहुत कम है। यह दुष्चक्र बेहद क्रूर है—कम शिक्षा बाल विवाह को जन्म देती है और बाल विवाह आगे की शिक्षा की संभावना लगभग समाप्त कर देता है। शादी के बाद ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, जल्दी गर्भधारण का सामाजिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, लड़की को स्कूल से स्थायी रूप से बाहर कर देते हैं।

इन सबके ऊपर आर्थिक बाधाएँ एक तरह से सील का काम करती हैं। भले ही सरकारी स्कूलों में फीस नाममात्र की हो या न हो, लेकिन यूनिफॉर्म, जूते-चप्पल, किताबें, कॉपियाँ, परीक्षा शुल्क, ट्यूशन, परिवहन—इन अप्रत्यक्ष खर्चों का बोझ गरीब परिवारों के लिए बहुत भारी होता है। ऐसे परिवारों की आर्थिक गणित अक्सर बेटे के पक्ष में झुक जाती है; उन्हें लगता है कि लड़के की शिक्षा पर निवेश का प्रतिफल नौकरी या कमाई के रूप में मिलेगा, जबकि लड़की की पढ़ाई निवेश से अधिक दान जैसी समझी जाती है। यह सोच कई बार लड़कियों को बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं से बाहर धकेल देती है, तो कई बार आठवीं, दसवीं या बारहवीं के मोड़ पर उनकी शिक्षा का धागा टूट जाता है।

हिंदी साहित्य के विकास में वैश्विक बाजार और उपभोक्तावाद की भूमिका

संजीव ठाकुर

इक्कीसवीं सदी का विश्व मूलतः उपभोक्तावाद की धुरी पर घूम रहा है। उत्पादन, विपणन, संचार और संस्कृति,सब कुछ बाज़ार के तर्कों से संचालित होने लगा है। ऐसे समय में भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि वह बाज़ार तक पहुँचने का सबसे प्रभावी औज़ार बन जाती है। इसी संदर्भ में हिंदी आज एक नई भूमिका में सामने आती है एक विशाल उपभोक्ता समाज की संपर्क भाषा के रूप में। हिंदी साहित्य, हिंदुस्तानी संस्कृति और उपभोक्तावाद के इस त्रिकोणीय संबंध ने हिंदी को न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान दी है।

भारत आज विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाज़ारों में से एक है। लगभग 141 करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश, विविध भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद, बाज़ार के स्तर पर एक साझा संप्रेषण भाषा की माँग करता है। यह भूमिका स्वाभाविक रूप से हिंदी निभाती है। किंतु यह हिंदी अपने शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ रूप में नहीं, बल्कि एक लचीले, मिश्रित और व्यावहारिक रूप में सामने आती है—जिसे प्रचलित भाषा में हिंग्लिश या हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसमें हिंदी के साथ अंग्रेज़ी और उर्दू के शब्द सहज रूप से घुले-मिले होते हैं।

आज की विडंबना यह है कि स्वयं भारत में विशुद्ध हिंदी का प्रयोग दिन-ब-दिन सीमित होता जा रहा है। समाचार चैनलों के एंकर, विज्ञापन, सोशल मीडिया, कॉरपोरेट संवाद—सब जगह हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का घालमेल सामान्य हो चुका है। टेलीविजन को दूरदर्शन, इंटरनेट को अंतरजाल और मोबाइल को चलदूरभाष कहना अब व्यवहारिक नहीं लगता। यह केवल भाषायी आलस्य नहीं, बल्कि उपभोक्ता बाज़ार की माँग का परिणाम है। बाज़ार वही भाषा स्वीकार करता है जो त्वरित, सरल और सर्वग्राह्य हो।

संचार क्रांति ने इस प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया है। टेलीविजन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल मंच सीधे-सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं। इन माध्यमों पर प्रयुक्त हिंदी वह हिंदी है जो तुरंत समझ में आए, भावनात्मक रूप से जुड़े और उपभोक्ता को आकर्षित करे। परिणामस्वरूप, विज्ञापनों में हिंदी का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा है, किंतु यह हिंदी संस्कृत की शुद्धता से अधिक बाज़ार की सरलता से संचालित होती है। यह भी एक तथ्य है कि आज के अनेक बड़े हिंदी साहित्यकार भी अपनी रचनाओं में अंग्रेज़ी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग सहजता से कर रहे हैं। यह कोई साहित्यिक पतन नहीं, बल्कि भाषा की जीवंतता का संकेत है। भाषा वही जीवित रहती है जो समय, समाज और बाज़ार के साथ स्वयं को ढाल लेती है। हिंदी का स्वभाव ऐतिहासिक रूप से ऐसा ही रहा है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि हिंदी ने कभी केवल विदेशी होने के कारण किसी शब्द का तिरस्कार नहीं किया। उर्दू, फ़ारसी और बाद में अंग्रेज़ी—हिंदी ने सभी को आत्मसात किया और अपनी अभिव्यक्ति को और समृद्ध बनाया। वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो हिंदी का विस्तार और भी रोचक दिखाई देता है। भारतीय मूल के लोग आज श्रीलंका, मॉरीशस, फ़िजी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। ये प्रवासी और अप्रवासी भारतीय अपने साथ हिंदी और हिंदुस्तानी संस्कृति को भी ले गए हैं। परिणामस्वरूप, हिंदी का वैश्विक विस्तार स्वाभाविक रूप से इन समुदायों के माध्यम से हो रहा है। इसी के साथ, अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और कोरिया जैसे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत को एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार के रूप में देखती हैं। एक ही देश में करोड़ों संभावित ग्राहक मिलना विश्व के किसी अन्य देश में संभव नहीं है। इसलिए ये कंपनियाँ अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाती हैं। विज्ञापन, ब्रांडिंग और डिजिटल कंटेंट में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यह बाज़ारवाद के दृष्टिकोण से हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति है।

भाषा-अध्ययनों में भी हिंदी की स्थिति लगातार सुदृढ़ होती दिखाई देती है। हालिया वैश्विक भाषायी अध्ययनों के अनुसार हिंदी (हिंदुस्तानी सहित) विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अग्रणी स्थान पर है। लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं।

साहिबज़ादे जोरावर सिंह और फतेह सिंहःसाहस, धैर्य और बलिदान की अमर गाथा

निखिलेश महेश्वरी

आज का बालक धीरे-धीरे अपना धैर्य खोता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि समाज में आत्महत्या, अपराध और संवेदनहीनता जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरों के प्रति सम्मान, आत्मगौरव तथा अपने धर्म के प्रति आस्था भी कम होती दिखाई दे रही है। जबकि वास्तव में बालक के भीतर साहस, धैर्य, आत्मगौरव, संवेदनशीलता और व्यवहार-कुशलता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने चाहिए। यही गुण उसे अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ करने में सक्षम बनाते हैं। यदि हमें बालकों में इन गुणों का विकास करना है, तो उन्हें ऐसे महापुरुषों और वीर बालकों के जीवन-चरित्र सुनाने होंगे, जिनसे वे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्हें ऐसे गीत सिखाने होंगे जिन्हें वे अपने जीवन में उतार सकें। ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा जो सीधे उनके हृदय को स्पर्श करें। साथ ही, ऐसी फिल्मों से उनका परिचय कराना होगा जिन्हें देखकर उनके भीतर आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक और जिम्मेदार नागरिक अपने-अपने स्तर पर बच्चों में इन गुणों के विकास का प्रयास करेंगे तो ही ध्रुव, प्रह्लाद, हकीकत, भगतसिंह जैसे बालक तैयार होंगे। 26 दिसंबर को हमारे सामने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो आत्मगौरव और बलिदान की भावना को जाग्रत करता है-यह अवसर है वीर बाल दिवस। संभव है कि अनेक बालकों को इसके विषय में पर्याप्त जानकारी न हो, इसलिए आइए, इस पावन अवसर के संदर्भ में हम सब मिलकर चर्चा करें और आने वाली पीढ़ी को उसके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएँ।

वर्ष 1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर सिख धर्म के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की।

उनके चारों पुत्र साहिबज़ादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह खालसा पंथ के अभिन्न अंग थे। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य मुगल शासन के अत्याचारों से समाज की रक्षा करना था, क्योंकि उस समय पंजाब पर मुगलों का प्रभुत्व था।

खालसा पंथ के इस जनजागरण और संघर्ष को समाप्त करने के लिए मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने हेतु अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। इसी क्रम में 20 दिसंबर 1704 की कड़ाके की ठंड में मुगल सेना ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर आक्रमण कर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों को करारा उत्तर देना चाहते थे, किंतु उनके साथियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। गुरु जी ने भी जत्थे की सम्मति स्वीकार की और अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर प्रस्थान किया।

मार्ग में सरसा नदी का वेग अत्यंत तीव्र था। नदी के प्रचंड बहाव के कारण उसे पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक-दूसरे से बिछुड़ गया। यही वह क्षण था, जिसने आगे चलकर इतिहास को बलिदान की अमर गाथाओं से भर दिया।

धर्म की रक्षा के लिए इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। चमकौर में जब मुगलों के साथ भीषण युद्ध चल रहा था, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्रों साहिबज़ादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी को क्रमशः युद्धभूमि में भेजा। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उत्साह, शौर्य और अदम्य साहस से परिपूर्ण इन वीर साहिबज़ादों ने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंततः रणभूमि में अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित कर अमर हो गए।

संपादकीय

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट

साल 1947 में भारत के बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में आगे और बंटवारे की संभावना दिख रही थी।कई जानकारों ने इसे एक भौगोलिक गड़बड़ी, मीलों दूर दो अलग-अलग इलाकों का एक ढीला-ढाला मेल बताया था। मुस्लिम बहुमत के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान; जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत कम समानता थी। साल 1971 के युद्ध के पीछे पाकिस्तान की नेशनल आर्मी के सैनिक स्थानीय बंगाली आबादी के साथ बलात्कार, मारपीट और दूसरे अपराध थे, जिससे तंग लोग भारत भाग गए। इतने बड़े पैमाने पर पलायन और अमानवीय गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी शासन से आजाद कराकर नया देश बनाने का फैसला किया। मुख्य संघर्ष के दौरान भारत द्वारा प्रशिक्षित बांग्ला मुक्ति वाहिनी ने खुफिया जानकारी इकट्ठा की और कुछ इलाकों में पाकिस्तान से सप्लाई बंद करने में मदद की। भारतीय सेना ने ज्यादातर सैनिक ट्रेनिंग, उपकरण और मैनपावर सप्लाई की। युद्ध की आधिकारिक शुरूआत से बहुत पहले भारतीय सेना, मुक्ति फौज से मिलकर लड़ रही थी। पहली झड़प 01 जुलाई 1971 में हुई जब 57 आर्टिलरी ब्रिगेड ने कर्नल पीके गौतम के ऑपरेशन बांग्लादेश के तहत आतग्राम और चग्राम में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऐसी मुठभेड़ें दिसंबर तक जारी रहीं, जिसके दौरान मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध, तोड़फोड़ और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि वे सीधे मुकाबले में भारतीय सेना पर निर्भर थे क्योंकि वे सीधे मुकाबले में कमजोर लड़ाके थे। दिसंबर 1971 में भारत ने 3900 सैनिक खो दिए। पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद भारत ने उन्हें घर लौटने में मदद की, ट्रांसपोर्टेशन दिया और सड़कों एवं पुलों की मरम्मत में सहायता की। भारत ने बांग्लादेश को जो लगभग 232 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया था, वह दे दिया गया। साल 1972 में बांग्लादेश को खाद्यान्न मदद का सबसे बड़ा हिस्सा भारत का था। भारत- बांग्लादेश व्यापार समझौते से बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ। 28 मार्च 1972 को 5 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त स्विंग लिमिट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे बांग्लादेश को कोयला और अन्य जरूरी सामान और संसाधन खरीदने की अनुमति मिली। भारत में लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों का स्वागत किया गया और देश के आम नागरिकों ने स्वेच्छा से वित्तीय बोझ साझा किए। देश के नागरिकों ने पूर्वी पाकिस्तानी प्रतिरोध बलों का जोरदार समर्थन किया और एक युद्ध कर लगाया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के लगातार अत्याचारों के कारण स्थिति और खराब होने की आशंका थी इसलिए भारत को आखिरकार सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

वीर बाल दिवस हमें साहस, सत्य, आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान की प्रेरणा देता है

यह बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। सिख धर्म की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व का विषय है। नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान और मूल्यों से परिचित कराना हमारा नैतिक दायित्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। इससे बच्चों और युवाओं में शौर्य, साहस और राष्ट्रप्रेम की भावना प्रबल हुई है। जब हम साहिबजादों के जीवन को देखते हैं, तो हमें दशम गुरु , गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षाओं पर गर्व होता है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग दिखाया ”

मोहन लाल
प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा

"वीरता उम्र से बंधी नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के दृढ़ विश्वासों से परिभाषित होती है।" 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम दशम गुरु , गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों – बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी – के अद्वितीय बलिदान को नमन करते हैं। केवल 9 वर्ष और 7 वर्ष की अल्पायु में साहिबजादों ने जिस अदम्य साहस, आस्था और बलिदान का परिचय दिया, वह मानव इतिहास में अनुकरणीय है।इतनी छोटी उम्र में भी साहिबजादे किसी दबाव के आगे नहीं झुके, अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए और धर्म एवं सत्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। सिख धर्म की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व का विषय है। नई पीढ़ी को साहिबजादों के बलिदान और मूल्यों से परिचित कराना हमारा नैतिक दायित्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2022 से वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। इससे बच्चों और युवाओं में शौर्य, साहस और राष्ट्रप्रेम की भावना प्रबल हुई है। जब हम साहिबजादों के जीवन को देखते हैं, तो हमें दशम गुरु , गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षाओं पर गर्व होता है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग दिखाया। उनकी प्रेरक पंक्तियाँ सवा लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊँ, तबै गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊँ। आज भी हर भारतीय के भीतर साहस और संघर्ष की चेतना जागृत करती है।यह पंक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि साधन नहीं, साहस और संकल्प ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत की धरती धन्य है, जिसने ऐसे महान गुरुओं और साहिबजादों को जन्म दिया। साहिबजादों का बलिदान हमें निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रप्रथम की भावना का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। राष्ट्र, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए चारों साहिबजादों ने अन्याय, अत्याचार के सामने झुकने से मना करते हुए धर्म परिवर्तन नहीं किया।छोटी सी आयु में भी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, यह अडिग आस्था, वीरता एवं साहस की मिसाल है।वीर बाल दिवस पर मैं देश के सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा, तो वो अपने जीवन में, अपने करियर में भी सुपरहिट होगा। भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे आप दिन में या सप्ताह में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? आप सुपरफूड मिलेट्स-श्रीअन्न के बारे में जानते हैं लेकिन क्या आपने इसे अपनी डाइट में शामिल कर रखा है? डिजिटल डीटॉक्स, डिजिटल डीटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं? आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? क्या आप एक दिन में पर्याप्त नींद लेते हैं या फिर नींद पर उतना ध्यान ही नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज की आधुनिक युवा पीढ़ी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं।

एक और बहुत बड़ी समस्या भी है, जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है, नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवाशक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ-साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा।गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के शहादत दिवस को ह्यवीर बाल दिवसह्न घोषित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनके बलिदान की गाथा को देश और दुनिया के हर कोने में फैलाया है। गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्रों, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की मार्मिक कहानी से वीर बाल दिवस प्रेरित हुआ है। प्रत्येक पुत्र ने सिख मूल्यों की रक्षा, पालन और संरक्षण के लिए असाधारण वीरता और समर्पण का परिचय दिया। बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह ने दिसंबर 1705 में चमकौर के युद्ध में वीरतापूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुगल सेना ने उनके छोटे भाइयों, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया। मात्र 9 और 6 वर्ष के इन दोनों छोटे साहिबजादों ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर शहादत स्वीकार कर ली और उन्हें एक दीवार में जिंदा दफना दिया गया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक कायम रही है क्योंकि उनके बलिदान न केवल अटूट आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि दृढ़ विश्वास और धार्मिकता की अपार शक्ति को भी दशार्ते हैं। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इन युवा शहीदों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने के लिए 2022 में इस दिवस को राष्ट्रीय अवकाश की शुरूआत की, जिन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाए रखी। एक बार पुनः महान गुरू परंपरा को, शहादत को नया सम्मान, नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मअपने लेख को विराम देता हूं।जय जय चारों साहिबजादे,जय मां गुजरी का बलिदान ।ऐसे ही वीरों के दम पर हिंदुत्व सुरक्षित हिंदुस्तान।हम सभी ऋणी उन वीरों के उनको हम शीश झुकाते हैं।जिन बलिदानों के बल पर हम सब गर्व से हिंदू कहते हैं।।

मिर्जा गालिब - महान रचनाकार

डॉ. प्रितम भि. गेडाम

"हाथों की लकीरों पर मत जा ऐ गालिब, नसीब उनके भी होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते।"

उर्दू-फारसी के सर्वकालिक महान शायर मिर्जा असदुल्लाह बेग खान उर्फ गालिब अपने मन व देश की मनोदशा को स्वंयम की गजलो व शायरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उनके द्वारा रचित शेरो-शायरी आज भी लोगों के जेहन और जुबान पर बनी हुई हैं। कितने ही दौर आये और गए लेकिन गालिब का जादू जो का त्यों है, गालिब को शायरी का पर्यायवाची भी कहा जाता है उनके द्वारा लिखी गई शायरी हर वर्ग के व्यक्ति को पसंद हैं। गालिब की रचनाएँ न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय कराने का श्रेय भी इनको दिया जाता हैं। गालिब के लिखे पत्र, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, इन पत्रों को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता हैं। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। इनके पूर्वज तुर्की में रहा करते थे, उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग खान और माता का नाम इज्जत-उत-निसा बेगम था। 1803 में अलवर में एक युद्ध के दौरान मिर्जा गालिब के पिता की मृत्यु हुई। 11 वर्ष की उम्र से ही मिर्जा गालिब ने कविता लिखना शुरू कर दिया था एवं 13 वे साल में उनकी शादी उमराव बेगम से हुई। उनके सात बच्चे हुए लेकिन एक भी जीवित नहीं रह पाया। आरिफ अर्थात गोद लिया हुआ बेटे को भी अपने बच्चे की तरह पाला पर फिर भी अन्य बच्चो की तरह यह बच्चा भी ज्यादा समय नही जी पाया। ताउम्र उन्हें इस बात का दुख था, इस बात का जिक्र उन्होने अपनी कविता कैद-ए-हयात-ओ-बंद-ए-गम मे दर्शार्या था। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। 1850 में बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में गालिब को दबीर-उल-मुल्क की उपाधि से नवाजा गया और इसके अलावा उनको नज्म-उद-दौला के खिताब से नवाजा गया। मिर्जा गालिब का मुगल दरबार में बहुत मान-सम्मान था। 1854 में खुद बहादुर शाह जफर ने उनको कविताओं के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, व्यंग्य करने वालों पर गालिब शायरी लिख दिया करते थे। मुगलों के पतन के दौरान उन्होंने मुगलों के साथ बहुत वक्त बिताया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गालिब पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें दी जाने वाली पेंशन भी बंद करवा दी। वह अपनी हर रचना मिर्जा, असद या गालिब के नाम से लिखते थे, इसलिए वह इस नाम से प्रसिद्ध हो गये। मिर्जा गालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था।

वस्त्र विन्यास पर विशेष ध्यान रखते थे। खाने-खिलाने के शौकीन, स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रेमी थे। मिर्जा गालिब जीवन के संघर्ष से भागते नहीं थे, वह इस संघर्ष को जीवन का एक अंश तथा आवश्यक भाग समझते थे। मानव की उच्चता तथा मनुष्यत्व को सब कुछ मानकर उसके भावों तथा विचारों का वर्णन करने में वह अत्यंत निपुण थे।

विचार

साहिबजादे: साहस, धैर्य और बलिदान की अमर गाथा

निखिलेश

आज का बालक धीरे-धीरे अपना धैर्य खोता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि समाज में आत्महत्या, अपराध और संवेदनहीनता जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरों के प्रति सम्मान, आत्मगौरव तथा अपने धर्म के प्रति आस्था भी कम होती दिखाई दे रही है। जबकि वास्तव में बालक के भीतर साहस, धैर्य, आत्मगौरव, संवेदनशीलता और व्यवहार-कुशलता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने चाहिए। यही गुण उसे अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ करने में सक्षम बनाते हैं। यदि हमें बालकों में इन गुणों का विकास करना है, तो उन्हें ऐसे महापुरुषों और वीर बालकों के जीवन-चरित्र सुनाने होंगे, जिनसे वे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्हें ऐसे गीत सिखाने होंगे जिन्हें वे अपने जीवन में उतार सकें। ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा जो सीधे उनके हृदय को स्पर्श करें। साथ ही, ऐसी फिल्मों से उनका परिचय कराना होगा जिन्हें देखकर उनके भीतर आत्मगौरव और राष्ट्रीय भावना जागृत हो सके। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक और जिम्मेदार नागरिक अपने-अपने स्तर पर बच्चों में इन गुणों के विकास का प्रयास करेंगे तो ही ध्रुव, प्रह्लाद, हकीकत, भगतसिंह जैसे बालक तैयार होंगे। 26 दिसंबर को हमारे सामने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो आत्मगौरव और बलिदान की भावना को जाग्रत करता है-यह अवसर है ह्लवीर बाल दिवसह्व। संभव है कि अनेक बालकों को इसके विषय में पर्याप्त जानकारी न हो, इसलिए आइए, इस पावन अवसर के संदर्भ में हम सब मिलकर चर्चा करें और आने वाली पीढ़ी को उसके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएँ। वर्ष 1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर सिख धर्म के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उनके चारों पुत्र साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह खालसा पंथ के अभिन्न अंग थे। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य मुगल शासन के अत्याचारों से समाज की रक्षा करना था, क्योंकि उस समय पंजाब पर मुगलों का प्रभुत्व था। खालसा पंथ के इस जनजागरण और संघर्ष को समाप्त करने के लिए मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ने हेतु अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। इसी क्रम में 20 दिसंबर 1704 की कड़ाके की ठंड में मुगल सेना ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर आक्रमण कर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों को करारा उत्तर देना चाहते थे, किंतु उनके साथियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। गुरु जी ने भी जत्थे की सम्मति स्वीकार की और अपने पूरे परिवार के साथ आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर प्रस्थान किया। मार्ग में सरसा नदी का वेग अत्यंत तीव्र था। नदी के प्रचंड बहाव के कारण उसे पार करते समय गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार एक-दूसरे से बिछुड़ गया। यही वह क्षण था, जिसने आगे चलकर इतिहास को बलिदान की अमर गाथाओं से भर दिया। धर्म की रक्षा के लिए इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। चमकौर में जब मुगलों के साथ भीषण युद्ध चल रहा था, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्रों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी को क्रमशः युद्धभूमि में भेजा। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उत्साह, शौर्य और अदम्य साहस से परिपूर्ण इन वीर साहिबजादों ने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंततः रणभूमि में अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पित कर अमर हो गए। दूसरी ओर माता गुजरी देवी अपने दो छोटे पौत्रों–साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा उनके रसोइए गंगू के साथ एक गुप्त स्थान पर शरण लेने को विवश हुईं। किंतु दुर्भाग्यवश, लालच में आकर गंगू ने माता गुजरी जी और उनके पौत्रों की सूचना मुगल अधिकारियों तक पहुंचा दी।

इसके परिणामस्वरूप गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादे मुगलों की गिरफ्त में आ गए और उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने प्रस्तुत किया गया। वजीर खान ने इन नन्हे वीरों पर अमानवीय अत्याचार किए और उन्हें जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने अपने धर्म और आस्था से विचलित होने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।
संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)
'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

आकाश-एनजी: आत्मनिर्भर भारत का अभेद्य और अजेय शस्त्र

आरके जैन

23 दिसंबर 2025 का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, जब डीआरडीओ ने नेक्स्ट जेनरेशन आकाश (आकाश-एनजी) मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न किया। यह केवल एक तकनीकी परीक्षण नहीं था–यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। उच्च गति वाले, कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों से लेकर दूरस्थ उच्च ऊंचाई वाले खतरों तक, आकाश-एनजी ने हर परिस्थिति में निर्भीकता और सटीकता से दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता साबित की। जब पड़ोसी देश लगातार ड्रोन स्वार्म, क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ फाइटर के जरिए भारत की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, तब यह सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ढाल बनकर उभरा है–एक ऐसा हथियार जो आकाश को भारत का अभेद्य किला बना देगा। यूजर ट्रायल्स की यह ऐतिहासिक सफलता इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि आकाश-एनजी ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों की तरह कई चुनौतीपूर्ण सिनेरियो में अपनी क्षमता साबित की। निकट सीमा पर अत्यंत निम्न ऊंचाई (नीयर-बाउंड्री लो-अल्टीट्यूड) से लेकर लंबी दूरी की उच्च ऊंचाई (लॉन्ग-रेंज हाई-ऑल्टीट्यूड) तक के लक्ष्यों को सटीकता से इंटरसेप्ट किया गया। डीआरडीओ के अनुसार, सभी प्रारंभिक सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं (प्रिलिमिनरी सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स) पूरी हुईं, जिनमें उच्च गति, चपलता और जटिल हवाई खतरों के खिलाफ उत्कृष्ट सटीकता शामिल थी। यह अत्याधुनिक सिस्टम वायु रक्षा को नई ऊंचाई देगा–और वास्तव में, यह अब केवल परीक्षण नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी का सबसे भरोसेमंद प्रमाण बन चुका है।

आकाश-एनजी की असली ताकत इसकी 100% स्वदेशी तकनीक में छिपी है। इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) सीकर लगा है, जो लक्ष्य को मिलीसेकंड्स में लॉक कर देता है और उच्चतम सटीकता सुनिश्चित करता है। ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर की दो-चरणीय शक्ति इसे मैक 2.5 की गति और अद्वितीय मैन्यूवरेबिलिटी देती

खतरे में है परिवार

मनोज कुमार अग्रवाल

देश में दाम्पत्य जीवन के लिए खतरा बढ़ गया है लगातार इस तरह की वारदातों की झड़ी लगी है जिसमें छोटी मोटी बातों पर लोग पति पत्नी लिव-इन पार्टनर रिश्तेदारों सगे संबंधियों का खून बहाने से नही चूक रहे हैं समाज में परिवर्तन के इस दौर में जहां सेक्स और अर्थ को स्वछंद जीने की होड़ लगी है वहीं इंसानियत के सद्गुणों को छोड़ कर मनमानी और हिंसा की ओर जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यौन अपराध बढ़ रहा है वहीं जरा जरा सी बात पर लोग कत्ल कर रहे हैं कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिल कर सात फेरों वाले पति का कत्ल कर रही है तो कभी पति शराब के नशे में चूर हो कर अपनी अर्धांगिनी का कत्ल कर रहे हैं।

मयार्दापूर्ण जीवन बिताने का सारी दुनिया को संदेश देने वाले भारत में ही अब चंद लोग रिश्तों का सम्मान भूलते जा रहे हैं और लाइफ पार्टनर की हत्या तक कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों की घटनाएं जो अखबारों की सुर्खियां बनी उन्हें सामने रखकर समाज में बढ़ रही अमानवीयता क्रूरता हैवानियत और प्रतिशोध की भावना को समझ सकते हैं।

कभी मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम द्वारा पति की हत्या की वारदातों से हतप्रभ हुए भारतीय समाज को अब आए दिन ऐसी वारदातों से दो चार होना पड़ रहा है जिनमें अबला सबला बन कर अपने विवाहेत्तर संबंधो के लिए पति को नृशंसता के साथ रास्ते से हटा रहीं हैं।

ताजा वारदात मेरठ की मुस्कान की तर्ज पर एक और हत्यारिन विवाहिता रूबी ने अंजाम दिया है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से लोहे के हथियार और ग्राइंडर से हाथ पैर काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई. फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए हाथ-पैर और सिर कुछ बरामद कर लिया है और पत्नी व दो लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया.

मृतक राहुल की शादी 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी।

Support me by Joining my Private channel 🏡

♦️I DON'T RUN ANY PUBLIC CHANNELS, I DON'T ASK FOR MONTHLY SUBSCRIPTION, IF YOU HAVE EITHER OF THEM THAT'S NOT MY CHANNEL

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard

+All Editorial PDFs

Uploding starts from 5AM

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)

शिखरों की ऊँचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती : धर्मवीर भारती

हिन्दुओं की मॉब लिंचिंग पर चुप्पी

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर वैसी मुखरता दिखायी नहीं दे रही, जैसी अन्य मामलों में दिखायी देती है। हालिया उदाहरण गाजा का लिया जा सकता है, जहाँ दो देशों की आपसी संघर्ष में सैन्य हमलों का शिकार बने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भारत में प्रदर्शन किए गए। हालांकि, यहाँ भी चयनात्मक पाखंड देखा गया था। इस्लामिक चरमपंथियों की ओर से यहूदी महिलाओं एवं लोगों के साथ किए गए घिनौने कृत्यों पर यहाँ भी चुप्पी साध ली गई थी। बांग्लादेश के प्रकरण में केवल भाजपा और राष्ट्रीय विचार के लोग ही हिन्दुओं के हितों की चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी चयनात्मक चुप्पी को कठघरे में खड़ा किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और उस पर विपक्ष की चुप्पी को मुद्दा बनाया। उनका यह सवाल वाजिब है कि जो राजनीतिक दल गाजा की घटनाओं पर कैंडल मार्च निकालते हैं, वे पड़ोसी देशों (पाकिस्तान और बांग्लादेश) में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार पर मौन क्यों साध लेते हैं? यह 'चयनात्मक संवेदना' न केवल मानवाधिकारों के प्रति दोहरे चरित्र को उजागर करती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ दल राष्ट्रीय हितों और अपने ही मूल के लोगों की सुरक्षा के प्रश्न पर समझौता कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी छद्म सेक्युलरिज्म ने हिन्दू-मुस्लिम समस्याओं को बढ़ावा दिया है। बीते दिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी छद्म सेक्युलरिज्म की ओर संकेत कर रहे थे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से एक निर्दोष युवक दीपू की हत्या की गई है, वह जघन्य है और इस्लामिक कट्टरता के घिनौने पक्ष को सामने लाती है। दीपू की हत्या योजनापूर्वक की गई है और दुर्भाग्य की बात है कि इस नृशंस अपराध में उसके ही करीबी दोस्त शामिल रहे हैं। दीपू के मुस्लिम दोस्तों ने एक प्रकार से दोस्ती जैसे विश्वसनीय रिश्ते को भी कलंकित किया है। उन्होंने उस आरोप को साबित किया है, जिसमें कहा जाता है कि एक मुस्लिम के लिए उसका 'दीन' ही सबसे ऊपर है। जब भी दीन की बात आएगी तो वह सबकुछ कुर्बान कर देगा। बहरहाल, बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हिंसक हमलों को लेकर भारत में सबसे अधिक मुखर भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद जैसे राष्ट्रीय विचार के संगठन ही दिखायी दे रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए चुप्पी साध रखी है। उन्हें डर है कि दीपू को न्याय दिलाने की माँग करने से उनका वोटबैंक नाराज हो सकता है। हद है। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि इन राजनीतिक दलों को भारत के मुसलमानों पर विश्वास नहीं है कि वे किस ओर खड़े हैं? कहना होगा कि राजनीतिक दलों का यह व्यवहार मुस्लिम समुदाय की छवि को गहरा धक्का पहुँचाते हैं। मुसलमानों के उदारवादी वर्गों को चाहिए कि वे स्वयं आगे आकर कट्टरपंथी सोच का विरोध करें। निर्दोष दीपू एवं उसके परिवार को न्याय दिखाने के लिए हो रहे प्रदर्शनों का नेतृत्व उन्हें करना चाहिए। इसके साथ ही, भारत के तथाकथित सेकुलर वर्ग को भी अपनी चयनात्मक चुप्पी को छोड़कर एक सुर में सांप्रदायिक हिंसा की आलोचना एवं विरोध करना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर वैसी मुखरता दिखायी नहीं दे रही, जैसी अन्य मामलों में दिखायी देती है। हालिया उदाहरण गाजा का लिया जा सकता है, जहाँ दो देशों की आपसी संघर्ष में सैन्य हमलों का शिकार बने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भारत में प्रदर्शन किए गए। हालांकि, यहाँ भी चयनात्मक पाखंड देखा गया था।

नया कानून रोजगार का कानूनी अधिकार बनाए रखता है, अधिकारों को बढ़ाता है

वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 संरचनात्मक कमियों को दूर करता है

शिवराज सिंह चौहान
भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है और सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और व्यापक वितरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, ताकि ग्रामीण भारत मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके।

भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी है। यह कानून वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है और सशक्तिकरण, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और व्यापक वितरण के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करता है, ताकि ग्रामीण भारत मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके।

सुधारों की गलत व्याख्या

वीबी- जी राम जी अधिनियम लागू होते ही कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, जो गहराई से देखने पर सही नहीं ठहरतीं। कहा जा रहा है कि रोजगार गारंटी कमजोर कर दी गई है, विकेंद्रीकरण और मांग-आधारित अधिकारों को बिना परामर्श के कमज़ोर किया गया है और यह सुधार असल में राजकोषीय खर्च घटाने का तरीका है, जिसे ढांचे में बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन ये सभी दावे इस कानून के असली उद्देश्य और प्रावधानों को ठीक से न समझ पाने के कारण किए जा रहे हैं।

इस गलतफहमी का मूल कारण एक गहरी वैचारिक त्रुटि है- यह मान लेना कि कल्याण और विकास एक दूसरे के विरोधी विरोधी विकल्प हैं। नया ढांचा इसके बिल्कुल उलट सोच पर आधारित है: कल्याण, जो कि वैधानिक आजीविका गारंटी को मजबूत करने पर केंद्रित है, और विकास, जो कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित है, परस्पर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आय सहायता, संपत्ति सृजन, कृषि स्थिरता और लंबे समय की ग्रामीण उत्पादकता को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि कानूनी संरचना में ही शामिल सोच है।

केंद्रीकरण का आरोप इस कानून की पूरी संरचना को नज़रअंदाज़ करता है। ग्राम पंचायतें पहले की तरह ही योजना बनाने और लागू करने की प्रमुख संस्था बनी रहती हैं और ग्राम सभाओं के पास स्थानीय योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार यथावत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब विकेंद्रीकरण बिना व्यवस्था के या कभी-कभार होने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि एक नियमित, व्यवस्थित और सहभागी प्रणाली के रूप में होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, समन्वय और पारदर्शिता हो सके — न कि स्थानीय प्राथमिकताओं को दबाने के लिए। केंद्रित किया गया है सिर्फ व्यवस्था और सामंजस्य को, निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ही रहेगा। इस तरह यह कानून बिखराव को ठीक करता है, विकेंद्रीकरण को कमज़ोर नहीं करता।

यह आरोप भी सही नहीं है कि इस सुधार को बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया गया। इस विधेयक से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श, तकनीकी कार्यशालाएं और विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं। गांव-स्तरीय योजना संरचना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय की व्यवस्था और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम जैसे प्रमुख प्रावधान राज्यों से मिले सुझावों और वर्षों के अनुभव से सीखे गए सबक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

आवंटन में वृद्धि, समानता

यह धारणा भी तथ्यों से मेल नहीं खाती कि पिछले दशक में रोजगार गारंटी को लगातार कमजोर किया गया। बजट आवंटन 2013-14 के रु.33,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में रु.2,86,000 करोड़ हो गया। 2013-14 तक कुल 1,660 करोड़ मानव-दिवस के बदले अब तक 3,210 करोड़ मानव-दिवस का सृजन हुआ। केंद्र से जारी धनराशि रु.2.13 लाख करोड़ से बढ़कर रु.8.53 लाख करोड़ हो गई और पूरे हुए कार्य 153 लाख से बढ़कर 862 लाख तक पहुंच गए। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 56.73% हो गई। अब 99% से अधिक फंड ट्रांसफर आदेश समय पर जारी होते हैं और लगभग 99% सक्रिय श्रमिक आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़े हैं। ये सभी रुझान उपेक्षा नहीं, बल्कि निरंतर प्रतिबद्धता और बेहतर प्रदर्शन को दिखाते हैं।

लेकिन समय के साथ यह भी साफ हो गया कि पुराने ढांचे में खुद कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं-जैसे बीच-बीच में ही काम मिलना, बेरोजगारी भत्ता लागू कराने की कमजोर व्यवस्था, बिखरे हुए और असंगठित तरीके से संपत्ति/संसाधन निर्माण, और दोहराव व फर्जी प्रविष्टियों की गुंजाइश। ये कमजोरियां सूखे के समय, बड़े पैमाने पर पलायन के दौर में और कोविड-19 जैसी आपदा के दौरान जमीन पर साफ दिखाई दीं।

नए कानून के तहत की गई वित्तीय व्यवस्था को भी गलत तरीके से सरकारी जिम्मेदारी छोड़ने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सच यह है कि केंद्र सरकार का योगदान बढ़ रहा है। केंद्र का हिस्सा रु.86,000 करोड़ से बढ़कर लगभग रु.2,95,000 करोड़ तक हो रहा है, जो ग्रामीण रोजगार के प्रति मजबूत और बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। 60:40 की फंडिंग व्यवस्था वैसे ही है जैसी अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में वर्षों से लागू है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 का अलग अनुपात रखा गया है। इसलिए यह किसी तरह की वित्तीय पीछे हटने का संकेत नहीं, बल्कि साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही को और मजबूत करने का संकेत है।

यह कानून राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे पहले से ही एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की अवधि तय कर सकें, जो बुआई और कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसमों को कवर करे, और उन दिनों के दौरान काम न कराया जाए। यह घोषणा ज़िला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर, स्थानीय मौसम और कृषि परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग ढंग से की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ी हुई रोजगार गारंटी कृषि कार्यों में बाधा न बने, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर चले।

यूपीए का रिकॉर्ड

कांग्रेस नेतृत्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही मनरेगा से जुड़े वादों को अमल में लाने में विफल रही। कांग्रेस के घोषणापत्र में 'प्रतिदिन 100 रुपये की वास्तविक मजदूरी पर कम से कम 100 दिन का काम' देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने 2009 में ही मज़दूरी 100 रुपये पर सीमित कर दी और कई सालों तक महंगाई और ग्रामीण संकट की अनदेखी करते हुए इसे इसे बढ़ाया भी नहीं। केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि राज्य सरकारें इस योजना के तहत मनमाने ढंग से काम कर रही थीं और मज़दूरी न बढ़ाने का कारण भी राज्यों के 'अनियंत्रित बढ़ोतरी' को बताया। यह स्वीकारोक्ति अपने आप में शासन की एक गंभीर विफलता दिखाती है: कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी ही राज्य सरकारों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी, जिसके कारण मनरेगा में दुरुपयोग, फर्जी जॉब कार्ड और वित्तीय गड़बड़ियां जैसी समस्याएं पैदा हो गईं।

यूपीए के दूसरे कार्यकाल में इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता लगातार कमजोर होती गई। 2010-11 में रु.2,40,100 करोड़ के बजट को घटाकर 2012-13 तक सिर्फ रु.33,000 करोड़ कर दिया गया, जबकि राज्यों की ओर से मांग बढ़ रही थी। 2013 में संसद में दिए गए जवाब में तत्कालीन राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने माना कि मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों की संख्या 2010-11 के 7.55 करोड़ से घटकर नवंबर 2013 तक सिर्फ 6.93 करोड़ रह गई। महालेखा परीक्षक (कैग) की 2013 की रिपोर्ट ने यूपीए के समय मनरेगा की असल स्थिति उजागर कर दी। रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन सामने आया- 4.33 लाख से ज्यादा फर्जी या गलत जॉब कार्ड, हजारों करोड़ रुपये बिना हिसाब के निकासी और अनियमित कामों में गंवाए गए, 23 राज्यों में मजदूरी का भुगतान देर से हुआ या रोका गया, और देश की आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सही रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब हैं-बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वे अपने आवंटित धन का केवल लगभग 20% ही खर्च कर पाए। यानी योजना वहीं नाकाम रही, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

कल्याण और विकास के बीच चयन के रूप में बहस को प्रस्तुत करना गलत है। जब कल्याण मजबूत रोजगार गारंटी पर आधारित हो और विकास टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे और उत्पादकता पर आधारित हो, तो ये एक-दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक-दूसरे पर निर्भर हैं। असली निर्णय यह था कि क्या उस ढांचे को स्थिर रखा जाए जो अक्सर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था, या इसे एक आधुनिक, लागू करने योग्य और एकीकृत रोजगार गारंटी प्रणाली में सुधारा जाए जो विकास के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा दे। नया कानून रोजगार का कानूनी अधिकार बनाए रखता है, अधिकारों को बढ़ाता है, श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करता है और वर्षों के कार्यान्वयन में सामने आई संरचनात्मक कमजोरियों को ठीक करता है। यह विनाश नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित नवीनीकरण की प्रक्रिया है।

यह लेखक के निजी विचार है

सवा लाख से एक लड़ाऊं, चमकौर को याद करने के दिन

विजय मनोहर तिवारी
कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल

अंग्रेजी कैलेंडर में दिसंबर का महीना भारत के संघर्षपूर्ण इतिहास की चमकदार यादों का महीना है। खासकर आखिरी के ये दिन। ये दिल्ली पर मुगलों के कब्जे के समय की बात है, जब गुरु गोविंद सिंह उनकी नींव हिलाने में लगे थे। यही दिन थे, जब गुरू गोविंद सिंह अपने जीवन की सबसे विकट लड़ाई में उतरे। औरंगजेब उन्हें जिंदा या मुर्दा कैसे भी देखना चाहता था।

22 दिसंबर, एक ऐसे दुखद प्रसंग का दिन, जिसने भारत को भारत होने के अर्थ दिए हैं। जिसने अपने समय के अनर्थ को चुनौती दी। अपने और अपने पूरे परिवार को इस देश के धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान करने वाले महान सिख गुरू गोविंदसिंह के जीवन में आए सबसे विकट समय का एक दिन, जब उनके बेटे उनकी आंखों के सामने उनकी ही इजाजत से एक युद्ध के लिए जाते हैं। चारों तरफ से घेरे हुए मुगलों के भूखे भेड़ियों के आगे वे झुके नहीं। लड़े। जल्दी ही वे दीए बुझा दिए गए। यह 315 साल पहले की बात है मगर हमारी स्मृतियों में बहुत है नहीं। आजादी के बाद इस संघर्ष के पाठ हरेक भारतीय को स्कूल की शुरुआती कक्षाओं में ही पता होने थे, लेकिन वह सिर्फ सिखों का इतिहास होकर सिमट गया।

दिसंबर के उस पूरे घटनाक्रम को हर भारतीय को याद होना जरूरी है : वह 1704 का साल था। दिसंबर के उस पूरे घटनाक्रम को हर भारतीय को याद होना जरूरी है। वह महान योद्धा गुरुओं की ही आपबीती नहीं है। वह सिखों का भी इतिहास नहीं है। वह पंजाब की कहानी भी नहीं है। वह भारत का इतिहास है। हर भारतीय को पता होना चाहिए था। लेकिन उन्हें मारने वाले मुगल भारत का इतिहास बना दिए गए। उन्हें ग्रेट मुगल और महाबली अकबर, जाने क्या-क्या कहा गया। हम उन्हें ही सुनते-पढ़ते बड़े हो गए।

गुरू गोविंद सिंह ने आनंदपुर में 1699 में खालसा की स्थापना कर औरंगजेब के सामने यह जाहिर कर दिया था कि हुकूमत के नाम पर कायम इस्लामी आतंक के सामने झुकने वाली कौम हम नहीं हैं। 1701 से दोनों के बीच खुली जंग का दौर शुरू हो गया, जो 1704 तक चला है। भारत के इतिहास की यह विडंबना ही रही है कि हम अपनों से ही हारे हैं। हर तरह के लालची धोखेबाज हर सदी में हर जगह रहे हैं, जिन्होंने अपनी संकीर्ण दृष्टि में सिर्फ अपने ही हित देखे। उनके पास दूर तक देखने की सामर्थ्य नहीं थी। वे देश को भी दाव पर लगा सकते थे। धर्म परिवर्तन तो वे कर ही रहे थे। वह हर हाल में अपनी जिंदगी और अपने हित ही चाहते थे। गुरूजी खालसा की स्थापना के बाद हासिल अपार लोकप्रियता और ताकत के कारण सबसे पहले आसपास के पहाड़ी हिंदू राजाओं की आंखों में खटके। वे मूर्ख राजे उनसे लड़े। हार गए तो औरंगजेब में उन्हें अपना तारणहार नजर आया।

गुरुजी आनंदपुर में थे : गुरूजी आनंदपुर में थे। इन धोखेबाज पहाड़ी राजाओं और मुगलों के लुटेरे हमलावरों ने उन्हें करीब छह महीने से चारों तरफ से घेर रखा था। जो उन्मादी भीड़ आज कई शहरों में भारत को मॉब-लिंचिंग का शिकार बनाने पर आमादा है, वैसी ही उन्मादी भीड़ वह थी। सत्ता के सब तरह के लालचियों का एक ताकतवर झुंड सत्य के दीए को बुझाने के लिए तब भी तत्पर था। 38 वर्षीय गुरू गोविंदजी से आनंदपुर के किले से सुरक्षित जाने का एक वादा किया जाता है। मुगल कुरान की कसमें खाते हैं। पहाड़ी राजे पवित्र गाय की सौगंध कि गुरुजी को सुरक्षित जाने दिया जाएगा, बशर्ते किला हमारे हवाले कर दिया जाए। खालसा के योद्धा सिख गुरूजी को बाहर लाते हैं। लेकिन जिनके रक्त में ही फरेब और धोखा बहता हो, उनसे किसी किस्म की समझदारी, संवेदनशीलता और वचनबद्धता की उम्मीद बेकार तब भी थी, अब भी है।

अचानक हमले की उस भगदड़ में गुरुजी का परिवार बिछड़ जाता है : मुगल चारों तरफ से गुरूजी के समूह पर टूट पड़े। वे किसी भी कीमत पर गुरूजी को जिंदा या मुर्दा चाहते थे। अचानक हमले की उस भगदड़ में गुरूजी का परिवार बिछड़ जाता है। दो बेटे उनके साथ रह जाते हैं-अजीत सिंह और जुझार सिंह। दो छोटे बेटे अपनी दादी माता गूजरी के साथ किसी और रास्ते पर निकल जाते हैं-फतेह सिंह और जोरावर सिंह। चारों तरफ से हजारों की पागल भीड़ भूखे भेड़ियों की तरह उनके शिकार की घात में है। कोई नहीं जानता कि अगले पल कौन बचेगा, कौन मरेगा। सरसा नदी खतरों से भरे इस संघर्ष में महान सिखों की वीरता की गवाह है। शाम होते ही अंधेरा छा गया था। अपने दो बेटों और 40 सिखों के साथ वे चमकौर की तरफ रवाना होते हैं। वे कुल 43 थे। उनसे हजार गुना बड़ी और ताकतवर धर्मांध भीड़ चप्पे-चप्पे में उन्हें ढूंढ रही थी।

चमकौर कोई बहुत महत्वपूर्ण किलेबंदी वाला ठिकाना नहीं था। उसका जिक्र ऊंचे टीले पर बनी एक छोटी सी गढ़ी के रूप में है। बुधिचंद नाम का एक व्यक्ति इतिहास में इस नाते दर्ज हुआ कि उस जानलेवा हालात में उसने गुरूजी को अपनी हवेली में शरण दी। अब वे चमकौर की गढ़ी में थे, जहां का पता लगते ही मुगल भेड़िए और धोखेबाज हिंदू लकड़बग्गों ने चीख-पुकार मचाते हुए उन्हें वहां भी आ घेरा।

दिसंबर के तीन महत्वपूर्ण दिन : यह 21, 22, 23 दिसंबर के तीन महत्वपूर्ण दिन हैं। मैं इसे भारत की आजादी के लंबे धारावाहिक की ही एक अहम और चमकदार कड़ी मानता हूं। सुहेल देव ने गजनवी के भांजे सालार मसूद को बहराइच में मार गिराया तो वह भी इस देश को बचाने की एक महान कोशिश थी। राणा प्रताप अगर आजाद भारत में 'ग्रेट मुगल' कहकर नवाजे गए महाबली अकबर को चुनौती देते हैं तो वह भी विदेशी हुकूमत के खिलाफ मेवाड़ की एक बुलंद आवाज है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से हुंकार भरते हैं तो वह बहुत स्पष्ट रूप से स्वराज्य की घोषणा है।

आजादी की लड़ाई कोई 1857 के किसी शुभ मुहूर्त में आरंभ हुई हो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिना खड्ग बिना ढाल के उसे किसी शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचा दिया हो, इस खाम-ख्याली में किसी भारतीय को रहना नहीं चाहिए। वह एक अंतहीन संघर्ष था। सशस्त्र संघर्ष। औरंगजेब के समय चमकौर में गुरू गोविंदसिंह उस विकट संघर्ष के महानायक थे।

एक-एक सिख को सवा-सवा लाख से लड़ाने का महाघोष वे ही कर सकते थे : वे अपने दो बेटों और 40 सिखों के साथ इस गढ़ी के चारों तरफ मंडरा रही मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे। सरहिंद का नवाब वजीर खान मुगलों के इस गिरोह का सरगना था, जिसके पास 10 लाख लुटेरे हमलावरों की फौज थी। यह एक ऐसी मॉब-लिचिंग थी, जिसका परिणाम गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जानता था। एक-एक सिख को सवा-सवा लाख से लड़ाने का महाघोष वे ही कर सकते थे। 18 साल के अजित सिंह और 14 साल के जुझार सिंह में भी उनका ही लहू बह रहा था। वे उनके आसपास थे।

नारा बुलंद होता है- बोले सो निहाल, सतश्री अकाल : गुरूजी ने 5-5 सिखों को सबसे पहले मुगलों की भगदड़ में लड़ने भेजा। वे चमकौर की गढ़ी से मुकाबला देख रहे हैं। मुगलों के बीच मारकाट मचाते हुए वे पांचों महावीर धराशायी होते हैं। फिर एक और समूह अपने हिस्से की बहादुरी दिखाकर इस्लामी फौज को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हुए अपनी उम्र पूरी करता है। अब अजित सिंह जंग में जाने की इजाजत मांगते हैं। नारा बुलंद होता है-बोले सो निहाल, सतश्री अकाल। चार सिखों के साथ यह महान युवा योद्धा मौत के मुंह की ओर प्रस्थान करता है। एक दीया आंखों के सामने बुझ जाता है। अब अजित से चार साल छोटे जुझार सिंह आगे आते हैं। चमकौर के मैदान में औरंगजेब की विक्षिप्त इस्लामी फौज से टकराते हैं। कड़े मुकाबले में इतिहास देखता है कि उनका सिर भी झुकता नहीं है। उनकी तलवार हवाओं में बिजली सी कौंधती है। दूसरा दीया भी बुझ गया। देश के लिए खून का वह आखिरी कतरा किसी भाषण में नहीं बहा, चमकौर के मैदान में गिरा।

लेकिन वे इस वक्त कहां थे?

कड़ाके की सर्दी का वह दिन अस्त हो गया। वह 22 दिसंबर का ही दिन था। गुरु गोविंद सिंह को उस शाम शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी मां माता गूजरी और उनके दो मासूम बेटे इस वक्त कहां हैं, किस हाल में हैं, जीवित भी हैं या नहीं। फतेह सिंह उम्र 8 साल और जोरावर सिंह उम्र 7 साल। लेकिन वे इस वक्त कहां थे?

सरहिंद से निकलते समय हुए मुगलों के हमले की भगदड़ में वे गंगू नाम के एक सेवक के साथ सुरक्षित निकल गए थे। एक धोखेबाज हिंदू यहां भी निकला। खुद गंगू, जिसने अपने तात्कालिक फायदे के लालच में सरहिंद के नवाब वजीर खान को उन्हें सौंप दिया। औरंगजेब के इस टुकड़खोर गवर्नर के सामने वे दोनों बेटे लाए जाते हैं। इस्लामी कानून (वल्लाह, क्या कानून है!) के मुताबिक उन्हें जिंदा रहने के लिए इस्लाम कुबूल करने को कहा जाता है।

गुरूजी के दोनों बेटे सीना तानकर ऐसा मजहब कुबूल करने से साफ इंकार कर देते हैं, जो जिंदा रहने की सजा के तौर पर उन्हें जिंदगी भर ढोना होगा और फिर उनकी अंधी औलादें इस अंधेरे को फैलाएंगी। वे साफ इंकार कर देते हैं। यह मजहबी सजा उन्हें कबूल नहीं थी। इस्लामी कानून इन मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा सुनाता है। वे देखते ही देखते जिंदा दफन कर दिए जाते हैं। माता गूजरी को एक बुर्ज से नीचे फैंककर मार दिया गया। घृणा किसके रक्त में बहती दिख रही है? बेरहमी किसकी वैचारिक विरासत है? सेक्युलर सिस्टम में ऐसे असुविधाजनक सवालों को करना गुनाह है। आप सांप्रदायिक घोषित हो सकते हैं। इसलिए चुप रहिए। झुककर रहिए।

गुरु गोविंद सिंह के बेटे झुकते नहीं हैं : गुरु गोविंद सिंह के बेटे झुकते नहीं हैं। अपना सम्मान गिरवी नहीं रखते। उनकी नजर में जो छल-बल से गले उतारा जाए वो धर्म दो कौड़ी का था। और जिन्होंने ताकत या लालच में आकर अपना धर्म बदल लिया, इतिहास ने उनकी औलादों को बाद में एक उन्मादी भीड़ में बदलते देखा। उसी भीड़ ने सन 47 में इस धरती के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उसी भीड़ ने कश्मीर को लहूलुहान कर डाला। मुंबई से लेकर जयपुर तक, अक्षरधाम से लेकर संकटमोचन हनुमान तक धमाके करती रही। वह बात-बात पर भारत के माथे पर पत्थर बरसाती रही।

खण्डित भारत के लालची हुक्मरानों ने : खण्डित भारत के लालची हुक्मरानों ने अपने देश को एक मजार बना लिया और जालीदार टोपी लगाकर सेक्युलरिज्म की हरी चादर चढ़ाकर चैन से हुकूमत में लग गए। इस चादर को ओढ़े हुए हम 70 साल से पढ़ते रहे कि मुगल महान थे। अकबर दयावान थे। औरंगजेब ने मंदिरों के लिए सनदें लिखी थीं। सूफी परंपरा की खुशबू क्या कमाल है। 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' के रचयिता ने ऐसा इंडिया डिस्कवर किया!

नेहरू की इस महान डिस्कवरी में हम चमकौर के बारे में कितना जानते हैं? क्या वह सिर्फ पंजाब का इतिहास है? क्या वह सिख की आंख से गिरा आंसू है, जिसका हमसे कोई लेना-देना नहीं? क्या वे गुरू पंजाब की सत्ता पर कब्जा करने के लिए खड़े हुए थे? पंडितजी से कौन कहां जाकर पूछे कि गंगा-जमनी रवायत का एक कतरा चमकौर की खूनी भगदड़ में कहां नजर आ रहा है?

चमकौर की रोशनी में इन बंद दिमाग लोगों को : सरहदें खिंचने के बाद भी औरंगजेब की वह जहरीली विरासत जेहन में फैली हुई है। मगर वे तो मुगल नहीं हैं। वे बादशाह और नवाब भी नहीं हैं। वे संख्या के पशु बल में बदल दी गई एक ऐसी उन्मादी भीड़ हैं, जिन्हें तलवार के जोर पर मजहब बदलने वाले अपने बेइज्जत पुरखों का चेहरा याद नहीं है। चमकौर की रोशनी में इन बंद दिमाग लोगों को अपना आहत अतीत महसूस करना चाहिए।

यह महीना और ये दिन उन अनगिनत वीर योद्धाओं के पवित्र स्मरण का अवसर हैं, जिसने गुरू गोविंद सिंह, उनके पिता गुरू तेग बहादुर सिंह और उनके चार मासूम बेटों की अमिट स्मृतियों से भारत को जगमगाया है। और वो कौन लोग हैं, जो भारत को अंधेरे से भर देना चाहते हैं? सर्वस्वदानी गुरू गोविंदसिंह उसी तरह के अंधे और अंधेरे युग में प्रज्वलित एक मशाल हैं। यह इस देश के धर्म पर महान सिखों का कर्ज है, जो कभी नहीं उतर सकता। हर भारतीय के मन में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है, जितनी अपने देव और महादेव पर।

विकसित भारत का कृषि मॉडल: गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन

राजेन्द्र शुक्ल
मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास के उस मार्ग पर अग्रसर है, जहां आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। इसी समग्र दृष्टि के अंतर्गत भारतीय कृषि को भी एक नए युग की ओर ले जाया जा रहा है। कृषि सदियों से हमारी सभ्यता की रीढ़ रही है। आधुनिक युग में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता ने खेती की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता, उसकी जलधारण क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, हमारे भोजन की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भारतीय कृषि की मूल आत्मा से जुड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और आत्म निर्भरता के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सह-अस्तित्व और संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें गौमाता की भूमिका केंद्रीय रही है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा का आधार रही हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि गौवंश का संरक्षण सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गोबर और गोमूत्र से भूमि को पोषण मिलता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और मिट्टी पुनः जीवंत होती है। स्वस्थ मिट्टी से प्राप्त अन्न अधिक पौष्टिक, सुरक्षित और मानव शरीर के अनुकूल होता है।

प्राकृतिक खेती कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति

प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि में प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की भारतीय पद्धति है। वे इसे किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और उन्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करने का सशक्त माध्यम मानते हैं। साथ ही, यह देशवासियों को रसायन-मुक्त, विषरहित भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग है। यही कारण है कि प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा गया है।

प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली सरल, स्वदेशी और प्रभावशाली है। इसमें गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि कृषि आदानों के उत्पादन के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे प्राकृतिक इनपुट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और भूमि की उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाते हैं। पलवार (मल्चिंग) जैसी तकनीकें मिट्टी की नमी बनाए रखती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों की रक्षा करती हैं। इन उपायों से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे शून्य बजट प्राकृतिक खेती का लक्ष्य व्यवहारिक रूप से संभव होता है।

सहकारिता से समृद्धि और संस्थागत शक्ति

प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विजन 'सहकारिता से समृद्धि' के तहत, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को संगठित किया जा रहा है एवं किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को न केवल सस्ती दरों पर प्राकृतिक खाद-बीज मिल सकें, बल्कि उनके विषमुक्त उत्पादों को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और सहकारिता का मेल ही ग्रामीण समृद्धि का नया मार्ग है।

प्राकृतिक खेती का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं है; इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य और जीवनशैली से है।

भारत की पारंपरिक चिकित्सा की रोशनी में विश्व-स्वास्थ्य

ललित गर्ग

आज जब वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 4.6 अरब लोग, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, तब भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ आशा की किरण बन सकती हैं। ये प्रणालियाँ न केवल रोगों के उपचार में सहायक हैं, बल्कि रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संतुलित आहार, नियमित योगाभ्यास, प्राकृतिक औषधियों और मानसिक अनुशासन के माध्यम से अनेक बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकता है।

आज की दुनिया गहन और बहुआयामी स्वास्थ्य संकटों से गुजर रही है। एक ओर जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ, मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और असंतुलन तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर संक्रामक रोग, महामारी और पर्यावरणीय विषमताएँ मानव जीवन को निरंतर चुनौती दे रही हैं। इन परिस्थितियों के बीच यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा के सहारे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का संपूर्ण समाधान संभव नहीं है। यही कारण है कि विश्व समुदाय का ध्यान पुनः भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की ओर आकर्षित हो रहा है, जिनमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पद्धतियाँ शामिल हैं। जिन्हें ह्यआयुषह्ण के नाम से जाना जाता है; ये प्रणालियाँ समग्र स्वास्थ्य, प्राकृतिक उपचार और शरीर-मन संतुलन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिनमें आयुर्वेद सबसे प्राचीन और सुव्यवस्थित प्रणालियों में से एक है, जो अपने दार्शनिक आधार और विविध उपचार विधियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चिकित्सा प्रणालियों का आधार केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है।

आयुर्वेद शरीर के तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) के संतुलन पर केंद्रित; आहार, जीवनशैली, जड़ी-बूटी और पंचकर्म (शुद्धिकरण) जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। अष्टांग आयुर्वेद अर्थात कायचिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा), शल्य (सर्जरी), कौमारभृत्य (बाल चिकित्सा), भूतविद्या (मनोविज्ञान), अगद तंत्र (विष विज्ञान), रसायन (जराचिकित्सा), वाजीकरण (प्रजनन) और शालक्य (नेत्र/कान/नाक) में विभाजित है। आयुर्वेद की ही भांति योग भी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो शारीरिक आसन (आसन), प्राणायाम (सांस लेने के व्यायाम), ध्यान (मेडिटेशन) और नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से मन-शरीर के समन्वय पर केंद्रित है। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी, पानी, धूप और आहार जैसी प्राकृतिक तरीकों से शरीर की स्व-उपचार क्षमता को बढ़ावा देती है। यूनानी चिकित्सा प्रणाली भी भारत में प्रचलित है, यूनान से आई यह प्रणाली शरीर के चार हमर (रक्त, बलगम, पीला पित्त, काला पित्त) के संतुलन पर जोर देती है और पर्यावरण के प्रभाव को मानती है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित है, जिसमें जड़ी-बूटियों और धातुओं से बनी दवाओं का उपयोग और योग व ध्यान पर जोर दिया जाता है। सोवा-रिग्पा पहाड़ों की चिकित्सा प्रणाली है, हिमालयी क्षेत्रों (जैसे लद्दाख, सिक्किम) में प्रचलित है, जिसे ह्यतिब्बती चिकित्साह्ण के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से इन प्रणालियों के विकास, अनुसंधान और मुख्यधारा की

स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण को बढ़ावा देता है। ये प्रणालियाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आधारित हैं और अब वैश्विक स्वास्थ्य मंच पर भी अपनी पहचान बना रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इन पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने इसे केवल सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की एक प्रभावी, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरूआत, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ पारंपरिक चिकित्सा को लेकर साझेदारी और वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन इस दिशा में ठोस कदम हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि भारत अब इस क्षेत्र में केवल सहभागी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में हुई वृद्धि इस परिवर्तनशील परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। 61.1 मिलियन डॉलर से बढ़कर 65.1 मिलियन डॉलर तक पहुँचना केवल आर्थिक आँकड़ा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक विश्वास का संकेत है। दुनिया के अनेक देश यह समझने लगे हैं कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ न केवल सस्ती और सुलभ हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती हैं। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी आर्थिक कारणों से बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में पारंपरिक चिकित्सा एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में उभरती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज भी दुनिया के लगभग 170 देशों में 40 से 90 प्रतिशत आबादी किसी-न-किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। यह आँकड़ा इस धारणा को तोड़ता है कि पारंपरिक चिकित्सा केवल विकासशील देशों तक सीमित है। वास्तव में विकसित देशों में भी योग, आयुर्वेदिक उपचार, हर्बल औषधियाँ और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण आधुनिक चिकित्सा से जुड़े दुष्प्रभाव, अत्यधिक दवाओं पर निर्भरता और महँगी उपचार प्रक्रियाएँ हैं। एलोपैथिक चिकित्सा ने जहाँ त्वरित राहत और शल्य चिकित्सा में अद्भुत प्रगति की है, वहीं इसके साथ दवाओं के साइड इफेक्ट, एंटीबायोटिक प्रतिरोध और दीर्घकालिक जटिलताएँ भी जुड़ी हैं। इसके विपरीत भारतीय पारंपरिक चिकित्सा रोग की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करती है। आयुर्वेद शरीर की प्रकृति, दोषों के संतुलन और जीवनशैली के सुधार पर बल देता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। इन पद्धतियों का उद्देश्य रोग को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक उपचार क्षमता को जाग्रत करना है। यही कारण है कि इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित, कम दुष्प्रभाव वाली और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।

पारंपरिक चिकित्सा के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत ने इस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से दुनिया के सामने रखा। ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, मेक्सिको, नेपाल, श्रीलंका सहित 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा अब कूटनीति और वैश्विक सहयोग का भी एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया ह्यआयुष मार्कह्ण एक ऐतिहासिक पहल है, जो आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता का वैश्विक मानक स्थापित करेगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता भी मजबूत होगी। हालाँकि यह भी सत्य है कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, वैज्ञानिक शोध और प्रमाणिकता के प्रश्न लंबे समय से उठते रहे हैं। कई बार अप्रमाणित दावे और मिलावटी उत्पाद इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं। किंतु ह्यआयुष मार्कह्ण जैसी पहलों और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बनाया जाए, ताकि दोनों की श्रेष्ठताओं का समन्वय हो सके।

आज जब वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 4.6 अरब लोग, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, तब भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ आशा की किरण बन सकती हैं। ये प्रणालियाँ न केवल रोगों के उपचार में सहायक हैं, बल्कि रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संतुलित आहार, नियमित योगाभ्यास, प्राकृतिक औषधियों और मानसिक अनुशासन के माध्यम से अनेक बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण दूरदर्शी कहा जा सकता है। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा को अतीत की विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखा है। वैश्विक मंचों पर भारत की इस चिकित्सा परंपरा को स्थापित करने के उनके प्रयास यह संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था में भारत की भूमिका और भी सशक्त होगी। जब आधुनिक चिकित्सा की सीमाएँ स्पष्ट हो रही हैं और विश्व एक समग्र, सुलभ और मानवीय स्वास्थ्य मॉडल की तलाश में है, तब भारतीय पारंपरिक चिकित्सा न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रही है। यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है।

संपादकीय

बाजार के विस्तार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई

जीएसटी कटौती से एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी नवंबर में गायब हो गई। बाजार का दीर्घकालिक रुझान भी जारी रहा है। एसयूवी की बिक्री खूब बढ़ी है, मगर छोटी कारों के मामले में मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज हुई।

धूम-धड़ाके से बचत उत्सव मनाने के बाद अब बारी उसकी कीमत चुकाने की है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस को लाल किले से जीएसटी ढांचे में बदलाव का एलान किया था। नवरात्रि के साथ नई दरें लागू हुईं, तो यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि भारतीय बाजार में मांग एवं उपभोग की कमी से उपजी तमाम आर्थिक समस्याओं का अब हल निकल आएगा। यह समाधान कितना हुआ, यह अपने-आप में महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मगर एक सवाल राजकोष पर इसके असर का भी है, जिसकी ओर तब अनेक हलकों से ध्यान दिलाया गया था। अब मुद्दा सामने है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा है कि कल्याण योजनाओं पर अधिक खर्च के कारण पहले से ही राजकोषीय दबाव में चल रही राज्य सरकार को जीएसटी दरों में कटौती से सालाना 15 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार उत्पाद शुल्कों में बदलाव पर विचार कर रही है। यानी जीएसटी में मिली राहत को उत्पाद शुल्क में वृद्धि से वापस लिया जाएगा। या फिर पहले से ही 9.32 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बोझ तले दबी राज्य सरकार नए ऋण लेगी। कर्ज का गणित यह है कि उसका ब्याज चुकाना होता है और वह भी करदाताओं की जेब से ही आता है। कर्जदाता मोटी जेब वाली कंपनियां और लोग होते हैं, जबकि ज्यादा बोझ फटी जेब वालों पर पड़ता है।

अब अगर जीएसटी कटौती से हुए फायदों पर ध्यान दें, तो कुछ ताजा आंकड़े इसकी कहानी बता देते हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियों की बिक्री दर में अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी नवंबर में गायब हो गई। और अक्टूबर की कथा भी यह थी कि बिक्री में बढ़ोतरी बाजार के दीर्घकालिक रुझान के अनुरूप ही रही। मसलन, अक्टूबर- नवंबर के साझा आंकड़ों के मुताबिक कार बाजार में एसयूवी की बिक्री 17 फीसदी बढ़ी, लेकिन छोटी कारों के मामले में यह तीन प्रतिशत ही रही। यानी बाजार के विस्तार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। लाभ धनी लोगों तक सीमित रहा, जबकि अब कीमत चुकाने का ज्यादा बोझ आम लोग उठाएंगे!

चिंतन-मनन

मुक्ति की तलाश

जापान में नानहेन नामक एक परम ज्ञानी फकीर थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। इसके लिए मैंने अपने घर-परिवार, रिश्ते-नाते सब को तिलांजलि दे दी है। फकीर ने पूछा, क्या तुम बिल्कुल अकेले हो? तुम्हारे साथ वास्तव में कोई नहीं है। व्यक्ति बोला, आप मेरे आगे-पीछे देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। फकीर बोले, अपनी आंखें बंद करो। अंदर झांककर देखो कि वहां कोई और तो नहीं है? जाओ, कुछ देर के लिए वटवृक्ष की छाया में बैठकर सोचो। थोड़ी देर बाद आना।

वह व्यक्ति वटवृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान करने लगा। जब उसने आंखें बंद कीं तो उसे अपने वृद्ध माता-पिता, पत्नी और बच्चों की छवि नजर आने लगी। वह चिंतित हो गया। घबराकर उसने अपनी आंखें खोलीं तो फकीर को अपने पास खड़ा पाया। व्यक्ति ने कहा, मैं तो अपना परिवार, नाते-रिश्ते सब पीछे छोड़ आया था, लेकिन यहां पर आंखें बंद करते ही उनकी छवि सामने घूम रही है। इस पर फकीर बोले, ध्यानमग्न होकर उन व्यक्तियों को अपने दिमाग से निकालने का प्रयत्न करो। कुछ देर बाद मेरे पास आना। दो घंटे बाद युवक ने फकीर का दरवाजा खटखटाया तो फकीर बोले, कौन है? युवक बोला, मैं हूं। फकीर ने कहा, अभी भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा मैं तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस मैं और भीड़ को छोड़ सको तो फिर यहां आने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तुम मैं से मुक्ति पा लो तो फिर संन्यास लेने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। व्यक्ति ने फकीर की बात समझ ली।

वीर बालकों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि है 'वीर बाल दिवस'

योगेश कुमार गोयल

26 दिसम्बर को गुरु गोबिंद सिंह जी के चार छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में 'वीर बाल दिवस' मनाया जाता है। इन वीर बालकों ने छोटी उम्र में ही अपने धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वीर बाल दिवस वही दिन है, जब साहिबजादों 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 6 वर्षीय फतेह सिंह को मुगलों द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबजादों ने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपना बलिदान कर अपनी वीरता और अपने आदर्शों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं।

गुरु गोबिंद सिंह और उनका पूरा परिवार सिख धर्म का प्रतीक था, जिनका एक ही प्रण था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे और मुगलों के खिलाफ एकता से लड़ेंगे। इसीलिए मुगलों द्वारा उनके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक कष्ट दिए गए। उनके दो बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह को उनके सामने ही मार डाला गया और दो छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म छोड़कर मुगल बनना कभी स्वीकार नहीं किया।

मुगल सेना द्वारा अचानक आक्रमण किए जाने पर गुरु गोबिंद सिंह को पूरे परिवार के साथ 20 दिसम्बर 1704 को कड़कड़ाती ठंड में आनंदपुर साहिब किला छोड़ना पड़ा था। किले को छोड़कर जब वे सरसा नदी को पार कर रहे थे तो नदी में पानी के तेज बहाव के कारण उनके परिवार के सदस्य एक-दूसरे से बिछुड़ गए। उनके दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह उनके साथ चमकौर पहुंच गए जबकि माता गुजरी तथा दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए, जिनके साथ गुरु गोबिंद सिंह का निजी सेवक गंगू था। गंगू माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को उनके परिवार से मिलाने का भरोसा देकर अपने गांव सहेड़ी ले गया और चंद सोने की मोहरों के लालच में इसकी खबर सरहिंद के नवाब वजीर खान को कर दी, जिसके बाद माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया।

साहिबजादों को वजीर खान के समक्ष पेश किया गया तो उसने उन्हें सिर झुकाकर खड़ा होने और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा लेकिन इतने छोटे होकर भी दोनों ने सिर झुकाने और इस्लाम धर्म अपनाने से इन्कार करते हुए कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के समक्ष सिर नहीं झुकाते। वजीर खां ने दोनों बच्चों को काफी ललचाया, डराया, धमकाया लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिरकार क्रूर वजीर खान ने दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दे डाला। जब उन्हें दीवार में चुना जाने लगा तो दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे। 26 दिसम्बर 1705 को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और इस प्रकार दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म की खातिर हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोनों इतने वीर थे कि दीवार पूरी बन जाने के बाद भी अंदर से इनके जयकारा लगाने की आवाजें आती रही।

कहा जाता है कि माता गुजरी को भी सरहिंद के किले से धक्का देकर मार डाला गया था। गुरु गोबिंद सिंह को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी माता और छोटे साहिबजादों की शहादत से दुखी होने और मुगलों के अत्याचारों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय औरंगजेब को एक जफरनामा (विजय पत्र) लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को स्पष्ट चेतावनी दी कि तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े

बेटे थे अजीत सिंह, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में केवल 17 साल की आयु में ही मुगल फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। तीर खत्म होने पर उन्होंने तलवार निकालकर दुश्मनों से युद्ध किया लेकिन युद्ध के दौरान तलवार टूट जाने पर वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद गुरु जी के दूसरे बेटे जुझार सिंह ने रणभूमि में मोर्चा संभाला और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। खेलने-कूदने की छोटी सी उम्र में गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान आज की युवा पीढ़ी को अपने देश और धर्म से प्रेम करने और इनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहने का संदेश देता है।

हिजाब विवाद : क्रिया से खतरनाक प्रतिक्रिया

निर्मल रानी

देश में पिछले दिनों उस समय हिजाब को लेकर फिर एक बहस छिड़ गयी जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में नव नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन जोकि चेहरा ढंकने वाला हिजाब पहने हुई थीं, का हिजाब सार्वजनिक मंच से उसके चेहरे से खींच कर उतारने की कोशिश की। उस समय डॉक्टर नुसरत परवीन स्टेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु आमंत्रित की गयी थी। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। इस घटना से संबंधित वायरल वीडीओ में देखा जा सकता है कि घटना के समय जहाँ डॉक्टर नुसरत असहज दिखीं वहीं उसी मंच पर मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी न केवल घटना से हतप्रभ नजर आये बल्कि उन्होंने नीतीश की ओर हाथ बढ़ाते हुये उन्हें हिजाब खींचने से रोकने की कोशिश भी की। जबकि उसी मंच पर मौजूद कुछ लोग हंसते हुये भी दिखायी दिये। इस घटना से एक बात तो साबित हो ही गयी कि नितीश कुमार जैसे अनुभवी राजनेता लगभग 75 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसी वजह से वे पहले भी महिलाओं को लेकर की गयी एक अत्यंत अभद्र टिप्पणी के लिये आलोचना का पात्र बन चुके हैं। कभी सार्वजनिक मंचों पर उनकी बेतुकी बातें व उनकी असामान्य हरकतें भी यही संकेत देती कि अब वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सार्वजनिक सक्रिय राजनैतिक जीवन से सन्यास ले लेना चाहिये।

परन्तु इस घटना के बाद जिस तरह से इसे परिभाषित करने की कोशिश की गयी वह और भी हैरान करने वाली बात थी। हिजाब खींचने की बहस को नितीश कुमार की मनोदशा से जोड़कर देखने के बजाये हिजाब धारण करने न करने को लेकर ही बहस छिड़ गयी। इस्लाम व मुस्लिम विरोध की राजनीति पर अपनी दुकानें चलाने वाले कुछ नेता तो बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुये नितीश कुमार के बचाव में उतर आये। कांग्रेस,आर जे डी व अन्य कई विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और मुस्लिम समुदाय का अपमान बताया। किसी ने नितीश से मुआफी की मांग की तो किसी ने इस्तीफा माँगा। जबकि कुछ ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। परन्तु इस विषय पर सबसे घटिया,ओछी अपमानजनक प्रतिक्रिया देने वाले दो नेता ऐसे भी हैं जो केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठकर इस मुद्दे पर जहर उगल रहे हैं तथा अपनी अशिष्ट शब्दावली से देश की संवैधानिक मयार्दाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। इनमें नितीश कुमार के हिजाब विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया संसद भवन में देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का खुलकर बचाव करते हुये कहा कि नितीश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नियुक्ति पत्र लेने आए व्यक्ति को चेहरा दिखाना चाहिए। क्या भारत कोई इस्लामिक देश है? एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय चेहरा दिखाना पड़ता है, तो यहां क्यों नहीं? जब उनसे सवाल किया गया कि खबर है कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के नौकरी छोड़ने की खबर है इस पर गिरिराज सिंह गुस्से में यह कहते सुनाई दिये कि नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। उनका यह बयान सबसे ज्यादा विवादित रहा और इसे सांप्रदायिक व अपमानजनक बयान के रूप में देखा गया।

ऐसा ही निम्नस्तरीय बयान उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद द्वारा दिया गया। उन्होंने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुये कहा कि अरे वो भी तो आदमी हैं न... नकाब छू दिया तो इतना बवाल? कहीं और छू देते तो क्या हो जाता? संजय निषाद के इस बयान को भी महिला गरिमा को आहत करने की नजरों से देखा गया। जे डी यू के नेता व बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने नितीश के प्रति अपनी वफादारी का सुबूत देते हुये यह कहा कि यह पिता जैसा स्नेह था। तो कुछ मुस्लिम व महिला संगठनों द्वारा इस मामले में एफ आई आर दर्ज कराने व कई जगह नितीश के विरुद्ध प्रदर्शन करने व उनका पुतला जलाने की भी खबरें हैं। परन्तु सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि इस घटना को लेकर नितीश के मानसिक स्वास्थ पर चर्चा होने के बजाये जिसतरह हिजाब पर ही बहस छेड़ दी गयी और वह भी अपने कुतर्कों के द्वारा, इससे यह साबित होता है कि साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाले मुस्लिम विरोध या इस्लामी प्रतीकों के विरोध का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते। अन्यथा किसी केंद्रीय मंत्री के इस बेहूदे कुतर्क का क्या अर्थ कि एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय चेहरा दिखाना पड़ता है, तो यहां क्यों नहीं? संविधान की शपथ लेने वाले इस केंद्रीय मंत्री गिरिराज को पता नहीं कि एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी महिला की स्वेच्छा से उसके अपने हाथों से हिजाब या पर्दा हटाने को कहा जाता है न कि नितीश कुमार की तरह बदतमीजी से किसी के चेहरे से हिजाब खींचा जाता है? ऊपर से पीड़िता को ही यह कहना कि वह नौकरी करे या जहन्नुम में जाए, इस तरह की शब्दावली देश का एक केंद्रीय मंत्री इस्तेमाल कर रहा है?

बुर्का पर्दा या हिजाब को लेकर खुद विश्व मुस्लिम जगत में ही बड़ा घमासान है। दुनिया के कई अलग अलग इस्लामी देश अलग अलग तरह के परदे या हिजाब की पैरवी करते रहे हैं। जबकि विश्व का एक बड़ा उदारवादी व प्रगतिशील वर्ग ऐसा भी है जो इस तरह की बंदिशों को गैर जरूरी समझता है। कोई इसे इस्लामिक व शरिया से जुड़ी व्यवस्था बताता है तो कोई इसे सामाजिक या भौगोलिक जरूरतों का हिस्सा बताता है। कई महिलायें स्वयं इसका विरोध करती हैं तो कई इसे अपनी इस्मत से जोड़कर देखती हैं। परन्तु यहाँ बहस इन विषयों पर नहीं होनी चाहिये बल्कि बहस का विषय नितीश कुमार द्वारा हिजाब को लेकर की गयी उनकी अभद्र क्रिया होनी चाहिये। और इस क्रिया से भी खतरनाक उन प्रतिक्रियाओं पर चर्चा होनी चाहिये जोकि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्री स्तर के लोगों द्वारा व्यक्त की गयी हैं।

दैनिक ट्रिब्यून
स्थापना 15 अगस्त 1978

सरसों का संकट

पंजाब के किसानों को आर्थिक संबल जरूरी

एक समय था जब पंजाब के ग्रामीण अंचलों में खिले हुए सरसों के खेत मौसमी बयार में बदलाव के प्रतीक हुआ करते थे। तमाम सांस्कृतिक प्रतिमानों में पीले सरसों के खेतों को मौसम के गौरव के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन वक्त की विडंबना है कि यह अब यह सुनहरी फसल सिमटती नजर आ रही है। जिसके परिणाम स्वरूप आज देश में हम खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारत लगातार आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। निश्चय ही यह स्थिति व्यवस्था के कई विरोधाभासों को भी उजागर कर रही है। यह तथ्य चौंकाता है कि पंजाब में सरसों के उत्पादन में इसलिए गिरावट नहीं आ रही है कि फसल उत्पादन क्षमता में किसी तरह की कोई कमी आई है। बल्कि यह स्थिति इसलिए है कि सरकारों की नीतियां प्रोत्साहन देने वाली साबित नहीं हो रही हैं। वहीं बाजार के रुझान इसे आर्थिक रूप से किसानों के हितों के प्रतिकूल बना रहे हैं। कहने को तो अकसर दलील दी जाती है कि पंजाब के किसानी से जुड़े संकटों का समाधान फसलों के विविधीकरण में निहित है। लेकिन विडंबना यह है कि विविधीकरण के दावों के बावजूद, सरसों के उत्पादक किसान प्रोत्साहन न मिल पाने से निराश हैं। दरअसल, किसान कम और अनिश्चित मुनाफे के चलते सरसों की फसल उगाने से गुरेज करता है। उसके सामने बड़ी चुनौती यह भी है कि सरसों की फसल की सरकारी खरीद सीमित मात्रा में होती है। जिसके चलते किसानों को खून-पसीने की उपज को बेचने के लिये व्यापारियों के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने मोटे मुनाफे के लिये किसान के हितों की अनदेखी करने से नहीं चूकते। यही वजह है कि गेहूं और धान के विपरीत, जिनकी खरीद सुनिश्चित है और उनके लिये मजबूत विपणन प्रणाली मौजूद है, सरसों की फसल किसानों को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना देती है। फलतः किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

दरअसल, इस संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब आज अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का एक मामूली हिस्सा ही स्थानीय उत्पादन से पूरा करता है। इससे हमारी महंगे आयात पर निर्भरता और भी बढ़ जाती है। तिलहन की खेती को बढ़ावा देना अक्सर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही मायनों में सरकारी तंत्र द्वारा सरसों की उपज की खरीद में सहायता और न्यायसंगत मूल्य दिलाने के वायदे खोखले साबित होने के कारण सरसों की पैदावार का रकबा बढ़ता नहीं है। जिस दिन किसानों को तंत्र की नीतियों पर भरोसा पैदा हो जाएगा, उस दिन निश्चय ही किसान प्रोत्साहन के चलते तर्कसंगत प्रतिक्रिया देंगे। निर्विवाद रूप से पंजाब की धरती में सरसों उत्पादन की स्थितियों से जुड़ी संभावनाएं पर्याप्त हैं। यकीनी तौर पर यह धान की तुलना में कम पानी की खपत करती है। साथ ही भूजल संकट को कम करने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण से जुड़ी रणनीतियों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठती है। लेकिन हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि पंजाब में विविधीकरण के लक्ष्य केवल नैतिक प्रोत्साहन से हासिल नहीं किए जा सकते। निश्चित रूप से इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि बाजार की संरचना में जरूरत के अनुरूप बदलाव प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। सही मायनों में सरसों के लिये एमएसपी समर्थित खरीद और स्थानीय प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश किसानों को सरसों की खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है। यही प्रयास पंजाब के खेतों में पीली आभा फिर से पैदा करने की दिशा में कारगर साबित होंगे। सही मायनों में पंजाब में सरसों की खेती की कहानी नीतिगत विसंगतियों को ही उजागर करती है। दरअसल, संस्थागत स्तर पर समर्थन कुछ चुनिंदा फसलों को दिया जाता रहा है। जब तक यह असंतुलन दूर नहीं किया जाता, सरसों एक खोये हुए अवसर का प्रतीक बनकर रह जाएगी। इस फसल के पुनरुद्धार के लिये महज नारों की ही नहीं, बल्कि उसी गंभीरता की आवश्यकता है, जो गेहूं और धान की फसलों को लेकर लंबे समय से बरती जाती रही है।

आज का विचार

सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है।

— सुभाष चंद्र बोस

एकदा

जिम्मेदारी से बदलाव

एक बार विनोबा भावे भूदान आंदोलन के दौरान एक गांव में थे। एक महिला ने विनोबा जी के पास जाकर अपने जिद्दी पुत्र के बारे में सलाह मांगी। विनोबा जी ने कहा, 'कल से शिविर में भेज दो।' महिला ने बेटे से बस एक दिन शिविर देखकर आने की बात कही। बेटा उत्सुक होकर शिविर में चला गया। विनोबा जी ने उसे उसी समय दो-तीन घंटे के लिए कुछ खास जिम्मेदारी सौंप दी। युवक को अपनी तवज्जो बहुत अच्छी लगी, और जब उसने जिम्मेदारी निभा दी। विनोबा जी ने उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए आग्रह किया, 'बेटा, आप बहुत योग्य हो, सात दिन यहीं रुक जाओ।' युवक को यह मनुहार भी बहुत आत्मीय लगी, और वह सात दिन वहां ठहर गया। सात दिन बाद विनोबा जी के पास महिला आई। उसने देखा कि बेटा किसी से आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रहा था। वह गुपचुप सुनने लगी और चौंक गई, जब बेटा किसी को सलाह देते हुए कह रहा था, 'देखो, मानव जीवन बहुमूल्य है, सजग और सतर्क रहकर दायित्व निर्वहन करो, यही सर्वोत्तम मार्ग है।' बेटे में इतना सकारात्मक सुधार देखकर वह अचंभित रह गई। विनोबा जी ने रहस्य सुलझाया और कहा, 'मैंने आपके पुत्र को सात दिन यहां कुछ छोटी-छोटी जिम्मेदारियां सौंपीं, और उन्हें पूरा करते-करते वह खुद ही परिपक्व हो गया, क्योंकि यह गुण उसमें पहले से विद्यमान थे।'

प्रस्तुति : मुग्धा पांडे

40 साल पहले

दैनिक ट्रिब्यून

युवक की मौत, गुरदासपुर में कर्फ्यू जारी

गुरदासपुर, 25 दिसंबर (प्रेट्र, वार्ता, हस)। कल शाम यहां दो सम्प्रदायों के मध्य हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय युवक राजन शर्मा की आज तड़के अस्पताल में मौत हो गयी। उसका दाह संस्कार आज कर्फ्यू के दौरान ही कड़े सुरक्षा प्रबंधों के मध्य कर दिया गया। नगर में तनाव व्याप्त है। कर्फ्यू में आज बिल्कुल ढील नहीं दी गयी। अधिकारियों ने तनाव को देखते हुए कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है।

शिमला में हिमपात

चंडीगढ़ (प्रेट्र, वार्ता)। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल के ऊंचे पहाड़ों पर कल रात से हो रहे हिमपात तथा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे से रुक-रुक कर हो रही हल्की वर्षा से समूचे उत्तर भारत में शीत का प्रकोप बढ़ गया है। श्रीनगर में आज मौसम का पहला लेकिन जोरदार हिमपात हुआ। शाम तक 15 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी थी। शिमला में भी हिमपात की खबर है।

रचनात्मकता में एआई के उपयोग की सीमा का प्रश्न

अतनु विश्वास

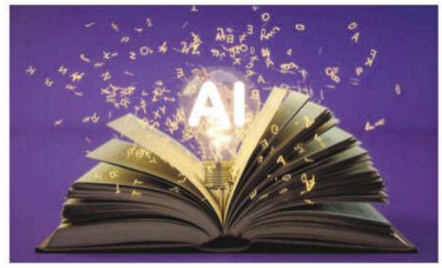

एक दिलचस्प समाचार के रूप में, न्यूज़ीलैंड के दो पुरस्कार विजेता लेखकों की किताबों, स्टेफनी जॉनसन के लघु कहानी संग्रह 'ओब्लिगेट कार्निवोर' और एलिजाबेथ स्मिथर के उपन्यास संग्रह 'एंजेल ट्रेन', को कृत्रिम बुद्धि (एआई) के उपयोग के कारण 65 हज़ार न्यूज़ीलैंड डॉलर पुरस्कार राशि वाले 2026 ओखम बुक अवॉर्ड्स (फिक्शन), जो देश का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार है, के लिए विचार करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह अस्वीकृति लेखन में एआई के उपयोग को लेकर नहीं बल्कि पुस्तकों के कवर डिज़ाइन के कारण हुई, जो एआई उपयोग संबंधी नए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते पाए गए। स्वाभाविक ही इस एआई युग में यह सवाल उठता है कि रचनात्मकता के संदर्भ में एआई का कितना उपयोग स्वीकार्य है। लक्ष्मण रेखा कहां होनी चाहिए?

मानव रचनात्मकता पर एआई के आक्रमण के प्रतिरोध और स्वीकृति का स्तर, समय और भूगोल के साथ बदलता रहता है। जर्मन फ़ोटोग्राफ़र बोरिस एल्डैग्सन 2023 में तब एक व्हिसलब्लोअर बन गए, जब उन्होंने सोनी वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी अवार्ड्स में क्रिएटिव ओपन श्रेणी का पुरस्कार यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि विजेता छवि बनाने के लिए उन्होंने एआई का उपयोग किया था। लेकिन बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेन यांग ने एआई का उपयोग करके केवल तीन घंटों में 'लैंड्स ऑफ मेमोरी' नामक पुस्तक बना दी और इसने अक्तूबर 2023 में, जियांग्सू यूथ पॉपुलर साइंस फिक्शन प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता। इसके अलावा, यह स्वीकार करने के बाद भी कि उनके उपन्यास 'टोक्यो-टू डोजो-टू' का 5 फीसदी शब्दशः चैटजीपीटी द्वारा बनाया गया था, जापानी लेखिका री कुडन ने 2024 में अकुतागावा पुरस्कार जीता, जो जापान के प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है! कुडन के अनुसार, उन्होंने 'नरम और अस्पष्ट' शब्द खोजने को एआई की मदद ली थी, वे जो उनके उपन्यास में व्याप्त न्याय की जटिल अवधारणाओं को समाहित करते हों, इसे चयन समिति ने 'कोई गलत नहीं' माना।

खैर, एड्रियन ब्रॉडी ने 'द ब्रुटलिस्ट' फिल्म में अपने द्वारा अभिनीत भूमिका में हंगेरियन भाषा बोलते समय, उच्चारण बेहतर बनाने के लिए, एआई के उपयोग के बावजूद इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। इस वर्ष की अन्य ऑस्कर-नामांकित फिल्मों में, एआई क्लोनिंग का उपयोग जैक्स ऑडियार्ड के ट्रांसजेंडर गैंगस्टर म्युज़िकल एमिलिया पेरेज़ में कार्ला सोफिया गैसकॉन की गायन आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए भी किया गया था। क्या यह स्पष्ट संकेत है कि हॉलीवुड भी मात्र दो सालों में एआई को स्वीकार कर अपने अभिनेताओं और पटकथा लेखकों के दोहरे हमले को मान्यता दे रहा है, यह सुनिश्चित करने को कि चलो श्रमिकों ने अपना काम नई तकनीक से बदलने की बजाय उस पर नियंत्रण तो बनाए रखा?

इसके उल्ट, अकादमिक पत्रिकाएं इन दिनों शोध पत्रों में एआई के उपयोग के विरुद्ध सख्त रुख रखे हैं, हालांकि चैटजीपीटी को 2022 के अंत व 2023 के शुरू में प्रकाशित कई शोधपत्रों में सह-लेखक सूचीबद्ध किया गया। सामान्यतः मानव रचनात्मकता के क्षेत्र में एआई की स्वीकृति या अस्वीकृति पर इंसान का दृष्टिकोण दुनियाभर में समान नहीं। क्या एक समान दृष्टिकोण असल में जरूरी है? एआई विकसित होने पर ट्रस्ट को मानदंडों की समीक्षा और सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है।

> जब हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है तो सवाल है कि रचनात्मकता यानी साहित्य व कला के संदर्भ में एआई का कितना उपयोग स्वीकार्य है। दरअसल, मानव सृजनात्मकता पर एआई के आक्रमण के प्रतिरोध और स्वीकृति का स्तर, समय व भूगोल के साथ बदलता रहता है। हालांकि कला क्षेत्र में रचनात्मकता को गंभीर मिलावट से तब तक बचाना चाहिये जब तक यह एक नई तरह की कला के लिए राह न खोल दे।

लगभग दो साल पूर्व, एआई टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेटर 'स्टेबल डिफ्यूजन' द्वारा बनाई एक छवि को बीजिंग अदालत द्वारा कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया गया, जिसका मत था कि कलाकृति 'वादी की बौद्धिक कल्पना से बनाई गई थी' और 'व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मूर्त रूप है'। क्या यह बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने को 'आधे-मानव, आधे-एआई कार्य' को मान्यता देने की दिशा में एक कदम है?

आइए साहित्य क्षेत्र की स्थिति और उसमें एआई के कारण आए भूचाल पर नजर डालें। सलमान रुशदी ने कुछ माह पहले कहा था कि लेखकों को एआई से तब तक खतरा नहीं जब तक यह लोगों को हंसाने लायक न बन जाए। रुशदी के अनुसार, उन्हें यह दिखावा करना पसंद है, मानो एआई का कोई वजूद ही न हो। प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका मार्गरेट एटवुड ने भी बीते साल साक्षात्कार में कहा कि वह अभी लेखन में 'अच्छा समय' बिता रही हैं और एआई के विकास बारे चिंतित होने के लिहाज से वे बहुत बूढ़ी हैं।

हालांकि, हर लेखक रुशदी या एटवुड की तरह अच्छी स्थिति में नहीं। और विचार भी भिन्न-भिन्न हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के पुस्तक समीक्षक एओ स्कॉट का मानना है कि लेखन में एआई का उपयोग एक नौटंकी और साहित्य के लिए घातक खतरा, दोनों है। जेनरेटिव एआई टूल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल - लिखित उपन्यासों की बाढ़ बाजार में आने के साथ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक नया अध्ययन, जिसमें यूके फिक्शन प्रकाशन क्षेत्र के सैकड़ों रचनाकारों को शामिल किया गया, कॉपीराइट उल्लंघन, राजस्व हानि और कला स्वरूप के भविष्य के बारे में व्यापक चिंताओं का खुलासा करता है।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मिंडेरू सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी (एमसीटीडी) की डॉ. क्लेमेंटाइन कोलेट ने एक हालिया अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट के लिए 332 लेखकों को शामिल कर सर्वेक्षण किया। इसके अनुसार, इन यूके के लेखकों में से आधे से अधिक (51 प्रतिशत) का मानना है कि एआई अंततः कथा लेखकों के रूप में उनके पेशे को बदल देगा। लगभग दो-तिहाई (59 प्रतिशत) लेखकों ने यह अहसास होने का दावा किया कि एआई एलएलएम मॉडल को उनकी सहमति या बिना पारिश्रमिक उनके काम का उपयोग कर प्रशिक्षित किया गया। एक-तिहाई से अधिक लेखक का दावा है कि जेनरेटिव एआई उनकी आय नकारात्मक प्रभाव डाल चुका है, शायद अन्य नौकरि छूटने के चलते वे उपन्यास लेखन में आए होंगे अधिकांश उपन्यासकारों का अनुमान है कि भविष्य एआई उनकी आय कम कर देगा। मनुष्यों पर एआई प्रभुत्व की शुरुआत - मानव सभ्यता में एक परिवर्त बिंदु - 1997 में चिन्हित हुई जब आईबीएम के सु कम्प्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गै कास्परोव को हराया था। दो दशक बाद, एआई खतरा मानने वाले कई आलोचकों के उलट, कास्परो ने अपनी 2017 की पुस्तक 'डीप थिंकिंग' में तर्क दि कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने को मानवता इसके सब उल्लेखनीय आविष्कारों से डरने के बजाय स्वाग करे। हालांकि, किस स्तर तक? मानव रचनात्मक किस हद तक एआई तूफान के बावजूद बच सकती है

आज, एआई का उपयोग मूर्तियां, पेंटिंग अ तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा है, जिनमें कुछ हजारों डॉलर में बिक रही हैं। क्या हमें इस पुनर्विचार की ज़रूरत है कि कला क्या है? निश्चि रूप से, नई तकनीक को लेकर विगत की मिसालें जो हमें रचनात्मकता के बंधनों से मुक्त कराती है जब 19वीं शताब्दी में पहली बार फोटोग्राफ विकसित हुई तो कई कलाकारों का मानना था कैमरा कलाकार का दुश्मन है और इससे ब छवियां कला प्रतिष्ठान की दुश्मन हैं। हालांकि फोटोग्राफी ने पेंटिंग की जगह नहीं ली; बल्कि 20 सदी के प्रायोगिक आधुनिक कला आंदोलन विकास में उत्प्रेरक का काम किया, क्योंकि कलाक यथार्थवाद से अमूर्तता की ओर स्थानांतरित हो ग और आज की समकालीन कला का आधार तैय किया। फोटोग्राफी भी कला का दूसरा रूप बन गई

बहरहाल, हमारा दायित्व है कि हम मान रचनात्मकता को गंभीर मिलावट से तब तक बच जब तक यह एक नई तरह की कला के लिए रास न खोल दे, जो चले आ रहे रिवायती मानव क रूपों से अलग हो। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण इस युग में, एक समान मानदंड बनाने के लि दुनिया भर के विधायकों और अदालतों को नी निर्माताओं के रूप में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए

लेखक भारतीय सांख्यिकी संस्थान में प्रोफेसर हैं।

सरलीकरण से राहत

चक्रव्यूह से मुक्त वसीयत का 'आजादी महोत्सव'

डॉ. सुधीर कुमार

भारत में अपनी ही संपत्ति को अपनों के नाम छोड़ जाने की प्रक्रिया अक्सर एक कानूनी दुःस्वप्न बन जाती थी। लेकिन संसद ने 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' के जरिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की बेड़ियां काटकर एक नई सुबह का आगाज किया है। सालों से चली आ रही 'प्रोबेट' की अनिवार्य शर्त को अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, अब मरने वाले की अंतिम इच्छा यानी उसकी 'वसीयत' को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अदालतों की लंबी कतारों और भारी-भरकम फीस से मुक्ति मिल गई है।

सरल शब्दों में समझें तो 'प्रोबेट' अदालत द्वारा जारी किया गया वह प्रमाणपत्र है, जो कानूनी रूप से यह तस्दीक करता है कि वसीयत पूरी तरह असली है और इसे बनाने वाला व्यक्ति (वसीयतकर्ता) इसे लिखते समय पूरी तरह होश-ओ-हवास और सही मानसिक स्थिति में था। अब तक हमारा कानून एक अजीब विरोधाभास और 'क्षेत्रीय भेदभाव' का शिकार था। अगर आप मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे पुराने 'प्रेसिडेंसी टाउन्स' में रहते थे, तो वसीयत होने के बावजूद संपत्ति हस्तांतरण के लिए प्रोबेट लेना अनिवार्य था।

यह प्रक्रिया किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी; इसमें न केवल सालों का समय बर्बाद होता था, बल्कि संपत्ति की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 2 से 5 प्रतिशत तक) भारी-भरकम 'कोर्ट फीस' और वकीलों के खर्च की भेंट चढ़ जाता था। 2025 का यह नया सुधार इसी विसंगति पर प्रहार करता है। अब चाहे आप दिल्ली के दिल में हों, पटना की गलियों में या मुंबई के समंदर किनारे- कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सरकार ने इस 'अनिवार्यता' को खत्म कर यह सुनिश्चित किया है कि अब विरासत पाने के लिए आपको अपनी ही जेब खाली नहीं करनी पड़ेगी।

यह ऐतिहासिक बदलाव रातो-रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे न्यायपालिका के दशकों पुराने कानूनी मंथन की गूंज है। इस सुधार की बुनियाद असल में साल 2001 में ही रख दी गई थी, जब 'क्लोरेंस पैस बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। हालांकि उस वक्त अदालत ने धारा 213 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संकेत भी दिया कि प्रोबेट की अनिवार्यता केवल कुछ विशेष और सीमित परिस्थितियों के लिए ही तर्कसंगत हो सकती है। इस फैसले ने भविष्य के लिए एक नई बहस छेड़ दी थी - कि क्या एक निर्विवाद वसीयत के लिए भी अदालती मुहर हर हाल में जरूरी होनी चाहिए?

साल 2005 में 'मैरी कोचु बनाम थॉमस' जैसे मामलों में अदालतों ने और भी सख्त रुख अपनाया। केरल हाईकोर्ट और बाद के विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि प्रोबेट की अनिवार्यता का नियम अक्सर न्याय दिलाने के बजाय केवल कानूनी पेचीदगियां और बोझ बढ़ाता है। हाल के वर्षों में तो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह दोहराया कि यदि वसीयत की सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, तो वारिसों को जबरन अदालती चक्रव्यूह में घसीटना 'ईज ऑफ लिविंग' (सुगम जीवन) के बुनियादी सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है। 2025 के इस नए कानून ने असल में न्यायपालिका की इन्हीं प्रगतिशील टिप्पणियों और वर्षों की कानूनी जद्दोजहद को एक 'वैधानिक कवच' प्रदान कर दिया है। संसद ने अदालतों की उस मंशा को कानून का रूप दे दिया है, जो लंबे समय से आम आदमी को वसीयत के नाम पर होने वाली कानूनी प्रताड़ना से बचाना चाहती थी।

> भविष्य की कानूनी लड़ाइयों से बचने के लिए आज भी दो गवाहों की मौजूदगी में स्पष्ट वसीयत लिखना ही एकमात्र अचूक मंत्र है। कानून ने अनिवार्य प्रोबेट की लाठी छीन ली है, लेकिन समझदारी का छाता आपके हाथ में छोड़ दिया है।

धारा 213 के हटने से वसीयत अब एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज बन गई है। अब उत्तराधिकारी प्रोबेट के बिना भी सीधे संपत्ति का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और बैंक खातों का सेटलमेंट करा सकेंगे। प्रोबेट अब 'अनिवार्य' नहीं है, लेकिन 'अप्रासंगिक' भी नहीं है। भले ही सरकार ने इसे थोपना बंद कर दिया हो, लेकिन इसे बेकार समझना भारी भूल होगी। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जरा भी आशंका है, तो प्रोबेट आज भी अदालत में सबसे मजबूत 'सुरक्षा कवच' है। विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संपत्ति या आपसी अनबन की स्थिति में 'स्वैच्छिक प्रोबेट' कराना एक स्मार्ट मूव है- यह भविष्य के महंगे मुकदमों से बचने का एक सबसे सस्ता और पक्का बीमा है।

निःसंदेह, सरकार का यह कदम संकेत देता है कि भविष्य 'डिजिटल उत्तराधिकार' का है। जब प्रोबेट की अनिवार्यता खत्म होती है, तो लोगों में वसीयत लिखने का उत्साह बढ़ेगा। मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि उनका जीवनभर का निवेश अब कानूनी दांव-पेंच में नहीं फंसेगा। संसद का यह फैसला 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' का जीवंत उदाहरण है, जिसने वसीयत को अदालती धूल और अंतहीन तारीखों से आजाद कर सीधे हकदारों को सौंप दिया है। यह कदम साहसिक है, लेकिन पाठकों को समझना होगा कि कानून 'सरल' हुआ है, 'खत्म' नहीं। सरकार ने प्रोबेट की अनिवार्यता हटाकर राह तो आसान कर दी है, लेकिन यह सरलीकरण 'सावधानी' का विकल्प नहीं है। अगर जरा सा भी अंदेशा हो कि भविष्य में 'अपनों' के बीच 'सपनों' की संपत्ति को लेकर 'तलवारें' खिंच सकती हैं, तो याद रखिए भविष्य की कानूनी लड़ाइयों से बचने के लिए आज भी दो गवाहों की मौजूदगी में स्पष्ट वसीयत लिखना ही एकमात्र अचूक मंत्र है। कानून ने अनिवार्य प्रोबेट की लाठी छीन ली है, लेकिन समझदारी का छाता आपके हाथ में छोड़ दिया है।

लेखक कुरुक्षेत्र विवि के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

तिरछी नज़र

आई सर्दी लाई खांसी और घर के वैद्य

अशोक गौतम

अबके भी वही हुआ, जो हर सर्दी आने पर मेरे साथ होता है। सर्दी आते ही मेरी नाक बहने लगी, मुझे खांसी शुरू हुई तो मेरे घरवालों को पता चल गया कि सर्दी का मौसम आ गया है। वे मौसम बदलने की सूचना के लिए मौसम विभाग के बुलेटिन का इंतजार नहीं करते, मेरी नाक बहने, मुझे खांसी लगने का इंतजार करते हैं। इधर मुझे जुकाम, खांसी हुई तो मेरे घर के वैद्य मेरे आसपास एकाएक वैसे ही सक्रिय हो उठे जैसे वसंत आने पर गली-मोहल्लों के मनचले एकाएक सक्रिय हो उठते हैं। धन्य हैं वे परिवार, जिनके पास एमएमबीएस, एमडी डिग्रीधारियों से भी बड़े अपने अपने नुस्खेधारी, तुजुर्बेकार घर के वैद्य उनके आजू-बाजू मंडराते रहते हैं, हर बीमारी के अपने एक से एक चूक नुस्खे लिए।

> मुझे खांसी शुरू हुई तो मेरे घरवालों को पता चल गया कि सर्दी का मौसम आ गया है। वे मौसम बदलने की सूचना के लिए मौसम विभाग के बुलेटिन का इंतजार नहीं करते, मेरी नाक बहने, मुझे खांसी लगने का इंतजार करते हैं।

इधर ज्यों ही मुझे सर्दी के मौसम की पहली छींक आई, मेरे घरवालों ने अपने-अपने अस्पताल के कपाट खोल दिए। मेरे घर के सदस्य चार हैं तो वैद्य पांच। इनके अतिरिक्त मोहल्ला तो घरेलू वैद्यों से खचाखच भरा है, पर कायदे बेकायदे से पति पर पहला हक बीवी का होता है, इसलिए वह अपने पति की हर बीमारी का इलाज खुद करना चाहती है। सो, वह मेरी छींक का असफल इलाज अपने एक से एक चूक नुस्खों से करने लगी।

उसके पास सब पत्नियों की तरह अपने पति की हर बीमारी ठीक करने के यूनानी से लेकर मुल्तानी होते हुए रोमानी पद्धति तक के मौलिक नुस्खे सहज उपलब्ध हैं। एलोपैथी से लेकर बेलोपैथी तक। आयुर्वेद तो उसके आगे पानी भरता है। उसका हर नुस्खा हर पैथी को शर्म से पानी-पानी करता है। उसके आगे हाथ जोड़े उसकी जय-जयकार करता है।

मुझे छींके लगने पर पता नहीं मेरी बीवी को क्यों लगा कि जो मुझे ये छींकें आ रही हैं, इसकी वजह सर्दी नहीं, मेरे बाल सफेद हो जाने के बावजूद कोई जवानी के दिनों की अनामिका मुझे याद कर रही है। सच्ची कहीं की। पर विवाहित दिनों का कड़वा सच यह है कि अब मैं खुद भी अपने को याद नहीं करता।

हे सर्दियों में भी स्वस्थ रह अपनी बीवी के नुस्खों से जैसे-कैसे बचे रहने वालो भाग्यशालियो! मुझे तो खैर याद नहीं, पर अब वह भी नहीं जानती कि मुझे मेरी खांसी से छुटकारा दिलाने को हफ्ते भर में वह क्या-क्या मुझे खिला-पिला चुकी है। पर ये मुझे ही पता है कि जैसे-जैसे वह मेरी खांसी का इलाज कर रही है, मुझे जुकाम भी होने लगा है। पर वह मानने वाली नहीं। जो मान जाए, वह डॉक्टर ही कैसा?

हालांकि, मुझे पता है हर बार की तरह इस सर्दी में भी वह मेरी खांसी को बिगाड़ कर ही दम लेगी। पिछली दफा भी उसके हाथों चढ़ मेरी खांसी बिगड़ कर पता नहीं कैसे टीबी होने से बची थी।

आपकी राय

लोगों का जीना मुहाल

पराली जलाने के अलावा भ प्रदूषण बढ़ने के कई अन्य कार हैं, जिनमें सरकार और प्रशास की ढिलाई भी शामिल है संपादकीय 'जानलेवा आबोहवा' यह तथ्य सामने आया कि दिल्ल के आसपास के कई शहर भी गंभी प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। ची ने ई-वाहनों को अपनाया, भा उद्योगों को हटाया और पौधारोप किया। भारत को चीन के मॉडल का अनुकरण करना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों क पालन करना होगा। अन्यथ जमीनी स्तर पर कारगर प्रयासों क कमी से लोगों का जीना मुश्कि हो सकता है।

बीएल शर्मा, तराना, उज्जै

इंटरनेट मीडिया की चुनौत

तेईस दिसंबर के दैनिक ट्रिब्यून 'उग्र होते बच्चे' संपादकी सार्थक लगा। मोबाइल फोन औ इंटरनेट मीडिया का अत्यधि उपयोग बच्चों के लिए गंभी चुनौती बनता जा रहा है। देर रा तक स्क्रीन पर समय बिताने उनकी एकाग्रता, मानसि स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प नकारात्मक असर पड़ रहा है अभिभावक चिंतित हैं, जबकि रोक-टोक पर बच्चों का उ व्यवहार स्थिति को और जटि बना रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

अमृतलाल मारू, इंदौर, म.प्र

मनुष्यता की मौत

चौबीस दिसंबर के दैनिक ट्रिब्यून विश्वनाथ सचदेव के ले 'मनुष्यता की मौत है संवेदना धा का सूखना' में उन्होंने बढ़त संवेदनहीनता पर चिंता व्यक्त की उन्होंने 'मशाल' फिल्म क उदाहरण दिया, जिसमें दिली कुमार अपनी पत्नी की मदद के लिए गुजरते लोगों से गुहार लगा हैं। इसी तरह बेंगलुरु में स्कूल सवार पति-पत्नी की घटना क उल्लेख कर लेखक ने इंसानिय की कमी पर व्यथा व्यक्त की।

शामलाल कौशल, रोहत

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशनार्थ लेख इस ईमेल पर भेजें :-
dtmagzine@tribunemail.com

"धर्म एक ऐसा क्षेत्र है, जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनते हैं।

–अब्राहिम लिंकन

मंडी से सुखद पहल

हिमाचल महोत्सव संस्कृति की जिन गलियों से निकलते हैं, वहां मंडी शिवरात्रि की तैयारियों ने एक नया शपथ पत्र बनाया है। एक प्रतिज्ञा ली जा रही है इस बार शिवरात्रि पूरी तरह हिमाचली कला और कलाकार को समर्पित होगी। यहां इन मंसूबों को टॉर्च दिखाने का काम धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने किया है, तो उनके नाम हिमाचल के कलाकार जरूर शाबाशियां देंगे। इस मंच का संरक्षण जरूरी है और शिवरात्रि महोत्सव ने बाहें खोलकर हिमाचल गीत–संगीत का आलिंगन किया है। मंडी शहर अपनी स्थापना के पांच सौ वर्षों से गुजर रहा है, तो इतिहास भी अपने पन्नों के दिल खोल रहा है। बेशक हिमाचल के सांस्कृतिक समारोहों में विविधता आ रही है। पहली बार धर्मशाला कार्निवाल ने हनुमान मंदिर से शोभायात्रा की ओर कदम बढ़ाए हैं, तो अब साहित्य की ओज में ऐसे समारोहों की खिड़कियां खुल रही हैं। अंततः पूछा और महसूस तो यही किया जाएगा कि समारोहों का माहौल क्या है। एक रौनक का सफर, नए व्यापार की डगर, सरकारी विभागों की प्रदर्शनियों की नजर और गीत–संगीत का असर दिखाई देता है। महाशिवरात्रि के तीन जलेब के जरिए हम परंपराओं के कई युग लांघते हैं, तो पकवानों के जरिए कुछ नया अनुभव करते हैं, लेकिन इस उत्सव के अब सौदागर नजर आने लगे हैं। मेले और सांस्कृतिक समारोह बढ़ रहे हैं, तो इनके आयोजनों की परिधि, परिकल्पना और प्रशस्ति का मूल्यांकन भी होना चाहिए। जाहिर है भाषा, कला, संस्कृति विभाग या अकादमी के पास न ऐसा बजट और न ही आयोजन क्षमता है कि इनका नेतृत्व करे, इसलिए अब सांस्कृतिक आयोजन सियासी या प्रशासनिक मुद्रा व मुद्राओं में अपने होने की खबर देते हैं। बेहतर होगा एक मेला एवं महोत्सव विकास प्राधिकरण का गठन करके, ऐसे समारोहों के आयोजन का मानकीकरण करते हुए इन्हें आर्थिकी से जोड़ें। बात एक शिवरात्रि या कार्निवाल की नहीं, बल्कि दर्जनों समारोहों व मेलों की है। किसी एक समारोह की कश्तियां चलाने के लिए अगर तीन से पांच करोड़ भी खर्च हो गए, तो इसका अर्थ प्रादेशिक व्यवस्था व वित्तीय अनुशासन में खोजने होंगे। इन उत्सवों–महोत्सवों व मेलों का वार्षिक कैलेंडर, बजट, आर्थिक स्रोत तथा आयोजन की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। कलाकारों का वर्गीकरण तथा उनके साथ वार्षिक अनुबंध की रूपरेखा तय होनी चाहिए ताकि हर कलाकार के मानदंड व कार्यक्रमों की संख्या पहले से ही तय हो। अतीत में ऐसे भी रिकार्ड हैं कि कोई एक पंजाबी कलाकार पूरे साल में इतना पारिश्रमिक उगा कर ले गया जिससे नया उत्सव जन्म ले सकता था। वार्षिक उत्सवों और मेलों के आयोजन को अब नए स्थल, ट्रैफिक प्लान व पार्किंग व्यवस्था की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में हर प्रमुख शहर की चारों दिशाओं में कम से कम चार नए मैदान विकसित करने होंगे, जबकि हर गांव तक एक सामुदायिक मैदान की जरूरत पूरी होनी चाहिए। वार्षिक आयोजनों के अलावा मंदिर ट्रस्टों की आय से कलाकेंद्रों का विकास संभव है। कम से कम सरकार चामुंडा, कांगड़ा, बैजनाथ, दियोटसिद्ध, ज्वालामुखी, नयनादेवी, चिंतपूर्णी व बाला सुंदरी मंदिर परिसरों में हिमाचली कलाकेंद्र विकसित करके प्रदेश के कलाकारों का प्रदर्शन कर सकती है। ऐसा मंच मिलेगा, जहां हर दिन कला के शो चलाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं चंबा, मसरूर, सुजानपुर, पुराना कांगड़ा सहित तमाम ऐतिहासिक व धरोहर स्थलों पर वार्षिक समारोहों की शुरुआत होनी चाहिए जबकि शिमला के रिज, धर्मशाला के शहीद स्मारक तथा गरली–परागपुर जैसे स्थलों पर नियमित लेजर शो चलने चाहिएं। हिमाचल के भाषा, कला व संस्कृति विभाग को प्रदेश के इतिहास, जीवनशैली, ट्राइबल लाइफ, वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधनों, परंपराओं व विविध खान–पान के आधार पर तमाम संग्रहालयों में सजीव कार्यक्रम शुरू करने चाहिएं।

अंतरिक्ष में भारत का 'बाहुबली'

इस बार भारत ने अंतरिक्ष में 'बाहुबली छलांग' लगाई है। भारत ने सबसे अधिक वजन वाला, वाणिज्यिक उपग्रह, भेजने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। जिस अमरीकी 'ब्लूबर्ड ब्लॉक–2' उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने का इतिहास भारत ने रचा है, उससे संचार की दुनिया का चेहरा ही बदल जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से एलवीएम–3 के रॉकेट के जरिए भारत ने 6100 किग्रा. का उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजकर कीर्तिमान का एक और मील पत्थर स्थापित किया है। इससे पहले यह कीर्तिमान 4400 किग्रा. के सीएमएस–03 संचार उपग्रह के नाम था, जो 2 नवंबर को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो की वाणिज्यिक शाखा 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' ने अमरीकी कंपनी 'एएसटी स्पेसमोबाइल' के साथ करार किया था। लॉन्चिंग के 15 मिनट बाद ही यह उपग्रह रॉकेट से अलग हो गया और करीब 600 किमी. दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हो गया। प्रक्षेपण और उड़ान में मात्र 90 सेकंड की देरी इसलिए हुई, क्योंकि उपग्रह के उड़ान–पथ पर मलबा होने अथवा अन्य उपग्रहों के साथ टकराव की संभावनाएं थीं। इस 'बाहुबली उपग्रह' से संचार और मोबाइल की दुनिया इस कदर बदल जाएगी कि दुनिया में कहीं भी, पहाड़ों के बीच भी, 4 जी और 5जी सुविधा वाले मोबाइल से वॉयस और वीडियो कॉल, संदेश, स्क्रीमिंग, डाटा सेवाएं सहज और सुलभ हो जाएंगी। अब नेटवर्क की कोई भी चिंता नहीं होगी। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष से सीधे धरती पर कॉल की जा सकेंगी। संदेश भेजना संभव होगा। वीडियो कॉल के जरिए हम सब, एक–दूसरे के, रूबरू होंगे। क्या भारत ने इतनी विराट, अंतरिक्षी सफलता की कल्पना तक की थी? आर्यभट्ट से लेकर ब्लूबर्ड तक भारत ने एक बहुत लंबा और पेचीदा सफरनामा तय किया है। गौरतलब यह है कि पहली बार इसरो ने 52 दिनों की तैयारी में इस उपग्रह को लॉन्च किया है, जो एलएमवी–3 जैसे बाहुबली के लिए बहुत कम समय है। इस रॉकेट में पहली बार एस 200 बूस्टर को नियंत्रित करने के लिए नए कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। यही सिस्टम 'गगनयान मिशन' में भी इस्तेमाल होना है, लिहाजा एक तरह से उसकी सफल टेस्टिंग हो गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सफल लक्ष्यों की कहानी भी सामने आई है, क्योंकि 2026 में हर माह एक लॉन्चिंग होगी। उसमें सबसे खास मिशन 'गगनयान' है। कुछ स्टार्टअप के ऑर्बिटल लॉन्च भी होने हैं। 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का लक्ष्य तय किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 8–10 विश्व कीर्तिमान रचने की भी योजना है। आज यह याद करने का भी दिन है कि 2014 में इसरो ने 'मंगलयान' के साथ पहली कोशिश की थी और भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम देश बन गया था। 2017 में पीएसएलवी–सी 37 के साथ भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर भी इतिहास रचा था। 2023 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ, जब हमारा 'चंद्रयान–3' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर सका। वहां हमने 'तिरंगा' स्थापित किया। 'ब्लूबर्ड–2' के प्रक्षेपण और पृथ्वी की कक्षा में सफल स्थापना ने भी भारत की इन उपलब्धियों को एक और सेहरा पहनाया है। जो उपग्रह भेजा गया है, वह दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रह में 223 वर्ग मीटर का विशाल, एक खास किस्म का, एंटीना लगा है, जो अब तक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा वाणिज्यिक, संचार उपग्रह बनाता है। 'ब्लूबर्ड' की मदद से स्मार्टफोन वाणिज्यिक और सरकारी दोनों उद्देश्यों के लिए सीधे उपग्रहों से जुड़ सकेंगे। यह मिशन भविष्य में इंटरनेट जुड़ाव को बदलने वाला भी साबित होगा। इन उपलब्धियों पर अचरज भी होता है। भारत का अंतरिक्ष में अपना स्टेशन भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार यह घोषणा की है। उस दिन भारत अंतरिक्ष के भी सातवें आसमान पर होगा। बहरहाल इसरो को इस उपलब्धि के लिए बधाई। हालांकि यह कारवां और आगे जाना चाहिए। अभी कई कुछ करना बाकी है।

संपादकीय लेखों पर सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं, भेजें: पाठकों के पत्र, द्वारा संपादक, पोस्ट बॉक्स 14, धर्मशाला–176215
फोन: 01892–264713, 260676
फैक्स: 01892–264700
Email : feature@divyahimachal.com या edit.dshala@divyahimachal.com

बांग्लादेश की भीतरी हलचल

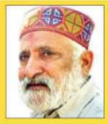

कुलदीप चंद अग्निहोत्री
वरिष्ठ स्तंभकार

बांग्लादेश के भीतर हो रही घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्यों में पकड़ पाने के लिए 1947 के भारत विभाजन को समझना जरूरी है। यह कहा जा सकता है कि 1947 के कृत्रिम विभाजन के झटके अभी तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अनुभव किए जा रहे हैं। दरअसल भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिसकी सीमा बहुत हद तक प्रकृति द्वारा ही निर्मित है। इसके नीचे की तीनों दिशाएं समुद्र से घिरी हुई हैं और उत्तर दिशा में नागराज हिमालय है। बाबा साहिब अंबेडकर ऐसा मानते हैं कि भारत की भौगोलिक सीमा प्रकृति ने स्वयं निर्धारित की है। जाहिर है जब इस प्रकार के देश की सीमाओं से छेड़छाड़ की जाती है तो उसके परिणाम लम्बे समय तक भोगने पड़ते हैं। यदि इस प्रकार के विभाजन का कोई तार्किक आधार न हो तो ये परिणाम बहुत लम्बे समय तक भी चलते रहते हैं। भारत विभाजन का कोई ठोस आधार न तो 1947 में था और न ही आज 2025 में है। मजहब के आधार पर देश का विभाजन भारतीय दर्शन और प्रकृति के विपरीत है। भारतीय समाज की पहचान के यदि विभिन्न आधार तलाशने भी हों तो वे उसके विभिन्न समुदायों में मिलेंगे न कि उनके मजहबों में। उदाहरण के लिए भारतीय समाज का एक समुदाय गुज्जर है। गुज्जर समुदाय के कुछ लोग शिया पंथ को मानने वाले हैं, कुछ इस्लाम पंथ को मानने वाले हैं, कुछ नानकपंथी हैं, कुछ शाक्त पंथ को मानने वाले हैं और कुछ वैष्णव मत के उपासक हैं। इसलिए उनकी सामूहिक पहचान गुज्जर होने की है न कि मजहब के आधार पर टिकी हुई है। एक दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है। भारतीय समाज का एक समुदाय बंगला भाषा के आधार पर बंगाली कहलाता है। बंगला समुदाय में लोग अलग अलग मजहबों को मानने वाले हो सकते हैं और हैं भी।

वे शाक्त मत को मानने वाले हैं, शिया मत को मानने वाले हैं और इस्लाम मत को मानने वाले हैं, शैव और वैष्णव मत को मानने वाले हैं। लेकिन उनकी समग्र पहचान उनकी बंगला भाषा पर टिकी है। मजहब के आधार पर देश गठित करने की विरासत यूरोप में मिल जाती है। यूरोप के लोगों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत को मजहब के आधार पर 1947 में विभाजित कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने कुछ भारतीयों को अपने साथ मिला लिया और उनके माध्यम से मजहब के आधार पर इस्लाम पंथ के लोगों को संगठित करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। अब एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। मुस्लिम लीग की सफ में भी राजपूत बैठा है और हिंदू की सफ में भी राजपूत बैठा है। मुस्लिम लीग की सफ में भी जाट बैठा है और हिंदू–सिख की सफ में भी जाट बैठा है। एक तमाशा और भी था। मुस्लिम लीग की सफ में अरब, तुर्क और मुगल मूल का मुसलमान भी बैठा है और भारत का देसी मुसलमान भी बैठा है जिनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। मजहब एक हो जाने से भी बंगाल के मुसलमान का भारत में रह रहे अरब मूल के सैयद मुसलमान से कोई रिश्ता नहीं बनता। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ लोगों के माध्यम से यह नकली ड्रामा भी कर दिखाया। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारे प्रयोग उत्तरी भारत तक ही सीमित थे। इन प्रयोगों के चलते पश्चिमोत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा मसलन बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनखवा, सिन्ध प्रदेश और पश्चिमी पंजाब इत्यादि देश से अलग हो गया। इसी प्रकार बंगाल का पूर्वी क्षेत्र भी देश से अलग हो गया। अलग हुए इन दोनों हिस्सों को पाकिस्तान का नाम दिया। लेकिन 1947 के लगभग पच्चीस साल से भी कम समय में पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में रहने से इंकार कर दिया। पाकिस्तान के हुकुमरानों ने बहुत समझाया कि हमारा तो मजहब एक ही है। लेकिन पाकिस्तान के बंगालियों ने कहा मजहब तो एक है लेकिन हमारी भाषा एक नहीं है। तुम्हारी भाषा उर्दू है। इतना ही नहीं हमने इस्लाम मजहब या शिया मजहब को अपनाया है, लेकिन रवीन्द्र नाथ ठाकुर को नहीं छोड़ा है। पूर्वी पाकिस्तान, जो दरअसल पूर्वी बंगाल था, वह पाकिस्तान से लड़ कर अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। इस प्रकार 1947 से बंटना शुरू हुआ भारत अब दो में नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बंट गया। क्योंकि विभाजन कृत्रिम था, इसलिए वह 1947 से लेकर अब तक दर्द दे रहा है। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि शरीर में सचमुच ट्यूमर हो, दर्द हो रहा हो, और उसे शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाए तो शरीर का दर्द दूर हो जाता है और उसे सुख मिलता है। लेकिन यदि शरीर में ट्यूमर ही न हो, लेकिन तब भी आप्रेशन कर उसका कोई अंग निकाल दिया जाए तो दर्द शुरू हो जाता है और निरन्तर होता रहता है। यही भारत के साथ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिंदू–मुस्लिम नाम से भारत के नाम से एक नकली ट्यूमर होने की अफवाह फैला दी। लेकिन शरीर में दर्द भी तो होना चाहिए। इस काम के लिए एटीएम मूल के दुखी मुसलमान लगा दिए जिन्हें भारत में से अपनी सत्ता खत्म हो जाने से लगातार दुख हो रहा था। उनका दुख भारत के देसी मुसलमानों का दुख नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह दर्द इनका भी है। उनमें से भी कुछ को महसूस होने लगा कि यह दर्द उनका भी है। यह कुछ उसी प्रकार था जिस प्रकार किसी हट्टे कट्टे आदमी को बार बार कहा जाए कि वह बीमार है तो उसे भी लगने लगता है कि वह बीमार है और उसे दर्द हो रहा है। चन्द लोगों के असली–नकली दर्द को आधार बना कर अंग्रेजों ने भारत बांट दिया और आप्रेशन के बाद कैंची पेट में ही छोड़ दी। तब बाबा साहिब अंबेडकर ने बहुत जोर से कहा कि धूर्त अंग्रेज हुक्मरान कैंची भारत पेट में ही छोड़ रहे हैं। जब तक यह कैंची पेट में रहेगी, दर्द देती रहेगी। इसलिए इसे पेट से निकालो। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं माने। अब मामला यह है कि भारत में दर्द इसलिए होता है क्योंकि कैंची पेट के अन्दर है और पाकिस्तान में दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां के बलूच, पश्तून, सिन्धी चिल्ला रहे हैं कि हमारी पहली पहचान सिन्धी, बलूच और पश्तून होने की है न कि मजहब की।

पाकिस्तान में वहां नाग कुंडली मार कर बैठा सैयद समझा रहा है तुम्हारी बलूच, सिन्धी और पश्तून होने की पहचान खत्म हो गई है, अब तुम केवल मुसलमान हो और कुछ नहीं। यही कारण है कि वहां रोज बलूच और पश्तून पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि भारत (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश) में विभाजन की प्रक्रिया अभी तक जारी है। दो शक्तियों में रस्साकशी जारी है। वे शक्तियां जो आज 2025 में भी मजहब की पहचान को अन्य सभी पहचानों पर थोप कर, देश का मुकम्मल विभाजन करना चाहती हैं। दूसरी वे शक्तियां हैं जो मजहब को किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला मानती हैं और उसके आधार पर विभाजन को कृत्रिम मानती हैं। इतना ही नहीं, मजहब के नाम पर हो चुके विभाजन को अस्वीकार कर उसे पुनः एक करना चाहती हैं। तीसरी वे शक्तियां हैं जो जहां से मुगल छोड़ कर गए थे, वहीं से दोबारा यात्रा शुरू करना चाहती हैं और पूरे भारत को ही दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित करने के अभियान को पुनः शुरू करना चाहती हैं। तीनों शक्तियां लड़ती हैं, कभी एक पराजित हो जाती है तो समझ लिया जाता है, वह खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह कमजोर होती है। समय पाकर उठ खड़ी होती है, बांग्लादेश में यही हो रहा है। 1971 में जो शक्तियां पराजित हो गई थीं, वे समय पाकर फिर उठ खड़ी हैं और एक बार फिर वहां मजहबी पहचान के आधार पर परचम लहराना चाहती हैं। यही कारण है कि अब बांग्लादेश के शासक पाकिस्तान को वापस बुला रहे हैं। बहरहाल कई शक्तियां इस समय संघर्षरत हैं।

ईमेल:kuldeepagnihotri@gmail.com

> दो शक्तियों में रस्साकशी जारी है। वे शक्तियां जो आज 2025 में भी मजहब की पहचान को अन्य सभी पहचानों पर थोप कर, देश का मुकम्मल विभाजन करना चाहती हैं। दूसरी वे शक्तियां हैं जो मजहब को व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला मानती हैं और उसके आधार पर विभाजन को कृत्रिम मानती हैं...

प्रसंगवश

इसरो की ऐतिहासिक उड़ान

हाल ही में बुधवार 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने बाहुबली प्रक्षेपण यान एलवीएम–3 से पहली बार 6100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। वास्तव में यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव का क्षण है। स्वयं इसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने भी इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। यह एक तरह से देश की अंतरिक्ष इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज कहा जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमरीकी उपग्रह ब्लूबर्ड–6 सीधे स्मार्ट फोन तक 4 जी और 5 जी इंटरनेट, वॉयस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं प्रदान करेगा। पाठकों को बताता चलूं कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लांच पैड से एलवीएम–3 एम–6 ने निर्धारित समय 8.54 बजे उड़ान भरी और 16 मिनट बाद ब्लूबर्ड उपग्रह को 520 किमी वाली वृत्ताकार कक्षा में सटीकता के साथ स्थापित कर दिया। गौरतलब है कि यह भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले, नवंबर में लॉन्च किया गया एलवीएम3–एम5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट–03 करीब 4400 किलोग्राम का था। इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया था। ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 को जिस एलवीएम3–एम6 रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका वजन 640 टन है। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 नेक्स्ट–जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। खास बात यह है कि इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4जी और 5जी वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और अमेरिका स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) के बीच हुए एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यूस्पेस इंडिया, इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है। कहना गलत नहीं होगा कि इसरो की हाल की उपलब्धि ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को और मजबूत किया है। सच तो यह है कि एलवीएम 3 ने फिर एक बार विश्वसनीयता और उपयोगिता साबित की है। उल्लेखनीय है कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यह 104 वां लॉन्च मिशन था। पहली बार ऐसा हुआ है, जब केवल 52 दिन के अंतराल पर एक के बाद एक एलवीएम–3 के दो मिशन प्रक्षेपित किए गए। कितनी अच्छी व बड़ी बात है कि टेक्सास स्थित अमरीकी कंपनी एएसटी मोबाइल का उपग्रह ब्लूबर्ड–6 सीधे स्मार्ट फोन तक 4 जी और 5 जी इंटरनेट, वॉयस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं प्रदान करेगा। वास्तव में इससे संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए सैटेलाइट हैंडसेट से ही उपग्रहों के जरिए संचार संभव था। बहरहाल इस उपलब्धि पर इसरो को बधाई।

–सुनील कुमार

हिमाचल : खेल

प्रदेश में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैसे हो?

भूपिंद्र सिंह
अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक

हिमाचल प्रदेश खेल विभाग खेल प्रशिक्षण के लिए राज्य में वह वातावरण ही नहीं बन पाया है, जिसमें प्रशिक्षक खिलाड़ी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण एक दशक से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतनी लंबी समय अवधि खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम को देकर ही कोई किस्मत वाला खिलाड़ी अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं बन पाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के प्रशिक्षकों को कभी विभिन्न विभागों की भर्तियों में ड्यूटी तो कभी मेलों व उत्सवों में हाजिरी भरनी पड़ती है। खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति ही उच्च खेल परिणामों के लिए की गई होती है, मगर यहां पर प्रशिक्षकों को केवल मल्टीपर्पज कर्मचारी बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मेलों व उत्सवों में किसी और खेल का प्रशिक्षक किसी और ही खेल की प्ले फील्ड में नजर आता है। इसी तरह पुलिस आदि विभागों की भर्तियों में एथलेटिक्स प्रशिक्षकों की ड्यूटी तो समझ आती है मगर वहां तो हर खेल के प्रशिक्षक को भेज दिया जाता है। नियमानुसार इन भर्तियों के लिए एथलेटिक्स प्रशिक्षक ही सक्षम है, क्योंकि इस टैस्ट में केवल एथलेटिक स्पर्धाओं को ही रखा गया है।

ऐसे में एथलेटिक्स प्रशिक्षक की ड्यूटी तो समझ आती है, मगर वहां अन्य खेलों– कुश्ती, मुक्केबाजी, हैंडबाल व वॉलीबाल आदि के प्रशिक्षक का क्या औचित्य है, इस बात का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। जो प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षण से दूर रह कर मौज मस्ती कर रहा है, वह तो खुश रहता होगा, मगर जो सच ही में प्रशिक्षण करवा रहा होगा वह जब कई दिनों तक खेल मैदान से दूर रहेगा तो फिर कौन अभिभावक अपने बच्चे को बिना प्रशिक्षक के मैदान में भेजेगा। हद तो तब हो जाती है जब राज्य में चल रहे खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी भर्तियों में लगा दी जाती है और खेल छात्रावास में रह रहे खिलाड़ियों को भी खेल प्रशिक्षण से दूर कर दिया जाता रहा है। क्या प्रतिभा खोज से चयनित इन अति प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षक से कुछ समय के लिए ही सही, इस तरह सरकार का अपने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूर करना कहां तक उचित है। खेल छात्रावासों में नियुक्त प्रशिक्षकों की ड्यूटी खेल प्रशिक्षण के सिवा और कहीं भी नहीं होनी चाहिए । प्रशिक्षण पर बार–बार इस कॉलम के माध्यम से खेलने व खिलाने वालों को जागरूक किया जाता रहा है। स्तरीय प्रशिक्षण के बिना उत्कृष्ट प्रदर्शन बहुत कठिन है। आजकल हर शिक्षित मां–बाप के दो और कई जगह तो एक ही बच्चा है, ऐसे में वह उसे उस क्षेत्र में उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहता है जिसमें बच्चे की रुचि व उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिभा भी हो। आज का अभिभावक अपने बच्चों के कैरियर की खातिर ही सरकार की मुफ्त शिक्षा सुविधाओं को छोड़कर निजी क्षेत्र की महंगी मगर अधिक गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है। आज लाखों प्रतिभाशाली विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्थानों में डाक्टर व इंजीनियर बनने इसलिए जमा दो की परीक्षा से कई वर्ष पहले पहुंच रहे हैं। इसी तरह अब खेल क्षेत्र में भी हो रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए खेलों में भी कैरियर तलाश रहा है और इस सबके लिए अच्छी खेल सुविधाओं के साथ–साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षक भी लगातार कई वर्षों तक उसके बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता बनने का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इसलिए देश में निजी खेल अकादमियों का चलन भी बढ़ रहा है। गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी के विश्व स्तर के परिणाम सबके सामने हैं। यह सब लगातार अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम का ही नतीजा है। इस समय विभिन्न खेलों के लिए देश में निजी स्तर पर कई अकादमियां शुरू हो चुकी हैं। इन खेल अकादमियों को अधिकतर पूर्व ओलंपियन चला रहे हैं और यहां से अच्छे खेल परिणाम भी मिल रहे हैं। इन अकादमियों में जो विशेष है, वह यह है कि यहां उच्च क्षमता वाला प्रशिक्षक लगातार उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के पास आज विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तैयार हैं, वहां पर या तो प्रशिक्षक हैं ही नहीं और जहां है भी, वे या तो प्रशिक्षण से बेरुख हैं या उनमें अच्छे स्तर के खेल परिणाम दिलाने की क्षमता ही नहीं है। क्या सरकार उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षकों को यहां लगातार कई वर्षों के लिए अनुबंधित कर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य में ही प्रशिक्षण सुविधा दिला कर खेल प्रतिभा का पलायन रोक नहीं सकती है।

इससे प्रदेश में खेल वातावरण बनेगा तो हर खेल प्रशिक्षक प्रेरित होकर चाहेगा कि उसके शिष्य भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस सबके लिए हर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में अच्छे क्षमतावान प्रशिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण खिलाड़ियों को किसी भी स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। खेल विभाग को चाहिए कि वह अपने यहां नियुक्त प्रशिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण करवाने के लिए योजना तैयार कर उसे धरातल पर उतारे, तभी इस बर्फ के प्रदेश की संतानें अपने राज्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर हिमाचल प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बन कर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विजेता बना कर तिरंगे को सबसे लहराते हुए जन गण मन की धुन सारे विश्व को सुनाए।

ईमेल: bhupindersinghhmr@gmail.com

> इन अकादमियों में जो विशेष है, वह यह है कि यहां उच्च क्षमता वाला प्रशिक्षक लगातार उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के पास आज विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तैयार हैं, वहां पर या तो प्रशिक्षक हैं ही नहीं और जहां है भी, वे या तो प्रशिक्षण से बेरुख हैं या उनमें अच्छे स्तर के खेल परिणाम दिलाने की क्षमता ही नहीं है। क्या सरकार उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षकों को यहां लगातार कई वर्षों के लिए अनुबंधित कर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य में ही प्रशिक्षण सुविधा दिला कर खेल प्रतिभा का पलायन रोक नहीं सकती है...

प्रेरक कहानी

सच्चा स्वांग...

स्वामी श्रीरामसुखदास जी महाराज

एक राजा था। उसके पास एक बहुरूपिया आया। वह तरह–तरह के स्वांग धारण किया करता था। उसमें देवी की ऐसी शक्ति थी कि वह जो भी स्वांग धारण करता, उसको पूरा वैसा का वैसा निभाता था। उसमें वह कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त, त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गयी तो वह साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वह सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता। किसी से न राग रखता, न द्वेष। भिक्षा में जो मिल जाए, उसी में सन्तोष करता। लोगों को खूब अच्छी–अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त, त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मन्त्री को भेजा कि जाकर देखो, वही बहुरूपिया है या कोई और सन्त है? मन्त्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही बहुरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम सन्त के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत–सी अशर्फियां भर लीं और भेंट–पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट–बाट से वहां गया। मन्त्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे सन्त के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं! राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थाल उसके सामने रखा। सन्त ने अशर्फी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया और शिव–शिव कहते हुए उठकर वहां से चल दिया। लोग कहने लगे कि अच्छा सत्संग होता था, पर राजा को पता नहीं क्या सूझी कि सत्संग में बाधा लगा दी! राजा की भेंट क्या काम आयी! वह बहुरूपिया अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला कि अन्नदाता! इनाम मिल जाए। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारे मन में है कि मैं इतने रुपये इनाम में दूंगा। वह बोला कि आप अपनी मरजी से जो देंगे, उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोला– तू मूर्ख है! मैंने इतनी अशर्फियां तुम्हारे सामने रखीं, पर तुमने उनको छोड़ दिया! वह बोला– अन्नदाता! मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वह काम कैसे कर सकता था, जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए! अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि यह बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत–सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहुरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। वह बोला कि अन्नदाता! मैं स्वांग पूरा करता हूं, उसमें चूकता नहीं हूं। इसलिये आप मेरे से सिंह के स्वांग के लिए न कहें। यह स्वांग खतरनाक है! राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। बहुरूपिये ने कहा– अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा– हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहुरूपिया सिंह की खाल पहनकर सिंहावलोकन करता हुआ, इधर–उधर देखता हुआ आया। वह आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का लड़का वहां खेल रहा था। वह खेलते–खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहुरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया! राजा को बड़ा दुःख हुआ कि यह कैसा स्वांग है कि मेरा लड़का मर गया! दूसरे दिन बहुरूपिया रोता–रोता आया और बोला– अन्नदाता! आप क्षमा करें! मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मेरे से मत मंगाओ। मेरा शक्ति मां का इष्ट है, अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो मां नाराज हो जाए। राजा बोला– तुम्हारा तो स्वांग है, पर हमारा कितना नुकसान हो गया, राजकुमार मर गया! परन्तु अब राजा कर भी क्या सकता था! वह वचनबद्ध था। बहुरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। बाद में उसने कई स्वांग रचे। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए। पिता का, मां का, पुत्र का, भाई का, बहन का, बेटी का, सास का, बहू का, जो भी स्वांग धारण किया है, उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं।

पाठकों के पत्र

मुंबई की सियासत में बदलाव...

कट्टर हिंदुत्ववादी और मराठी अस्मिता के प्रखर प्रतीक बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद जिस शिवसेना की राजनीति बिखराव, टूट और आपसी संघर्ष की मिसाल बन गई थी, वही राजनीति अब एक बार फिर एकता के सूत्र में बंधती दिखाई दे रही है। वर्षों तक एक–दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 'बंटेंगे तो बिखरेंगे' की सोच के साथ आगामी महानगरपालिका चुनाव एक साथ लड़ने का निश्चय कर महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय खोल दिया है। यह फैसला सिर्फ एक चुनावी समझौता नहीं, बल्कि बाला साहेब की विरासत को फिर से जीवित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे के जीवित रहते शिवसेना एक मजबूत कैडर आधारित पार्टी थी, जिसकी जड़ें मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कोने–कोने तक फैली थीं। अब सियासत में बदलाव आया है।

–कांतिलाल मांडोत, सूरत

कल्पमेधा

हम सिर्फ उस व्यक्ति से ईर्ष्या कर सकते हैं, जिसके पास ऐसा कुछ है, जिसे हमारे विचार से हमारे पास होना चाहिए।

– मार्गरेट एटवुड

न्याय की राह

एक ओर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लग पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है, वहीं कानूनी नुक्तों का फायदा उठा कर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के दोषी को भी कई बार रियायत दे दी जाती है। संभव है कि कानून की किसी व्याख्या के मुताबिक, अदालत में बलात्कार के दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति को जमानत का पात्र समझा जाए, लेकिन इससे पीड़ित महिला के लिए न्याय सुनिश्चित किए जाने की प्रक्रिया गंभीर रूप से बाधित होती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा हुई थी। अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के मामले और बच्चे-बच्चियों के यौन शोषण से सुरक्षा के कानून 'पाक्सो' में गंभीर यौन हिंसा के प्रावधानों के मुताबिक सजा दी थी। तब यह घटना देश भर में व्यापक चिंता और आक्रोश का कारण बनी थी। मगर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने का आदेश दे दिया। इस संदर्भ में एक अहम तथ्य यह है कि दोषी सिद्ध होने के बाद निचली अदालत ने साफ कहा था कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा।

जाहिर है, अपराध की गंभीरता और प्रकृति के मद्देनजर निचली अदालत में सेंगर को मिली सजा को कानून के मुताबिक माना जा रहा था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिस आधार पर उस सजा को निलंबित करने का आदेश दिया, वह स्वाभाविक ही विवादों के घेरे में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल, इस घटना के बाद पीड़िता को जिन हालात का सामना करना पड़ा और उसके जीवन तक पर जिस तरह के जोखिम खड़े हुए थे, वे बेहद अप्रत्याशित थे, मगर उससे साफ था कि जघन्य अपराधों के बाद एक ऊंचे राजनीतिक रसूख वाला आरोपी पीड़िता को खामोश करने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस दौरान पीड़िता के पिता की जान चली गई; एक ट्रक ने उस कार को टक्कर मार दी, जिसमें वह परिवार के अन्य लोगों के साथ जा रही थी। उस घटना में पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह घायल हो गए, जबकि उसकी दो मौसियों की मौत हो गई। समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पीड़िता को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा।

अक्सर समूचे देश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर काबू पाने, खासकर बलात्कार के दोषियों के प्रति बेहद सख्त रुख अख्तियार करने और यहां तक कि फांसी की सजा की मांग की जाती है। मगर जब किसी रसूख वाले अपराधी की सजा को लेकर रियायत बरतने की खबर आती है, तब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कानून के काम करने के पैमाने क्या हैं! यह बेवजह नहीं है कि तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद इस अपराध का खौफ व्यापक स्तर पर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। बलात्कार के मामले में सजा होने की बेहद कम दर को लेकर पहले ही चिंता जताई जाती रही है। इसका मुख्य कारण कानून की बारीकियों के आधार पर कई बार वास्तविक दोषियों का बच निकलना रहा है। कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। मगर राजनीति या अन्य क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाले सजायाफ्ता दोषी भी जब कानून से रियायत हासिल कर लेते हैं, तब न्याय की अवधारणा को गहरी चोट लगती है।

शिक्षा की सूरत

देशभर में लाखों बच्चे अगर परीक्षाओं में विफल हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसे गंभीर चुनौती मान लेने भर से इस समस्या का निवारण हो जाएगा? क्या यह जानने का प्रयास नहीं होना चाहिए कि शिक्षा में गुणवत्ता आखिर कहां कम रह गई और इसकी वजह क्या थी? विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो जाहिर है कि पूरी व्यवस्था को अब दुरुस्त करने की जरूरत है। केवल चिंता जता देने और सतही कदम उठा लेने भर से काम नहीं चलेगा। फिलहाल तथ्य यही है कि देश में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में हर वर्ष करीब पचास लाख विद्यार्थी विफल हो रहे हैं। इनमें अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। खासतौर से लड़कियां विद्यालय नहीं लौटतीं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लड़के परिवार का बोझ उठाने के लिए काम करने लग जाते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की नाकामी तो है ही, वहीं शिक्षित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी आघात है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की विफलता बताती है कि विद्यालयी शिक्षा को हम गंभीरता से नहीं ले रहे।

अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे गंभीर चुनौती मानते हुए ऐसे विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है। इसके तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह विद्यार्थियों तक पहुंचे और उन्हें पढ़ाई बीच में न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करे। मगर सच यह है कि पिछले कई वर्षों से शिक्षा के दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव किसी से छिपा नहीं है। कई राज्यों में तो कहीं-कहीं एक या दो शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चलने की खबरें आई हैं। आए दिन शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना से लेकर जनगणना, आधार सत्यापन और चुनावी कार्य में उन्हें उलझाए रखना कोई नई बात नहीं। ऐसे में बच्चों को शिक्षा देने का मूल कार्य प्रायः हाशिये पर चला जाता है। उनका पाठ्यक्रम तक पूरा नहीं होता और वे पढ़ाई में निरंतर पिछड़ते चले जाते हैं। देश में ऐसा परिदृश्य बन रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार इस स्थिति से अनजान नहीं है। उसे इस दिशा में सतही उपाय करने के बजाय ठोस कदम उठाने होंगे।

भारत-रूस संबंधों के नए आयाम

पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति-संतुलन बदल रहा है। ऐसे में भारत-रूस के बीच शीर्ष-स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकेत है कि दोनों देश अपनी सामरिक साझेदारी को नई ऊर्जा देना चाहते हैं।

धीरज यादव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ऐसे समय में हुई, जब वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ समय से दुनिया में शक्ति-संतुलन बदल रहा है और विभिन्न देशों की विदेश नीतियों में नई प्राथमिकताएं आकार ले रही हैं। ऐसे में भारत और रूस के बीच शीर्ष-स्तरीय संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि दोनों देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी सामरिक साझेदारी को नई ऊर्जा देना चाहते हैं। पुतिन की यह यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस यात्रा का महत्त्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि विश्व स्तर पर यूक्रेन युद्ध, रूस और पश्चिम देशों के बीच तनाव, रूस-चीन नजदीकी और अमेरिका की नई व्यापार नीतियां मिलकर एक जटिल भू-राजनीतिक वातावरण बना रही हैं। भारत, जो आज वैश्विक दक्षिण की प्रमुख आवाज बनकर उभरा है, ऐसी स्थिति में अपनी विदेश नीति में परिपक्वता और संतुलन दोनों का परिचय दे रहा है। पुतिन की यात्रा का सार यही रहा कि भारत किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेता है।

भारत और रूस के संबंधों की नींव शीत युद्ध काल में पड़ी थी। वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच ऐसे विश्वास का निर्माण किया, जिसे समय और सत्ता परिवर्तन भी कमजोर नहीं कर सके। रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और विज्ञान-तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने में रूसी वैज्ञानिक सहयोग निर्णायक रहा। रक्षा क्षेत्र में भी द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। भारतीय सेना के लगभग 60-70 फीसद उपकरण किसी न किसी रूप में रूसी तकनीक पर आधारित हैं। एसयू-30 एमकेआइ लड़ाकू विमान, टी-90 टैंक, एस-400 मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाएं इस विश्वास का प्रमाण हैं। यही ऐतिहासिक संबंध आज भी दोनों देशों को एक-दूसरे की सुरक्षा और रणनीतिक प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं।

यूक्रेन युद्ध ने यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की भू-राजनीति को बदल दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर नए सहयोगियों की तलाश के लिए प्रेरित किया। एशिया, विशेषकर भारत और चीन, रूस की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरे। भारत ने यूक्रेन संकट पर शुरुआत से संतुलित रुख अपनाया और न तो युद्ध का समर्थन किया, न ही किसी पक्ष का कठोर विरोध, बल्कि संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। यह नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत-रूस संवाद की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के प्रभाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देता है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने इस अवधि में रूस से व्यापक स्तर पर तेल खरीदा, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को महंगाई और आपूर्ति संकट से बचाने में मदद की।

हाल के वर्षों में रूस-चीन संबंधों में भी काफी प्रगाढ़ता आई है। यह

निकटता पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर इसके भारत पर कई प्रभाव हैं। चीन, भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और रूस का महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि

> **हाल के वर्षों में रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। यह पश्चिमी प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक तनावों का स्वाभाविक परिणाम है, मगर भारत पर इसके प्रभाव को लेकर गौर करना जरूरी है। चीन, भारत का प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और रूस का महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार भी बन गया है। यह स्थिति पहली दृष्टि में भारत के लिए चुनौती बन सकती है, हालांकि इसके भीतर अवसर भी निहित है। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसे को केवल चीन की निकटता कम नहीं कर सकती।**

इसके भीतर अवसर भी निहित है। भारत के लिए रूस सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोगी है। रूस के वैज्ञानिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत के साथ दशकों से बने भरोसे को केवल चीन की निकटता कम नहीं कर सकती। इस जटिल त्रिकोणीय परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त रणनीतिक अवसर हैं, जिनके माध्यम से वह रूस के साथ अपने संबंधों को चीन-रूस समीकरण से अलग दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इसी संतुलनकारी भूमिका ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

अमेरिका की ओर से चीन पर शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखला का पुनर्गठन तेज हो गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत सहित एशिया के अन्य देशों में वैकल्पिक विनिर्माण क्षमता तलाश रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, पर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर चलता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, जबकि रूस इस क्षेत्र में चीन के साथ गहरी साझेदारी चाहता है। इस विरोधाभासी परिदृश्य में भारत की कूटनीति को अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भारत ने अभी तक इस संतुलन को कुशलता से निभाया है और यही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो भविष्य की दिशा संयुक्त उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण के माडल पर आधारित होगी। भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन सकता है। ब्रह्मोस जैसी सफल परियोजनाएं दोनों देशों की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। व्यापार के क्षेत्र में 'नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कारिडोर' भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया से जुड़ने का नया मार्ग खोल सकता है। इसके अलावा, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही बातचीत भविष्य में भारत के व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। वैश्विक व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है। अमेरिका, चीन, रूस और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच शक्ति का पुनर्संतुलन बन रहा है। भारत-रूस संबंध इस व्यापक वैश्विक भूमिका के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

आने वाले वर्षों में भारत और रूस ऊर्जा, रक्षा, उर्वरक, आर्कटिक सहयोग, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अपने सहयोग को नई दिशाओं में विस्तार दे सकते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच तेज आपूर्ति शृंखला विकसित करने में भारत की भूमिका भविष्य में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लिए रूस उर्वरक का एक स्थिर और किफायती स्रोत बना हुआ है, जिसने वैश्विक मूल्य-वृद्धि के दौर में भारतीय किसानों को बड़ी राहत दी है। रूस की ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की भागीदारी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में नई गहराई जोड़ सकती है। साइबर सुरक्षा और नवोन्मेषी डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में रूस की विशेषज्ञता और भारत की तकनीकी क्षमता मिलकर महत्त्वपूर्ण वैश्विक खतरों से निपटने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी संभावनाएं व्यापक हैं, विशेष रूप से गगनयान मिशन और भविष्य की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजनाओं में रूस की भूमिका अहम है। इन सभी आयामों के बीच भारत-रूस संबंधों की स्थिरता इस बात को रेखांकित करती है कि यह साझेदारी केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय होती वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक आवश्यकता है। मौजूदा परिस्थितियां यही संकेत देती हैं कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत, बहुआयामी तथा भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विकसित होगी।

अंतर्मन की यात्रा

मनीषा मंजरी

दुनिया मेरे आगे

हमारा जीवन मात्र बाह्य घटनाओं की शृंखला नहीं, बल्कि यह उससे कहीं अधिक एक आंतरिक यात्रा है। हम एक ऐसी यात्रा पर होते हैं, जो हमारे जन्म के साथ शुरू होती है और अंतिम सांस तक निरंतर चलती रहती है। इस यात्रा का पहला संकेत हम अपने भीतर निहित उस स्वाभाविक आकांक्षा में देखते हैं, जो हमें वर्तमान से आगे, ज्ञात से परे और साधारण से श्रेष्ठ की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। यह आकांक्षा केवल सुविधाओं, उपलब्धियों या मान-सम्मान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके मूल में स्वयं को गहराई से जानने, अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने और आत्म-संतोष की अवस्था तक पहुंचने की मौन चाह छिपी होती है।

हम दरअसल परिस्थितियों से कहीं अधिक खुद को बदलना चाहते हैं। हम जीवन से केवल उत्तर नहीं, बल्कि स्पष्टता चाहते हैं। यही कारण है कि हर युग, हर समाज और हर संस्कृति में मनुष्य ने दर्शन, कला और अध्यात्म के माध्यम से अपने भीतर झांकने का प्रयास किया है। यह आंतरिक पुकार हमें बार-बार यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया भी है। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे-जैसे जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, वैसे-वैसे यह आंतरिक ऊर्जा अक्सर विस्तार के स्थान पर संकुचन का रूप ले लेती है। हमारा मन जो कभी निर्भीक होकर संभावनाओं की ओर दौड़ता था, वही मन धीरे-धीरे अपने ही अनुभवों के बोझ तले दबने लगता है। असफलताएं, ठोकरें और टूटे हुए सपने मन में एक अदृश्य भय का निर्माण करते हैं। यह भय बाहर से नहीं आता, बल्कि यह हमारे मन के भीतर ही भीतर आकार लेता है।

> **एक मुक्त और ग्रहणशील मन ही जीवन को स्पष्टता के साथ देख सकता है। जब मन खुला होता है, तब वह स्वयं को निरंतर विकसित होने की अनुमति देता है। वह यह स्वीकार करता है कि अपूर्णता कोई दोष नहीं, बल्कि मानव होने का स्वभाव है। यही स्वीकार हमें स्वयं के प्रति करुणामय बनाता है।**

जीवन के प्रारंभिक चरण में हमारा दृष्टिकोण सहज और विश्वास से भरा होता है। तब जीवन एक खुला मैदान प्रतीत होता है, जहां गिरना भी खेल का हिस्सा है। असफलता उस समय आत्म-संदेह नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम होती है। बाल्यावस्था और युवावस्था में मन भविष्य की संभावनाओं से इतना आच्छादित रहता है कि जोखिम भी रोमांच लगने लगता है। तब मन यह नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा, बल्कि यह महसूस करता है कि प्रयास स्वयं में कितना मूल्यवान है। पर समय के साथ जीवन दायित्वों की सीढ़ियां चढ़ाने लगता है। परिवार, सामाजिक अपेक्षाएं, आर्थिक सुरक्षा और स्वयं से जुड़ी जिम्मेदारियां मन को धीरे-धीरे बांध देती हैं। अनुभव, जो विवेक का आधार बनने चाहिए थे, कई बार भय का कारण बन जाते हैं। मन अतीत की स्मृतियों में उलझकर वर्तमान को खोने लगता है।

बार-बार की असफलताएं केवल घटनाएं नहीं रह जातीं, बल्कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अनुभव का उद्देश्य हमें सीमित करना नहीं, बल्कि समझदार बनाना है। इस बिंदु पर मन सृजनात्मकता से हटकर सुरक्षा की ओर झुकने लगता है। वह संभावनाओं की जगह संभावित हानि की बातें करता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। अतीत पछतावे का भार बन जाता है और भविष्य भय का। इस मानसिक युद्ध में वर्तमान, जो वास्तव में जीवन का एकमात्र वास्तविक क्षण है, वह हमारे हाथों से फिसल जाता है। हम कुछ नया आरंभ करने से पहले ही मानसिक रूप से थक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन पहले ही हार की कल्पना कर चुका होता है। यह स्थिति एक गहरे दार्शनिक प्रश्न को जन्म देती है- क्या अनुभव का अर्थ भयभीत हो जाना है? क्या परिपक्वता का तात्पर्य यह है कि हम जीवन से दूरी बना लें? अगर अनुभव हमें संकुचित कर दे, तो वह ज्ञान नहीं, केवल आत्म-संरक्षण की प्रवृत्ति बनकर रह जाता है।

जीवन हमसे पूर्ण होने की नहीं, खुला होने की अपेक्षा करता है। यह सत्य जितना सरल है, उतना ही गहन भी। पूर्णता का आग्रह मन को कठोर बना देता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहीं खुलापन मन को लचीला बनाता है, जहां सीखने, बदलने और फिर आरंभ करने की संभावना बनी रहती है। जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है, जिसे नियंत्रित करने का प्रयास हमें तनाव देता है।

एक मुक्त और ग्रहणशील मन ही जीवन को स्पष्टता के साथ देख सकता है। जब मन खुला होता है, तब वह स्वयं को निरंतर विकसित होने की अनुमति देता है। वह यह स्वीकार करता है कि अपूर्णता कोई दोष नहीं, बल्कि मानव होने का स्वभाव है। यही स्वीकार हमें स्वयं के प्रति करुणामय बनाता है। और जब हम स्वयं के प्रति करुणामय होते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति भी संवेदनशील हो पाते हैं। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें ठहराव, भटकाव और पुनः दिशा पाना, ये तीनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। इस यात्रा में लिया गया हर छोटा निर्णय, हर ईमानदार प्रयास और हर साहसिक स्वीकार जीवन की दिशा बदल सकता है। खुलापन हमें यह भी सिखाता है कि असफलता हमारे अस्तित्व का मापदंड नहीं है। वह केवल एक अनुभव है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है, तब भय का स्थान जिज्ञासा ले लेती है। तब मन जीवन से पूछता है कि इस अनुभव में मेरे लिए क्या छिपा है।

हमारी वास्तविक उन्नति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है। वह स्वतंत्रता जो भय से परे जाकर अनुभव करने का साहस देती है। वह स्वतंत्रता जो यह स्वीकार करती है कि रुकना भी यात्रा का हिस्सा है और फिर शुरू करना कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना का प्रमाण है। जब मन मुक्त होता है, तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वह एक सतत् संवाद बन जाता है। और उसी संवाद में मनुष्य धीरे-धीरे स्वयं को, अपने उद्देश्य को और उस मौन और शाश्वत सत्य को समझने लगता है, जो उसे हर क्षण आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता रहता है।

जागरूकता के मायने

हमारे देश में सरकारें लोगों को बाजार की धोखाधड़ी से बचाने के लिए कायदे-कानून और इसके प्रति जागरूक करने के लिए कई प्रयास करती हैं। मगर यह प्रयास तब तक निरर्थक है, जब तक लोग इसके प्रति गंभीर नहीं होते। बिना बिल के कोई सामान लेना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ लोग थोड़े से पैसे बचाने के फेर में बिल लेने से परहेज करते हैं। बिना बिल के तो खराब सामान की शिकायत करना भी मुश्किल है। सरकार को नौकरी देने संबंधी भ्रामक विज्ञापनों और आनलाइन बाजार के लिए भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि इनका कोई शिकार न हो सके। अगर गलत और मिलावटी खानपान से हमारी सेहत खराब होगी, तो इससे परेशानी और आर्थिक नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए खानपान की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमें शासन का मुंह नहीं ताकना चाहिए, बल्कि खुद ही जागरूक होकर इसके लिए अपने स्तर पर उपाय करने चाहिए। एक तरफ तो भारत को स्वस्थ बनाने का सपना देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसे बनेगा स्वच्छ भारत?

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

बुजुर्गों को वरीयता

वरिष्ठ नागरिक कार्ड योजना बुजुर्गों के लिए सार्थक पहल है। हालांकि, इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए कुछ सुविधाओं का इसमें समावेश आवश्यक है। वर्तमान में, इस कार्ड से रेल यात्रा में कोई रियायत, तत्काल टिकट की सुविधा या दो माह पहले टिकट बुकिंग में वरीयता नहीं मिलती। इन सेवाओं को कार्ड की विशेषताओं में शामिल करने से बुजुर्गों की यात्रा को सुगम और सस्ता बनाएगा। साथ ही, आयकर नियमों में भी एक बदलाव की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य आयु सीमा को बढ़ा कर 65 वर्ष किया जाना चाहिए। इससे इस आयु के बाद उन्हें नियमित रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता नहीं रहेगी। इन सुधारों से न केवल वरिष्ठ जनों का जीवन आसान होगा, बल्कि यह समाज के प्रति उनके सम्मान और देखभाल का एक सार्थक प्रयास भी साबित होगा। बुजुर्गों का जीवन सहज बनने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए।

– भगवानदास छारिया, इंदौर

पीढ़ियों की फिक्र

प्रदूषण, टूटी हुई सड़कें, गलियों में फैली गंदगी, भरी हुई नालियां, सड़कों पर लंबा जाम, आज यह दिल्ली की तस्वीर है। जिन लोगों को इस शहर की ओर ध्यान देना चाहिए, वे सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कर कुछ भी नहीं रहे। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। प्रदूषण से बचने के लिए कभी कहते हैं कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, कभी पराली जलाने से मना किया जाता है, तो कभी लालबत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करने की बातें होती हैं। सम-विषम की अब बात नहीं होती। पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ खानापूर्ति है। ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे हालात और खराब होते जा रहे हैं। लोग भी सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं, यातायात नियमों को तोड़ने में भी शेखी समझते हैं। दीपावली पर चेतावनी देने के बावजूद करोड़ों रुपए के पटाखे चलाते हैं। आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या हाल कर दिया इस शहर का।

– चरनजीत, नरेला, दिल्ली

राजस्व के बहाने

'महंगा सफर' (संपादकीय, 23 दिसंबर) पढ़ा। जब से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है, तब से यात्री सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही है। ऐसा लगता है कि औपचारिक परंपराएं समाप्त हो गई हैं। एक दशक पहले रेलवे का वार्षिक बजट जब संसद में पेश किया जाता था, तो उसी में ही यात्री किराए तथा मालभाड़े में वृद्धि आदि की घोषणा के साथ ही परिचालन प्रणालियों के रखरखाव के लिए उपकरण आदि पर खर्च के लिए बजट में प्रावधान किया जाता था। मगर अब तो सरकार जब चाहे अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर देती है। रेल भाड़े में वृद्धि तथा तय सीमा से अधिक वजन ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क की घोषणा को किस नजरिए से देखा जाएगा। सरकार को यह तो ध्यान में रखना चाहिए था कि लोगों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

शाह टाइम्स

सम्पादकीय

शुक्रवार, 26 दिसम्बर 2025

बांग्लादेश में नई सुबह

बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। उनके लौटने पर बांग्लादेश में एक नई सुबह की सुगबुगाहट दिखी है। ढाका में लाखों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक फरवरी चुनाव में पीएम पद के बड़े दावेदार हैं। बदले राजनीतिक हालात में उनकी वापसी अहम मानी जा रही है, ढाका में सुरक्षा कड़ी है। वह 17 साल से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होंगे, जिसमें पीएम का निर्वाचन होगा। यहां शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया है। जिसके कारण अब मुकाबला केवल युनूस की पार्टी और खालिदा जिया की पार्टी के बीच तय है। जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनी है, तब से वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। अल्पसंख्यक डर के बीच जीवन जी रहे हैं।अगर खालिदा जिया के बेटे पीएम बनते हैं, तो इस पर रोक संभव है। भारत भी तारिक हसन के लौटने को सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। क्योंकि अगर पड़ौस में शांति रहती है, तो अपना देश भी शांत रहता है। बांग्लादेश व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो भारत के पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश आवश्यक है। आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा सुरक्षा और अन्य सुरक्षा मामलों पर सहयोग दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह आर्थिक संबंध भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्धारित लक्ष्यों का समर्थन करता है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उसके उद्देश्य में योगदान देता है। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण है। उनके पिता जियाउर रहमान देश के पहले सेना प्रमुख थे। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की थी और 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। 1981 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तारिक रहमान की वापसी ऐसे समय हो रही है, जब अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। बदले राजनीतिक हालात में बीएनपी देश की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। पहले बीएनपी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी और उसके इस्लामी सहयोगी अब उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगाया हुआ है।

इमिग्रेशन व्यवस्था संभालना सरकारी जिम्मेदारी

देश की सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को ठीक से संभालना सरकार की जिम्मेदारी है, अगर भारत में घुसपैठ हो रही है या लोग वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहे हैं, तो यह सिस्टम की नाकामी और बॉर्डर व इमिग्रेशन कंट्रोल में कमियों को दिखाता है, सरकार के पास गैरकानूनी तरीके से रहने वालों को कानून के तहत बाहर निकालने का पूरा अधिकार है, अगर लोग अवैध तरीके से देश में घुस रहे हैं, तो क्या यह हमारी नाकामी नहीं है, इसलिए सरकार को बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, सरकार के पास नियम तोड़ने वालों के पर एक्शन लेने का पूरा हक है , कानून का पालन जरूरी है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने देने का फैसला इंसानी सोच दिखाता है।

-शशि थरूर, कांग्रेस सांसद

दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण और बेबस सरकारी तंत्र

रजनीश कपूर

हर साल की तरह दिल्ली.एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। दिसंबर 2025 में एक बार फिर AQI बहुत खराब से गंभीर और सीवियर प्लस श्रेणी तक पहुंचा, जिसने सरकार की नीतियों, इच्छाशक्ति और क्षमता तीनों पर कठोर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़े दिखाते हैं कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में दिल्ली का औसत AQI लगातार बहुत खराब (259-372) के बीच रहा। 13-14 दिसम्बर को कई इलाकों में AQI 450 से ऊपर चला गया, जिससे हवा सीवियर और कुछ घंटों के लिए सीवियर प्लस श्रेणी में दर्ज हुई। वहीं सरकार यह तर्क दे रही है कि 2016 की तुलना में बेहतर रुझान दिख रहे हैं और औसत AQI कुछ घटा है, लेकिन नागरिक के फेफड़ों के लिए यह सांख्यिकी नहीं, सांस की लड़ाई है। कागज पर सरकार ने कड़े कदमों का एक पूरा ढांचा बनाया है, लेकिन जमीनी असर सीमित है। यह वही कहानी है, जिसमें जिम्मेदारी सबकी है और जवाबदेही किसी की नहीं। ग्रेप की पाबंदी GRAP, स्मॉग टावर, एंटी-स्मॉग गन, पानी का छिड़काव, निर्माण पर रोक, स्कूलों की छुट्टियां, डीजल गाड़ियों पर पाबंदी जैसे आपात उपाय हर साल दोहराए जा रहे हैं, पर हवा हर सर्दी में उतनी ही घुटन भरी रहती है। केंद्र और राज्य सरकारें पराली, उद्योगों, थर्मल पावर, डीजल जेनरेटर, निर्माण धूल और वाहनों की भूमिका पर एक-दूसरे को कटघरे में खड़ा करती हैं पर दीर्घकालिक समाधान जैसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज संक्रमण, सार्वजनिक परिवहन का आक्रामक विस्तार और इंडस्ट्रियल क्लस्टर का सख्त नियमन धीमी रफ्तार में चलते हैं। यह बेबसी महज संसाधन समस्या नहीं, राजनीतिक प्राथमिकताओं की भी कहानी है। चुनावी बहस में प्रदूषण अभी भी हाशिए का मुद्दा है। इसलिए आपातकालीन प्रेस कांफ्रेंस तो दिखती हैं, लेकिन संरचनात्मक सुधारों का साहस नदारद है। दिल्ली-एनसीआर की हवा की कहानी अरावली की पहाड़ियों और जंगलों से कटकर नहीं देखी जा सकती। अरावली दिल्ली. एनसीआर के लिए प्राकृतिक फेफड़े और धूल-तूफानों के खिलाफ ढाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में केंद्र सरकार की ऊंचाई.आधारित परिभाषा को स्वीकार करते हुए अरावली हिल्स और रेंज की नई परिभाषा तय की है और साथ ही एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार होने तक नई खनन लीज पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कोर इनवायलेट और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इलाकों में खनन पर सख्त पाबंदियां रहेंगी और सिर्फ वैज्ञानिक रूप से उचित अपवादों में ही सीमित खनन की इजाजत दी जा सकेगी। यहीं से भ्रम और चिंता दोनों शुरू होते हैं। विशेषज्ञों का तर्क है कि ऊंचाई-आधारित परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा, जो भूगर्भीय और पारिस्थितिक दृष्टि से पहाड़ी तंत्र का भाग है, कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और रियल एस्टेट के लिए दरवाजा खुलने का खतरा है। अगर अरावली के निम्न क्षेत्र और वनांचल में खनन या निर्माण बढ़ता है तो यह न सिर्फ धूल और पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ाएगा, बल्कि उन प्राकृतिक वायु-मार्गों को भी बाधित करेगा जो राजस्थान की ओर से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकते और फिल्टर करते हैं। सरकार जहां सस्टेनेबल माइनिंग और रोजगार. विकास की दलील दे रही है, वहीं पर्यावरणविद इसे दिल्ली-एनसीआर के दीर्घकालिक वायु-सुरक्षा के खिलाफ एक खतरनाक झरोखा मान रहे हैं।

हर साल सर्दियां आते ही दिल्ली-एनसीआर गैस-चैंबर क्यों बन जाता है? इस पर वैज्ञानिक सहमति अब काफी स्पष्ट है, यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि कई कारकों का संयुक्त परिणाम है।सर्दियों में टेम्परेचर इनवर्जन यानी ऊपर गरम और नीचे ठंडी हवा की परत बनती है, जो जमीन के पास प्रदूषकों के ऊपर ढक्कन की तरह जम जाती है। न हवा ऊपर उठती है, न जहरीले कण बिखर पाते हैं। हवा की रफ्तार कम, नमी ज्यादा, बारिश नगण्य यह सभी मिलकर दिल्ली को एक ऐसी घाटी जैसा बना देते हैं जहां प्रदूषण स्टोर होता रहता है और सर्दी उसे लॉक कर देती है। उत्सर्जन के स्रोत भी बहुस्तरीय हैं और यही नीति-निर्माताओं की सबसे बड़ी परीक्षा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में पराली जलाना अक्टूबर-नवम्बर में प्रदूषण के स्पाइक को तेज करता है, कभी-कभी दिल्ली के PM2.5 में 30-40 फीसदी तक योगदान देता है, लेकिन पूरे सीजन की हवा सिर्फ पराली से खराब नहीं रहती। वाहनों का धुआं, कोयला-आधारित बिजली घर, औद्योगिक इकाइयां, ईंट-भट्टे, ठोस कचरा जलाना, निर्माण-धूल और दिल्ली-एनसीआर के भीतर की डीजल-निर्भर अर्थव्यवस्था मिलकर साल भर का बेसलाइन प्रदूषण बनाती है, जो सर्दियों में मौसम की वजह से खतरनाक स्तर पर दिखाई देता है। क्लाइमेट वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि दिल्ली का संकट एपिसोडिक नहीं, स्ट्रक्चरल है यानी यह सिर्फ पराली या कुछ हफ्तों तक चलने वाली ठंड का नहीं, बल्कि एक गलत तरीके से बढ़े हुए शहरी-औद्योगिक मॉडल का परिणाम है। दिल्ली-एनसीआर की ताजा AQI स्थिति यह संकेत देती है कि अब फायर-फाइटिंग नहीं, सिस्टम-रीडिजाइन की जरूरत है। प्रदूषण-पॉलिटिक्स का रुख अभी तक आरोप-प्रत्यारोप पर अटका हुआ है केंद्र बनाम राज्य, पंजाब-हरियाणा बनाम दिल्ली, पर्यावरण मंत्रालय बनाम परिवहन-उद्योग लॉबी और इस बीच नागरिक का फेफड़ा सबसे कमजोर और सबसे अकेला पक्ष बना हुआ है। अरावली की परिभाषा से लेकर खनन नीति, पराली प्रबंधन से लेकर सार्वजनिक परिवहन, एनर्जी ट्रांजिशन से लेकर शहरी नियोजन सभी मोर्चों पर ऐसे फैसलों की जरूरत है जो GDP नहीं, जन-स्वास्थ्य को प्राथमिक सूचक बनाएं। अगर अरावली को कागज पर सिकोड़ दिया गया, अगर सस्टेनेबल माइनिंग के नाम पर पहाड़ियों की आखिरी हरियाली भी कंक्रीट और खदानों के हवाले कर दी गई, तो दिल्ली एनसीआर की सर्दियां सिर्फ ठंडी नहीं, और भी ज्यादा घुटन भरी, बीमार और अमानवीय हो जाएंगी। क्या सरकारें हवा को भी जगह की राजनीति और फेडरल झगड़े के बीच बांटती रहेंगी या वह दिन आएगा जब दिल्ली एनसीआर की सांस को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा, जितनी स्टॉक मार्केट के सूचकांकों को दी जाती है? जवाब अभी धुंध में छिपा है ठीक उसी तरह, जैसे हर सर्दी दिल्ली का आसमान।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

शुक्र ग्रह से पानी शायद तेजी से गायब हुआ!

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों वर्ष पूर्व शुक्र ग्रह पर महासागर रहे होंगे, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि और जोरदार ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण संभवतः अधिकांश पानी वाष्पित हो गया होगा। लेकिन शेष बचे थोड़े से पानी (अंतिम लगभग १०० मीटर की परत) के खत्म होने की व्याख्या नहीं कर सके हैं। इस नए अध्ययन में एक नई प्रक्रिया - HCO+ क्रियाविधि पर चर्चा की गई है जो शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में चलती है। इसमें सूर्य का प्रकाश न सिर्फ पानी के अणुओं को बल्कि कार्बन डाईऑक्साइड को भी तोड़ देता है। कार्बन डाईऑक्साइड के टूटने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप HCO+ नामक एक अस्थिर आयन का निर्माण होता है। यह आयन तत्काल विघटित हो जाता है।

हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र की सतह का आजकल का तापमान सीसे को भी पिघला सकता है लेकिन अध्ययन बताते हैं कि किसी समय यहां समुद्र लहराते रहे होंगे और वातावरण जीवन के अनुक. ूल रहा होगा। तो सारा पानी गया कहां? यह एक मुश्किल सवाल रहा है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित हालिया अध्ययन ने पानी के ह्रास की एक ऐसी क्रियाविधि को उजागर किया है जो शुक्र के वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर काम करती है और दुगनी रफ्तार से पानी के ह्रास के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसका यह भी मतलब है कि शुक्र ज्यादा हाल तक जलीय व जीवनक्षम रहा होगा। दूरबीनों व अंतरिक्ष यानों से प्राप्त आंकड़े शुक्र के वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति दर्शा चुके थे। 1970 के दशक में पायोनीयर वीनस ऑर्बाइटर से शुक्र पर अतीत में समुद्र की उपस्थिति के संकेत मिले थेय वहां के वायुमंडल में हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक (ड्यूटीरियम) की उपस्थिति। आगे चलकर किए गए मॉडलिंग से अनुमान लगाया गया था कि किसी समय शुक्र पर इतना पानी थी कि उसकी पूरी सतह पर 3 किलोमीटर गहरी पानी की परत रही होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों वर्ष पूर्व शुक्र ग्रह पर महासागर रहे होंगे, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि और जोरदार ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण संभवतः अधिकांश पानी वाष्पित हो गया होगा। लेकिन शेष बचे थोड़े से पानी (अंतिम लगभग 100 मीटर की परत) के खत्म होने की व्याख्या नहीं कर सके हैं। इस नए अध्ययन में एक नई प्रक्रिया - HCO+ क्रियाविधि पर चर्चा की गई है जो शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में चलती है। इसमें सूर्य का प्रकाश न सिर्फ पानी के अणुओं को बल्कि कार्बन डाईऑक्साइड को भी तोड़ देता है। कार्बन डाईऑक्साइड के टूटने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप HCO+ नामक एक अस्थिर आयन का निर्माण होता है। यह आयन तत्काल विघटित हो जाता है। चूंकि हाइड्रोजन अत्यंत हल्की होती है, वह वायुमंडल से पलायन कर जाती है। यह प्रक्रिया शुक्र के वायुमंडल से रहे-सहे पानी को खत्म करने के अवसर प्रदान करती है। इस नए पहचानी गई प्रक्रिया को पहले से ज्ञात प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर शोधकर्ताओं का सुझाव है कि शुक्र का पूरा पानी उड़ने में केवल 60 करोड़ वर्ष लगे होंगे। यह अवधि पूर्व अनुमान से आधी है। इसका तात्पर्य यह है कि शुक्र पर, आज की दुर्गम दुनिया बनने से पहले, संभवतः 2 से 3 अरब साल पहले तक महा. सागर रहे होंगे। शुक्र के विकास को समझना न केवल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को जानने बल्कि सुदूर चट्टानी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। शुक्र और पृथ्वी के बीच समानताएं इस बात की जांच के महत्व पर प्रकाश डालती हैं कि समान संघटन वाले ग्रह किस तरह अलग-अलग तरीके से विकसित हो सकते हैं। शुक्र के इतिहास से प्राप्त जानकारी ब्रह्मांड में अन्यत्र जीवन योग्य वातावरण की पहचान करने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है। एक अनुमान है कि

शुक्र के समान मंगल से पानी के ह्रास में भी इस प्रक्रिया की भूमिका रही हो सकती है। हालांकि, निकट भविष्य में कोई मिशन प्रत्यक्ष रूप से शुक्र पर HCO+ प्रक्रिया की खोजबीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र की वायुमंडलीय गतिशीलता को समझना जारी है। जल्दी ही कोई उपकरण ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन के ह्रास की जांच के लिए सामने आ जाएगा। तब भविष्य के मिशन शुक्र पर पानी की उपस्थिति और ग्रह विज्ञान के व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर अधिक जानकारी एकत्रित कर पाएंगे।

-स्रोत फीचर्स

छोटे साहिबजादों ने हंसते-हंसते दी जान पर नहीं त्यागा ईमान

योगेश कुमार गोयल

26 दिसम्बर को गुरु गोबिंद सिंह जी के चार छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इन वीर बालकों ने छोटी उम्र में ही अपने धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। वीर बाल दिवस वही दिन है, जब साहिबजादों 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 6 वर्षीय फतेह सिंह को मुगलों द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबजादों ने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपना बलिदान कर अपनी वीरता और अपने आदर्शों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं।

गुरु गोबिंद सिंह और उनका पूरा परिवार सिख धर्म का प्रतीक था, जिनका एक ही प्रण था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे और मुगलों के खिलाफ एकता से लड़ेंगे। इसीलिए मुगलों द्वारा उनके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक कष्ट दिए गए। उनके दो बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह को उनके सामने ही मार डाला गया और दो छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म छोड़कर मुगल बनना कभी स्वीकार नहीं किया। मुगल सेना द्वारा अचानक आक्रमण किए जाने पर गुरु गोबिंद सिंह को पूरे परिवार के साथ 20 दिसम्बर 1704 को कड़कड़ाती ठंड में आनंदपुर साहिब किला छोड़ना पड़ा था। किले को छोड़कर जब वे सरसा नदी को पार कर रहे थे तो नदी में पानी के तेज

बहाव के कारण उनके परिवार के सदस्य एक-दूसरे से बिछुड़ गए। उनके दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह उनके साथ चमकौर पहुंच गए जबकि माता गुजरी तथा दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए, जिनके साथ गुरु गोबिंद सिंह का निजी सेवक गंगू था। गंगू माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को उनके परिवार से मिलाने का भरोसा देकर अपने गांव सहेड़ी ले गया और चंद सोने की मोहरों के लालच में इसकी खबर सरहिंद के नवाब वजीर खान को कर दी, जिसके बाद माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया।

साहिबजादों को वजीर खान के समक्ष पेश किया गया तो उसने उन्हें सिर झुकाकर खड़ा होने और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा लेकिन इतने छोटे होकर भी दोनों ने सिर झुकाने और इस्लाम धर्म अपनाने से इन्कार करते हुए कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के समक्ष सिर नहीं झुकाते। वजीर खां ने दोनों बच्चों को काफी ललचाया, डराया, धमकाया लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिरकार क्रूर वजीर खान ने दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दे डाला। जब उन्हें दीवार में चुना जाने लगा तो दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे। 26 दिसम्बर 1705 को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और इस प्रकार दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म की खातिर हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोनों इतने वीर थे कि दीवार पूरी बन जाने के बाद भी अंदर से इनके जयकारा लगाने की आवाजें आती रही।

कहा जाता है कि माता गुजरी को भी सरहिंद के किले से धक्का देकर मार डाला गया था। गुरु गोबिंद सिंह को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी माता और छोटे साहिबजादों की शहादत से दुखी होने और मुगलों के अत्याचारों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय औरंगजेब को एक जफरनामा द्धविजय पत्रऋ लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को स्पष्ट चेतावनी दी कि तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है।

गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े बेटे थे अजीत सिंह, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में केवल 17 साल की आयु में ही मुगल फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। तीर खत्म होने पर उन्होंने तलवार निकालकर दुश्मनों से युद्ध किया लेकिन युद्ध के दौरान तलवार टूट जाने पर वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद गुरु जी के दूसरे बेटे जुझार सिंह ने रणभूमि में मोर्चा संभाला और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। खेलने-कूदने की छोटी सी उम्र में गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान आज की युवा पीढ़ी को अपने देश और धर्म से प्रेम करने और इनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहने का संदेश देता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

You will Get access to these 3 channels in just 19 rupees

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times

And more Newspapers

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International

[Genaral & Exam related]

Click here to join

📍You will be given lifetime Validity📍

No Monthly subscription

अरावली को जीवनदान

अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास भारत से भी पुराना है। अरावली पर्वत तब बने थे जब गंगा नदी नहीं थी। हिमालय नहीं था। महाद्वीप आपस में जुड़ रहे थे। जीवन की उत्पत्ति की शुरूआत हो रही थी। 250 करोड़ साल पुरानी और 670 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला एक भौगोलिक चमत्कार है। यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। यह दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। यह राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में है। यह भारत की प्राकृतिक हरी दीवार है। जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। बिना अरावली के हरियाणा और दिल्ली भी रेगिस्तान होते। यह मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है और वर्षा बढ़ाती है। अरावली कई नदियों का स्रोत है। यह जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का पानी चट्टानों से रिसता है और भूजल बनता है। यह एक तरह से प्राकृतिक स्पांज जैसा है जो बारिश का पानी नीचे जमीन में भेजता है। यह एक इकोलोजिकल हॉटस्पॉट है जो 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों को संरक्षण देता है और वनस्पति का संरक्षक है। इतिहास की बात करें तो अरावली पर्वत माला को राजपूतों की ढाल और मुगलों के लिए काल कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए सुरक्षित स्थान दिया था। कुंभलगढ़ और चित्तौढ़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोम में विकास बनाम प्राकृति के संरक्षण को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। जिस देश में पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हों उस समाज में प्राकृति के संरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। सन् 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अंतत: राजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था और बिश्नोई गांव के आसपास के पेड़ों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था।

देशभर में जागरूक समाज और पर्यावरणविदों ने पहाड़ बचाने के लिए आवाज बुलंद की क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर प्राकृतिक का बेलगाम दोहन जारी रहा तो जीवन नहीं बचेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा। अरावली की नई परिभाषा को लेकर बहुत सारी आशंकाओं ने जन्म ले लिया कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन निर्माण और अन्य गतिविधियां जारी रहीं तो इसके गम्भीर पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। लोग सड़कों पर उतरने लगे। सोशल मीडिया पर अरावली बचाओ अभियान ट्रेंड करने लगे। इसके बाद केन्द्र सरकार ने भी पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करते हुए और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर हंटर चला दिया। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा। पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद खनन माफिया के नए खेल की कोई संभावना नहीं बची है। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, मंत्रालय ने 'इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन' को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन' को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आईसीएफआरई एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' (एमपीएसएम) तैयार करेगा। इस प्लान में यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुक्सान हो। सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है।

> **देशभर में जागरूक समाज और पर्यावरणविदों ने पहाड़ बचाने के लिए आवाज बुलंद की क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर प्राकृतिक का बेलगाम दोहन जारी रहा तो जीवन नहीं बचेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा। अरावली की नई परिभाषा को लेकर बहुत सारी आशंकाओं ने जन्म ले लिया कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन निर्माण और अन्य गतिविधियां जारी रहीं तो इसके गम्भीर पर्यावरणीय प्रभाव होंगे।**

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी 100 मीटर के नियम पर फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि जब तक नई खनन योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के खिलाफ हरियाणा के रिटायर्ड वन संरक्षक आर.पी. बलवान की याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला पुराने टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा है, जिसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 'वन' की व्यापक परिभाषा दी थी। नवंबर 2025 में कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को मानते हुए अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की थी इसके तहत स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, साथ ही उनकी ढलान और आसपास की जमीन भी इसी दायरे में आएगी लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी जिससे पर्यावरण को बड़ा नुक्सान होगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अरावली की सही परिभाषा क्या हो पिछले कुछ दशकों से अवैध खनन माफिया और न्यू माफिया ने पहाड़ों को निगल लिया है और वहां कंक्रीट की कालोनियां खड़ी कर दी हैं। एक बार खनन का दरवाजा खुला तो अवैध खनन माफिया फिर सक्रिय हो जाएगा।

बेटियों को बनाएं महफूज

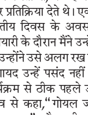

गीता पाढा

"कैसे हम बेटियां समाज में खुद को महफूज पाएं,
जब बलात्कार के दोषी सजा से बचने के नए नए हथकंडे अपनाए,,
कानूनी दांव-पेंच जब अपराधी के बचाव के लिए हथियार बन जाएं,
तब-तब न्याय का मंदिर खुद को शर्मिंदा पाएं,,
सड़कों से लेकर संसद तक केवल कोलाहल नजर आएं,
और देश की आधी से ज्यादा आबादी एक सुर में समता और स्वतंत्रता की गुहार लगाएं...।।"

प्रियंका का डंका

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

'**पिछले** सप्ताह समाप्त हुआ तीन सप्ताह का संसद सत्र अनुमान के अनुरूप ही रहा: हंगामा, तीखी नोकझोंक, बार-बार व्यवधान और अंतत: स्थगन। आज के दौर में संसदीय कार्यवाही की यह स्थिति लगभग स्थायी हो चुकी है। सत्र के दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष आमने-सामने रहे। विपक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार का कहना था कि यह विषय भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए सरकार के दायरे से बाहर है।

लंबे गतिरोध के बाद मामला तब सुलझा जब, विपक्ष के शब्दों में, सरकार ने एसआईआर पर चर्चा की मांग "मान ली", हालांकि कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त यह थी कि चर्चा एसआईआर के नाम से नहीं, बल्कि 'चुनाव सुधारों' के अंतर्गत होगी। दूसरी यह कि इस बहस से पहले वंदे मातरम् पर चर्चा कराई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन वंदे मातरम् पर होने वाली बहस से पहले इसे रखना उचित नहीं होगा।

इस बहस की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने तुष्टिकरण की राजनीति के दबाव में राष्ट्रीय गीत को "विभाजित करने" पर सहमति जताई। नेहरू को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर वंदे मातरम् के उन अंतरों को हटाया जिनमें देवी की वंदना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे भी आगे बढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू को सीधे तौर पर राष्ट्रीय गीत को केवल दो अंतरों तक सीमित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसे तुष्टिकरण की नीति (जिसे उन्होंने "तुष्टिकरण की नीति" कहा) का परिणाम बताया। बिना किसी लाग-लपेट के अमित शाह ने कहा कि यदि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वंदे मातरम् को विभाजित न किया होता तो देश का विभाजन नहीं हुआ होता।

विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा वंदे मातरम् को केंद्र में इसलिए ला रही है ताकि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ साधा जा सके। हालांकि सत्तापक्ष ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बहस के समय और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, जब युवाओं में वास्तविक बेरोजगारी 20 प्रतिशत से अधिक है, जब दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 के पार पहुंच चुका है और लोग दम घुटने की स्थिति में हैं, जब भाजपा विपक्ष शासित राज्यों को मनरेगा के धन से वंचित कर रही है और जब सत्र दर सत्र विपक्षी सदस्यों को डराया-धमकाया जाता है तथा राष्ट्रीय मुद्दे उठाने से रोका जाता है, तब इस तरह की बहस कराई जा रही है। उन्होंने वंदे मातरम् को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाते हुए इसे "खराब ढंग से लिखी गई एक कॉमेडी" करार दिया। इसके बावजूद जो भाषण सबसे अधिक चर्चा में रहा, वह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का था।

अपने तीखे और आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी ने नेहरू पर सत्तापक्ष के लगातार हमलों को लेकर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ किए जाने वाले आरोपों और अपमानों की एक सूची बना लें। उन्होंने कहा, चाहे वह संख्या 999 हो या 9,999 एक सूची तैयार कर लीजिए और फिर समय तय कर लीजिए। जैसे वंदे मातरम् पर दस घंटे बहस हो रही है, वैसे ही इस पर भी जितनी देर चाहें, बहस कर लीजिए लेकिन संसद के इस बहुमूल्य समय का उपयोग उस काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए जनता ने प्रतिनिधियों को चुना है। एक बार और हमेशा के लिए इस अध्याय को बंद कर देना चाहिए, यह कहते हुए उन्होंने विपक्षी बेंचों की जोरदार तालियां बटोरीं।

उन्होंने आगे कहा, "देश ये सारी शिकायतें सुन लेगा, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, वंशवाद की राजनीति क्या है, नेहरू की क्या गलतियां रहीं-इन सब पर बात कर लेते हैं और यहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा कर लेंगे लेकिन जो भाषण वास्तव में वायरल हुआ, वह प्रियंका गांधी का था, विषयवस्तु और प्रस्तुति, दोनों के लिहाज़ से। भाषण की सामग्री सशक्त, प्रासंगिक और नपी-तुली थी लेकिन सबसे अधिक सराहना उनकी प्रस्तुति ने बटोरी। प्रियंका गांधी का आकर्षक व्यक्तित्व सर्वविदित है। संसद में उन्होंने अपने व्यवहार और शैली से एक अलग पहचान बनाई है। उनकी मुस्कान सहज है और उनका स्त्रीत्व जो वे स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती हैं, पूरी तरह निरस्त्र कर देने वाला है। वे प्रहार करती हैं लेकिन शहद में डूबे तीरों से। यदि उनकी तुलना उनके भाई राहुल गांधी से की जाए तो चमक प्रियंका की ही अधिक दिखाई देती है। वर्तमान सत्र में दोनों ने भाषण दिए लेकिन सुर्खियों में सिर्फ प्रियंका गांधी का वक्तव्य रहा। राहुल गांधी ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, इस पर लगभग कोई चर्चा नहीं हुई। हां, इतना अवश्य रहा कि इस बार उन्होंने अपनी पहचान बन चुके टी-शर्ट के बजाय कुर्ता-पायजामा पहना शायद इसलिए कि उनकी शुरुआती टिप्पणी खादी और महात्मा गांधी पर केंद्रित थी, जो चुनाव सुधारों की चर्चा से कुछ हटकर थी। इसलिए तुलना को एक ओर भी रख दें तो भी अपने स्तर पर राहुल गांधी ऐसा एक भी ठोस तर्क या बिंदु नहीं रख पाए जिसे याद रखा जाए, सिवाय 'वोट चोरी' और 'धांधली' के उनके लगातार दोहराए गए आरोपों के। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है और जो आम जनता के बीच कोई खास प्रतिध्वनि नहीं पैदा करता। बिहार के चुनाव परिणाम इसका स्पष्ट प्रमाण हैं, लेकिन चर्चा फिर लौटती है प्रियंका गांधी पर और वंदे मातरम् की बहस के दौरान उनके उस प्रदर्शन पर, जिसे अब "शानदार" कहा जा रहा है। जिस रफ्तार से वे आगे बढ़ रही हैं, उसमें जल्द ही वे अपने भाई राहुल गांधी से भी आगे निकल सकती हैं। यहीं से पारिवारिक राजनीति का प्रश्न सामने आता है। परिवार के भीतर भी यही सोच वर्षों तक प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति से दूर रखे रही। राहुल गांधी के राजनीति में स्थापित होने के बाद ही उन्होंने, अपने भाई के संसद में प्रवेश के लगभग बीस वर्ष बाद पहला चुनाव लड़ा और एक वर्ष से भी कम समय में उन्होंने वह दूरी बड़ी सहजता से तय कर ली, जो उनके भाई दो दशकों में भी तय नहीं कर पाए।

यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। क्या उनसे भी यही अपेक्षा की जाएगी कि वे पीछे रहें और अपने भाई को आगे बढ़ने दें, जिन्हें उनके समर्थक 'प्रधानमंत्री पद का दावेदार' मानकर पेश कर रहे हैं? क्या उन्हें भी किनारे किया जाएगा और उनका राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी के लिए दांव पर लगा दिया जाएगा? और क्या उनका हश्र भी 2004 की युवा ब्रिगेड के उन होनहार नेताओं जैसा होगा, जिनकी चमक समय से पहले फीकी पड़ गई ? इसका जवाब तो समय ही देगा लेकिन यदि ऐसा हुआ तो इसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी, एक ऐसी पार्टी को, जिसे मौजूदा संकट से उबारने के लिए प्रतिभाशाली और भरोसेमंद नेतृत्व की सख्त जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस को राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए एक नहीं, एक से कहीं अधिक राहुल गांधी जैसे चेहरों की आवश्यकता है।

गरिमामयी राजनीति के 'अटल' प्रतीक

विजय गोयल
पूर्व केन्द्रीय मंत्री
Contact@vijaygoel.in

कहते हैं कि समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सकता, बस उसकी शीतलता और प्रवाह को महसूस किया जा सकता है। कुछ वैसा ही अनुभव मेरे जीवन में तब हुआ जब मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का अवसर मिला। उनके सान्निध्य में रह कर यह महसूस होता था कि आप किसी साधारण राजनेता के नहीं, बल्कि एक ऐसे युगपुरुष के सामने हैं, जिनमें सौम्यता, स्नेह, विनोद, दृढ़ता और राष्ट्रभक्ति, सब एक साथ प्रवाहित होते हैं। वे जितने कोमल हृदय के कवि थे, उतने ही अडिग और निर्णायक राष्ट्रनायक।

देशहित की बात आती तो उनके भीतर का कवि योद्धा में बदल जाता था। पोखरण परमाणु परीक्षण इसका जीवंत उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों की आशंका और वैश्विक आलोचनाओं की परवाह किए बिना उन्होंने देश के स्वाभिमान और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। उस निर्णय में न तो दिखावा था, न ही आवेश, बल्कि एक शांत, पर अटल संकल्प था। यही अटलता उन्हें "अटल" बनाती थी।

मेरा यह सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहते हुए मुझे उनके साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। यात्राओं, बैठकों और अनौपचारिक संवादों में उन्हें नजदीक से देखने-समझने का अवसर मिला। एक बार विमान यात्रा के दौरान उनसे हल्की-फुल्की बातचीत हुई। उन्होंने हंसते हुए बताया कि वे खाने के बड़े शौकीन हैं, वेज और नॉनवेज दोनों। चांदनी चौक की चाट के तो वे विशेष प्रशंसक थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, "आपने विवाह क्यों नहीं किया?" मुस्कराकर बोले, "समय ही नहीं मिला।"

अटल जी के व्यक्तित्व में एक सहज फक्कड़पन था, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार मैंने उनसे पूछा, "आप क्या चीज़ मिस करते हैं?" उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, "फक्कड़पन।" सत्ता से उन्हें कोई मोह नहीं था। 1996 में जब उनकी सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई तब उन्होंने सत्ता से चिपकने का प्रयास नहीं किया। बल्कि संसद में खड़े होकर आत्मविश्वास से कहा, "हम फिर लौटेंगे।" और वे लौटे भी पूरे जनादेश के साथ। उसके बाद पांच वर्षों तक उन्होंने स्थिर, सशक्त और सुशासन देने वाली सरकार चलाई, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।

प्रधानमंत्री के रूप में मैंने उन्हें सदैव धैर्यशील, संयमी और सहज मुस्कान से युक्त पाया। कठिन से कठिन निर्णयों के क्षणों में भी वे कभी भावनाओं में नहीं बहते थे, बल्कि परिस्थितियों का ठंडे मन से मूल्यांकन कर राष्ट्रहित में निर्णय लेते थे। संसद पर हमले का दिन आज भी स्मृतियों में अंकित है। जब मैंने उन्हें उस भयावह घटना की सूचना दी तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि पूरे संयम और गंभीरता के साथ स्थिति को संभालने में जुट गए। पाकिस्तान के साथ शांति की पहल करते समय वे संभावित खतरों से भली-भांति अवगत थे, फिर भी उन्होंने साहस और उदारता के साथ संवाद का मार्ग चुना। दिल्ली-लाहौर बस सेवा और लाहौर घोषणापत्र उनकी इसी दूरदर्शी और मानवतावादी सोच के प्रतीक बने।

पोखरण परमाणु परीक्षण अटल जी की अडिग दृढ़ता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता का सर्वोच्च उदाहरण है। 1998 में भारत द्वारा किए गए इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, किंतु इन सबके बावजूद विश्व में भारत की प्रतिष्ठा सुदृढ़ हुई। यह निर्णय न केवल साहसिक था, बल्कि भारत को सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ। उनके कार्यकाल में देश ने विकास के अनेक नए अध्याय देखे। टेलिकॉम क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ, ट्राई की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन, स्पेक्ट्रम के पारदर्शी आवंटन और त्वरित निर्णयों ने मोबाइल क्रांति की मजबूत नींव रखी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया सर्व शिक्षा अभियान बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल सिद्ध हुआ।

वाजपेयी जी वास्तव में राजनीति के "अजातशत्रु" थे, जिनका कोई स्थायी शत्रु नहीं रहा। विपक्षी दलों के नेता भी उनके व्यक्तित्व के प्रशंसक थे। संसद में अक्सर यह सुनने को मिलता, "अटल जी अच्छे आदमी हैं, बस गलत पार्टी में हैं।" जब वे बोलते थे, तो पूरा सदन 'पिन ड्रॉप साइलेंस' में बदल जाता था। उनकी वाणी में आक्रोश नहीं, तर्क था,' कटुता नहीं, संवेदना थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके पहले संसदीय भाषण के बाद ही भविष्यवाणी कर दी थी, "यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा।" समय ने इस भविष्यवाणी को अक्षरश: सत्य सिद्ध किया।

गठबंधन की राजनीति को मर्यादा और गरिमा के साथ निभाने की कला देश ने उनसे ही सीखी। एनडीए का गठन उनके नेतृत्व में हुआ, जिसमें वैचारिक रूप से भिन्न दलों को भी साथ लेकर चला गया। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, संवाद की शक्ति और आपसी सम्मान का भाव—ये गुण वाजपेयी जी को विशिष्ट बनाते थे। उन्होंने "रिमोट कंट्रोल" की राजनीति की संस्कृति को समाप्त कर सहयोग और सहमति पर आधारित राजनीतिक परंपरा की नींव रखी। उनका व्यवहार कभी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्ति की ऊंच-नीच से प्रभावित नहीं हुआ। छोटा कार्यकर्ता हो या देश का राष्ट्रपति, सबके प्रति वही आदर, वही अपनापन। मंत्री बनने से पहले भी जब मैं उन्हें सुझाव भेजता था, वे उन्हें गंभीरता से पढ़ते और प्रतिक्रिया देते थे। एक बार प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भाषण की तैयारी के दौरान मैंने उन्हें एक कविता दी। उन्होंने उसे अलग रख दिया। मुझे लगा शायद उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले उन्होंने अपने सचिव से कहा, "गोयल जी की वह कविता लाना।" और वही कविता उन्होंने मंच से पढ़ी। छोटे-बड़े हर व्यक्ति के योगदान को महत्व देना उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में था।

अटल जी के जीवन से जुड़ी स्मृतियां असंख्य हैं-कभी मजाकिया प्रसंग, कभी गंभीर राजनीतिक क्षण, कभी कविताओं की पंक्तियां। वे राजनीतिज्ञ, कवि और ओजस्वी वक्ता, तीनों का दुर्लभ संगम थे। उनके बारे में लिखना सचमुच सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। दिल्ली में उनकी समाधि "सदैव अटल" के नाम से जानी जाती है और यह नाम मात्र प्रतीक नहीं, एक सत्य है। वे सदैव अटल रहेंगे, हमारी स्मृतियों में और हमारे हृदयों में भी।

बिन मोबाइल टावर के आपको लिंक मिलेगा

आकाश चोपड़ा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के ऐतिहासिक प्रक्षेपण से लेकर, देश ने पीएसएलवी के ज़रिए लागत-प्रभावी उपग्रह प्रक्षेपणों में अग्रणी भूमिका निभाई है और 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक अहम मोड़ 2014 में प्रमुख अंतरिक्ष सुधारों की शुरुआत के साथ आया। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खोलने के मकसद से कई नीतिगत बदलाव शुरू किए हैं। ये सुधार क्रांतिकारी बदलाव साबित हुए हैं, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को उजागर किया है और भारत के लिए एक बड़ी छलांग के लिए एक मंच तैयार किया है। इसरो संचार, नेविगेशन, आपदा न्यूनीकरण और संसाधनों की निगरानी के लिए उपग्रहों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुल मिलाकर प्रयोगों के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर भारतीयों को उतारने सहित अंतरग्रहीय अन्वेषण के लिए एक प्रवेश द्वार का निर्माण करना एक प्रमुख लक्ष्य है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति, इसरो द्वारा संचालित, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी नवप्रवर्तकों द्वारा समर्थित, तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाती है। विश्वस्तरीय अंतरिक्ष प्रणालियों को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और तैनात करके राष्ट्र न केवल अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपना गौरवपूर्ण स्थान भी मज़बूत कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को साकार करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में बाहुबली एलवीएम3-एम6 रॉकेट ने अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 'लो अर्थ ऑर्बिट' में स्थापित कर दिया। इसरो की 100 फीसदी सफलता वाली एलवीएम3 सीरीज की छठी उड़ान है जो पहले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवैब के

72 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। इसरो की ये कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि कई और देशों ने इस तरह के अंतरिक्ष मिशन के दौरान तगड़े झटके लगे थे। उन्होंने स्पेस मिशन को लेकर तैयारी तो बहुत की थी लेकिन प्रक्षेपण के समय तगड़ा झटका लगा था। इसमें ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया के नाम प्रमुख हैं।

बिना मोबाइल टावर के आपको लिंक मिलेगा, यह कोई साधारण सैटेलाइट नहीं है। एक बार जब यह अपनी कक्षा में पहुंच जाएगा तो इसमें लगा एक विशाल एंटीना खुलेगा। ब्लू बर्ड ब्लाक-2 कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है, यह लो अर्थ आबिंट यानी लो अर्थ में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशंस सैटेलाइट होगा। इसका सबसे खास फीचर इसका एंटीना है। इसमें 223 वर्ग मीटर विशाल एंटीना है। इसमें 223 वर्ग मीटर विशाल 'फेज्ड एरे' लगा है, जिसका आकार 2400 स्क्वायर फीट होगा।

आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना विशाल होगा। यह कंपनी के पुराने ब्लू बर्ड 1-5 सैटेलाइट्स के मुकाबले साढ़े तीन गुना बड़ा है। कंपनी का दावा है कि इसकी डेटा कैपेसिटी 10 गुना ज्यादा होगी। इसका मकसद दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाना है। यह सीधे आम लोगों के स्मार्ट फोन्स से कनेक्ट होगा। यानी बिना मोबाइल टावर के आपको नेटवर्क मिलेगा। इसका मुख्य काम मोबाइल फोन को डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के स्पेस से ही तेज इंटरनेट, वॉयस और वीडियो कॉलिंग। इससे उन इलाकों में मदद मिलेगी जहां ग्राउंड नेटवर्क कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। इस मिशन का सीधा फायदा आम मोबाइल यूजर्स को मिलेगा। यह सैटेलाइट स्पेस से सीधे आपके मोबाइल पर 4जी और 5जी की सुविधा देगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपको नेटवर्क मिलेगा। इससे वॉयस कॉल और वीडियो कॉल करना आसान हो जाएगा। साथ ही टेक्स्ट मैसेज और स्ट्रीमिंग भी बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। यह सैटेलाइट एक ग्लोबल एलईओ कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है जिसका मकसद हर जगह और हर समय कनेक्टिविटी देना है। एनसिल और अमेरिकी कंपनी एएसटी एंड साइंस के बीच यह डील कमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत का कद बढ़ाएगी। स्पेस इंडस्ट्री में एएसटी स्पेस मोबाइल बड़ा नाम है। यह कंपनी अब तक अपने कई लॉन्च के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का इस्तेमाल करती आई है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सैटेलाइट तकनीक को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए विदेशी कंपनियां भारत के 'बाहुबली' रॉकेट एलवीएम3 पर भरोसा कर रही हैं। इसका सफल रिकार्ड 100 प्रतिशत होने के कारण ही अमेरिकी कंपनी ने इस पर भरोसा जताया है। इस लॉन्च के जरिए भारत ग्लोबल स्पेस मार्केट में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा। यह मिशन भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करेगा। इसरो अब विदेशी कॉमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बन चुका है। यह लॉन्च इसरो की कॉमर्शियल क्षमता को बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा।

वनवेब के बाद एएसटी स्पेस मोबाइल दूसरी बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनी है जो एलवीएम3 की सवारी कर रही है। इससे पहले इसरो ने वनवेब के 72 सैटेलाइट्स को दो बार में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अमेरिकी कंपनी के सीईओ हाबेल एवेलेन का कहना है कि वे स्पेस कनेक्टिविटी में अमेरिका का नेतृत्व दिखाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उन्होंने भारतीय रॉकेट पर भरोसा जताया। यह भारत की 'हेवी-लिफ्ट' क्षमता का लोहा मनवाता है। एएसटी स्पेस मोबाइल का प्लान बहुत बड़ा है। कंपनी तेजी से अपने सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा रही है। 2026 की शुरुआत तक 40 सैटेलाइट्स के बराबर हार्डवेयर तैयार हो जाएगा। कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही के अंत तक पांच और ऑर्बिटल लॉन्च की योजना बनाई है। हालांकि वे लॉन्च फिलहाल स्पेसएक्स के रॉकेट से होने की उम्मीद है लेकिन इस पहले और सबसे भारी सैटेलाइट की जिम्मेदारी इसरो के कंधों पर है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

SIR का गहन पुनरीक्षण जारी

देश के 12 राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कर रहा है जिसमें करोड़ों मतदाताओं के नामों को काटने का काम भी हो रहा है। इसे लेकर देश में विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही हैं मगर सूचियों के शुद्धिकरण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही है। संवैधानिक रूप से यह उसी की जिम्मेदारी है कि भारत के केवल वयस्क नागरिकों के नाम ही इन सूचियों में हों और एक भी वैध मतदाता का नाम न छूटे तथा नये वयस्क बने मतदाताओं के नाम इन सूचियों में दर्ज हों। अतः मतदाता सूचियों के बनाने पर किसी को भी आशंका नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग को अपना काम पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करने की छूट मिलनी चाहिए। हालांकि संसद के समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा चुनाव सुधारों के नाम पर हुई मगर विरोधी दल यह सिद्ध नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की नीयत में किसी प्रकार का दोष है। हां प्रक्रियागत खामियां जरूर गिनाई जा सकती हैं, मसलन पुनरीक्षण के काम के भारी दबाव में कई राज्यों में बीएलओ ने आत्महत्याएं तक कीं परन्तु इससे चुनाव आयोग की नीयत में खोट साबित नहीं होता है क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त वह अपना काम ही कर रहा है। चुनाव आयोग किसी भी सरकार का नहीं होता, बल्कि वह भारत राष्ट्र का होता है और अपना काम सीधे संविधान से शक्ति लेकर करता है। संविधान उसे मतदाताओं के प्रति सीधे जवाबदेह बनाता है लेकिन इस प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी बीच में आते हैं क्योंकि भारत के लोकतन्त्र में इनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है और आम लोग इन्हीं के माध्यम से चुनावों में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। यह इच्छा मतदाताओं को मिले एक वोट के संवैधानिक अधिकार के प्रयोग से ही प्रदर्शित होती है। भारत में आम जनता को यह एक वोट का अधिकार लम्बे संघर्ष के बाद मिला है। इसे लेने के लिए देश की आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों ने अपनी जान खपाई तब जाकर स्वतन्त्रता के बाद यह अधिकार आम लोगों को मिला और भारत गणतन्त्र बना। गणतान्त्रिक भारत में लोगों की सरकार का गठन ही वोट की ताकत के माध्यम से होता है। यह वोट की ही ताकत है कि हर पांच साल बाद होने वाले चुनावों में देश की जनता सरकार तक बदल सकती है। यह ताकत भारत के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही देकर गये हैं जिन्होंने 1928 में ही घोषणा कर दी थी कि स्वतन्त्र भारत में वोट देने का अधिकार केवल कुछ संभ्रान्त कहे जाने वाले नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह बिना किसी ऊंच-नीच व स्त्री-पुरुष के भेदभाव के प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान रूप से मिलेगा। यह अधिकार बिना किसी धार्मिक भेदभाव के प्रत्येक जाति व वर्ग और सम्प्रदाय के व्यक्ति के पास होगा जिससे भारत सच्चे अर्थों में गणतन्त्र बने और प्रशासकों का जन्म इसी वोट की ताकत से हो। अतः इस वोट के अधिकार की रक्षा के लिए स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र चुनाव आयोग का गठन किया गया और इसका चरित्र पूरी तरह 'अराजनैतिक' रखा गया तथा इसे सरकार का अंग नहीं बनाया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने आयोग पर जिम्मेदारी डाली कि वह देश में संसदीय लोकतन्त्र की जमीन इस प्रकार तैयार करेगा कि इसमें प्रत्येक भारतीय की बराबर की हिस्सेदारी हो। यह हिस्सेदारी एक वोट के अधिकार के जरिये इस प्रकार तय की गई कि किसी उद्योगपति या मजदूर के वोट की कीमत में कोई अन्तर न हो और एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धान्त पर चलकर सरकारों का गठन राज्य स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक हो। भारत अपने पुरखों के बनाये इसी सिद्धान्त पर चल रहा है और इस देश के लोग हर पांच साल बाद अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इसे ही राजनीतिक स्वतन्त्रता व बराबरी का नाम दिया गया मगर इस बराबरी को कायम रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही डाली गई। अतः मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण भी लोकतन्त्र के शुद्धिकरण से सीधे जुड़ा हुआ है। मतदाता सूचियों में यदि फर्जी मतदाता पाये जाते हैं तो यह चुनाव आयोग की कमजोरी ही कहलायेगी इसलिए उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह ऐसे मतदाताओं के नाम काटे और तय करे कि एक मतदाता केवल एक बार ही वोट डाल सके। इसके साथ ही कोई भी मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत न हो और किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर वोट न डाले जायें। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में से केरल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार की पुनरीक्षित सूची का दूसरा प्रारूप जारी कर दिया है जिसमें कुल तीन करोड़ 68 लाख मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। हालांकि अंडमान निकोबार छोटा सा केन्द्र प्रशासित द्वीप समूह है जिसमें कुल तीन लाख दस हजार मतदाता हैं परन्तु इसमें सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें से 16.72 प्रतिशत मतदाता अन्य स्थानों को स्थानान्तरित हो चुके हैं तथा 2.56 प्रतिशत की मृत्यु हो चुकी है तथा .94 प्रतिशत एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग की मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया में यदि 21 प्रतिशत मतदाता फर्जी पाये जाते हैं तो हम किस प्रकार चुनावों के शुद्धिकरण की शेखी बघार सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 74 लाख मतदाता थे जिनमें से केवल पांच करोड़ 31 लाख ही वैध पाये गये। जहां तक दक्षिणी राज्य केरल का सवाल है तो इसमें दो करोड़ 78 लाख मतदाता थे इनमें से केवल दो करोड़ 54 लाख ही जायज निकले। छत्तीगढ़ में भी यह संख्या दो करोड़ 12 लाख से घटकर एक करोड़ 84 लाख रह गई। वोटों के कम होने पर विपक्षी दल प्रश्न चिन्ह तो लगाते हैं मगर यह बताना भूल जाते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों से रोजी-रोटी की तलाश में लोगों का पलायन अन्य राज्यों व देशों तक में किस गति से होता है। चुनाव आयोग की आलोचना करते समय इन सभी अवयवों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

पगलाया पप्पू पुनः,पग-पग करे प्रयास
अर्थव्यवस्था देश की, अबकी सत्यानाश
अबकी सत्यानाश, जर्मनी में भी बोला
देखो बुड़बक आज, जहर वाणी में घोला
कह सुरेश कविराय किसी को समझ न आया
पृथ्वी यहां वहां पप्पू फिर से पगलाया

अरावली पर्वत शृंखला : सुरक्षा कवच या डेथ वारंट?

> अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो गुजरात से दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बनाती है। अरावली थार मरुस्थल को जयपुर-दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। अरावली की घाटियां बरसात के पानी को जमीन में उतारती हैं।

केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा गया है कि सरकार अरावली इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ताजा घोषणा के बावजूद अरावली की नई परिभाषा को लेकर विवाद खत्म नहीं होने वाला। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात से दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी बनाती है लेकिन आज यह अपने अस्तित्व के संकट से जूझती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उससे जनमानस उद्वेलित है। फैसले में अरावली की 'केवल 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचे पहाड़' को ही अरावली का दर्जा किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इससे पर्वतमाला का 90 प्रतिशत हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। यह स्थिति खनन माफिया के लिए वरदान साबित होगी। पर्यावरणविद इसे 'अरावली का डेथ वारंट' बता रहे हैं। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इसे 'अरावली के प्रोटेक्शन का प्लान' बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है कि अरावली की हर हालत में सुरक्षा की जाएगी। केंद्र और राजस्थान सरकार के स्पष्टीकरणों के बावजूद सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान तो जोरशोर से चल ही रहा है, धरने—प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्र और राजस्थान सरकार की भूमिका तथा कथित रूप से खनन लॉबी के प्रभाव को लेकर समाज के बड़े हिस्से में बेचैनी है। सड़क से

लेकर सोशल मीडिया तक सेव अरावली मुहिम चल रही है जिसे विद्यार्थियों, पर्यावरणविदों, स्थानीय ग्रामीणों और शहरी मध्यवर्ग – सबका समर्थन मिल रहा है। राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली में आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है। खासतौर पर राजस्थान में अरावली को बचाने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चो खोल दिया है। कांग्रेस ही नहीं, भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, राष्टीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनिवाल भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। अब यह सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन गया है। इसे महाराणा प्रताप के शौर्य और मुगलों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ दिया गया है। तीन सौ साल पहले खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई समेत 363 लोग शहीद हो गए थे। आंदोलन के दौरान इन शहीदों की भी दुहाई दी जा रही है। अब यह आंदोलन किसी एक दल का नहीं होकर जन आंदोलन बनने की राह पर है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की भूगर्भीय विरासत ही नहीं, उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ भी है। ढाई अरब वर्ष पुरानी यह पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अनियंत्रित खनन और अनियोजित शहरीकरण ने इस पर्वत श्रृंखला को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला समूची अरावली की तबाही के रास्ते पर धकेलने वाला माना जा रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली जैसे क्षेत्रों की पहचान भू—वैज्ञानिक दृष्टि से की जाती है, यानी चट्टानों की उम्र, बनावट और संरचना इसका आधार हो। ऊंचाई तो समय, क्षरण और खनन के साथ बदलती रहती है। सौ मीटर की कट—ऑफ लाइन तय कर देना वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है क्योंकि इससे वही क्षेत्र अरावली से बाहर हो जाएंगे जो पहले ही नुकसान झेल चुके हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। आशंका यह है कि नई परिभाषा के बाद अरावली का लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा असुरक्षित हो जाएगा। अवैध खनन, स्टोन क्रशर और फार्महाउस—रिसॉर्ट के कारण पहले ही अरावली को काफी नुकसान हो चुका है। जब नई परिभाषा मंजूर हुई तो लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन पुराने आदेशों की वजह से अरावली को संरक्षण मिला हुआ था, अब वह समाप्त हो जाएगा। आंदोलनकारियों ने इसे 'माइनिंग लॉबी की जीत' तक करार दिया है। यह बात सही है कि पहले की सरकारों ने अरावली के संरक्षण के मामले में गंभीरता नहीं बरती लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वर्तमान सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरावली का जंगल और पहाड़ी संरचना हजारों गांवों के लिए जल का प्रबंध करती है। पहाड़ियों में रिसते पानी से ही कुंए, तालाब और नलकूप भरते हैं। खनन और पेड़ कटने से इन जल स्रोतों पर सीधा असर पड़ेगा। पहाड़ और कटेंगे तो पीने के पानी—कृषि दोनों पर भारी संकट आएगा, जो मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। अरावली थार मरुस्थल को जयपुर—दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ियां नहीं रहीं तो रेगिस्तान और गर्म हवाओं को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अरावली की घाटियां बरसात के पानी को जमीन में उतारती हैं। कई मौसमी नदियां और नाले इन्हीं से निकलते हैं। पहाड़ियों में पथरीली सतह के बीच जो मिट्टी और पेड़ हैं, वही पानी को रोककर धीरे—धीरे नीचे भेजते हैं। अगर यह संरचना टूटी तो 'बाढ़' और 'सूखा' – दोनों की आशंका बनी रहेगी। यह पूरा क्षेत्र वन्यजीव गलियारा भी है। बड़ी संख्या में तेंदुआ, लंगूर, नीलगाय, सियार, सैकड़ों पक्षी बेघर होंगे और औषधीय पौधे काट दिए जाएंगे। अरावली के जंगलों और पहाड़ियों में अनेक धर्मस्थल, आश्रम और ग्राम्य वन हैं जिन्हें ग्रामीण समुदाय पीढ़ियों से संभालते आए हैं। ये सभी खतरे में आ जाएंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि बेहतर तो यह है कि 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाए, लेकिन सरकार अरावली को तय करने वाली नई परिभाषा को सही ठहराने के लिए प्रचार अभियान चलाने में जुटी हुई है। इस बीच राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की 'परिभाषा' के फॉर्मूले के मामले में याचिका मंजूर कर ली है। यह याचिका हरियाणा के रिटायर्ड वन अधिकारी आरपी बलवान ने दायर की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों तथा पर्यावरण मंत्रालय से जवाब भी मांगा है। कोर्ट अब सभी पक्षों के जवाब के बाद आगे सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का भी यही कहना है कि नई परिभाषा से 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। याचिका में केंद्रीय मंत्रालय की कमेटी की ओर से पेश किए गए हलफनामे में विरोधाभास की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अरावली को बचाने के लिए सभी जरूरी कानूनी उपाय किए जाने चाहिए।

■ज्ञान चंद पाटनी

पाकिस्तान की राह पर बढ़ता बांग्लादेश

बांग्लादेश के हालात दो तरफ इशारा कर रहे हैं और दोनों ही भारत के लिए खतरनाक हैं । एक तरफ बांग्लादेश भारत से दुश्मनी के रास्ते पर जा रहा है तो उसका दूसरा रास्ता उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश का दुश्मनी के रास्ते पर जाना खतरनाक है तो बांग्लादेश का बर्बाद होना भी बुरी खबर है। पाकिस्तान अपने जन्म के बाद ही भारत का जानी दुश्मन बना बैठा है और अब वो बांग्लादेश को खींचकर उसी रास्ते पर ले जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और भारत को उम्मीद है कि उसके बाद बांग्लादेश के हालात बेहतर हो सकते हैं। चुनाव से पहले ही बांग्लादेश के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि चुनाव पर ही खतरा नजर आने लगा है। एक अंदेशा यह भी है कि बांग्लादेश के हालात मोहम्मद यूनुस की ही साजिश है क्योंकि वो चुनाव नहीं करवाना चाहता है। उसे पता है कि अगर चुनाव हुए तो सत्ता उसके हाथ से चली जायेगी । मोहम्मद यूनुस एक गैर-निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है, कहने को वो सरकार का मुख्य सलाहकार है । ऐसा लगता है कि सत्ता का लालच इतना बढ़ गया है कि उसे देश की बर्बादी नजर नहीं आ रही है। यूनुस ने ही बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को इतना बढ़ावा दिया है कि आज वो सड़क पर उतरकर हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं। एक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अब एक और छात्र नेता की हत्या हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इन हत्याओं के पीछे गहरी साजिश है। इन हत्याओं में भारत का हाथ बताकर हिंदुओं पर हमले किये जा रहे हैं। एक

हिन्दू युवक को हज़ारो जेहादियों की भीड़ ने लिनचिंग करके मारने के बाद उसके शव को लटकाकर जला दिया । ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि पूरे हिन्दू समुदाय पर हमला है, इसलिए इसके खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी जेहादियों पर क्या इस प्रदर्शन का कोई असर होगा। ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बांग्लादेश में हिन्दू आबादी बिखरी हुई है। बिखरी हुई हिन्दू आबादी पर जेहादियों द्वारा हमले किये जा रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार इस तरफ से आंखे बंद किये हुए है। मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे और देश में सबकी सुरक्षा की जाएगी। उनका ये बयान दबाव में दिया गया है, अन्यथा उनका इन जेहादियों को पूरा समर्थन है। उस्मान हादी के भाई ने उसकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि ये चुनाव रोकने की साजिश के तहत की गई हत्या है। पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच रक्षा समझौते की तैयारी की जा रही है और पाकिस्तान ने बयान दिया है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान उसकी रक्षा करेगा। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भारत को दो मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के कमजोर होने के बावजूद हम इस कोशिश को हल्के में नहीं ले सकते। आज बेशक बांग्लादेश सैन्य रूप से कमजोर नजर आ रहा है लेकिन कई शक्तियां उसे भारत के खिलाफ तैयार कर रही हैं। बांग्लादेश से ज्यादा बड़ा खतरा उसके घुसपैठिएं हैं जो वक्त आने पर भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दो करोड़ से पांच करोड़ तक हो सकती है जिनसे निपटना हमारे सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में अपना एजेंडा चलाने में कामयाब हो रही है। जमात-ए-इस्लामी आईएसआई के साथ मिलकर बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करने की ओर बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि जमात सत्ता पर कब्जा चुनाव में जीतकर नहीं करना चाहती है। जमात अपने कट्टरपंथी समर्थकों की मदद से बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती है। ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहती है, जहां शरीयत का राज हो क्योंकि जमात को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है। सच तो यह है कि जिस जमात को यूनुस ने बांग्लादेश में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दिया, अब वही जमात यूनुस को सत्ता से बेदखल कर सकती है। बंगलादेश की राजनीति में सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। मोहम्मद यूनुस को जिन छात्रों ने तथाकथित क्रांति करके सत्ता में बिठाया था, वो भी दो धड़ो में बंट गए हैं। शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाकर उसे सत्ता की लड़ाई से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गई है। भारत सरकार बांग्लादेश के हालात को बड़ी सतर्कता से देख रही है और बीएनपी के सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। बीएनपी बेशक एक भारत विरोधी पार्टी मानी जाती है लेकिन उसे पता है कि बांग्लादेश को भारत की कितनी जरूरत है। बीएनपी पहले भी राज कर चुकी है, इसलिए वो एक हद तक ही भारत का विरोध कर सकती है। बांग्लादेश को चलाने के लिए भारत की अहमियत को बीएनपी जानती है। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के अन्य दुश्मन देश इसे समझ रहे हैं, इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि बीएनपी सत्ता में न आ पाए। बांग्लादेश की कट्टरपंथी शक्तियां भी नहीं चाहती हैं कि खालिदा जिया को सत्ता मिले, इसलिए उनके खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया गया है। समस्या यह है कि उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके बेटे तारिक अनवर बीएनपी का नेतृत्व करने के लिए लंदन से बांग्लादेश आना चाहते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा को भी बड़ा खतरा नजर आ रहा है। कट्टरपंथी पार्टी जमात का बीएनपी से गठबंधन था और दोनों ही मिलकर अवामी लीग से लड़ती थीं लेकिन अब ये गठबंधन टूट चुका है।

■राजेश कुमार पासी

महिलाओं के मोबाइल पर बैन

राजस्थान के जालोर जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के गाजीपुरा गांव में आयोजित एक सामाजिक पंचायत के पंच-पटेलों ने महिलाओं और बेटियों के लिए कैमरा युक्त मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। महिलाएं मोबाइल फोन को सार्वजनिक समारोहों के साथ-साथ पड़ोसियों के घर जाने के दौरान भी नहीं ले जा सकेंगी। यह पाबंदी किसी एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि 14 पट्टियों (उप-मंडलों) के अंतर्गत आने वाले 15 गांवों पर इसे लागू करने की तैयारी है। आगामी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से समुदाय की सभी महिलाओं और बेटियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जालोर से आई ये खबर सिर्फ एक गांव की सामाजिक सनक नहीं है बल्कि यह उस खतरनाक मानसिकता का खुला प्रदर्शन है जो आज भी भारत के संविधान से ऊपर खुद को समझती है। जाति पंचायत द्वारा महिलाओं के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान दरअसल तकनीक के खिलाफ नहीं, महिलाओं की आजादी, उनकी चेतना और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार के खिलाफ एक सुनियोजित हमला है। यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम 21वीं सदी के भारत में रह रहे हैं या फिर समाज का एक हिस्सा अब भी मनुवादी अंधकार में कैद है। मोबाइल फोन आज सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है। यह शिक्षा का दरवाजा है, रोजगार की संभावना है, सरकारी योजनाओं तक पहुंच का माध्यम है और सबसे बढ़कर महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का औजार है। ऐसे में जब किसी पंचायत द्वारा महिलाओं के हाथ से मोबाइल छीनने का आदेश दिया जाता है तो वह केवल एक उपकरण पर पाबंदी नहीं लगाती बल्कि महिलाओं की आवाज, उनकी स्वतंत्र सोच और उनके नागरिक अधिकारों पर ताला लगाने की कोशिश करती है। यह वही सोच है जो सदियों से महिलाओं को घूंघट, चूल्हा-चौका और खामोशी तक सीमित रखना चाहती रही है। इस फरमान के पीछे दिया गया तर्क भी उतना ही खोखला और पाखंडी है-कि मोबाइल से "संस्कृति बिगड़ती है" और "परंपरा खतरे में पड़ती है"। सवाल यह है कि क्या संस्कृति इतनी कमजोर होती है कि एक मोबाइल फोन से ढह जाए? या फिर सच्चाई यह है कि पुरुष वर्चस्व और जातिगत नियंत्रण की दीवारें दरकने लगी हैं और उसी डर में ऐसे फैसले सुनाए जा रहे हैं। संस्कृति के नाम पर महिलाओं की आजादी पर पहरा बैठाना दरअसल संस्कृति नहीं, सत्ता का संरक्षण है। यह मामला केवल सामाजिक नैतिकता तक सीमित नहीं है, यह सीधे-सीधे संवैधानिक संकट है। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देता है। समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार किसी पंचायत की दया पर निर्भर नहीं है। जाति पंचायत का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 की खुली अवहेलना है। यह फैसला यह सवाल उठाता है कि क्या देश में कानून का राज है या फिर गांव की चौपालें समानांतर अदालत बन चुकी हैं। सबसे विडंबनापूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे हर फरमान में "महिलाओं की इज्जत" का तर्क आगे किया जाता है लेकिन इज्जत का ठेका हमेशा महिलाओं के सिर पर ही क्यों? पुरुषों के मोबाइल, उनके सोशल मीडिया, उनकी आजादी पर कोई सवाल नहीं उठता। यानी नैतिकता सिर्फ महिलाओं के लिए और छूट पुरुषों के लिए।

आज का कार्टून

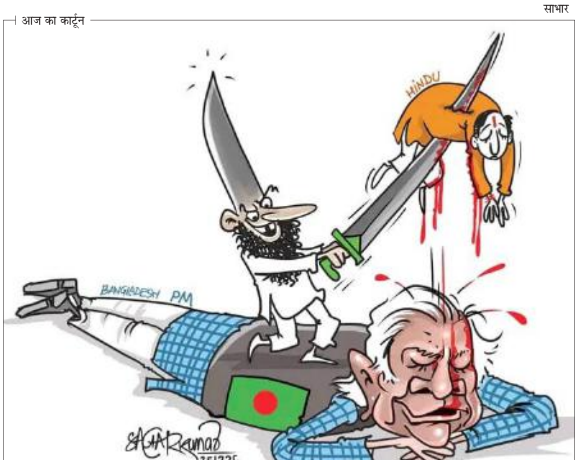

साभार

संकल्पों की भीड़ : इस वर्ष स्वयं से मिलने चलिए

कैलेंडर की दीवार पर टंगी पुरानी तारीखें उतरने को तैयार हैं। हम एक बार फिर उस दहलीज पर खड़े हैं जिसे दुनिया 'नया साल' कहती है। नववर्ष 2026 दस्तक दे रहा है। चारों ओर शोर है - पार्टियों का, आतिशबाजी का, और उन शुभकामनाओं का जो अक्सर फॉरवर्ड किए गए संदेशों की भीड़ में अपनी आत्मीयता खो देती हैं। लेकिन इस शोरगुल के बीच, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दबे पाँव हमारे मन के भीतर प्रवेश करता है— क्या वास्तव में कुछ बदल रहा है? हर साल तारीख बदलती है, डायरी बदलती है, और दीवार का कैलेंडर बदल जाता है। लेकिन यदि दर्पण में झाँकने पर वही पुराना, हताश, क्रोधित या दिशाहीन चेहरा दिखाई दे, तो क्या वाकई नया साल आया है? नववर्ष 2026 हमारे सामने कोई जादुई छड़ी लेकर नहीं, बल्कि एक मौन चुनौती लेकर खड़ा है। यह चुनौती है, तारीख बदलने के साथ-साथ 'इंसान' के बदलने की। हम सबने यह अनुभव किया है। 31 दिसंबर की रात हम एक अजीब से उत्साह (Adrenaline) में होते हैं। हम खुद से बड़े-बड़े वादे करते हैं— "मैं इस साल वजन कम कर लूँगा," "मैं गुस्सा करना छोड़ दूँगा," या "मैं रोज सुबह 5 बजे उठूँगा।" मनोविज्ञान कहता है कि ये संकल्प अक्सर 'बदलाव की इच्छा' से नहीं बल्कि 'वर्तमान के असंतोष' से जन्म लेते हैं। विडंबना यह है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जिम खाली होने लगते हैं और डायरियां धूल खाने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण बहुत स्पष्ट है, हम बदलाव को एक 'घटना' (Event) मान लेते हैं जबकि वास्तव में बदलाव एक 'प्रक्रिया' (Process) है। हम रातों-रात परिणाम चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन बड़े और नाटकीय संकल्पों से नहीं, बल्कि छोटे, अदृश्य और उबाऊ दिखने वाले अनुशासित सुधारों से बदलता है। 2026 में हमें 'जोश' की नहीं, 'होश' की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण जीवन में एक बहुत ही अद्भुत अघोषित नियम हुआ करता था, जिसे आज की आपाधापी में हम भूल चुके हैं। एक पुरानी कथा याद आती है - एक गाँव में एक बुज़ुर्ग महिला थीं। जब भी परिवार या पड़ोस में कोई आवेश में आकर चिल्लाने लगता या कड़वा बोलने लगता, तो वह महिला उसे चुप नहीं कराती थीं। वह बस अपने काम को रोक देती थीं, एक गहरी साँस लेती थीं और एक विशेष प्रकार की हल्की आवाज करती थीं। वह संकेत था - "ठहरो।" वह एक क्षण का 'विराम' (Pause) जादू की तरह काम करता था। वह बोलने और प्रतिक्रिया देने के बीच का वह सूक्ष्म अंतराल था जहाँ विवेक का जन्म होता है। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, 5G नेटवर्क है लेकिन हमारे पास वह 'विराम' नहीं है। हम सुनते बाद में हैं, जवाब पहले टाइप कर देते हैं। नववर्ष 2026 का सबसे बड़ा उपहार जो आप खुद को दे सकते हैं, वह है यह 'ठहरने की कला'। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, निर्णय लेने से पहले सोचना, और बोलने से पहले तोलना। यह एक छोटी सी आदत आपके कई रिश्तों को टूटने से और कई बनते कामों को बिगड़ने से बचा सकती है। हम अक्सर बाहरी चकाचौंध को ही नयापन मान लेते हैं। नए कपड़े, नई गाड़ी, या नया घर। ये सब 'बाहरी आवरण' के बदलाव हैं। 2026 के लिए मैं एक नई अवधारणा प्रस्तावित करता हूँ - 'अंतःनया'। अंतःनया का अर्थ है - भीतर की सफाई। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर कुछ जोड़ता नहीं है, बल्कि अनचाहे पत्थर को हटा देता है ताकि मूर्ति प्रकट हो सके, वैसे ही हमें अपने भीतर से ईर्ष्या, आलस्य, और नकारात्मकता की परतों को छेनी-हथौड़े से हटाना होगा। कल्पना करें कि आप एक ऐसा वर्ष जी रहे हैं जहाँ आपका लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं को जीतना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षी न हों, इसका अर्थ है कि आपकी महत्वाकांक्षा का केंद्र 'दिखावा' न होकर 'सुधार' हो। हमें यह प्रण लेना होगा कि "आज का मैं, कल के मुझसे थोड़ा अधिक समझदार, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक कुशल हो।" यही अंतःनया है। आज की युवा पीढ़ी और हम सभी, प्रेरणा (Motivation) के अतिरेक से थके हुए हैं। सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। हमें अब 'मोटिवेशन' नहीं, 'डिसिप्लिन' (अनुशासन) चाहिए।

■उमेश कुमार साहू

सम्पादकीय...

शहरी समस्या प्रधान शिविर

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शहरी समस्या समाधान शिविर अब समस्या प्रधान शिविर बनते जा रहे हैं क्योंकि अधिकांश जगह स्थिति बहुत गंभीर है नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी नहीं है अन्य अधिकारी नहीं है या एक अधिकारी को दो या दो से ज्यादा जगह का चार्ज दे रखा है इसलिए फाइलों का अंबार लग जाता है। सरकार का उद्देश्य ऐसे शिविर के लिए यह था कि तुरंत गति से सबके काम हो सामान्य कामकाज भी तेजी से पूरे हो लेकिन शिविर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अब जब जनप्रतिनिधि सक्रिय होने लगे हैं तो पोल खुल गई है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को इसलिए सक्रिय होना पड़ रहा है कि अप्रैल मई में निकाय चुनाव अब होने ही है क्योंकि अदालत ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और सरकार ने भी मान लिया है कि चुनाव अप्रैल मई में ही होंगे। ये शिविर तो लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता थी अब जब सर पर बात आ रही है तो जनप्रतिनिधि भी तेजी से जागरूक हो रहे हैं सीकर में दो दिन पहले एक मंत्री की इन शिविर को लेकर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से टकराव हो गया अन्य कई जगह भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपस में टकराव कर रहे हैं। क्योंकि जनता परेशान है इन शिविर में भी भारी भ्रष्टाचार की कई जगह से खबर मिल रही है अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि शिविर में ज्यादा से ज्यादा फाइल क्लीयर हो इसलिए वह लटका देते हैं छोटी-छोटी खामियां निकालते हैं इससे स्थिति और खराब हो रही है। उधर अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह से सही गाइडलाइन नहीं दी है पहले की सरकार कई तरह की रियायत देती थी, गाइडलाइन जारी करती थी और उसी के अनुरूप कार्य होता था तो आम जनता को राहत मिलती थी लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं हो पा रहा है विभाग के मंत्री को लेकर भी अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी है उनका कहना है कि जब ऐसी शिविर चल रहे हो या सरकार की योजना हो तो पहले सारे पद भरे जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ रहा है और आम जनता को भी।

वैभव लोढ़ा...

इतिहास में आज

1904: दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटरकार रैली का उद्घाटन।
1978: भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया।
1997: उड़ीसा की प्रमुख पार्टी, बीजू जनता दल (बीजद) की स्थापना वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने की।
2024: मनमोहन सिंह - भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन।

-धर्म चंद मेहता

क्रॉस फायर

❑ अरावली में केंद्र ने कोई भी नया खनन पट्टा नहीं जारी करने का राज्यों को निर्देश दिया।
◆ अब खाल बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा।

❑ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से उबाल, देश भर में प्रदर्शन।
◆ उबाल से क्या होगा सीधा-सीधा उपचार सरकार करें।

❑ इसरो के यान ने 6000 किलोग्राम के अमेरिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया।
◆ अमेरिका भी हिंदुस्तान के भरोसे।

❑ यूक्रेन रूस युद्ध में युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में 20 बिंदुओं का प्रस्ताव पेश।
◆ इतनी समझ से तो पत्थर भी मान जाते हैं।

❑ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नागरिकों को स्वच्छ हवा क्यों उपलब्ध नहीं कर पा रही है सरकार।
◆ सरकार को फुर्सत नहीं है अभी।

❑ बीएमसी चुनाव से पहले दोनों ठाकरे बंधुओं की पार्टियों ने गठबंधन की घोषणा की।
◆ मरता क्या नहीं करता।

❑ फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाली विधायक की बेटी को सरकार ने एपीओ किया।
◆ मजबूरी में कदम उठाना पड़ा।

❑ मुख्यमंत्री बोले प्रदेश में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं गुंडा आएगा तो जेल से वापस नहीं जाएगा।
◆ गुंडे जेल जाते भी कहां है।

..............अंजू लोढ़ा

आज का राशिफल

शुक्रवार 26 दिसम्बर, 2025

मेष राशि: आज आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे, यात्रा लाभकारी रहेगी। परिजनों तथा मित्रों के साथ समारोह में उपस्थित रह सकते हैं।

वृषभ राशि: आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा। आज परिश्रम अधिक और लाभ कम रहेगा। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। यात्रा न करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।

मिथुन राशि: अगर कोई नया रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करें, सफलता मिलेगी। अविवाहितों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। नए मित्र भी बनेंगे। व्यापार-व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि: आज संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। कोई नया ऑर्डर अथवा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। शत्रु बलहीन रहेंगे। उच्च अधिकारियों की शुभ दृष्टि आपका उत्साह बढ़ाएगी।

सिंह राशि: कारोबार सामान्य रहेगा। मनोरंजन कार्य पर खर्च हो सकता है। आज आपको अपनी प्रतिभा का लाभ मिलेगा और आपकी पहचान बनेगी। नई योजनाएं लाभ देंगी।

कन्या राशि: आज का दिन मध्यम फलदायी होगा। आज कोई नया कार्य न करें। जोखिमपूर्ण निवेश करने से बचें। पूरे दिन किसी से वाद-विवाद में न पड़ें।

तुला राशि: आज पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका मनोबल बढ़ेगा और कारोबार में बेहतरी आएगी। नए संपर्क बनेंगे और लाभकारी रहेंगे। भाइयों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि: आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा। लेन-देन के कार्यों में सावधान रहें। धन निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें। आज किसी को उधार न दें, क्योंकि आज दिए हुए धन के वापस आने की आशंका कम है।

धनु राशि: आज प्रयास अथवा स्वयं कोशिश करने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय में उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। सभी का सहयोग मिलेगा।

मकर राशि: आज का दिन मध्यम फलदायी होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण से अनावश्यक खर्च हो सकता है। व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है। दैनिक कार्य में विघ्न आ सकते हैं।

कुम्भ राशि: आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ होगा। जोखिमपूर्ण निवेश करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। ईश्वर की प्रार्थना तथा जप करने से राहत महसूस होगी। साथियों से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी।

मीन राशि: आज आपका सितारा अनुकूल है। लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी। कामकाज में आ रहीं बाधाएं दूर होंगी। गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कार्यालय तथा व्यावसायिक स्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

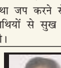

राजेन्द्र गुप्ता
ज्योतिषी और हस्तरेखाविद, मो. 9611312076

नोट- अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या इसी व्हाट्स एप नम्बर पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें, इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल और हैंडप्रिंट्स भेजें।

इसरो की ऐतिहासिक उड़ान: बाहुबली एलवीएम-3 से 6100 किलो से भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

-सुनील कुमार महला

हाल ही में बुधवार 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने बाहुबली प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 से पहली बार 6100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। वास्तव में, यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव का क्षण है। स्वयं इसरो चेयरमैन वी.नारायणन ने भी इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है।यह एक तरह से देश की अंतरिक्ष इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज कहा जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमरीकी उपग्रह ब्लूबर्ड-6 सीधे स्मार्ट फोन तक 4 जी और 5 जी इंटरनेट, वॉयस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं प्रदान करेगा।

पाठकों को बताता चलूं कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लांच पैड से एलवीएम-3 एम-6 ने निर्धारित समय 8.54 बजे उड़ान भरी और 16 मिनट बाद ब्लूबर्ड उपग्रह को 520 किमी वाली वृत्ताकार कक्षा में सटीकता के साथ स्थापित कर दिया। गौरतलब है कि यह भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले, नवंबर में लॉन्च किया गया एलवीएम3-एम5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट-03 करीब 4,400 किलोग्राम का था। इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया था। ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को जिस एलवीएम3-एम6 रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका वजन 640 टन है। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई-स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। खास बात यह है कि इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4जी और 5जी वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआइएल) और अमेरिका स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस, एलएलसी) के बीच हुए एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यूस्पेस इंडिया, इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच है। कहना ग़लत नहीं होगा कि इसरो की हाल की उपलब्धि ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को और मजबूत किया है।सच तो यह है कि एलवीएम 3 ने फिर एक बार विश्वसनीयता और उपयोगिता साबित की है।

उल्लेखनीय है कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यह 104 वां लॉन्च मिशन था। पहली बार ऐसा हुआ है, जब केवल 52 दिन के अंतराल पर एक के बाद एक एलवीएम-3 के दो मिशन प्रक्षेपित किए गए। कितनी अच्छी व बड़ी बात है कि टेक्सास स्थित अमरीकी कंपनी एएसटी मोबाइल का उपग्रह ब्लूबर्ड-6 सीधे स्मार्ट फोन तक 4 जी और 5 जी इंटरनेट, वॉयस, वीडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं प्रदान करेगा। वास्तव में, इससे संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए सैटेलाइट हैंडसेट से ही उपग्रहों के जरिए संचार संभव था। कहना ग़लत नहीं होगा कि अब तक का सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपण के प्रक्षेपण से एलवीएम-3 की उच्च पेलोड वहन क्षमता और विश्वसनीयता का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है तथा यह सफलता गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हेवी लोड को सुरक्षित कक्षा में स्थापित करने की इसरो की क्षमता प्रमाणित हुई है।सच तो यह है कि पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संपन्न इस मिशन ने भारत को भारी उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। साथ ही, इससे संचार, रक्षा और वैज्ञानिक अभियानों को नई मजबूती मिलेगी तथा वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसरो की साख और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और सुदृढ़ होगी। साल 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है लेकिन साल 2025 में इसरो ने कई ठोस और बहुआयामी सफलताएँ हासिल कीं, जिन्होंने भारत की अंतरिक्ष क्षमता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। विदेशी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 का सफल प्रक्षेपण ही नहीं, इसके अलावा भी पीएसएलवी और जीएसएलवी के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और संचार से जुड़े कई उपग्रहों की सफल तैनाती इसरो द्वारा की गई, जिससे कृषि, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं को मजबूती मिली। इतना ही नहीं, मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में भी 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम और मानव सुरक्षा से जुड़े परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए, जिससे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की नींव और मजबूत हुई। इसके साथ ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, उन्नत नेविगेशन सिस्टम और नई पीढ़ी की अंतरिक्ष तकनीकों का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम रहा। अंतरराष्ट्रीय सहयोगों और व्यावसायिक प्रक्षेपणों में बढ़ती भागीदारी ने भी इसरो को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक भरोसेमंद और सक्षम एजेंसी के रूप में स्थापित किया। कुल मिलाकर, यह बात कही जा सकती है कि वर्ष 2025 इसरो के लिए तकनीकी सफलता, वैज्ञानिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का वर्ष साबित हुआ। बहरहाल, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आज इसरो की बढ़ती विश्वसनीयता के कारण भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार सालाना 12.5% से 13.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है। इस क्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 के बीच इसरो ने 393 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर 439 मिलियन अमरीकी डॉलर, यानी 3900 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। बहरहाल, यदि हम यहां सरल शब्दों में कहें तो इसरो ने अपने शक्तिशाली रॉकेट एलवीएम-3 एम6 से अमेरिका का भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है तथा एलवीएम-3 वही रॉकेट है, जिसने पहले चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब मिशन जैसे बड़े अभियानों को सफल बनाया है। एक ही साल में दो एलवीएम-3 मिशन करना यह दिखाता है कि भारत अब भारी उपग्रह लॉन्च करने में तेजी से मजबूत हो रहा है।ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह की खास बात यह है कि इसके जरिए बिना मोबाइल टावर के भी मोबाइल फोन पर 4जी-5जी कॉल, इंटरनेट और मैसेजिंग संभव होगी, चाहे इलाका हिमालय हो, रेगिस्तान हो या समुद्र। गौरतलब है कि यह उपग्रह भारत की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के सहयोग से लॉन्च किया गया है।यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग का मजबूत उदाहरण है।

इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत सिर्फ लॉन्च सेवा देने वाला देश नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार भी है। इस सफलता से भारत को भविष्य में और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लॉन्च मिल सकते हैं। कम लागत, भरोसेमंद तकनीक और सफल अनुभव के कारण इसरो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कुल मिलाकर, यह प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है और आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व की ओर ले जा सकता है। अंत में यही कहूंगा कि भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी करीब 6,100 किलोग्राम उपग्रह एलवीएम-3 एम6 का सफल प्रक्षेपण इसरो की तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इससे निश्चित ही वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत तथा सुदृढ़ हुई है। अब तक छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण में दक्ष भारत ने इस मिशन के जरिए बड़े और अगली पीढ़ी के उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी अपनी विश्वसनीयता सिद्ध की है।

स्कूल के बाहर खड़ी आधी आबादी : जब बेटियाँ बीच रास्ते लौट आती हैं

- डॉ. प्रियंका सौरभ

छूटी हुई पाठशाला, छिनते सपने : भारत की बेटियों की अधूरी शिक्षा; अधिकार से वास्तविकता तक : लड़कियों की स्कूली ड्रॉपआउट की क्रूर सच्चाई; स्कूल के बाहर खड़ी आधी आबादी : जब बेटियाँ बीच रास्ते लौट आती हैं; किताब, काँच और क़ैद : पितृसत्ता के साये में लड़कियों की शिक्षा; ड्रॉपआउट की दीवार के पार : भारत की बेटियाँ और शिक्षा का संघर्ष; अनुच्छेद 21A से आगे की लड़ाई : क्यों छूट जाती हैं बेटियाँ स्कूल से?; संविधान ने हक़ दिया, समाज ने रोका : लड़कियों की अधूरी स्कूली यात्रा; सायकिल, शौचालय और सुरक्षा : तीन कुंजियाँ, जो बेटियों को स्कूल में रोक सकती हैं; बाल विवाह, घरेलू बोझ और डर : लड़कियों की शिक्षा के अदृश्य दुश्मन; जब स्कूल नहीं, घर बनता है किस्मत : बेटियों की शिक्षा और भारतीय समाज।

भारत में लड़कियों की स्कूली शिक्षा की कहानी आज़ादी के बाद के विकास-वृत्तांत की सबसे जटिल और मार्मिक कड़ी है। संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, पर ज़मीनी तस्वीर बताती है कि जैसे-जैसे कक्षा बढ़ती है, लड़कियों की संख्या कम होती जाती है और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुँचते-पहुँचते बड़ी संख्या में बेटियाँ स्कूल से बाहर हो चुकी होती हैं। यह केवल शैक्षणिक ढाँचे की विफलता नहीं, बल्कि गहरे बैठे सामाजिक पूर्वाग्रह, पितृसत्ता, आर्थिक अभाव और राज्य की अधूरी प्रतिबद्धताओं की संयुक्त देन है। सबसे पहले बात स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की, जो लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार और शिक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बीच की सबसे कठोर दीवार बनकर खड़ी हैं। आज भी अनेक सरकारी स्कूलों में अलग, सुरक्षित और कार्यशील शौचालयों की कमी है; जहाँ शौचालय बने भी हैं, वहाँ साफ-सफाई, पानी और रखरखाव की स्थिति अक्सर बेहद खराब रहती है। किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ और सम्मानजनक व्यवस्था जीवन की बुनियादी ज़रूरत है; लेकिन जब स्कूल इस ज़रूरत को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो परिवार के लिए सबसे आसान विकल्प लड़की को घर बैठा देना होता है। स्वच्छ पेयजल, सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता, कचरा निस्तारण जैसी बातें कागज़ी योजना-दस्तावेज़ों में चाहे जितनी आकर्षक दिखें, ज़मीन पर उनकी कमी लड़कियों के हौसले को बार-बार तोड़ती है।

यह वही उम्र है जहाँ शिक्षा आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का रास्ता खोल सकती है, लेकिन अवसंरचना की कमी उसे 'ड्रॉपआउट' के आँकड़ों में बदल देती है। दूसरा बड़ा कारक स्कूल तक पहुँच का है, जिसमें दूरी और सुरक्षा दोनों शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अक्सर गाँव से कई किलोमीटर दूर स्थित होते हैं। लड़के किसी तरह साइकिल या पैदल यह दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में हर किमी के साथ असुरक्षा, झिझक और जोखिम भी बढ़ जाता है। रास्ते में छेड़खानी, उत्पीड़न, सुनसान सड़कें, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और देर से घर लौटने का डर, माता-पिता के मन में यह धारणा गहरी कर देते हैं कि 'इतनी दूर भेजना सुरक्षित नहीं।' जहाँ-जहाँ साइकिल वितरण, छात्राओं के लिए सुरक्षित बस-सेवा, या क्लस्टर-स्कूल जैसा मॉडल ईमानदारी से लागू हुआ, वहाँ यह साफ़ दिखा कि परिवहन-सुरक्षा की समस्या हल होते ही लड़कियों की उपस्थिति, ट्रांज़िशन रेट और बोर्ड तक बने रहने के आँकड़े बेहतर हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सही नीतिगत हस्तक्षेप से 'दूरी' नाम की बाधा को शिक्षा का रास्ता रोके बिना भी संभाला जा सकता है। तीसरी वजह घर की चारदीवारी के भीतर छिपी है—घरेलू काम और देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना में बेटा अक्सर 'भविष्य का कमाने वाला' और बेटी 'परिवार की ज़िम्मेदारी' मानी जाती है। गरीब और निम्न-मध्यवर्गीय परिवारों में माँ के साथ खाना बनाना, बर्तन-कपड़े धोना, छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना, पानी लाना, खेत या दुकान में मदद करना—इन सभी कामों का सबसे आसान विकल्प लड़की ही बनती है।

उसके स्कूल-समय को 'लचीला' समझा जाता है; जैसे ही घर का बोझ बढ़ता है, सबसे पहले उसकी पढ़ाई कटती है। सर्वेक्षण बार-बार दिखाते हैं कि बहुत-सी लड़कियाँ 'पढ़ाई में रुचि नहीं' की वजह से नहीं, बल्कि 'घर के काम' और 'परिवारिक ज़िम्मेदारी' के कारण स्कूल छोड़ती हैं, लेकिन डेटा में इसे अक्सर गलत ढंग से दर्ज कर दिया जाता है। यह अदृश्य श्रम, जो घर और समाज के पहियों को चलाता है, लड़की के अधिकारों और भविष्य के रास्ते में सबसे बड़े रोड-ब्लॉक में बदल जाता है। चौथा निर्णायक तत्व है बाल विवाह और विवाह-केंद्रित सामाजिक मानसिकता। आज भी अनेक समुदायों में यह मान्यता जीवित है कि लड़की की 'इज़्ज़त' और 'भविष्य' का असली उपाय उसे जल्दी ब्याह देना है, न कि लंबी शिक्षा देना। ज़्यादा पढ़ाई को कई बार 'बिगड़ने', 'पति न मानने' या 'शादी देर से होने' के ख़तरे के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर के सर्वे साफ़ दिखाते हैं कि अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी लड़कियों में 18 वर्ष से पहले विवाह की संभावना कहीं अधिक होती है, जबकि उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों में यह अनुपात बहुत कम है।

यह दुष्चक्र बेहद क्रूर है—कम शिक्षा बाल विवाह को जन्म देती है और बाल विवाह आगे की शिक्षा की संभावना लगभग समाप्त कर देता है। शादी के बाद ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, जल्दी गर्भधारण का सामाजिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, लड़की को स्कूल से स्थायी रूप से बाहर कर देते हैं। इन सबके ऊपर आर्थिक बाधाएँ एक तरह से 'सील' का काम करती हैं। भले ही सरकारी स्कूलों में फीस नाममात्र की हो या न हो, लेकिन यूनिफॉर्म, जूते-चप्पल, किताबें, कॉपियाँ, परीक्षा शुल्क, ट्यूशन, परिवहन—इन अप्रत्यक्ष खर्चों का बोझ गरीब परिवारों के लिए बहुत भारी होता है। ऐसे परिवारों की आर्थिक गणित अक्सर बेटे के पक्ष में झुक जाती है; उन्हें लगता है कि लड़के की शिक्षा पर निवेश का प्रतिफल नौकरी या कमाई के रूप में मिलेगा, जबकि लड़की की पढ़ाई 'निवेश से अधिक दान' जैसी समझी जाती है। यह सोच कई बार लड़कियों को बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं से बाहर धकेल देती है, तो कई बार आठवीं, दसवीं या बारहवीं के मोड़ पर उनकी शिक्षा का धागा टूट जाता है।

इन कारणों का असर भारत के सार्वभौमिक विद्यालयीकरण के लक्ष्य पर गहरा और दूरगामी है। सबसे पहले तो यह संकट सतत विकास लक्ष्य 4 (सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) की दिशा में भारत की प्रगति को बाधित करता है। जब माध्यमिक स्तर पर ही लड़कियों की बड़ी संख्या स्कूल से बाहर हो जाती है, तो साक्षरता, नामांकन और परीक्षा-उत्तीर्णता के आँकड़ों में स्थायी लैंगिक खाई बन जाती है। 'सार्वभौमिक' शब्द केवल प्रवेश-सूची में दिखता है, लेकिन क्लासरूम और परीक्षा-परिणाम में नहीं। दूसरा असर अंतरपीढ़ी गरीबी पर पड़ता है। शोध लगातार दिखाते हैं कि शिक्षित माँ अपने बच्चों की सेहत, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा में अधिक सजग और निवेशकारी होती है। जब लड़की स्वयं शिक्षा से वंचित रह जाती है, तो उसके लिए अगली पीढ़ी को शिक्षा-केंद्रित जीवन देना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरह एक पीढ़ी का ड्रॉपआउट, अगली पीढ़ी के अवसरों को भी सीमित कर देता है और गरीबी की जंजीरें टूटने के बजाय और मजबूत हो जाती हैं। तीसरा बड़ा असर आर्थिक विकास और उत्पादकता पर दिखता है। यदि महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी, शिक्षा और कौशल के सहारे, पुरुषों के बराबर या उसके करीब पहुँच सके तो भारत की त्र्छक्र में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है; लेकिन जब लाखों लड़कियाँ माध्यमिक स्तर से बाहर हो जाती हैं, तो यह संभावित मानव-पूँजी कभी विकसित ही नहीं हो पाती।

वीर बाल दिवस : साहिबजादों के शहादत की अमर गाथा

बाल मुकुन्द ओझा

सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह के दोनों छोटे पुत्रों की शहादत को सम्मान देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह वही तारीख है जिस दिन उनके दोनों छोटे पुत्रों - साहिबजादे जोरावर सिंह (उम्र 7 वर्ष) और साहिबजादे फतेह सिंह (उम्र 9 वर्ष) को वजीर खान ने जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था। उनके सम्मान में 2022 से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 26 दिसंबर को सिक्खों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस और और त्याग को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस दुनियाभर में मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोराबर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की मानवता की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी की याद में वीर बाल दिवस आयोजित किया जाता है। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी ने दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाने के बाद शहीदी प्राप्त की थी। इन दो महान हस्तियों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मौत को चुना। गुरु गोविन्द सिंह की तरह उनके बेटे भी साहसी थे। युवा और मासूम लड़के, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने 26 दिसंबर, 1705 को शहादत प्राप्त की, जब उन्हें सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ऐतिहासिक घटना के अनुसार संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर साहिब किले से हुई। यह वह समय था जब गुरु गोबिंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों तक युद्ध चल रहा था। गुरु जी में गजब का साहस था और वे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके हौसले को देखकर औरंगजेब भी सदमे में था। अंत में गुरु जी को हराने के लिए औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लिया। इसलिए, उसने गुरुजी को एक पत्र लिखा 'मैं कुरान की कसम खाता हूं, अगर आप आनंदपुर के किले को खाली करते हैं, तो मैं आपको बिना किसी बाधा के यहां से जाने दूंगा।' गुरुजी को कुछ अंदेशा था कि औरंगज़ेब अपनी बात से कभी भी पलट सकता है। फिर भी, वह किला छोड़ने के लिए सहमत हो गए। गुरुजी का अंदेशा सही था। जल्द ही, मुगल सेना ने गुरुजी और उनकी सेना पर हमला कर दिया। सरसा नदी के तट पर एक लंबी लड़ाई हुई और गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे गुरूजी के साथ सरसा नदी पार कर चमकौर साहिब गढ़ी पहुंचे। वहीं दो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी देवी के साथ रवाना हुए। जंगल में तमाम मुश्किलों को पार करते हुए छोटे साहिबजादे अपनी दादी के साथ एक गुफा में रहे। गंगू जो एक ब्राह्मण था और लंगर का सेवक था और उसे इस बात की जानकारी मिली। वह सभी को अपने घर ले आया। पैसे के लालच में गंगू ने गुरुजी को धोखा दिया। पहले गंगू ने माता की अशर्फियां चुराईं और फिर कोतवाल को बताया कि माताजी और साहिबजादे उनके साथ रह रहे हैं। कोतवाल ने साहिबजादों और माताजी को कैद कर लिया। अगली सुबह उन्हें सरहिंद पुलिस थाने ले जाया गया।

साहिबजादों की शहादत और वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता

- महेन्द्र तिवारी

भारत के इतिहास में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जहाँ धर्म, सत्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन सिख इतिहास में गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की शहादत जैसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। भारत सरकार ने 2022 में 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में घोषित किया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उस अमर गाथा से प्रेरणा ले सकें जिसमें बाल उम्र में भी धर्म, साहस और आस्था की ज्योति बुझने नहीं दी गई। सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन ही संघर्ष, चेतना और धर्म की रक्षा का प्रतीक रहा है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के साथ उन्होंने सिख धर्म को एक ऐसी पहचान दी, जिसमें आध्यात्मिकता और वीरता एक-दूसरे से अलग नहीं थीं। उस समय का भारत धार्मिक असहिष्णुता, ज़बरदस्ती धर्मांतरण और सत्ता के दमन से ग्रस्त था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पष्ट किया कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की नैतिक शक्ति है। यही संस्कार उनके पुत्रों में भी उतरे, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब की घेराबंदी सिख इतिहास की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। महीनों तक चली इस घेराबंदी में भूख, प्यास और निरंतर युद्ध ने सिख समुदाय को तोड़ने का हर प्रयास किया। अंततः छलपूर्वक सुरक्षित मार्ग का आश्वासन देकर मुग़ल सेना ने गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को अलग-थलग कर दिया। इसी दौरान दो बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। वे युद्धभूमि में शहीद हुए, जहाँ मृत्यु भी पराजय नहीं, बल्कि गौरव का रूप थी। लेकिन इतिहास का सबसे हृदयविदारक प्रसंग तब सामने आया जब छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सिरहिंद पहुँचे। मात्र नौ और सात वर्ष की आयु में इन बालकों को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया। यह वह क्षण था जहाँ सत्ता को लगा कि भय और लालच से बालमन को झुकाया जा सकता है। परंतु इन नन्हे साहिबजादों ने जिस दृढ़ता से अपने धर्म और आस्था की रक्षा की, उसने मानव इतिहास में साहस की परिभाषा ही बदल दी।

उनका इनकार केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का घोष था। यातनाएँ दी गईं, भय दिखाया गया, किंतु वे टस से मस नहीं हुए। अंततः उन्हें दीवार में जीवित चिनवा देने का क्रूर आदेश दिया गया। यह घटना केवल शारीरिक यातना का वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक और नैतिक दृढ़ता का प्रमाण है, जो बालकों को भी वीर बना देती है। कहा जाता है कि जिस ठंडे दिसंबर के दिन यह अमानवीय कृत्य हुआ, उस दिन ईंटों के साथ केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था की नैतिकता भी चिन दी गई। माता गुजरी जी ने भी कारागार में ही अपने प्राण त्याग दिए। एक दादी, जिसने अपने पोतों की अडिग आस्था देखी थी, उसने भी जीवन की अंतिम साँस उसी विश्वास के साथ ली कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह प्रसंग भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है, जहाँ पारिवारिक प्रेम, धार्मिक निष्ठा और आत्मसम्मान एक साथ शहादत में परिणत हो जाते हैं। आज के समय में 'वीर बाल दिवस' की प्रासंगिकता केवल अतीत को स्मरण करने तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमने साहस को किस हद तक केवल प्रतीकात्मक बना दिया है। बच्चों के लिए वीरता आज अक्सर काल्पनिक पात्रों या स्क्रीन तक सिमट गई है। साहिबजादों की गाथा हमें बताती है कि सच्ची बहादुरी नैतिक निर्णयों से जन्म लेती है जहाँ गलत के सामने झुकने से इनकार करना ही सबसे बड़ा शौर्य है।